



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2015/चैत्र 17, 1937

No. 82]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2015/CHAITRA 17, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2015

अन्तिम जाँच परिणाम

**विषय :** चीन जन. गण. यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड में उदभवित अथवा वहाँ से निर्यातित "प्योरिफाइड टैरेफ्टैलिक एसिड" (पीटीए) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 14/7/2013-डीजीएडी : समय—समय पर यथासंशोधित सीमा—शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं सग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- यतः, मैसर्स एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) (जिन्हें एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने एक आवेदन—पत्र चीन जन.गण., यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी तथा थाईलैण्ड (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध दश कहा गया है) में उदभवित अथवा वहाँ से निर्यातित प्योरिफाइड टैरेफ्टैलिक एसिड (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु या पीटीए कहा गया है) के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच, अधिनियम एवं नियमों के अनुसार आरंभ करने के लिए पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप हुई क्षति का आरोप लगाते हुए दायर किया है तथा सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण करने का अनुरोध किया है।
- और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर नियमावली के उप—नियम 5 के अनुसार संबद्ध जाँच प्रारंभ करते हुए दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 को अधिसूचना सं. 14/7/2013-डीजीएडी के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया ताकि आरोपित पाटन की मौजूदगी मात्रा एवं प्रभाव का आकलन किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जो, यदि उपग्रहित की गई तो, घरेलू उद्याग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।
- और यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण., यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी, और थाईलैण्ड के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातिक सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अन्तिम पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हुए दिनांक 19 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या 14/7/2013-डीजीएडी के तहत प्रारम्भिक जाँच परिणाम जारी किए। पदनुसार केन्द्रीय सरकार

ने दिनांक 25, जुलाई 2014 को अधिसूचना सं. 36/2014—सीमा—शुल्क के तहत चीन जन.गण., यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड में उद्भवित अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अनन्तिम पाठनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया।

#### क. प्रक्रिया

5. सम्बद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

- (i) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में प्राधिकारी ने भारत में चीन जन. गण. यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड के राजदूतावासों/प्रतिनिधियों को सूचित किया।
- (ii) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम 5 के उपबंधों के अलावा भारत और कोरिया आरपी के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार(सीईपीए) के अनुच्छेद 2.14 के उपबंधों के अनुसार संबद्ध आवेदन की प्राप्ति के बारे में कोरिया आरपी की सरकार को भारत स्थिति उसके राजदूतावास के जारिए सूचित किया गया।
- (iii) प्राधिकारी ने दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में चीन. जन. गण., यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड के राजदूतावासों चीन. जन. गण., कोरिया आरपी और थाईलैण्ड के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार प्रेषित की और उनसे अनुरोध के या कि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना के 40 दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं।
- (iv) प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियमावली के नियम6(3) के अनुसार इस आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन. जन. गण., यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड के राजदूतावासों/प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई।
- (v) नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार इस जांच की शुरुआत के बारे में चीन जन. गण., यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड के भारत स्थित राजदूतावासों/प्रतिनिधियों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय—सीमा के अंतर्गत प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों के प्रेषित पत्र एवं प्रश्नावली की एक प्रति चीन.जन.गण., यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम एवं पते सहित उन्हें भी प्रेषित की गई।
- (vi) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम6(4) के अनुसार चीन. जन. गण. यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातक प्रश्नावली प्रेषित की :

- क. बीपीझुहाई कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन. जन. गण.
- ख. जियांग्लु पेट्रोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन. जन. गण.
- ग. जियाकिंग पेट्रोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन. जन. गण.
- घ. झेजियांग यिशेंग पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन. जन. गण.
- ङ. झेजियांग युआनडांग पेट्रोकैमिकल, चीन. जन. गण.
- च. यिशेंग दाहुआ पेट्रोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन. जन. गण.
- छ. हैंगली पेट्रोकैमिकल, चीन. जन. गण.
- ज. जिनान शिजिटानगडा कैमिकल कंपनि लिमिटेड, चीन. जन. गण.
- झ. सैमसंग टोटल पेट्रोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी
- ज. सैमसंग पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी
- ट. हायोशुंग पेट्रोकैमिकल, कोरिया आरपी
- ठ. हायोशुंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी
- ड. टैक्वांग इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड, कोरिया आरपी.
- ढ. होनाम पेट्रोकैमिकल कारपोरेशन, कोरिया आरपी.
- ण. सैमसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी
- त. सैमनाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी
- थ. एस. के. पेट्रोकैमिकल, कोरिया आरपी
- द. लोट्टे कैमिकल, कोरिया आरपी
- ध. इंडोरामा पेट्रोकैम लिमिटेड, थाईलैण्ड
- न. टीपीटी पेट्रोकैमिकल, पीसीएल कोरिया आरपी
- प. सियम मित्सुई पीटीए कंपनी, लिमिटेड, थाईलैण्ड
- फ. बीपी कैमबेल एन वी, बेल्जियम
- ब. सेप्सा कुझमिका एसए, स्पेन
- भ. लोट्टे कैमिकल यू. के. लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम
- म. बीपी कैमिकल्स लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम
- य. आर्टलान्ट पीटीए, पुर्तगाल

कक. पी के एन ओरलेन एसए, पौलेंड

(vii) चीन, जन. गण., कोरिया आरपी, यूरोपियन यूनियन और थाईलैंड के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया :

- क. इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड, थाईलैंड
- ख. टीपीटी पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लिमिटेड, थाईलैंड
- ग. सेमसंग सी एंड टी कारपोरेशन, कोरिया आरपी
- घ. सेमसंग पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी, जिसे अब सैमसंग जनरल कैमिकल्स कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।
- ड. एस के पेट्रोकैमिकल इंक, कोरिया आरपी (उत्पादक) को मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान (निर्यातक) के साथ टैक्बांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी
- च. ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी
- ज. झेयांग यिशेंग पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन. जन. गण.
- झ. निंग्बो हंगी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन. जन. गण.

(viii) चीन के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया :

- क. झेजियांग यिशेंग पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड
- ख. निंग्बो हंगी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- ग. यिशेंग दाहुआ पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड
- घ. हैनान यिशेंग पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड

(ix) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां प्रेषित कीं :

- क. वेलनोन पोलिस्टर लिमिटेड, मुंबई
- ख. जे बी एफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
- ग. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
- घ. इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया), लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा
- ड. दि बाबे डाइंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, मुंबई
- च. धुनसेरी पेट्रोकेम एंड टी लिमिटेड, कोलकाता
- छ. गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड, मुंबई
- ज. फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड, मुंबई
- झ. जिंदल पाली फिल्म लिमिटेड, नई दिल्ली
- ज. नकोदा लिमिटेड, मुंबई
- ट. सुमीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सूरत
- ठ. राज रेयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
- ड. एसोसिएशन आफ सिथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज (ए एस एफ आई), नई दिल्ली
- ढ. पीटीए यूजर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली

(x) निम्नलिखित आयातकों/उपयोक्ताओं ने विहित प्रपत्र में आयातक पश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया :

- क. धुनसेरी पेट्रोकेम एंड टी लिमिटेड
- ख. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
- ग. दि बाबे डाइंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
- घ. जिंदल पाली फिल्म्स लिमिटेड
- ड. जेबीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- च. वेलनोन पालिएस्टर्स लिमिटेड
- छ. इंडोरामा सिन्थेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड
- ज. सुमीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(xi) घरेलू उद्योग तथा निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच शुरुआत पश्चात प्रस्तुतिकरण भी किए गए :

- क. धुनसेरी पेट्रोकेम एंड टी लिमिटेड
- ख. फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड

ग. इंडोरामा सिन्थेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड  
 घ. दि बाब्दे डाइंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी  
 उ. जे बी एफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड  
 च. गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड  
 छ. सुमीत इण्डस्ट्रीज लिमिटेड  
 ज. आलोक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड  
 झ. राज रेयान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड  
 झ. जिन्दल पालीफिल्म्स लिमिटेड  
 ट. सैमसंग पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड  
 ठ. हयोसंग कारपोरेशन  
 ड. एस के पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड  
 ढ. टैक्वांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड  
 ण. इंडोरामा पेट्रोकैम लिमिटेड  
 त. टीपीटी पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी  
 थ. बीपी कैमबल एन वी, ईयू  
 द. बीपीएरोमैटिक्स, ईयू  
 ध. बी पी जुहाई कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन गण.  
 न. पोलिएस्टर फिल्म इंडस्ट्रीज एसोसिएशन  
 प. पीटीए यूजर्स एसोसिएशन  
 फ. दि सदन इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए)  
 ब. एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री  
 म. कैमिकल्स एण्ड पेट्रोकैमिकल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन

(xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षों का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा गया।

(xiii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से संबद्ध वस्तु के पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के दौरान किए गए आयातों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने इस अन्तिम जांच परिणाम में डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों पर भरोसा किया है।

(xiv) याचिकार्ता ने यह याचिका चीन. जन. गण ; यूरोपियन यूनियन, कोरिया आरपी और थाईलैण्ड से सम्बद्ध वस्तु के कथित पाटन का आरोप लगाते हुए दायर की है और उसने डी जी सी इर्झ एण्ड एस के प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत करने के लिए याचिकार्ता द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों पर भरोसा किया। जांच शुरुआत के पश्चात, प्रधिकारी ने डी जी सी आई एण्ड एस से सौदे-वार का आयात आंकड़े भी प्राप्त किए और प्रारम्भिक जाँच परिणाम जारी किया।

(xv) प्रारम्भिक जाँच-परिणाम के पश्चात कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क किया कि जाँच की अवधि के दौरान चीन. जन. गण. और यूरोपियन यूनियन. से सम्बद्ध बस्तु का निर्यात भारत में पीटीए के कुल आयातों का 3% से भी कम है और इसलिए, यूरोपियन यूनियन और चीन जन. गण. को सम्बद्ध देशों के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप सौदावार डी जी सी आई एण्ड एस आंकड़ों का पुनः विश्लेषण किया गया और उनका डी जी सिस्टम्स के आंकड़ों से प्रति –सत्यापन किया गया और यह नोट किया गया कि जाँच की अवधि के दौरान यूरोपियन यूनियन और चीन जन.गण. से सम्बद्ध वस्तु का आयात न्यूनतम पाया गया। उपर्युक्त रिपोर्ट और पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत निर्धारित निबंधनों को ध्यान में रखते हुए प्रधिकारी ने चीन जन. गण. और यूरोपियन यूनियन से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के सम्बंध में जाँच खरिज कर दी और कोरिया आरपी तथा थाईलैण्ड (जिन्हें एतदपश्चात सम्बद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों के सम्बंध में जाँच जारी रखी।

(xvi) सैनडिस्क इण्टरनेशनल लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 744 / 2015 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 18.03.2015 के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एस एल पी) दायर करने के प्रधिकारी के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना डीजीसीआई एण्ड एस से सम्बद्ध वस्तु के सौदावार आयातों के प्राप्त विवरण के अगोपनीय पाठ और इस अन्तिम जाँच परिणाम में भरोसा किए गए आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में खुला रखी।

(xvii) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर गैर-क्षतिकारी निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम तर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xviii) घरेलू उद्योग सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया। वर्तमान अन्तिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ, जहां कहीं लागू हुआ, केवल इस तरह सत्यापित सूचना, आवश्यक संशोधनों सहित, पर भरोसा किया गया।

(xix) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि को 12 अप्रैल, 2009 से जांच की अवधि की समाप्ति तक अर्थात् 2009–10, 2010–11, 2011–12 और जांच की अवधि को जांच की अवधि के रूप में माना गया है।

(xx) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने वाले पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुझाव दिया गया कि वे लिखित प्रस्तुतिकरण और प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत करें।

(xxi) जांच की कार्रवाई के दौरान घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और संगत माने गए प्रस्तुतिकरणों की जांच की गई और इस अन्तिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उनका समाधान कर दिया गया है।

(xxii) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच की मनाही की है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में भारी व्यवधान डाला है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगकर्ता के रूप में मान लिया और अन्तिम जांच परिणाम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड किए हैं।

(xxiii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है और इसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को यह निर्दश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं और उसे नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

(xxiv) पूर्वोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 28 मार्च, 2015 के प्रकटन विवरण के तहत इस जांच के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया और उन पर प्राप्त एवं प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों का इस अन्तिम जांच परिणाम में निराकरण कर दिया गया है।

(xxv) \*\*\*इस प्रारंभिक जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे वैसा ही माना है।

(xxvi) वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई विनियम दर 1 अमरीकी डालर=54.65 रुपए है।

(xxvii)

(xxviii) केन्द्रीय सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अपने दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 354/95/2014-टीआरयू के तहत इस जांच को पूरा करने और अन्तिम जांच परिणाम जारी करने की समय सीमा दिनांक 07 अप्रैल, 2015 तक बढ़ा दी है।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) प्यूरीफाइड टैरेपथैलिक एसिड (पीटीए), अपने सभी प्राकारान्तरों – मीडियम क्वालिटी टैरेपथैलिक एसिड (एमटीए) और क्वालीफाइड टैरेपथैलिक एसिड (क्यूटीए) सहित है। प्यूरीफाइड टैरेपथैलिक एसिड (पीटीए) एक सफेद फ्री फ्लोइंग क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो किसी भी द्रूटिंगोचर संदूषण से मुक्त है। टैरेपथैलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक फार्मूला सी<sub>6</sub> एच<sub>4</sub> (सीओआएच<sub>2</sub>) होता है। यह 402 डिग्री सेल्सियस पर अधर्वपातित हो जाता है और यह जल एवं अल्कोहल में कम घुलनशील है। पीटीए पालिएस्टर चिप्स बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा माल है जिसका टैक्सटाइल्स, पैकेजिंग, फर्नीशिंग, उपभोक्ता वस्तुओं, रेजिन्स और कोटिंग्स में कई अनुप्रयोगों हेतु प्रयोग किया जाता है। चूंकि क्यूटीए, एमटीए और पीटीए रासायनिक रूप से समान उत्पाद हैं और चूंकि उनका प्रयोग अंतर्निमय रूप से किया जाता है, इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में क्यूटीए और एटीए को भी शामिल किया जाता है। आवेदकों द्वारा किए गए दावे के अनुसार, डाइ-मिथाइल टैरेपथैलिक (डीएमटी) रसायनिक रूप से एक भिन्न उत्पाद है और इसलिए, यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। इस विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के उप-शीर्षक संख्या 29173600 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

## घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

(i) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद प्योरिफाइड टैरेपथैलिक एसिड, अपने सभी प्रकारान्तरों मीडियम क्वालिटी टैरेपथैलिक एसिड (एमटीए) और क्वालीफाइड टैरेपथैलिक एसिड (क्यूटीए) जिस एतदपश्चात 'विचाराधीन उत्पाद' या पीटीए कहा गया है। प्योरिफाइड टैरेपथैलिक एसिड (पीटीए) एक सफेद फ्री पलोइंग क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो किसी भी दृष्टिगोचर संदृष्टि से मुक्त है (जिसे एतदपश्चात विचाराधीन उत्पाद अथवा पीटीए कहा गया है) इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के उप-शीर्षक संख्या 2917 3600 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। टैरेपथैलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक फार्मूला सी<sub>6</sub> एच<sub>4</sub> (सीओओएच<sub>2</sub>) होता है। यह 42 डिग्री सेल्सियस पर उर्ध्वपातित हो जाता है और यह जल एवं अल्कोहल में कम घुलनशील होता है। पीटीए पालिएस्टर चिप्स बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा माल है जिसका टैक्सटाइल्स, पैकेजिंग, फर्निशिंग्स, उपभोक्ता वस्तुओं, रेजिन्स और कोटिंग्स में कई अनुप्रयोगों हेतु प्रयोग किया जाता है। एमटीए और क्यूटीए रासायनिक रूप से पीटीए के समान ही होते हैं। पीटीए, एमटीए और क्यूटीए के बीच एकमात्र अंतर क्यूटीए और एमटीए में मौजूद अशुद्धता के स्तर में होता है। पीटीए, एमटीए और क्यूटीए का उत्पादन समान प्रौद्योगिकी, संयंत्र एवं उपकरण, विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल का प्रयोग करके किया जाता है। तीनों समान कार्यों का निष्पादन करते हैं। यह सभी समान सीमा-शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तीनों उत्पादों के बीच अंतर केवल अशुद्धताओं के स्तर में होता है। वास्तव में, उत्पादक जैसे एस के कैमिकल एमटीए का उत्पादन करते हैं परंतु साहित्य में उसका उल्लेख पीटीए के रूप में किया जाता है।

(ii) डाइ-मिथाइल टैरेपथालेट (डीएमटी) रासायनिक रूप से पीटीए से भिन्न उत्पाद है। डीएमटी और पीटीए की उत्पाद प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र एवं उपकरण, कच्चा माल, तकनीकी विनिर्देशन अलग-अलग होते हैं। तथापि, डीएमटी और पीटीए का प्रयोग कुछ अनुप्रयोगों में अंतर्निमेय रूप से किया जाता है। तथापि, डीएमटी को सभी प्रयोगों में पीटीए के स्थान पर/प्रतिस्थानी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। भारत में डीएमटी का न तो उत्पादन होता है और न ही भारत में डीएमटी का आयात किया जाता है। वर्तमान याचिका पीटीए (इसके प्रकारान्तरों, एमटीए और क्यूटीए सहित) पर पाटनरेधी शुल्क के लिए है और यह याचिका भारत में पीटीए के उत्पादकों द्वारा दायर की गई है। डीएमटी वास्तव में एक ऐसा उत्पाद है जिसको चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा रहा है और डीमएटी के स्थान पर पीटीए को प्रतिस्थानीकर दिया गया है। चूंकि, इसका न तो भारत में उत्पादन होता है और न ही भारत में इसका आयात किया जाता है इसलिए उत्पाद के दायरे में डीएमटी शामिल नहीं है। चूंकि क्यूटीए, एमटीए और पीटीए रासायनिक रूप से समान उत्पाद हैं और इसके अतिरिक्त, चूंकि उनका प्रयोग अंतर्निमेय रूप से किया जाता है इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में क्यूटीए और एमटीए को शामिल किया जाता है।

## निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है।

## प्राधिकारी द्वारा जांच

9. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरणों कि जांच एवं उनका समाधान निम्नलिखित है :

(i) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित प्योरिफाइड टैरेपथैलिक एसिड (पीटीए), अपने सभी प्रकारान्तरों – मीडियम क्वालिटी टैरेपथैलिक एसिड (एमटीए) और क्वालीफाइड टैरेपथैलिक एसिड (क्यूटीए) सहित है। विचाराधीन उत्पाद प्योरिफाइड टैरेपथैलिक एसिड (पीटीए) एक सफेद फ्री पलोइंग क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो किसी भी दृष्टिगोचर संदृष्टि से मुक्त है। टैरेपथैलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक फार्मूला सी<sub>6</sub> एच<sub>4</sub> (सीओओएच<sub>2</sub>) होता है। यह 402 डिग्री सेल्सियस पर उर्ध्वपातित हो जाता है और यह जल एवं अल्कोहल में कम घुलनशील है। पीटीए पालिएस्टर चिप्स बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा माल है जिसका प्रयोग टैक्सटाइल्स, पैकेजिंग, फर्निशिंग्स, उपभोक्ता वस्तुओं, रेजिन्स और कोटिंग्स में कई अनुप्रयोगों हेतु किया जाता है। चूंकि क्यूटीए, एमटीए और पीटीए रासायनिक रूप से समान उत्पाद हैं और चूंकि उनका प्रयोग अंतर्निमेय रूप से किया जाता है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में क्यूटीए और एमटीए को भी शामिल किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के उप-शीर्षक संख्या 29173600 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

(ii) आवेदकों द्वारा यथा-दावाकृत डाइमिथायल टैरेपथैलेट (डीएमटी) रासायनिक रूप से एक भिन्न उत्पाद है और इसलिए वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है।

(iii) समान वस्तु के संबंध में पाटनरेधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है :

'समान वस्तु' का तात्पर्य ऐसी किसी वस्तु से है जो भारत में पाटन किए जाने हेतु जांचाधीन वस्तु के हर तरह से समानुरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में इसका आशय किसी ऐसी दूसरी वस्तु से है जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं।

(iv) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकारों एवं प्रयोगों, उत्पादन विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्तागण इसका प्रयोग अन्तर्निमय रूप से कर रहे हैं। इस विचाराधिन उत्पाद का आयात कर रहे उपभोक्ताओं ने इसकी घरेलू उद्योग से खरीद भी की है। उपर्युक्त के महेनजर, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद को नियमों के अनुसार घरेलू समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

#### ग. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

##### निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

10. घरेलू उद्योग के दायरे एवं आधार के संबंध में इस जांच की कार्रवाई के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- (i) आईओसीएल, जो इस सम्बद्ध वस्तु की बिक्री अन्य दो घरेलू आवेदक उत्पादकों से सस्ती कीमत पर कर रहा है और अपना पीटीए संयंत्र 100% क्षमता उपयोग पर लाभप्रद रूप से प्रचालित कर रहा है, उसने न तो इस जांच में भाग लिया है और न ही इस याचिका का समर्थन किया है। इसलिए, वर्तमान जांच को अविलम्ब समाप्त कर देना चाहिए।
- (ii) एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माने जाने के लिए अर्ह नहीं है क्योंकि वह अपनी शेयरधारिता के कारण मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान, मित्सुबिशी कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मरुबेनी कारपोरेशन जापान, सामयांग कारपोरेशन, कोरिया आरपी और साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी से संबद्ध हैं।
- (iii) एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प. इंडिया लिमिटेड (एमसीपीआई) मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान की एक 100 प्रतिशत अनुंगी है। मित्सुबिशी कारपोरेशन क्षति अवधि में संबद्ध देशों से अधिप्रापण करके भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने में संलिप्त रहा है। मित्सुबिशी कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआईएल) ने इनका आयात किया और भारत में उनकी बिक्री की। मित्सुबिशी कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआईएल) एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) का भारत में एजेंट के रूप में भी कार्य कर रहा था।
- (iv) निर्यातक (मित्सुबिशी कारपोरेशन – एमसी), आयातक (मित्सुबिशी कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – एमसीपीआईएल) और याचिकाकर्ता (एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड – एमसीपीआई) को मित्सुबिशी ग्रुप द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसलिए एमसीपीआई संबद्ध वस्तु के एक निर्यातक और आयातक से संबद्ध है।
- (v) मित्सुबिशी कारपोरेशन, की एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) में भारी शेयरधारिता है और वह अपनी एक पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमसीपीआईएल को एक बिक्री एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए एमसीपीआई पी दबाव डाल रहा है जिससे कि उसे लाभ हो सके।
- (vi) मरुबेनी कारपोरेशन, एमसीपीआईएल के शेयरधारक, एमसीपीआईएल का बिक्री एजेंट है और वह संबद्ध वस्तु का एक आयातक है। मरुबेनी एवं एम सी द्वारा संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का आयात/निर्यात किया जाता है। इसलिए, एतसीपीआई को घरेलू उद्योग के रूप में अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए।
- (vii) साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया पर मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन (एमसीसी) और सामयांग कारपोरेशन, कोरिया का नियंत्रण है क्योंकि उनका साम नाम में 80 प्रतिशत शेयर है। एमसीसी जापान की साम नाम पेट्रोकैमिकल्स कम्पनी लिमिटेड में सर्वाधिक शेयरधारिता (40%) है और इसलिए उसका अनुंगी के रूप में उल्लेख करता है। इसलिए एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) और सामयांग दोनों संबद्ध कंपनियां हैं।
- (viii) मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन का एमसीसी पीटीए में 66 प्रतिशत शेयर है और साम नाम पेट्रोकैमिकल्स, कोरिया में उसका 40 प्रतिशत शेयर है। एमसीसी द्वारा धरित इस शेयर के कारण उसका एमसीसी पीटीए और साम नाम पेट्रोकैमिकल्स के प्रचालनों तथा उसके अधिशासी निर्णयों में भी उसका नियंत्रण होता है। साम नाम पेट्रोकैमिकल्स इस जांच में एक नामित निर्यातक है, इसलिए नियम 2(ख) के स्पष्टीकरण के उपर्युक्त (i) (ख) के अनुसार एमसीसी पीटीए, एमसीसी और साम नाम पेट्रोकैमिकल्स कोरिया के बीच यह संबंध स्पष्टतः एमसीसी पीटीए का घरेलू उद्योग की परिभाषा से अपवर्जन कर देगा।
- (ix) साम नाम पेट्रोकैमिकल्स कम्पनी लिमिटेड कोरिया आरपी से सम्बद्ध उत्पाद की निर्यातक है। साम नाम में, मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन जापान और सामयांग कारपोरेशन कोरिया दोनों में से प्रत्येक की 40 प्रतिशत शेयरधारिता है और उसमें शेष 20 प्रतिशत जी. एस. काल्टेक्स कोरिया द्वारा धारित किया जाता है। चूंकि मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन जापान एमसीपीएल (भारत में घरेलू उत्पादक) और साम नाम (कोरिया आरपी से सम्बद्ध वस्तु का निर्यातक)दोनों को ही नियंत्रित कर रहा है, इसलिए एमसीपीएल को घरेलू उद्योग के एक संघटक के रूप में अनुर्ध्व कर दिया जाना चाहिए।

(x) मित्सुबिशी कारपोरेशन जापान और मरुबेणी कारपोरेशन जापान, एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प्राइवेट लिमिटेड की एकसम्बद्ध पक्षकार हैं और वे सम्बद्ध वस्तु की खरीद कम कीमतों पर करती हैं और उसका भारत को निर्यात करती है, जिससे जांच की अवधि के लिए सकारात्मक क्षतिमार्जिन की स्थिति सुरक्षित कर रहा है।

(xi) मित्सुबिशी कारपोरेशन जापान और सैमसंग कोरिया ने प्रतिमाह 4000–5000 एमटी पीटीए की खरीद/बिक्री करने के लिए 01 नवंबर 2012 को एक संविदा किया यह सभी किवे संव्यवहार भारतीय बाजार के लिए किया गया था। अतः एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई यह घोषणा गलत एवं भ्रामक है कि इसकी किसी भी सम्बद्ध/सहबद्ध कम्पनी ने सम्बद्ध वस्तु का भारत को निर्यात नहीं किया है।

(xii) क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से आयातों में वृद्धि हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बीपी कैमिकल्स (मलेशिया) एसडीएनबीएचडी (बीपीसीएम) में 100 प्रतिशत पांच प्राप्त कर लिया है। पीटीए के कच्चे माल को रिलायंस द्वारा मलेशिया भेजा गया और उसे पीटीए में संपरिवर्तित किया गया और फिर उसका भारत में पुनः आयात करके उसकी भारत में बिक्री की गई।

### घरेलू उद्योग द्वारा गए प्रस्तुतिकरण

11. घरेलू उद्योग के दायरे एवं आधार के संबंध में जांच की कार्रवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

(i) आईआसीएल के संबंध में यह तथ्य कि इसने वर्तमान याचिका का समर्थन नहीं किया है, प्राधिकारी को जांच की कार्रवाई से निवारित नहीं करता है। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल यह जांच करना होता है कि क्या (क) आवेदन का अभियक्त रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है; और (ख) आवेदन का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया जिनका सामूहिक उत्पादन, घरेलू उद्योग के आवेदन का समर्थन अथवा उसका विरोध करने वाले उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक है या नहीं। ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है जो यह विहित करती हो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस जांच की शुरुआत और यह जांच तभी करना चाहिए जब आई ओ सी एल ने वर्तमान याचिका का समर्थन किया है।

(ii) इस तर्क के लिए कोई आधार नहीं है कि आई ओ सी एल की कीमते, घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा पेशकश की जा रही कीमतों की तुलना में सस्ती हैं। यह निराधार है कि आईआसीएल के निष्पादन पर बढ़ती कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई ओ सी एल की कीमतें भी आयात कीमतों द्वारा शासित होती हैं।

(iii) एमसीसी पीटीए कार्प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) की शेयरधारिता पद्धति निम्नलिखित है :

क्र. सं.	शेयरधारक	शेयरधारिता
1	मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन, जापान	66%
2	मित्सुबिशी कारपोरेशन	10%
3	सॉजिटज कारपोरेशन	8%
4	मरुबेणी कारपोरेशन	6%
5	टोयोटा ट्सुशो	5%
6	वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	5%

(iv) कोरिया के उत्पादकों में से एक उत्पादक अर्थात मैसर्स साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी शेयर धारिता निम्नलिखित है :

क्र. सं.	शेयरधारक	शेयरधारिता
1	सामयांग कारपोरेशन, कोरिया	40%
2	जी. एस. कालेटक्स, कोरिया	20%
3	मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन, जापान	40%

(v) मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन जापान का एमसीसी पीटीए कार्प्राइवेट लिमिटेड, भारत में 66 प्रतिशत शेयर तथा साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया में 40 प्रतिशत शेयर है। अतः, एमसीसी पीटीए कार्प्राइवेट लिमिटेड भारत का सामयांग या जीएस कालेटक्स से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये कोरियाई कंपनियां हैं।

(vi) साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड के \*\*\* निदेशक हैं, जिनमें से \*\*\* प्रत्येक को \*\*\* द्वारा और \*\*\* द्वारा नामित किया गया है। एक निदेशक \*\*\* मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन, जापान द्वारा नामित किया जाता है, उसका साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। मित्सुबिशी कैमिकल्स कारपोरेशन, साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड को निदेश देने अथवा उस पर अन्यथा नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसकी शेयरधारिता में आंधिकता का अभाव है।

(vii) साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत में अपने उपभोक्ताओं में से एक को \*\*\* एमसी पीटीए की बिक्री की है। इसको छोड़कर, साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किया है। साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड ने \*\*\* को यह सामग्री परीक्षण उत्पाद के रूप में प्रदान की है। मैसर्स\*\*\*प्रति वर्ष \*\*\* एम टी (\*\*\*स्ट्रीम्स) का उत्पादन करने के लिए \*\*\*में एक संयंत्र की स्थापना कर रहा है जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। \*\*\* ने साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड से इस नए संयंत्र के लिए पीटीए खरीदने की संभावनाओं का पता लगाया है। इसलिए, इस कंपनी ने साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद का परीक्षण करने के लिए इस सामग्री की खरीद की। अतः, साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया यह निर्यात तकनीकी विचार के लिए एक आपवादिक लेनदेन है न कि साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया एक नियमित निर्यात है।

(viii) यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार प्राप्त है। किसी भी हाल में इस मामले में तथ्य स्पष्टतः यह सिद्ध करते हैं कि दोनों याचिकाकर्ता कंपनियों को नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत पात्र धरेलू उद्योग के रूप में समझा जाना चाहिए।

(ix) मित्सुबिशी ग्रुप जैसा कोई सांविधिक निकाय नहीं है। इसलिए इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि ऊपर सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी भी कंपनी पर नियंत्रण मित्सुबिशी ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एमसीपीआई को मित्सुबिशी कारपोरेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और न ही एमसीपीआई मित्सुबिशी कारपोरेशन को नियंत्रित करती है, न ही एमसीपीआई और मित्सुबिशी कारपोरेशन पर किसी तृतीय पक्षकार का नियंत्रण है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एम सी पी आई और मित्सुबिशी कारपोरेशन नियमों के अंतर्गत संबद्ध कंपनियों हैं।

(x) जहां तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि मरुबेणी कारपोरेशन एमसीपीआईएल का एक बिक्री एजेंट है, एमसीपीआईएल का एक शेयरधारक और संबद्ध वस्तु का आयातक है, इस विचारार्थ मरुबेणी की निम्नलिखित शेयरधारिता प्रतिमान प्रासंगिक है:

शेयरधारिता प्रतिमान	
वित्तीय संस्थान	***%
व्यक्तिगत	***%
घरेलू निकाय	***%
गैर-घरेलू निकाय	***%
अन्य	***%
प्रमुख शेयरधारक	
दि मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान लिमिटेड	***%
जापान ट्रस्टी सर्विसेस बैंक लिमिटेड	***%
सोम्पो जापान इंश्योरेंस इंक	***%
जे पी मार्गन चेज बैंक	***%
जापान ट्रस्टी सर्विसेज बैंक	***%
मैजी यशुदा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	***%
टोकियो मेरीन एंड निकिडो फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	***%
मिज्जुहो बैंक	***%
बरकलेज सिक्योरिटीज जापान लिमिटेड	***%
निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी	***%

(xi) अतः, एमसीपीआई को मरुबेणी कारपोरेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, न ही एमसीपीआई मरुबेणी कारपोरेशन को नियंत्रित करती है, न ही एमसीपीआई और मरुबेणी कारपोरेशन को तृतीय पक्षकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एमसीपीआई और मरुबेणी कारपोरेशन नियमों के अंतर्गत संबद्ध पक्षकार हैं।

(xii) एमसीपीआई का पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या नियर्तक से कोई संबंध नहीं है क्योंकि उनमें से कोई भी दसरे पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रण नहीं करता है; न ही एमसीपीआई और न ही नियातकों/आयातकों पर तृतीय व्यक्ति का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई विचार नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त, यह विश्वास करने अथवा संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि इस संबंध का प्रभाव ऐसा है जो उत्पादकों को असंबद्ध उत्पादकों से मिन्न व्यवहार करने के लिए मजबूर करें।

(xiii) इस तर्क के संबंध में कि मित्सुबिशी कारपोरेशन और सैमसंग ने 1 नवम्बर, 2012 को यह समझौता किया कि वे प्रतिमाह 4000–5000 एमटी पीटीए की बिक्री/खरीद करेंगे, जो सारा का सारा भारतीय बाजारों के लिए होगा, मित्सुबिशी कारपोरेशन एमसीपीआई से संबद्ध नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ताओं में से किसी भी एक का मित्सुबिशी कारपोरेशन के भारत में उत्पाद का पाटन करने के निर्णय पर कोई नियंत्रण नहीं है।

(xiv) इस तर्क के संबंध में कि एमसीपीआई ने अपनी संबद्धता का खुलासा नहीं किया है और न ही यह स्पष्ट किया है कि मित्सुबिशी कारपोरेशन ने नियमित आधार पवर भारी मात्रा में आयात किया है। एमसीपीआई मित्सुबिशी कारपोरेशन से संबद्ध नहीं है और इसलिए वह मित्सुबिशी कारपोरेशन को भारत में अपने उत्पाद की बिक्री करने से प्रतिवारित नहीं कर सकता है।

(xv) मलेशिया से निर्यात न्यूनतम है और इसलिए किसी एक याचिकाकर्ता कंपनी का किसी एक मलेशियाई उत्पादक के साथ संभावित सम्बंध होने का मुद्दा पूरी तरह से असंगत है।

(xvi) याचिकाकर्ता ने सम्बद्ध देशों से भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। वे नियम 2(ख) के आशय के अन्तर्गत इस विचाराधीन उत्पाद के आयातक नहीं हैं। याचिकाकर्ता भारत में इसी विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से सम्बद्ध नहीं हैं। यद्यपि एम सी सी पीटीए कार्प. प्राइवेट लिमिटेड इंडिया निर्यातक देशों में किसी उत्पाद/निर्यातक से सम्बद्ध नहीं है, और यदि यह माना भी जाता कि यह कंपनी कोरिया के उत्पादकों में से किसी एक उत्पादक अर्थात मैसर्स साम नाम पेट्रोकैमिकल्स कम्पनी लिमिटेड की सम्बद्ध कम्पनी है तो भी मैसर्स साम नाम पेट्रोकैमिकल कम्पनी लिमिटेड इस विचाराधीन उत्पाद का भारतीय बाजार में एक नियमित निर्यातक नहीं है। इसलिए, दोनों याचिकाकर्ता कम्पनियों को नियम 2(ख) के आशय के अन्तर्गत पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

(xvii) विधिकी यह एक सुस्थापित रिथ्टि है कि प्राधिकारी, अपने विवेक से किसी ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट कर सकता है जो या तो सम्बद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों से सम्बद्ध हो या उसने घरेलू उद्योग के दायरे के अन्तर्गत सम्बद्ध वस्तु का आयात किया हो। इसलिए, यदि यह मान भी लिया जाता है कि एमसीपीआई का विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों से सम्बद्ध है तो भी निर्दिष्ट प्राधिकारी एमसीपीआई को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानने के लिए स्व-विवेक का प्रयोग कर सकते हैं इस कम्पनी द्वारा किए गए निर्यात को भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के इस विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन और खपत संबंध में बहुत कम हिस्सा है। इसलिए किसी भी हाल में, यह निर्यात कम्पनी को घरेलू उद्योग के रूप समझे जाने से उसकी हकदारी नहीं छीन सकते हैं।

(xviii) यह तर्क कि मित्सुबिशी कारपोरेशन जापान (एमसी) और मरुबेणी कारपोरेशन जापान, कोरिया आरपी से कम कीमतों पर खरीद कर रहे हैं और उसका क्रमशः मित्सुबिशी कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मरुबेणी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बहुत कम उत्तराई कीमत की घोषणा करकेनियांत कर रहे हैं निराधार है। मित्सुबिशी कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मरुबेणी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का घरेलू उद्योग से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, घरेलू उद्योग को इसके असम्बद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए किसी क्रियाकलाप के कारण उपचार प्राप्त करने से मना नहीं किया जा सकता है। यह भी सिद्ध नहीं होता है कि भारत को निर्यात कीमत कीमत की तुलना में वास्तव में कम है।

(xix) एक और तो, पीटीए प्रयोगकर्ता एसोसिएशन ने यह इंगित किया है कि आई ओ सी एल की इसमें कोई प्रतिभागिता नहीं है। वहीं दूसरी ओर, इस एसोसिएशन ने यह प्रश्न किया है कि जब आर आई एल ही घरेलू उद्योग है तो एमसीपीआई ने घरेलू उद्योग के रूप में प्रतिभागिता क्यों की है। कोई भी कम्पनी जिसे इस उत्पाद के पाटन के कारण क्षति हुई हो वह उपचारार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

(xx) यह तर्क देने का कोई विधिक आधार नहीं है कि जब तक कम्पनी की आपात्रता को सिद्ध करने लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक एमसीपीआई घरेलू उद्योग का एक भाग हो सकती है। अकेले एमसीपीआई का उत्पादन ही कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है और निर्दिष्ट प्राधिकारी अकेले एमसीपीआई को ही नियमावली के अन्तर्गत घरेलू उद्योग के रूप में मान सकते हैं।

(xxi) याचिकाकर्ता निमावली के अन्तर्गत घरेलू उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त इस आधार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) द्वारा शासित किया जाता है और इस मामले में याचिकाकर्ता उसे पूरा करते हैं।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

12. घरेलू उद्योग के दायरे एवं आधार के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा विचारार्थ संगत माने गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों की जांच एवं उनका समाधान निम्नलिखित है :

(i) यह आवेदनपत्र घरेलू उद्योग की और से मैसर्स एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) द्वारा दायर किया गया है इन दो घरेलू उत्पादकों के अलावा भारत में पीटीए का एक अन्य उत्पादक भी है नामशः इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)। तथापि, पीटीए के उक्त घरेलू उत्पादक ने न तो इस आवेदन का समर्थन किया है और न ही उसका विरोध किया है। आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, मैसर्स एम सी सी पीटीए इंडिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन समान उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है। आवेदकों ने घोषित किया है कि विचाराधीन उत्पाद का न तो उहोंने आयात किया है और न ही भारत में उनके किसी संबद्ध पक्षकार ने इस उत्पाद का आयात किया है। पुनः यह घोषित किया गया है कि आवेदकों का भारत में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक से या संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के

निर्यातकों से कोई संबंध नहीं है। पाटनरोधी के नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या (क) आवेदन का अभिव्यक्त रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है; और (ख) आवेदन का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया जिनका सामूहिक उत्पादन, घरेलू उद्योग के आवेदन का समर्थन अथवा उसका विरोध करने वाले उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक है या नहीं। इसलिए, वर्तमान जांच के लिए आई ओ सी एल द्वारा किए गए किसी भी समर्थन के अभाव कोई महत्व नहीं है। विरोधकर्ता पक्षकारों द्वारा किए गए यह प्रस्तुतिकरण कि आई ओ सी एल घरेलू उद्योग की कीमतों से सस्ती कीमतों पर सम्बद्ध वस्तु की बिक्री कर रहा है और अपना पीटीए संयंत्र 100% क्षमता उपयोग के साथ लाभप्रद ढंग से प्रचालित कर रहा है, के सम्बंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

(ii) जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि एमसीपीआई को निर्यातकों और/या आयातकों के साथ संबंध होने के कारण घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में योग्य नहीं माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम में यह प्रावधान है कि :

(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में वाक्यांश “घरेलू उद्योग” का शेष उत्पादकों के रूप में उल्लेख किया जा सकता है।

(iii) विकीपीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि मित्सुबिशी ग्रुप जापान की स्वशासी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक समूह है जो व्यासाय की एक व्यापक शृंखला को कवर करता है और मित्सुबिशी ब्रांड, ट्रेडमार्क और लीगैसी को शेयर करता है। इसलिए, एमसीपीआई का ‘मित्सुबिशी ग्रुप’ के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(iv) इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी “मित्सुबिशी काम” पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट करते हैं कि “मित्सुबिशी” एक समुदाय है जिसमें स्वतंत्र कंपनियों का एक गुणक शामिल है। उनमें सकं अधिकांश कंपनियों के नाम में “मित्सुबिशी” शब्द का उल्लेख रहता है परंतु यह नाम सभी में नहीं होता है और अधिकांश कंपनियां थी-डायमंड मित्सुबिशी चिन्ह का प्रयोग करती हैं। परंतु इनमें से कोई भी अपने को सामान्यतः “मित्सुबिशी” नहीं कहता है। इसके अतिरिक्त, वेब आधारित सूचना यह उल्लेख करती है कि ये कंपनियां अपने व्यवसाय क्रियाकलाप स्वतंत्र रूप से करती हैं और कई क्षेत्रों में तो वह एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करती हैं। चूंकि, वे सामान आधारभूत प्रबंधन दर्शन को शेयर करती हैं, इसलिए वे सामान्य हित के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करती हैं जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जनहित क्रियाकलाप। इन कंपनियों ने इंटरनेट पर एक मित्सुबिशी पोर्टल ‘मित्सुबिशी.काम’ नाम से स्थापित किया है जिससे मित्सुबिशी के संबंध में एक व्यापक परिदृश्य प्रदान किया जा सके। परंतु चूंकि उक्त वेब आधारित सूचना यह दर्शाती है कि इन कंपनियों में निर्णय करने वाला कोई निकाय नहीं होता है जो इन कंपनियों की समग्र नीति का निर्धारण करता हो।

(v) घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न पक्षकारों, जिनके साथ एमसीपीआई के संबंधों का आरोप लगाया है, के शेयरधारिता प्रतिमान निम्नलिखित है :

क. एमसीसी पीटीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमसीपीआई) का शेयरधारिता प्रतिमान

क्र. सं.	नाम	शेयरधारिता%
1	मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन, जापान	66%
2	मित्सुबिशी कारपोरेशन	10%
3	सोजिटल कारपोरेशन	8%
4	मरुबेणी कारपोरेशन	6%
5	टोयोटा ट्सुशो कारपोरेशन	5%
6	पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	5%

ख. मित्सुबिशी कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक प्रतिमान

नाम	शेयरधारिता(%)
मित्सुबिशी कारपोरेशन	100%

ग. मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन के शेयरधारिता प्रतिमान

नाम	शेयरधारिता (%)
दि मास्टर ट्रस्ट बैंक आफ जापान, लिमिटेड (ट्रस्ट एकाउंट)	***
मैजी यशुदा लाइफ इंस्योरेंस कंपनी (ट्रस्ट एकाउंट)	***
जपान ट्रस्टी सर्विसेस बैंक, लिमिटेड, (ट्रस्ट एकाउंट)	***
निप्पन लाइफ इंस्योरेंस लिमिटेड	***
बैंक आफ टोकिया — मित्सुबिशी यू एफ जे, लिमिटेड	***
टकेडा फामास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	***
टोकियो मैरी एंड निचिडो फायर इंस्युरेंस कंपनी लिमिटेड	***
दि बैंक आफ न्यूयार्क, द्वीटी जेएसडीईसी एकाउंट	***
ताइयो लाइफ इंस्युरेंस कंपनी	***
जापान ट्रस्टी सर्विसेस बैंक लिमिटेड	***

घ. मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान के शेयरहोल्डिंग प्रतिमान

नाम	शेयरधारिता (%)
वित्तीय संस्थान	***
विदेशी कंपनियां	***
व्यक्तिगत	***
अन्य कंपनियां	***

ड. मरुबेणी कारपोरेशन का शेयरधारिता प्रतिमान

शेयरहोल्डिंग प्रतिमान	(%)
वित्तीय संस्थान	***
व्यक्तिगत	***
घरेलू निकाय	***
गैर-घरेलू निकाय	***
अन्य	***

प्रमुख शेयरधारक	
नाम	शेयरधारिता (%)
दि मास्टर ट्रस्ट बैंक आफ जापान, लिमिटेड (ट्रस्ट एकाउंट)	***
जपान ट्रस्टी सर्विसेस बैंक लिमिटेड (ट्रस्ट एकाउंट)	***
सोम्पो जापान इंस्युरेंस इंक	***
जे पी मारगन चेज बैंक 380055	***
जपान ट्रस्टी सर्विसेस बैंक लिमिटेड (ट्रस्ट एकाउंट)	***
मैजी यशुदा लाइफ इंस्योरेंस कंपनी	***
टोकियो मैरीन एंड निचिडो फायर इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड	***
मिश्नो बैंक लिमिटेड	***
बार्कलेस सिक्योरिटीज जापान लिमिटेड	***
निप्पन लाइफ इंस्योरेंस कंपनी	***

च. साम नाम पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी की शेयरधारिता प्रतिमान

क्र. सं.	शेयरधारक	शेयरधारिता
1.	सैमयांग कारपोरेशन, कोरिया	40%
2.	जी एस काल्टेक्स, कोरिया	20%
3.	मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन, जापान	40%

(vi) प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि नियमों के अंतर्गत संबद्ध पक्षकार को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

(i) उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों के साथ संबद्ध केवल तभी माना जा सकता है जब :-

क) उनमें से एक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे पर नियंत्रण करता हो; या

ख) उनमें से दोनों पर किसी तृतीय व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रण किया जाता हो; या

ग) उनका एक साथ किसी अन्य पुरुष पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रण इस शर्त के अध्यधीन हो कि यह संदेह करने अथवा यह विश्वास करने के आधार हैं कि इस संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादकों को अन्य असंबद्ध उत्पादकों से भिन्न व्यवहार करने के लिए मजबूर होना पड़ता हो।

(ii) ऐसा माना जाएगा कि किसी उत्पादक का किसी दूसरे उत्पाद पर नियंत्रण तभी है जब पूर्ववर्ती विधिक रूप से या प्रचलनात्मक रूप से ऐसी स्थिति में हो कि वह उत्तरवर्ती पर अवरोध या नियंत्रण कर सके।

(vii) अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दो निकायों को एक दूसरे से संबद्ध निकाय के रूप में तभी माना जा सकता है जब उपर्युक्त में से कोई एक शर्त पूरी होती हो। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एमसीपीआई मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन, जापान से इस आधार पर एक सम्बद्ध कर्पनी है कि परवर्ती कर्पनी का अधिकांश शेयर उसके पास है। तथापि, जापान वर्तमान जांच में सम्बद्ध देश न होने के कारण उसके इस सम्बद्धता से कोई संगतता नहीं है।

(viii) प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि साम नाम पेट्रोकैमिकल कर्पनी लिमिटेड, कोरिया, जिसमें मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन, जापान की भारी शेयरधारिता है, न जांच की अवधि के दौरान \*\*\*एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया है। तथापि, आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान साम नाम द्वारा भारत को किए गए संबद्ध वस्तु के आयात आपवादिक हैं और यह कोई नियमित व्यापारिक प्रक्रिया नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार, साम नाम कोरिया में मित्सुबिशी कैमिकल कारपोरेशन जापान की शेयरधारिता को ऐसे नहीं माना जा सकता है कि उसका साम नाम कोरिया के वाणिज्यिक क्रियाकलापों में निदेशक मंडल में अधिकांश प्रतिनिधित्व के बिना, नियंत्रणकारी प्रभाव हैं।

(ix) प्राधिकारी नोट करते हैं कि साम नाम कोरिया आरपी द्वारा संगत अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यात संबद्ध देशों से कुल निर्यातों का महज \*\*\*% बनते हैं और जांच की अवधि के दौरान कोरिया आरपी से किए गए कुल आयातों का केवल \*\*\*% है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में कोरिया आरपी एक संबद्ध देश है और एमसीपीआई के संबद्ध पक्षकार होने के बावजूद, साम नाम कोरिया द्वारा किए गए निर्यात भी पाटनरोधी उपायों, यदि उनका अधिरोपण किया गया तो, के अध्यधीन होंगे। अतः, यदि निर्णयक पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण किया जाता है तो इस संबंध के कारण एमसीपीआई को कोई अनुचित लाभ नहीं होगा।

(x) प्राधिकारी नोट करते हैं कि मरुबेणी कारपोरेशन की एमसीपीआई में कोई महत्वपूर्ण शेयरधारिता नहीं है। मरुबेणी कारपोरेशन की भारत में मरुबेणी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक पूर्णस्वामित्व वाली अनुंपंगी कर्पनी है जिसने भारत में इस विचाराधी उत्पाद का आयात किया है। तथापि, मरुबेणी कारपोरेशन द्वारा एमसीपीआई में धारित अमहत्वपूर्ण शेयरधारिता को एमसीपीआई की निर्णय करने की प्रक्रिया में वास्तविक प्रभाव के रूप में उपचित नहीं किया जा सकता है।

(xi) जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान और मरुबेणी कारपोरेशन जापान सम्बद्ध वस्तु की खरीद कोरिया आरपी से कर रहे हैं और उसकी भारत में बिक्री अपने सम्बद्ध निकायों के माध्यम से कम कीमत पर कर रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रथमतः तो यह सभी तर्क आसाक्षयांकित है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में जापान एक असंबद्ध देश है।

(xii) जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान और सैमसंग, कोरिया ने प्रतिमाह 4000–5000 एमटी पीटीए की खरीद/बिक्री करने की एक संविदा की है और यह सभी संव्यवहार भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाकर किए जाएंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त संविदा, यदि कोई है तो, वह दो स्वतंत्र निकायों के बीच की गई है और ऐसी वाणिज्यिक व्यवस्था का वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है।

(xiii) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि रिलायंस अपने अधिगृहीत मलेशियाई संयंत्र अर्थात् बी पी कैमिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बी एच डी (बी पी सी एम)में कच्चे माल का संपरिवर्तन करने और उसका भारत को पुनः करने में सक्षिप्त है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त संविदा, यदि कोई है तो, वह दो स्वतंत्र निकायों की कोई संगतता नहीं है। इसके अतिरिक्त, मलेशिया से आयात न्यूनतम है।

13. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एमसीपीआई को अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस तथ्य पर विश्वास करने अथवा उसमें संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि किसी निर्यातक या आयातक के साथ एमसीपीआई के संबंधों का प्रभाव ऐसा होगा कि वह कंपनी गैर-संबद्ध उत्पादक से भिन्न व्यवहार करने लगे। एमसीपीआई का प्रधान व्यवसाय उत्पादन है न कि आयात/व्यापार करना। इसके अतिरिक्त, यदि इस संबंध से एमसीपीआई को कोई अनुचित लाभ उपचित होता तो

रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो एक संयुक्त आवेदक है, ने वर्तमान जांच में एमसीपीआई के साथ सहयोग करने का विकल्प नहीं दिया होता। उपर्युक्त के महेनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि मैसर्स एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड एक पात्र घरेलू उत्पादक है जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

14. विस्तृत जांच के पश्चात् प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि मैसर्स एमसीसी पीटीए इंडिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है और इसलिए वे नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप मानदण्डों का पूरा करते हैं।

#### घ. गोपनीयता

##### निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

15. गोपनीयता के संबंध में जांच की अवधि के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :—

- आवेदकों ने, विशेषकर साम नाम के निदेशकों के ब्यौरों के सम्बद्ध में सूचना के लिए, अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। साम नाम के निदेशकों के ब्यौरों के लिए आवेदकों द्वारा की गई गोपनीयता का दावा बहुत अधिक है और उसे समाप्त कर दिया जाना अपेक्षित है।
- प्राधिकारी ने भी कीमत से सम्बद्धित सूचना, मालसूची आदि के सम्बद्ध में अत्यधिक गोपनीयता की अनुमति दी है।
- सार्वजनिक फाइल में सौदावार आयात आंकड़ों का भी प्रकटन नहीं किया गया है।

##### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण :

16. गोपनीयता के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :—

- याचिकाकर्ता ने केवल ऐसी सूचना के लिए ही गोपनीयता का दावा किया है जिसकी गोपनीयता की अनुमति देना प्राधिकारी की सुसंगत परम्परा के अनुरूप है और नियमों के अंतर्गत जिसकी अनुमति दे दी गई है।
- याचिकाकर्ता ने आवेदन का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान किया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार किसी ऐसी सूचना पर उंगली उठाने में समर्थ नहीं हुआ है जिसका गोपनीयता का दावा किया गया हो और नियमों के अंतर्गत जिसकी गोपनीयता न्यायोचित न ठहरायी गयी हो।
- साम नाम के निदेशकों के लिए गोपनीयता के दावे के संबंध में यह तथ्य कि कोई नियंत्रण नहीं है, का आशय यह नहीं है, कि संगत सूचना का प्रकटन किया जा सकता है।
- भारत में निर्यात की सकल मात्रा, घरेलू बाजार में बिक्री की सकल मात्रा, उत्पादन, बिक्री, भारत को निर्यातों के लिए औसत कीमत जैसी सूचना के लिए प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा गोपनीयता का दावा किया गया है। वास्तव में इस सूचना में वाणिज्यिक रूप से कुछ भी संवेदनशील नहीं है।
- अधिकांश निर्यातकों ने अनुक्रमित सूचना भी प्रदान नहीं की है, यद्यपि सूचना अनुक्रमित रूप में सारांशीकरण किए जाने के योग्य है।
- हितबद्ध पक्षकारों ने, उनके द्वारा प्रश्नावली प्रत्युत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का आश्रय लिया है।
- प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सौदावार गोपनीय डीजीसीआई एण्ड एस आयात आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे जा सकते हैं।

##### प्राधिकारी द्वारा जांच

17. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरणों की जांच और उनका समाधान निम्नवत किया गया है :

- सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है :—

गोपनीय सूचना — (1) नियम 6 के उप-नियम (7), नियम 12 के उप-नियम (2) (3), (2) नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) तथा उप-नियमों में किसी बात का उल्लेख होने के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों की प्रतियां या जांच की कार्रवाई के दौरान किसी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रदान कराई

गई किसी सूचना को केवल तभी गोपनीय माना जाएगा जब निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गापनीयता से संतुष्ट हों और ऐसी सूचना का, उक्त सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राविकृतिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को, प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी यह अपेक्षा करते हैं कि गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार उसका अगोपनीय सारांश भी प्रस्तुत करेंगे और यदि, सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव न हो तो उक्त पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत करेंगे कि उक्त सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के हाते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए उनकी चाह वांछनीय नहीं है या ऐसी सूचना का प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है अथवा वह उसे सामान्यकृत या सार रूप में प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत करें तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

(ii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है और इसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षों का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी भी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

(iii) सैनडिस्क इण्टरनेशनल लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 744/2015 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 18.03.2015 के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने के प्राधिकारी के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, सम्बद्ध वस्तु के आयातों के सम्बंध में डी जी सी आई एण्ड एस से प्राप्त सौदेवार आयातों को विवरण का अगोपनीय पाठ विवरण और इस अन्तिम जांच परिणाम में भरोसा किए गए अगोपनीय पाठ को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

#### उ. विविध प्रस्तुतिकरण

##### निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

18. विविध मुद्दों के संबंध में जांच की कार्रवाई के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित है :-

- (i) वर्तमान जांच की शुरुआत और प्रारम्भिक जांच परिणाम आवेदकों की पात्रता में गम्भीर त्रुटि होने, आवेदकों को, कीमतया लाभक्षति का अभाव होने और सम्बद्ध आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव होने के कारण विधि विरुद्ध है।
- (ii) प्रारम्भिक जांच परिणाम में डीजीएडी ने यह जांच नहीं की कि क्या जांच की कार्रवाई के दौरान क्षति का निवारण करने के लिए अनन्तिम शुल्क अपेक्षित है। इसका निर्धारण किए बिना, डीजीएडी को अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए।
- (iii) भारत में मांग और आपूर्ति के बीच में भारी अन्तर है। कुल 2179204 एमटी की मांग की तुलना में घरेलू उत्पादक केवल 1531245 एम टी की आपूर्ति ही कर सके। देश में उत्पादित किए जा रहे सम्पूर्ण पीटीए का अवशोषण उपयोक्ता उद्योग द्वारा कर लिया जाता है और आपूर्ति में होने वाली कमी की पूर्ति आयातों द्वारा की जाती है। चूंकि पीटीए का आयात करना अनिवार्य हो गया है इसलिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अनधिपत्रित है।
- (iv) पीटीए पालिएस्टर फिलामेंट, स्टेपल फाइबर, पालिएस्टर फिल्म आदि के लिए एक आधारभूत कच्चा माल है जिनका प्रयोग वस्त्रों, पैकेजिंग सामग्री, और पीटीए बोतलों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू बाजार में पीटीए की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी और इसका अनुप्रवाही उत्पादों की उत्पादन लागत एवं विपणयता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से इसके अनुप्रवाही उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में कमी आएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात् से सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग अधिक आयातों, न्यून क्षमता उपयोग और अधिक बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है।
- (v) पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण और अन्तिम उत्पादों पर कोई पाटनरोधी शुल्क न लगाने से अन्तिम उत्पादों का भारत से खरीद करने के बजाय घरेलू क्रेतागण आयात करने को प्रोत्साहित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इससे न केवल अत्यावश्यक विदेशी विनियम का निर्गमन होगा बल्कि इससे आयातों के प्रतिरक्षणीय अन्तिम उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को भी क्षति सहन करनी होगी।

(vi) चूंकि पैराक्सीलीन के आयातों की अनुमति शून्य सीमा—शुल्क पर दी जाती है, इसलिए भारत में पीटीए के विनिर्माताओं को कोई अतिरिक्त संरक्षण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा, पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पालियस्टर सेक्टर में प्रतिलोमित शुल्क ढांचा सृजित होगा। पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात् शुल्क में 10% से 16% वृद्धि तक की हो गई है जबकि अन्तिम उत्पादों पर केवल 5% आयात शुल्क ही लगाया गया है। इस प्रतिलोमित शुल्क ढांचा के कारण घरेलू उद्योग को अधिक आयातों घरेलू उत्पाद की संबंधित लागत, कम क्षमता उपयोग और बेरोजगारी के कारण नुकसान हुआ है।

(vii) पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उद्योगों की क्षमता उपयोग में पालियस्टर स्टैपल फाइबर (पीएसएफ), पालियस्टर फिलामेंट यार्न (पीफाई) और पालियस्टर चिप्स के आयातों में वृद्धि होने के कारण 10% की कमी आई और भारत से वस्त्र के निर्यातों में कमी आई है।

(viii) आर आई एल एक समन्वित रिफाइनरी एवं रसायन कम्पनी है जो क्रूड आयल से पीटीए का उत्पादन करती है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पीईटी के अन्य विनिर्माताओं को, न कि आर आई एल को, नुकसान होगा क्योंकि आरआई एल के पास पीटीए का ग्राही विनिर्माण करने की सुविधा है।

(ix) तथापि, एमसीसीपीआई क्रय किए गए पीएक्स से पीटीए का उत्पादन कर रही है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति में कमी होने के कारण पीएक्स की कीमत बहुत अधिक थी, परन्तु पीटीए की कीमत घट गई। तदनुसार आर आई एल और एमसीसीपीआई के बीच लागत का भारी अन्तर होना चाहिए और उत्पादन लागत का साधारण संचयन करने से कीमत निग्रहण विश्लेषण का परिणाम विकृत हो जाएगा।

(x) याचिकाकर्ताओं ने मौखिक सुनवाई के दौरान यह उल्लेख किया कि जांच की शुरुआत करने के पश्चात् खासकर अप्रैल—जून 2014 में, पीटीए के आयातों में वृद्धि हुई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीटीए के प्रयोक्ताओं के पास घरेलू उत्पादकों द्वारा उसकी आपूर्ति करने में अक्षम रहने के कारण आयातों में वृद्धि करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त, आई ओ और एल का संयंत्र एक बड़ी खाराबी के कारण 45 दिनों या उसके अधिक समय के लिए बंद हो गया था।

(xi) यदि आवेदक पीटीए की बिक्री पर घाटे का दावा कर रहे हैं तो डीजीएडी को आवेदक द्वारा उसे रिपोर्ट किए गए इन घाटों के सम्बंध में क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पादकर आयुक्तालय से सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य नहीं किया गया। इस प्रस्तुतिकरण पर विचार न किए जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है।

(xii) पीटीए पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से आर आई एल को छोड़कर अन्य सभी घरेलू उत्पादकों ने पीटीए की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी। इसका अनुप्रवाही पालियस्टर उद्योग पर गम्भीर एवं गैर-न्यायोचित विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि आर आई एल को छोड़कर अन्य सभी पालियस्टर उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की राशि के द्वारा कच्चे माल (घरेलू और आयातित दोनों) की लागत में वृद्धि हो गयी। इसलिए, पीटीए की विनिर्माताओं को कथित क्षति से रक्षा करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप इसके अनुप्रवाही पालियस्टर उद्योग को गम्भीर क्षति हुई।

(xiii) आर आई एल का पीटीए की बाजार में 51% हिस्सा होने के कारण उसकी घरेलू फाइबर मध्यवर्ती बाजार में प्रमुख स्थिति है। आर आई एल की अनुप्रवाही उत्पादों में भी अच्छी स्थिति है। उन्होंने पीटीए का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता में विस्तार भी किया है। पीटीए की आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से आर आई एल की पीटीए तथा अनुप्रवाही उत्पादों में एकधिकारावादी स्थिति हो जाएगी। रिलायन्स ने पीटीए की कीमतों में वृद्धि की है परन्तु उसने अनुप्रवाही उत्पादों की कीमत में वृद्धि नहीं की है और इस प्रकार उसने कीमत निर्धारण में लूट मचा रखी है।

(xiv) सम्बद्ध उत्पाद, नवीन पीटीए, की मांग में, यदि पीटीए के कतिपय प्रयोक्ताओं ने पुनर्वर्कणीय सामग्री जैसे पीईटी बोतलें जो नवीन पीटीए की प्रतिस्थापन हैं का प्रयोग करना प्रारम्भ नहीं कर दिया होता तो, अवश्य वृद्धि हुई होती। निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि यदि पीटीए के कतिपय प्रयोक्ता पुनर्वर्कणीय सामग्री का प्रयोग नहीं करने लगे होते तो उसकी मांग में किस तरह वृद्धि हुई होती।

(xv) अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात् पालियस्टर फिलामेंट यार्न (पीएफ वाई) और पालियस्टर स्टैपल फाइबर (पीएसएफ) के आयातों में वृद्धि होना प्रारम्भ हो गयी और उनके लिए कच्चे माल की लागत में वृद्धि होने लगी, इसलिए उपयोक्ता उद्योग, जो पहले से ही लगभग 65% से 70% की उप-इष्टतम क्षमता से कार्य कर रहा था, ने पालियस्टर फिलामेंट यार्न और स्टैपल फाइबर दोनों के लिए अपनी क्षमता में 10% की और कटौती कर दी। क्षमता उपयोग में इस तरह कमी करने से पीटीए की आफ-टेक में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप मालसूची में वृद्धि हुई, हालाँकि प्रतिवादियों ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

(xvi) वर्तमान जॉच में क्षति का निर्धारण करने के लिए जॉच की अवधि के पश्चात् की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण करना पूर्णतया अनधिपत्रित है।

(xvii) पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण केवल इसलिए करना कि चीन ने कोरिया और थाईलैण्ड से पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण कर रखा है, उचित नहीं है, क्योंकि इसका आशय यह तो नहीं है कि निर्यातों का ज्ञाकाव भारत की ओर हो रहा है। किसी अन्य देश द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जा रही जॉच का प्रतिस्थानी नहीं हो सकता है। इन देशों में अधिक क्षमता की मौजूदगी का आशय यह नहीं है कि सम्बद्ध उत्पाद का अन्य देशों से भारत में पाटन होने लगेगा।

(xviii) पाटनरोधी शुल्क का पूर्वापेक्षी अधिरोपण विधि के अन्तर्गत संधारणीय नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जॉच परिणाम पहले से ही जारी कर रखे हैं। सम्बद्ध उत्पाद के निर्यातकों की ओर से पाटन करने का कोई इतिहास नहीं है और न ही सम्बंधित निर्यातकों किसी तरह का पाटन किए जाने के प्रति प्रयोक्तागण जागरूक हैं। आवेदक घरेलू उद्योग को अपनी आम्यन्तरिक समस्याओं के कारण क्षति हो रही है, न कि सम्बद्ध उत्पादों के आयातों के कारण। सम्बद्ध उत्पाद पर पूर्वापेक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करना एक ऐसी कार्यनीति है जिसका प्रयोग आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए किया गया है जिससे कि वह इससे अनुचित लाभ अर्जित कर सके।

(xix) निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह हितबद्ध पक्षकारों को बताए कि डी जी सी आई एण्ड एस से अनन्तिम आयात आंकड़े किस आधार पर मंगाए गए, सौदावार आयात आंकड़ों में परिशोधन करने के लिए कौन-सी कियापद्धति अपनाई गई, परिशोधित आयात आंकड़े और इन आयात आंकड़े के प्रस्तुतिकरण तथा साथेक विश्लेषण के लिए वह उन्हें प्रदान करें। निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह उनके द्वारा भराँसा की गई सूचना उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी से यह अनुरोध भी किया जाता है कि वह अनुरोधकृत सूचना प्रदान कराने के पश्चात् सुनवाई का अवसर भी प्रदान करें।

(xx) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए करनिर्धार्य मूल्य में समायोजन करने कि लिए प्रयोग किए गए साक्ष्यों एवं आधार का प्रकटन करें।

(xxi) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रकटन विवरण में सभी अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन कर सकते हैं और उसके पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकते हैं।

#### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

19. जॉच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विविध प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं:-

(i) किसी भी प्रत्युत्तरदाता निर्यातक ने पैराक्सीलीन का मूल्यांकन करने के संबंध में किए गए प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, सैमसंग पेट्रोकैमिकल्स और एस के पेट्रोकैमिकल्स ही ऐसी सम्बद्ध कम्पनीयाँ हैं जो पैराक्सीलीन का उत्पादन कर रही हैं और इन कंपनियों का उसकी आपूर्ति करती है।

(ii) प्रश्नावली प्रत्युत्तर सकल रूप से त्रुटिपूर्ण है; प्राधिकारी उसे इस अन्तिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ नामंजूर कर सकते हैं।

(iii) निर्यातकों द्वारा किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तरों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सम्बंधित उत्पादक ने कैसे संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया और उसकी एक ऐसी व्यापारिक कंपनी को आपूर्ति की जिसने भारत को उस वस्तु की अंततोगत्वा आपूर्ति की।

(iv) इस तर्क के संबद्ध में कि पीएक्स की आपूर्ति कम है और इसके अनुप्रवाही उद्योग द्वारा इसकी कम उपयोग क्षमता के कारण आरआईएल को लाभ होगा, यह उल्लेख किया जाता है। कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अनुमति देना है।

(v) यह तर्क निराधार है कि जॉच की यह शुरुआत आवेदकों का कोई आधार न होने और क्षति एवं कारणात्मत सम्बंधों का अभाव होने के कारण विधिविरुद्ध है। आवेदकों का नियमों के अन्तर्गत आधार है। इस जॉच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए याचिका में घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाले पाटन के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

(vi) बाजार की मौजूदा समस्तस्थिति सम्बद्ध देशों में भारी अप्रयुक्त क्षमताओं और चीन में भारी क्षमता सम्बर्धन के कारण बनी है। चीन पिछले 2-3 वर्षों में अपनी क्षमता में भारी संवृद्धि किए जाने से पीटीए की सम्पूर्ण विश्व में मौजूदा मांग/खपत मौजूदा वैश्विक क्षमताओं की तुलना में बहुत कम है, इसके परिणामस्वरूप कोरिया और थाईलैण्ड के उत्पादकों के पास भारी बेशी क्षमताएं सजित हो गई हैं। कोरिया और थाईलैण्ड के उत्पादकों के पास उनकी घरेलू बाजार में मांग की तुलना में पीटीए उत्पादन की भारी बेशी क्षमताएं हैं। पहले इस बेशी उत्पादन का निर्यात चीन को किया जाता था। तथापि, चीन द्वारा एक ओर तो पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने तथा दूसरी ओर अपनी क्षमताओं में भारी वृद्धि करने से कोरिया और थाईलैण्ड के उत्पादकों को अपनी बाजार की भारी क्षति हुह है। इस भारी बाजार क्षति का सामना करते हुए इन देशों के उत्पादक अब अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए अन्य बाजारों की तलाश कर रहे हैं।

(vii) पीटीए की कीमतों में उत्तार-चढ़ाव, इसके प्रमुख कच्चे माल पैराक्सीलीन की लागत में उत्तार-चढ़ाव के कारण होता है। पीएक्स और पीटीए (जिसे बिजनेस में डेल्टा, के नाम से जाना जाता है) के बीच कीमत अन्तर कम से कम 150 यूएस डालर प्रति एमटी

न्यूनतम होना चाहिए। तथापि, वैशिक उत्पादक पीएक्स और पीटीए के बीच मार्जिन को कम होता महसूस कर रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में पीटीए के उत्पादकों को भारी वित्तीय घटा हो रहा है।

- (viii) भारतीय उद्योग, भारत में मांग एवं आपूर्ति के बीच अन्तर को देखते हुए अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए कम्पनी को भारी पैंजी व्यय करना होगा।
- (ix) याचिकाकर्ता आन्तरिक रूप से आयातों के विरुद्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ आयात अनिवार्य हों वहाँ किसी भी बिजनेस निकाय के लिए यह वुद्धिमानी नहीं होगी कि अपने माल की सस्ती कीमतों पर आक्रामक बिक्री करें, जबकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि घरेलू उत्पादकों की क्षमता मांग से अधिक होने के कारण बाजार में उसकी बिक्री तर्क संगत कीमतों पर की जा सकती है।
- (x) अतः, जब आयात अनिवार्य हों तो किसी विदेशी उत्पादक को भारतीय बाजार में उत्पाद की कीमत निश्चय करने, और वह भी भारतीय बाजार के लिए विभेदकारी ढंग से का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। इसका एकमात्र युक्ति युक्त स्पष्टीकरण विदेशी उत्पादकों की बेशी क्षमताएं हो सकती हैं। विदेशी उत्पादकों की बेशी अप्रयुक्त क्षमताएं उन्हें अपने उत्पाद की भारतीय बाजार में आक्रामक बिक्री करने के लिए मजबूर कर रही हैं। चीन ने कोरिया और थाईलैण्ड से पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया है। इसके परिणामस्वरूप, कोरिया और थाईलैण्ड के निर्यातकों ने पीटीए का निर्यात भारत की बाजार में करने के लिए मन बना लिया है। पिछले दो वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग ने प्रतिदिन 5 करोड़ रुपये तक का घाटा उठाया है।
- (xi) अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात् पीटीए प्रयोक्ता उद्योग अनुप्रवाही उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के सम्बंध में तथ्यों का दुष्प्रतिनिधित्व दुर्भावनावश कर रहा है। मानव निर्मित फाइबर तथा वस्त्रों का निर्यात विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत बढ़ा है।
- (xii) फिलामेंट यार्न की कीमतों में निरन्तर गिरावट होती रही है जिससे मानव निर्मितफेब्रिक्रों का उत्पादन करने और उसका निर्यात बढ़ाने में सहयोग मिला है। भारत में पीएसएफ की बिक्री भी बहुत कम कीमतों पर की जा रही है। इसलिए यह कहना गलत है कि पीटीए पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का यार्न और फेब्रिक विनिर्माता उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। इसके बजाय, चीन जनगण से पीएसएफ और पीएफवाई के आयातों में उद्वेक मानव निर्मित फाइबर के भारतीय अनुप्रवाही उद्योग को प्रभावित कर रहा है। चीन को पीएसएफ और पीएफवाई उद्योग चलाने से रोकने के उद्देश्य से इन उत्पादों पर सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाना चाहिए।
- (xiii) पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पीटीए तथा अन्य कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आ रही है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही फाइबर, यार्न या फेब्रिक उद्योग की कीमत प्रभावित होगी। वास्तव में भारतीय घरेलू पीटीए और एमजीएफ, जो पालिएस्टर का विनिर्माण करने के लिए आधारभूत कच्चा माल है, ने अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप ही, पाटनरोधी शुल्क से प्रभावित हुए बिना, गति की है।
- (xiv) देश में अनुप्रवाही यार्न और वीविंग उद्योग द्वारा खपत किए जा रहे कुल पालियेस्टर का 3/4 भाग पालियेस्टर फिलामेंट यार्न का होता है और भारतीय उत्पादक चीन की उत्तराई कीमत से कम पर नकारात्मक ईबीआईटीडीए पर बिक्री रहे हैं।
- (xv) मानव निर्मित फाइबर का चीन से आयात अनुप्रवाही यार्न और फेब्रिक उद्योग को प्रभावित कर रहा है क्योंकि भारत ने इन टैरिफ लाइनों पर शुल्क अधिरोपित किया है जबकि चीन ने 18% सीमा-शुल्क अधिरोपित किया है।
- (xvi) पीटीए उपयोक्ता एसोसिएशन इस तथ्य का गलत प्रतिनिधित्व कर रहा है कि पाटनरोधी शुल्क ने यार्न और फाइबर की हजारों अनुप्रवाही यूनिटों को प्रभावित किया है। पालिएस्टर फाइबर का प्रयोग पालियेस्टर यार्न बनाने के लिए केवल 30-35 सिपनिंग मिलों में ही किया जाता है। भारत में 105 स्पिनिंग मिलों हैं जो पालियेस्टर काटन और पालियेस्टर विस्कोस यार्न का निर्माण करने के लिए पालियेस्टर को अन्य फाइबरों के साथ ल्येण्ड करने हेतु प्रयोग कर रही हैं। इस प्रकार केवल 150 अनुप्रवाही उद्योग ही पालियेस्टर का प्रयोग कर रहे हैं।
- (xvii) भारत में लगभग 300 मिलों हैं जो वियंडित सेक्सन में पालियेस्टर फेब्रिक्स का उत्पादन कर रही हैं। यह मिलों चीन से सस्ते आयातों द्वारा प्रभावित हैं। अतः पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन का यह उल्लेख करने का दावा गलत है कि हजारों अनुप्रवाही यूनिटें इससे प्रभावित हैं।
- (xviii) संत रूप से अल्प अवधि में भारी पाटन हुआ है और घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि हो रही है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क का पूर्वापेक्षी अधिरोपण करने पर विचार करना चाहिए।
- (xix) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि पालियेस्टर के सभी उत्पादक पीटीए की खरीद अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कर रहे हैं, इसलिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय पालियेस्टर उद्योग को कीमत घाटा होगा। यह तर्क बिना किसी आधार के है और वर्तमान प्रयोजन के लिए असंगत है। पाटनरोधी शुल्क का महत्व एवं प्रयोजन पाटन का निवारण करके घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करना है और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का माहौल सृजित करना है। यदि पीटीए की खरीद

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर की जाता है और यह अभी भी पाटिट स्तर पर है तो इसका आशय यह होगा कि विदेशी उत्पादक इस उत्पाद का पाटन कर रहे हैं। यदि यह पाटन क्षति करित कर रहा है तो पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण करना अपेक्षित होगा।

(xx) वास्तव में, विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूएसए और विकासशील देश जैसे चीन पाटन के मार्जिन तक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण कर रहे हैं, जबकि भारतीय विधि इसे क्षति मार्जिन तक प्रतिबंधित करती है और भारत ने अब एन आई पी की संकल्पना का विकास करके न्यूनतम शुल्क नियम की खोज की है। वास्तव में, दोनों बड़े देशों, कोरिया और थाइलैण्ड की सरकारें यह सोचती हैं कि पाटन के मार्जिन तक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण कराके पाटन की निन्दा की जानी चाहिए, निर्यातक यह चाहते हैं कि भारत सरकार क्षति मार्जिन तक भी पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण न करें।

(xxi) इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय पालियस्टर उद्योग को किस तरह कीमत घाटा होगा। चैंकि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण गैर-विभेदकारी आधार पर किया जाता है इसलिए इसका पालियस्टर के किसी विशिष्ट उत्पादक पर कोई विभेदकारी प्रभाव नहीं होता है। जहाँ तक भारतीय पालियस्टर उत्पादकों की विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता का सम्बन्ध है, पाटनरोधी शुल्क किसी भी हाल में शुल्क छूट स्कीम के अन्तर्गत किए गए आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

(xxii) इस तर्क का कोई विधिक आधार नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदकों की संयुक्त जॉच के साथ-साथ व्यक्तिगत जॉच भी करनी चाहिए। इस तरह के विश्लेषण की न तो पाटनरोधी अधिनियम अथवा नियमावली में कोई विधिक अपेक्षा है और न ही इस प्रक्रिया को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अथवा अन्य देशों के जॉचकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपनाया जाता है।

(xxiii) यह तथ्य कि नियन्त्रण न होने का आशय यह नहीं है कि सूचना में कोई संवेदनशीलता नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति/पक्षकार जिसकी किसी कम्पनी में 5% शेयरधरिता है, वह कम्पनी को नियन्त्रित करने में सक्षम नहीं होगा। तथापि, इसका आशय यह नहीं है कि कोई व्यक्ति संबंधित कम्पनी से कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकता जो अन्यथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

(xxiv) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुद्वेदन का उल्लंघन किया क्योंकि उन्होंने इस मुद्रे की जॉच नहीं की कि क्या जॉच की कार्रवाही के दौरान क्षति को निवारित करने के लिए अनन्तिम शुल्क अपेक्षित हैं, याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक जॉच परिणाम के पैरा 105 में अनन्तिम शुल्क के अधिरोपण के लिए जरूरत की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से की है।

(xxv) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का परिणाम यह होगा कि उन भारतीय प्रयोक्ताओं और विभिन्न अनुप्रवाही उपयोगों पर अनुचित अधिक बोझ पड़ जाएगा जो सम्बद्ध उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्होंने पुनः यह तर्क दिया कि पिछले 6 महीनों में पीएसएफ और पीएफबाइ के आयातों में 80%-130% तक की वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में घरेलू उद्योग यह प्रस्तुतिकरण करता है कि इससे पर्याप्त रूप से प्रदर्शन हुआ है कि यह क्षति सम्बद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण हुई है। इस विचाराधीन उत्पाद के भारतीय विनिर्माताओं को विचाराधीन पक्षकारों की कुछ ऐसी आशंकाओं के कारण कट्ट सहन करन की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसके दावों के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस एसोसिएशन ने विस्तार से यह तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में क्षति मार्जिन बहुत कम है। ऐसा मामला होने पर याचिकाकर्ता यह समझाने और मानने में असफल रहे कि पाटनरोधी शुल्क से किस तरह करित अनुचित उच्च बोझ को दूर किया जा सकेगा। वास्तव में, पाटनरोधी शुल्क से पाटिट आयातों तक पहुँच के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अर्जित किया जा रहा अनुचित लाभ समाप्त हो गया है। तथापि: उपभोक्तागण पाटिट कीमतों पर किसी सामग्री तक पहुँच की मांग नहीं कर सकते हैं, खासकर तब जब उससे घरेलू उद्योग का क्षति हो रही है।

(xxvi) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि भारत में पीटीए के सम्पूर्ण उत्पाद की खपत हो जाती है और आपूर्ति में कमी को केवल आयातों द्वारा ही पूरा किया जाता है। उन्होंने पुनः यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण करने के कारण आयातकों को बाजार में अपनी लागत बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है: जहाँ पीटीए की पहले से ही कमी होती है। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि उनके पास अक्टूबर 2014 में \*\*\* एमटी मालसूची थी। ऐसी स्थिति में जहाँ घरेलू उद्योग अपनी मालसूची की बिक्री करने में अक्षम रहा, आयातकों के इस अभिकथन में कोई अच्छाई नहीं है कि वे भारत में उक्त माल उपलब्ध न होने के कारण आयात कर रहे हैं और यह तथ्यात्मक रूप से असत्य है। यह तथ्य आयात को स्वतः न्यायोचित ठहराता है कि भारत में खपत भारतीय उत्पादकों की क्षमता से अधिक है। तथापि, इससे पाटन का औचित्य तो नहीं ठहरता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वे भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पाटन का आश्रय ले रहे हैं।

(xxvii) जहाँ तक इस तर्क का सम्बन्ध है कि मांग और आपूर्ति के बीच भारी अन्तर है और यदि घरेलू उद्योग अपनी 100% क्षमता से भी कार्य करता है तो भी यह उस मांग को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए आयात अनिवार्य है, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि यदि विदेशी उत्पादक इस विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करना चाहते हैं तो वे इस उत्पाद की बिक्री उचित कीमतों पर करके, न कि पाटिट कीमतों पर करके ऐसा कर सकते हैं। घरेलू उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(xxviii) चीन और यूरोप से आयात न्यूनतम नहीं है। यह सम्भव है कि कोरिया, थाइलैण्ड अथवा कुछ अन्य देशों के निर्यातकों द्वारा कुछ माल का निर्यात चीन और यूरोप को किया गया था और तथापि उस माल की निकासी चीन और यूरोप में नहीं हो सकी इसलिए उसका ट्रानशिप भारत को किया गया। ऐसी स्थिति में इन आयातों को चीन द्वारा या यूरोप द्वारा किए गए आयात ही मानना चाहिए।

(xxix) यदि यह मान भी लिया जाए कि जॉच की अवधि में चीन और यूरोपियन यनियन से आयातों की मात्रा न्यूनतम रही है, तब भी इसका आशय यह नहीं है कि चीन और यूरोपियन यनियन के सम्बंध में जॉच समाप्त कर दी जाए। ऐसी स्थिति में नियम 14 में यह प्रावधान है कि वास्तविक और सम्भावित दोनों ही स्रोतों पर विचार करना चाहिए। यदि वास्तविक आयात न्यूनतम हैं तो प्राधिकारी को सम्भावित आयातों पर विचार करना चाहिए।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

20. विविध मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विविध प्रस्तुतिकरणों की जांच एवं समाधान निम्नलिखित हैं:

- i. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क निराधार है कि आवेदकों के आधार के अभाव, क्षति न होने तथा कारणात्मक सम्बंध के अभाव के कारण इस जांच की शुरुआत ही विधि विरुद्ध है। मौजूदा अन्तिम जांच परिणाम इस सम्बंध में स्वतः स्पष्ट है।
- ii. जहाँ तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का सम्बंध है कि प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जॉच नहीं की है कि क्या जॉच की कार्रवाई के दौरान क्षति का निवारण करने के लिए अन्तिम शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रारम्भिक जॉच परिणाम के पैरा 105 में अन्तिम शुल्क का अधिरोपण करने की जरूरत को स्पष्ट किया गया है।
- iii. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि भारत में मांग एवं आपूर्ति में भारी अन्तर है और चूँकि पीटीए के आयात अनिवार्य है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अनिवार्य है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है जिसमें यह अधिदेश दिया गया हो कि घरेलू उद्योग को देश की सम्पूर्ण मांग पूरी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यापार की पक्षपातरहित स्थिति को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग अपनी क्षमता से देश की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग भारत में मांग के अनुरूप अपनी क्षमताओं में विस्तार कर रहा है। एक बार यह उपलब्धि प्राप्त हो जाने और पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करके पक्षपातरहित व्यापार की स्थिति सुनिश्चित हो जाने पर, घरेलू उद्योग इस स्थिति में हो जाएगा कि वह सम्पूर्ण घरेलू मांग को पूरा कर सके।
- iv. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि पीटीए कई अनुप्रवाही उत्पादों के लिए आधारभूत कच्चा माल है और उत्पादों की उत्पादन लागत घट-बढ़ सकती है जिसका उनकी विपणनयोग्यता और व्यवहार्यता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं में सुधार लाना है और घरेलू उद्योग को व्यापार के समान अवसर प्रदान करके उनके क्षतिकारी प्रभावों का निराकरण करना है। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों की यह विंता उनकी अपरिक्वता की द्योतक है कि पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुप्रवाही उद्योगों के उत्पादों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 2% से 11% की रेंज में अन्तिम पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का पीएफ वाई और पीएसएफ की उत्पादन लागत पर लगभग 2-3% की लागत वृद्धि होगी। अतः अधिरोपित अन्तिम पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पर विचार करते हुए अनुप्रवाही उद्योगों के उत्पादों की उत्पादन लागत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीटीए के अन्तिम प्रयोक्ता, जिनको पाटन के कारण लाभ हुआ है, उन्हें अब कच्चे माल के लिए अनपाटित/उचित कीमतों पर भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण करने से आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।
- v. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना और अन्तिम उत्पाद पर कोई पाटनरोधी शुल्क न होने का परिणाम यह होगा कि घरेलू क्रेता अन्तिम उत्पादों का आयात करने लगेंगे और उसके परिणाम स्वरूप देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित में कमी आएगी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के विरुद्ध घरेलू उद्योगों को समान अवसर प्रदान करना है।
- vi. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि चूँकि पैरास्टीलीन, पीटीए के लिए कच्चे माल का आयात शून्य सीमा शुल्क पर किए जाने की अनुमति है इसलिए भारत में पीटीए के विनिर्माताओं को कोई अन्य संरक्षण प्रदान कराने की जरूरत नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का आशय पाटन से घरेलू उद्योग की रक्षा करना है। शुल्क मुक्त कच्चे माल, यदि कोई है, की फैक्टरिंग की पाटनरोधी साधनों का निर्धारण करने में कोई संगतता नहीं है।
- vii. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से एक प्रतिलोमित शुल्क ढांचा तैयार हो जाएगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीटीए तथा अनुप्रवाही उत्पादों पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) एक समान है अर्थात् यह पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पहले और उसके पश्चात् 5 प्रतिशत ही है। चूँकि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का उद्देश्य पीटीए के आयातों द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर करना है, इसलिए इसे बीसीडी का भाग नहीं समझना चाहिए। इसलिए, विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से प्रतिलोमित शुल्क ढांचा सृजित होगा, गलत है।

viii. यह तर्क कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पीईटी के अन्य विनिर्माताओं का नुकसान होगा, न कि आर. आई. एल. को जिसकी पीटीए विनिर्माण की ग्राही क्षमता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के सम्बंध में यह अन्तिम जॉच परिणाम स्वतः स्पष्ट है। तथापि, यह स्पष्ट है कि जिन उद्योगों का पिछड़ा समन्वयन है उनकों ऐसी अन्य सुविधाओं युक्त उद्योगों की तुलना में लाभ होगा प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षति का विश्लेषण समग्र रूप से घरेलू उद्योग के रूप में, न कि विखंडित रूप में, किए जाने की जरूरत है।

ix. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि डीजीएडी. क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पादकर आयुक्तालय से घरेलू उद्योग द्वारा पीटीए की बिक्री पर दावा किए गए घाटे के सम्बंध में सूचना की मांग कर सकते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

x. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से आर. आई. एल की एकाधिकारिता हो जाएगी और आर. आई. एल. लुंठक कीमतें निर्धारित करेंगे जो अन्य समान उत्पादकों के लिए घाटक होगी प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह रिति परिकल्पित स्थिति है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से आयात बढ़ियत नहीं होते हैं। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के विरुद्ध घरेलू उद्योग को व्यापार के समान अवसर प्रदान करना है। तथापि, ऐसी रिति होने पर, पीडित पक्षकार प्रतिस्पर्धा आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

xi. प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि यह तर्क कि सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ होगा, दुराशयी है। पाटनरोधी जॉच तथ्यों पर आधारित होती है। और विधि में विश्लेषण और पाटन की मात्रा और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन करना अधिरेशित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों में ऐसा उपयुक्त एवं पर्याप्त पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की व्यवस्था है जिससे पाटन की तुलना में घरेलू उद्योग को व्यापार के उचित एवं समान अवसर प्रदान करना निश्चित हो सके।

xii. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि यदि पीटीए के कतिपय उपयोक्ताओं ने पुनर्चक्रणीय सामग्री जैसे पीईटी बोतलों का प्रयोग करना शुरू न कर दिया होता तो पीटीए की मांग में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई होती, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस तर्क की पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों का निर्धारण करने से कोई संगतता नहीं है।

xiii. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के सम्बंध में कि पीटीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई है, क्षमता उपयोग कम हुआ है और टेक्सटाइल सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ी है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस तर्क, कि पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के कारण ही वस्त्र उद्योग पर प्रभाव पड़ा है, के समर्थन में कोई साक्षात्कृत साक्ष्य नहीं दिया है।

xiv. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि सम्बद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं की मौजूदगी की आशय यह नहीं है कि सम्बद्ध उत्पाद का अन्य देशों में पाटन किया जाएगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जॉच के तथ्य एवं विश्लेषण इस अन्तिम जॉच-परिणाम में स्वतःस्पष्ट हैं। भारत में अनुकूल बाजार स्थितियां और वैशिक बेशी उत्पादन बेशी क्षमताओं से ग्रसित सम्बद्ध देशों के पीटीए के उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है।

xv. जहाँ तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का सम्बद्ध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह डीजीसीआईएण्डएस से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़े, जिनमें परिष्कृत आंकड़े और उसका सारांश शामिल हो, उपलब्ध कराएं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सैनडिस्क इंटरनेशनल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय दिल्ली उच्चन्यायालय द्वारा उद्घोषित दिनांक 18.03.2015 के निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करने के निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकारों के बिना, प्राधिकारी सम्बद्ध वस्तु के डीजीसीआईएण्डएस से प्राप्त सौदेवार आयात संस्थिकी का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध करा दिया है करा दिया है।

xvi. जहाँ तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का सम्बंध है कि प्राधिकारी द्वारा सौदेवार आयात आंकड़े तथा प्रकटन पश्चात आंकड़े प्रदान कराने स्तर पर सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 19 नवम्बर 2014 को मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और इस मौखिक सुनवाई के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रत्युत्तियों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जॉच की कार्यवाई के दौरान किए गए प्रस्तुतिकरणों, लिखित प्रस्तुतिकरणों, प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरणों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरणों की जॉच की गई और उनका इस अन्तिम जॉच परिणाम में निराकरण कर दिया गया है।

xvii. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन जन. गण और यूरोपियन यूनियन (ई. यू.) से आयात, डीजीसीआईएण्डएस से उनके द्वारा प्राप्त आयात आंकड़े के अनुसार, न्यूनतम नहीं हैं। इस सम्बंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रारम्भिक जॉच परिणाम जारी करते समय प्राधिकारी द्वारा डीजीसीआईएण्डएस से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया था।

प्रारम्भिक जाँच परिणाम के स्तर पर उक्त आंकड़ों का विश्लेषण करते समय प्राधिकारी ने उदगम के देश के रूप में 'सीएनटीआरआई—ओआरजी' नामक क्षेत्र के अन्तर्गत डीजीसीआईएण्डएस आंकड़ों में दिए गए देश कोड पर विचार किया था और तदनुसार सम्बद्ध देशों के लिए जाँच की अवधि के दौरान आयात मात्रा का निर्धारण किया था। तदनुसार, जाँच की अवधि के दौरान चीन जन. गण और यूरोपियन यूनियन से आयात की मात्रा क्रमशः 22160 एमटी तथा 27896 एमटी थी जिसे न्यूनतम स्तर से अधिक माना गया था।

प्रारम्भिक जाँच परिणाम जारी करने के पश्चात कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि चीन जन. गण और ईयू से आयात की मात्रा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध—आयात आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम से कम है। इसलिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएण्डएस से यह स्पष्टीकरण मांगा कि उनके द्वारा घरेलू उद्योग को प्रदान कराए गए आंकड़ों और वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों में अन्तर क्यों हैं।

डीजीसीआईएण्डएस ने 26 मार्च 2015 को यह सूचना प्रदान की कि जुलाई 2013 में घरेलू उद्योग को प्रदान कराए गए सौदावार आयात आंकड़े उस समय तक की रिपोर्ट के अनुसार अनन्तिम आंकड़े थे, क्योंकि वर्ष 2012–13 के लिए सम्पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। डीजीसीआईएण्डएस ने पुनः यह सूचना दी है कि साप्टवेअर की कुछ समस्या के कारण कुछ बिल प्रविष्टियों के लिए खेप के देश, आई ई सी संख्या, आदि को त्रुटीपूर्वक पोस्ट कर दिया गया था और कुछ समय पश्चात उसमें सुधार कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में आयातित वस्तुओं का देशवार वितरण करने में भारी परिवर्तन आया है। तत्पश्चात संशोधित आंकड़े वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर होस्ट कर दिए गए।

इसके अतिरिक्त, डीजीसीआईएण्डएस से दिनांक 26 मार्च 2015 को इस तथ्य का स्पष्ट कारण पूछा गया कि वर्ष 2012–13 के लिए नवम्बर 2013 के आंकड़े में विसंगतियाँ क्यों थीं और डीजीसीआईएण्डएस से प्राप्त अभी हाल ही का स्पष्टीकरण उपरोक्त है।

डीजीसीआईएण्डएस ने अपने दिनांक 27 मार्च 2015 के संप्रेषण के तहत यह सूचित किया कि क्षेत्र नाम (सीएनटीआरवाई\_ओआरजी) के अन्तर्गत उल्लिखित कन्ट्री कोड में अनभिपृष्ठ आंकड़ों का उल्लेख था और वे उदगम के देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सूचना भी दी गई कि क्षेत्र नाम "सीएनटीआरवाई\_कोड" के अन्तर्गत उल्लिखित आंकड़ों में अभिपृष्ठ आंकड़ों का उल्लेख था जिनका प्रयोग देशवार आंकड़ों का सूजन करने के लिए किया गया था। इस सम्बंध में डीजीसीआईएण्डएस एस द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निम्नलिखित है।

'ऐसा प्रतीत होता है कि चीन और ईयू से कुल आयातों से सम्बंधित आंकड़े सूजित करते समय डीजीएडी ने क्षेत्र नाम 'सीएनटीआरवाई\_ओआरजी' के उन्नर्गत उल्लिखित कण्ट्री कोड्स पर विचार किया गया था। चूँकि इस क्षेत्र में अनभिपृष्ठ आंकड़ों का उल्लेख था इसलिए इस क्षेत्र नाम "सीएनटीआरवाई\_कोड" (जिसमें अभिपृष्ठ कण्ट्रीकोड का उल्लेख किया गया था) के अन्तर्गत उल्लिखित आंकड़ों का प्रयोग देशवार कुल आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए सूजन किया जाना चाहिए था। आंकड़ों के इन 2 सेट्स में अन्तर (विसंगति) अभिपृष्ठ क्षेत्र (सीएनटीआरवाई\_कोड) के स्थान पर अनभिपृष्ठ क्षेत्र (सीएनटीआरवाई\_आग) का चयन किए जाने के कारण आया है। यदि उपयुक्त क्षेत्र (सीएनटीआरवाई\_कोड) का चयन किया गया होता तो चीन और ईयू के लिए कुल मात्रा संख्या में कोई अन्तर नहीं होता जैसा कि नवम्बर 2013 में पेशित किया गया और मार्च 2015 में उसका स्पष्टीकरण दिया गया।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि डीजीसीआईएण्डएस के उदगम के देश द्वारा आयातों से सम्बंधित कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। इसे डीजीसीआईएण्डएस के दिनांक 18.03.2015 में मेल द्वारा भी स्पष्ट किया गया है।

घरेलू उद्योग को जुलाई 2013 में प्रदान किए गए आंकड़ों और डीजीएडी को प्रदान किए गए आंकड़ों में विसंगति होने के कारणों का हमारे दिनांक 26–03–2015 के मेल में संक्षिप्त रूप से उल्लेख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आइसगेट (कस्टम्स) से प्राप्त ईडीआई आंकड़े दो भागों में प्राप्त होते हैं। प्रत्येक प्रविष्टि बिल (आयातक नियर्तक कोड), समल भार आदि जैसी सूचना का उल्लेख रहता है और एक या अधिक मद रिकार्ड में आयातित मद, मात्रा, मूल्य आदि का उल्लेख रहता है।

मद और मूल्य रिकार्डों को प्रसंस्करण के प्रथम स्तर पर विलयित कर दिया जाता है। यदि किसी एक बीई (बिल प्रविष्टि) के लिए 4 मद रिकार्ड होते हैं और एक मुख्य (मास्टर) रिकार्ड होता है तो उसके चार विलयित रिकार्ड होंगे जिनमें उस सभी चार में मुख्य सूचना को दोहराया जाता है।

इस विलयन प्रक्रिया के लिए आइस एवं मास्टर रिकार्डों का मिलान बी ई संख्या और बी ई तारीख से किया जाता है। बी ई संख्या, जो पहले 6 अंकीय थी बढ़ाकर अब 7 अंकीय कर दी गई है। चूँकि डीजीसीआईएण्डएस डाटाबेस में 6 अंकीय बी ई संख्या का प्रावधान होता है, इस लिए 7–अंकीय संख्या 1–अंक से विकृत हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप समान बी ई संख्या से दो या दो से अधिक अन्यथा सुव्यक्त 7 अंकीय बी ई संख्या का सूजन हो जाता है। उदाहरण के लिए 1234567 और 12345678 संख्या युक्त दो बी ई बिकृत होकर उनकी बी ई संख्या 123456 हो जाती हैं इससे मिलान प्रक्रिया प्रभावित होती है और प्रमुख सूचना जिसमें खेप देश को कोड, आई ई सी कोड, सकल भार आदि सूचना का उल्लेख होता है जिनमें पहले 6 अंक समान होते हैं (जैसा कि ऊपर के उदाहरण में दर्शाया गया है)।

चूँकि इन अपवादों के कारण हुई त्रुटि का संदेश सूजित करने के लिए किसी साप्टवेयर का प्रावधान नहीं था इसलिए त्रुटि का पता लगाने में डीजीसीआईएण्डएस को कुछ समय लगा। तथापि, जैसे ही इस भूल का संसूचन हुआ तुरन्त साप्टवेयर में सुधार कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 और वर्ष 2012–13 के लिए आयात आंकड़ों को प्रमुख (मास्टर) सूचना के सम्बंध में संशोधित कर दिया गया। इसका देशवार संख्या पर प्रभाव पड़ा है।

डीजीएडी को नवम्बर 2013 में भेजे गए आंकड़ों के संशोधित डेटाबेश तैयार किए गए हैं।

इसलिए न्याय, सद्कार्य और यथार्थ विश्लेषण के हित में यह प्राधिकारी पर निर्यात करता है किवह चीन जन. गण. और ईयू से आयात की मात्रा में, जिसका प्रारम्भिक जांच परिणाम में उल्लेख किया गया था, सुधार कर ले और इस अन्तिम जांच परिणाम में सही-सही स्थिति का परावर्तन करें। रिकार्ड में स्पष्ट रूप से उल्लिखित भूल में न्याय के हित में सुधार कर लिया गया है इसलिए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्तिम जांच परिणाम में चीन जन. गण. और ई. यू. से निर्यात मात्रा विचार की गई न्यूनतम स्तर से कम है।

xviii. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि जॉच की अवधि में यदि चीन से आयातों की मात्रा को न्यूनतम स्तर के रूप में माना जाता है, तो भी प्राधिकारी को उनके विरुद्ध जॉच समाप्त नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सम्भावित आयातों पर विचार करना चाहिए। इस सम्बंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सम्भावित स्थिति पाठन एवं क्षति की सम्भावना का विश्लेषण करने और उसे सिद्ध करने के लिए समीक्षा जॉच की विषयवस्तु है न कि नवीन पाटनरोधी जॉच की। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-२ के अनुसार नवीन पाटनरोधी जॉच में क्षति का निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी को जॉच की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव का एक उद्देश्यपरक विश्लेषण करना अपेक्षित होता है जिससे कि कारणात्मक सम्बंध स्थापित हो सके। पाटनरोधी नियमावली की नियम १४, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान करता है कि यदि किसी देश से पाटित आयातों की वास्तविक या सम्भावित मात्रा, उस समय उत्पाद के आयातों का ३ प्रतिशत है, तो जॉच समाप्त की जा सकती है। इस नियम का पाठन यह स्पष्ट करता है कि कोई भी जॉच तभी समाप्त की जा सकती है जब वास्तविक आयात या सम्भावित आयात कुल आयातों का ३ प्रतिशत से कम है और इसलिए घरेलू उद्योग का यह तर्क सही नहीं है कि जब वास्तविक पाटित आयात न्यूनतम से कम है, तो सम्भावित आयातों पर भी जॉच को समाप्त करने के लिए निर्धारणों का निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का यह तर्क कि यह सम्भव है कि कुछ सामग्री का कोरिया, थाईलैण्ड या कुछ अन्य देशों के निर्यातकों द्वारा चीन और यूरोपियन यूनियन को निर्यात किया गया है और उसका जहाजान्तरण भारत को किया गया हो, मात्र एक निराधार कल्पना है तथा उसके सम्बंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

#### च. बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाठन मार्जिन

##### निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

21. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाठन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों की जांच एवं उनका समाधान निम्नलिखित है:-

- I. कच्चे माल और पीटीए की कीमतों में वृद्धि होने, व्यापार का सामान्य अनुक्रम (व्यवहार्यता/सीओपी) परीक्षण (80:20) और पाठन मार्जिन/क्षति मार्जिन, यदि जांच की अवधि के दौरान औसत लागत के आधार पर अनुप्रयुक्त की जाती है, तो यह जॉच पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और अतीर्किक होगी। लागत एवं कीमत के बीच समुद्धित तुलना करने के लिए व्यवहार्यता परीक्षण को मासिक आधार पर जाना चाहिए है और पाठन मार्जिन का परिकलन प्रतिमाह के लिए किया जाना चाहिए। जॉच की अवधि के लिए व्यवहार्यता जांच (80%20) लागू करने के लिए औसत आधार पर एक लागत को अंगीकार करने से विषम परिणाम प्राप्त होंगे।
- II. पीटीए का व्यवपार एवं उसकी बिक्री उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों (अंतिम प्रयोक्ता एवं वितरकों) को की जाती है। यदि बिक्रियां वितरकों को की जाती हैं तो निर्यातक की वितरण लागत कम हो जाती है।
- III. संबद्ध वस्तु का निर्यात पैकड़ और भारी मात्रा में किया जाता है इसलिए व्यवहार्यता परीक्षण करते समय उत्पादन लागत और घरेलू बिक्रियों दोनों को तटस्थ कर दिया जाना चाहिए।
- IV. पीटीए कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों द्वारा किया जाता है, जिनकी घोषणा रसायन बाजार कीमत सूचना वेबसाइटों द्वारा की जाती है। आरआईएल का प्रबल बाजार हिस्सा है और वह अपनी बिक्री कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत तथा आयात शुल्क तथा आयात से संबंधित व्ययों के अनुसार करता है। एमसीपीआई और आईओसी आरआईएल की कीमतों का अनुसरण करते हैं। कोरियाई उत्पादक भी निर्यात कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर करता है इसलिए चूंकि आई सी आई एस कीमतों की घोषणा साप्ताहिक आधार पर करते हैं, इसलिए मासिक औसत साप्ताहिक कीमत का परिकलन पोतलदान की माह समाप्ति (कलोजिंग) के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए कोरियाई उत्पादक अस्थायी कीमत को लागू करते हैं और मासिक आधार पर उसका निपटारा करते हैं। कोरिया की आयात कीमत, समुद्री भाड़ा और भुगतान की अवधि के अंतरालों पर विचार करने के पश्चात आईसीआईएस, पीएलएटीटीएस और पीसीआई द्वारा जारी औसत मासिक कीमत के समान ही होते हैं। कोरिया में घरेलू बाजार कीमत का निर्धारण भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसलिए कोरिया द्वारा पाठन किया जाना तथ्यतः गलत है।
- V. हयोसंग ट्रेडिंग पीजी एक पृथक कम्पनी नहीं है परन्तु यह हयोसंग कारपोरेशन का एक प्रभाग है। दि ट्रेडिंग पीजी इस संबद्ध उत्पाद की अन्य उत्पादकों जैसे एस के पेट्रोकैमिकल, साम नाम पैट्रोकैमिकल और लोट्टे पैट्रोकैमिकल से खरीद की है तथा उसने जॉच की अवधि के दौरान उसका भारत को निर्यात किया है। हयोसंग कारपोरेशन इस संबद्ध उत्पाद का अधिग्रापण अन्य उत्पादकों

से करता है क्योंकि आधे से अधिक की खपत आन्तरिक रूप से हो जाती है और शेष वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

VI. इस सम्बद्ध उत्पाद का हयोसंग कारपोरेशन का उत्पादन अनिवार्यतः उच्चतर विशुद्धता का होता है। दि ट्रेडिंग पीजी मुख्यतः एमटीए (मीडिया क्वालिटी टैरेफैलिक एसिड) की खरीद और बिक्री करता है जिससे कि भारतीय ग्राहकों की विशेष मांग पूरी हो सके।

VII. एस.के. पेट्रोकेमिकल हयोसंग कारपोरेशन की सम्बद्ध कम्पनी नहीं है। चीन में भारी क्षमता विस्तार के कारण एस.के. पेट्रोकेमिकल प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका और इसलिए कम्पनी बंद हो गयी। अतः एस.के. पेट्रोकेमिकल इस जॉच में और अधिक प्रतिभागिता नहीं करेगा।

VIII. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 6.10 जॉचकर्ता प्राधिकारी पर प्रत्येक ज्ञात निर्यातक अथवा उत्पादक के किए अलग—अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का दायित्व सौंपता है। डीजीएडी को पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए और इण्डोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड, थार्टलैण्ड और टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी थार्टलैण्ड के लिए शुल्क की अतिरिक्त दर की सिफारिश करनी चाहिए।

IX. झेजियांग इशेंग पेट्रोकेमिकल कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निर्यात आंकड़ों का अपर्याप्त मात्रा के आधार पर अस्वीकरण अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है।

X. चीन जन—गण से आयात की मात्रा कम होने से घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं हो सकती है।

XI. झेजियांग यीशेंग पेट्रोकेमिकल कम्पनी लिमिटेड और इसके सम्बद्ध एसोसिएटों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने की मनाही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के अन्तर्गत प्रचालन करते हैं।

**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण**

22. जांच की कायावाही के दौरान सामान्य मूल्य, निर्यात और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं:

- I. इस दावे के संबंध में क्रूड आयल, नापथा, पीएक्स और पीटीए की बाजार कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर किया जाता है और मांग/आपूर्ति की स्थिति के कारण ही मुख्यतः कीमतों में उतार—चढाव होता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान जांच पीटीए के आयातों के संबंध में है और इसलिए पैरासीलीन, प्रमुख कच्चा माल होने और पीटीए की कीमतों में उतार—चढाव वर्तमान जांच के लिए संगत है न कि अन्य उद्धृत कारक।
- II. इस दावे के संबंध में कि आरआईएल का प्रमुख बाजार हिस्सा है तथा अन्य उत्पादक इसी की कीमत का अनुसरण करते हैं, वास्तव में आरआईएल की बिक्री मात्रा, प्रमुख स्थिति ग्रहण नहीं करती है। प्रत्युत्तरदाता पक्षकार यह स्पीकार करते हैं कि एमसीपीआई की कीमतों आयात कीमतों से जुड़ी होती हैं न कि आरआईएल कीमतों से। यहां तक कि आरआईएल की कीमतों आयात कीमतों से संबद्ध होती हैं।
- III. यह दावा कि कोरिया की आयात कीमतें लगभग आईसीआईएस, पीएलए टीटीएस और पीसीआई द्वारा जारी औसत मासिक कीमतों होती हैं, जो समुद्री भाड़ा और भुगतान की अवधि के अन्तर पर विचार करने के पश्चात् यह दर्शाता है कि कोरियाई उत्पादकों ने भारत को निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को अनुसरण किया है और उन्होंने अपनी घरेलू कीमत तथा उत्पादन लागत पर विचार नहीं किया। अतः यदि घरेलू कीमतें अधिक हैं और वे घरेलू कीमतें लाभप्रद हैं तो यह कोरियाई उत्पादकों द्वारा पाटन को सिद्ध करता है।
- IV. यह दावा कि कोरिया में घरेलू बाजार कीमत का निर्धारण भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत के आधार पर किया जाता है, यह सिद्ध नहीं करता है कि निर्यातकरण अपने उत्पाद की भारत में बिक्री पाटित कीमतों पर नहीं करते हैं। यदि कोरिया में घरेलू बाजार कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के समान है तो इसका आशय यह हुआ कि कोरियाई उत्पादकों को, संगत अवधि के दौरान पीएक्स की प्रचलित कीमतों पर विचार करते हुए वित्तीय घाटा हो रहा है।
- V. प्रश्नावली प्रत्युत्तर यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि सम्बंधित उत्पादक ने वस्तु का उत्पादन किस तरह किया और किस तरह उसने उस वस्तु की आपूर्ति एक ऐसी व्यापारिक कम्पनी को की है जिसने उक्त वस्तु की आपूर्ति अन्ततः भारत को की है। क्या निर्यातक प्रश्नावली में घोषित बिक्री चैनल पूर्ण है अथवा कुछ और बिक्री चैनल भी है, क्या हमें प्रतिवादी निर्यातक से इसका स्पष्टीकरण लेना चाहिए।
- VI. प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जॉच परिणाम में निर्धारित पाटन मार्जिन सकलतः कम है।

VII. कोई कीमत जो समान वस्तु के लिए, जबवह निर्यातक देश में खपत के लिए हो, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में तुलनीय कीमत का प्रतिनिधित्व करती है, उसे सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नहीं लिया जा सकता है। पैराक्सीलीन (पीएक्स) की कीमत और संपरिवर्तन लागत पर विचार करते हुए, सम्बद्ध देशों के सभी उत्पादकों के घाटा हो रहा है। सम्बद्ध देशों की घरेलू बाजार में इस उत्पाद की बिक्री कीमत इस कारण से व्यापार के सामान्य अनुक्रम में नहीं है क्योंकि उक्त कीमत घरेलू बाजार में उत्पादन लागत की प्रतिप्राप्ति की अनुमति प्रदान नहीं करती है। इसलिए, सम्बद्ध देशों में प्रचलित कीमत के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अंगीकार नहीं किया जा सकता।

VIII. एमसीपीआई और कोरियाई कम्पनियों द्वारा भुगतान की गई पीएक्स की कीमत वास्तविक रूप से अलग नहीं हो सकती है। प्रतिवादी उत्पादकों के लिए पैराक्सीलीन के तीन स्रोत हो सकते हैं –(क) निजी उत्पादन, (ख) सम्बद्ध पक्षकार से अधिप्रापण; (ग) असहबद्ध पक्षकार से अधिप्रापण। यदि यह अधिप्रापण असहबद्ध पक्षकार से किया जाता है तो यह अधिप्रापण कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्याप्त कीमतों से तुलनीय होनी चाहिए। यदि किसी उत्पादक ने पैराक्सीलीन की खरीद किसी सहबद्ध आपूर्तिकर्ता से की है तो भी क्रय कीमत से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमत की सम्पुष्टि होनी चाहिए।

IX. यदि किसी माल की खरीद सम्बद्ध आपूर्तिकर्ता से की गई है या उसका ग्राही रूप से उत्पादन किया गया है तो विदेशी उत्पादक को निम्नलिखित सूचना प्रदान करना अपेक्षित होगा :

- क. विचार किए गए माल की कीमत निर्धारण का आधार
- ख. निर्यातक यह कैसे मानता है कि विचार की गई कीमत उचित बाजार कीमतों को प्रतिबिम्बित करती है और उसके तुलनीय है।
- ग. एक समकक्ष या तुलनीय इनपुट उत्पाद के लिए स्वतंत्र पक्षकारों से क्रय कीमत प्रदान करेगा।
- घ. ग्राही रूप से अधिप्राप्त या सहबद्ध आपूर्तिकर्ता से अधिप्राप्त मद की उत्पादन लागत प्रदान करेगा।

X. निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या किसी सहबद्ध आपूर्तिकर्ता से अधिप्रापण कीमत बाजार मूल्यों की प्रतिनिधिक कीमत है।

XI. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जिनके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण किया है पीटीए के उन विदेशी उत्पादकों में से किसी के भी पास पैराक्सीलीन का उत्पादन करने की अपनी क्षमता नहीं है। ऐसा मामला होने पर, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई खपत कीमत व्यापार पत्रिकाओं में रिपोर्ट की गई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप होनी चाहिए। प्राधिकारी को उसकी जाँच व्यापार पत्रिकाओं में रिपोर्ट की गई कीमतों के साथ खपत/क्रय कीमत की समरूपता करके करनी चाहिए।

XII. सामान्य मूल्य निर्धारण किसी एक सम्बंधित उत्पादक तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जहाँ अधिकांश बाजार में आयातित वस्तु की आपूर्ति की जा रही हो और इसके अतिरिक्त, एक ऐसी स्थिति में जहाँ घरेलू उत्पादक अपनी घरेलू बिक्री की लगभग 80–90% की बिक्री अपनी सहबद्ध कम्पनी को कर रहा हो और शेष 10–20% की बिक्री (जो विचारधीन उत्पाद की कुल बिक्री का मुश्किल से 3–5% हिस्सा बनता है) ही बचती हो, और एक एकसी स्थिति में जहाँ घरेलू उत्पादक अपने उत्पाद की बिक्री ऐसी कीमत पर कर रहा हो जो बाजार कीमत से 30–40% कम हो, एक प्रश्न जो विचारार्थ उत्पन्न होता है वह यह है कि उत्पादक इस उत्पाद की बिक्री इतनी कम कीमत पर क्यों कर रहा है। यह स्पष्ट है कि यह बिक्री संव्यवहार व्यापार के सामान्य अनुक्रम में तुलनीय कीमतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

XIII. निर्दिष्ट प्राधिकारी इस सन्तुष्टि के बिना निर्यातक की उत्पादन लागत को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं कि क्या उससे उक्त विचारधीन उत्पाद उत्पादन और बिक्री उससे जुड़ी लागत को तर्कसंगत ढंग से प्रतिबिम्बित करती है। उचित एवं समुचित तुलना करने के लिए प्राधिकारी से पी एक्स की कीमती के सम्बंध में उत्पादन लागत में सुधार करने का अनुरोध किया जाता है।

XIV. पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बाद भी घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रही क्योंकि पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा बहुत कम थी जो पाटन का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

XV. याचिकाकर्ता स्वतः ही आयात के विपरीत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ आयात अनिवार्य हो जाएं वहाँ किसी भी व्यवसाय निकाय के लिए यह बुद्धिमानी पूर्ण नहीं होगा किवह अपने माल की बिक्री आक्रामक रूप से कम कीमतों पर करे, जब यह एक सुन्नात तथ्य है कि वस्तु को बाजार में युक्तियुक्त कीमतों पर बेचा जा सकता था क्योंकि मांग घरेलू उत्पादकों की क्षमता की तुलना में अधिक है।

**XVI.** इस प्रकार, जब आयात अनिवार्य हो तब किसी विदेशी उत्पादक के लिए ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि वह भारतीय बाजार में अपने उत्पाद के लिए कीमतों का निग्रहण करे, और वह भी भारतीय बाजार में अत्यधिक विभेदपूर्ण ढंग से। केवल सत्याभाषी स्पष्टीकरण यह है कि विदेशी उत्पादकों के पास बेशी क्षमता थी। विदेशी उत्पादकों की बेशी अनप्रयुक्त क्षमता उन्हें भारतीय बाजार में अपना उत्पाद आक्रमक ढंग से बेचने को मजबूर कर रही है।

**XVII.** संगततः अल्प अवधि में भारी पाटन हुआ है और घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि हो रही है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को पूर्वापेक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने पर विचार करना चाहिए।

**XVIII.** किसी भी डब्ल्यूटी ओ सदस्य देश ने चीन के उत्पादकों को संगत मानदण्ड का विस्तृत अद्यतन विश्लेषण करने के आधार पर, जिसमें उप-पैराग्राफ 8(3) में विहित मापदण्ड भी शामिल हैं, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है। इसलिए, चीन की किसी भी कम्पनी को बाजार अर्थ व्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए और चीन के लिए सामान्य मूल्य की रचना पाटनरोधी नियामावली के नियम-7 में उल्लिखित निबंधनों के अनुरूप करनी चाहिए।

**XIX.** जहाँ तक झेजियांग यिशेंग और इसके एसोसिएट्स द्वारा निर्यातों की अल्प मात्रा के मुद्रे का सम्बंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्यातकों को यह सिद्ध करना चाहिए कि उसकी कीमतें प्रचलित कीमतों का प्रतिनिधित्व कैसे करती है। उदाहरण के लिए, कोई पक्षकार प्रतिदर्श बिक्री के आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की मांग नहीं कर सकता है।

**XX.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि चीन जन गण से आयातों की मात्रा बहुत कम है और वह घरेलू उद्योग को क्षतिकारित करने में सक्षम नहीं है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चीन जन गण से आयातों की मात्रा न्यूनतम से अधिक है और वह घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने के लिए पर्याप्त है।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

23. चूंकि इस जाँच में चीन जन गण, और ईयू का ऊपर पैरा 19 (xvii) में उल्लिखित कारणों से सम्बद्ध देशों के दायरे से अपवर्जन कर दिया गया है, इसलिए प्राधिकारी इन देशों से सम्बंधित मुद्रों की जाँच करना संगत नहीं समझते हैं। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जाँच में सम्बद्ध देशों (कोरिया और थाईलैण्ड) के सम्बंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन से सम्बंधित प्रस्तुतिकरणों का प्राधिकारी द्वारा निम्नवत सामाधान कर दिया गया हैं:-

- i. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि कच्चे माल और पीटीए की कीमतों में उत्तार-चढ़ाव के कारण व्यापार का सामान्य अनुक्रम परीक्षण और पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन का निर्धारण मासिक आधार पर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी ने इसका माहवार विश्लेषण किया है।
- ii. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि जब बिकियां वितरकों को की जाती हैं तो निर्यातकों को कम वितरण लागत खर्च करनी पड़ती हैं और निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय उसे ध्यान में रखना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोकर्ता निर्यातकों के सम्बंध में निर्यात कीमत का निर्धारण सत्यापित आंकड़े और संगत नियमों के अनुसार किया गया है।
- iii. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध वस्तु का निर्यात पैकड और बल्क फार्म में किया जाता है और इसलिए व्यवहार्यता परीक्षण करते समय उत्पादन लागत और घरेलू बिक्रियों दोनों में विभिन्न प्रकार की पैकिंग की लागत को तटस्थ कर दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण निर्धारित नियमों तथा डीजीएडी की प्रचलित परम्परा के अनुसार किया जाता है।
- iv. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि नाफ्था, कूड आयल, पीएक्स और पीटीए की बाजार कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर किया जाता है, इसलिए वैशिक अर्थव्यवस्था तथा मांग/आपूर्ति की स्थिति ही कीमत उत्तार-चढ़ाव की मुख्य कारक होती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच पीटीए के आयातों के संबंध में है और इसलिए पैराक्सीलीन, जो प्रमुख कच्चे माल होता है और पीटीए की कीमत में उत्तार-चढ़ाव वर्तमान जाँच के लिए संगत हैं और न कि कोई अन्य कारक।
- v. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कोरिया द्वारा पाटन तथ्यतः गलत है क्योंकि कोरियाई उत्पादक अपनी बिक्री कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर करते हैं और इसी तरह आर आई एल, एमसीपीआई तथा आईओसी भी वैसा ही करते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी के अनुसार वास्तविक पाटन मार्जिन का परिकलन संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और संबद्ध वस्तु की फैक्टरी बाह्यस्तर पर वास्तविक निर्यात कीमत के बीच अन्तर के रूप में किया जाता है। यदि सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से अधिक है तो पाटन मार्जिन इस तथ्य के बाबजूद भी सकारात्मक हैं। निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातिक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर किया गया है।

### सामान्य मूल्य का निर्धारण

कोरिया गणराज्य तथा थाईलैण्ड में उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कोरिया गणराज्य में उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

24. धारा 9 के (1) (ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का आशय निम्नलिखित है:

i. सामान्य वस्तु जब उसका आशय उप धारा (6) के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुरूप यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खेत से हो, के लिए सामान्य व्यापार की स्थिति में तुलनीय कीमत अथवा

ii. निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बाजार की सामान्य स्थिति में समान वस्तुओं की कोई बिक्री न होती हो अथवा जब किसी खास बाजार स्थिति अथवा नियातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की मात्रा कम हो तब ऐसी बिक्री के लिए उचित तुलना की अनुमति प्रदार नहीं करती हैं तो, सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

(क) सामान्य वस्तु की तुलनीय सांकेतिक कीमत जब उप धारा (6) के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुरूप यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किया गया हो :

(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुरूप यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि के साथ-साथ मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागतः

बशर्ते कि मूल देश के अलावा किसी देश जहां इस वस्तु को केवल निर्यातक देश से लदान करके लाया गया है अथवा ऐसी वस्तु निर्यातक देश में उत्पादित न हो, से इस वस्तु के आयात के संबंध में, निर्यातक देश में कोई तुलनीय मूल्य न हो, सामान्य मूल्य का निर्धारण मूल देश में इसकी कीमत के संबंध में किया जायेगा।

### कोरिया आरपी

25. कोरिया आरपी के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है।

- ग. सैमसंग पेट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी जिसे अब सैमसंग जनरल कैमिकल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया आरपी (निर्यातक) के रूप में जाना जाता है।
- क. एस के पेट्रोकैमिकल इंक, कोरिया आरपी (उत्पादक) मित्सुबिशी कारपोरेशन जापान (निर्यातक) सहित
- ख. हयोसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी
- घ. टैक्वांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी, (उत्पादक/निर्यातक)

### एस के पेट्रोकैमिकल इंक कोरिया आरपी

26. वर्तमान जाँच में एस के पेट्रोकैमिकल इंक कोरिया आरपी (उत्पादक) ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान (निर्यातक) के साथ दायर किया था। अपने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर में एस. के. पेट्रोकैमिकल इंक ने यह घोषित किया कि उनकी घरेलू बिक्री का केवल एक चैनल है और जाँच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में सम्बद्ध वस्तु की ग्राहकों को बिक्री प्रत्यक्षतः ही करता है। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा की गई कि कम्पनी ने घरेलू बाजार में सम्बद्ध उत्पाद की बिक्री अन्तिम प्रयोक्ता और वितरक दोनों को ही की है, तथापि, ग्राहक की श्रेणी के आधार पर बिक्री प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं है। निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कम्पनी ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को इस सम्बद्ध वस्तु की भारी मात्रा का निर्यात दो अन्य कम्पनियों अर्थात मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान और हयोसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी, जो वर्तमान जाँच में एक अन्य प्रतिवादी कम्पनी है, के माध्यम से किया था। कम्पनी ने मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान के माध्यम से \*\*\*एमटी सम्बद्ध वस्तु का निर्यात तथा हयोसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी के माध्यम से \*\*\*एम टी सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया था। निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करने पश्चात एस. के. पेट्रोकैमिकल, इंक कोरिया आरपी ने यह सूचित किया कि उन्होंने अब इस सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करना बंद कर दिया है और वर्तमान जाँच से बाहर रहने का विकल्प दिया है। चूंकि एस. के. पेट्रोकैमिकल इंक, कोरिया आरपी ने वर्तमान जाँच से बाहर रहने का विकल्प दिया है इसलिए प्राधिकारी इस कम्पनी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

### मैसर्स हयोसंग कारपोरेशन कोरिया आरपी

27. निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर में कंपनी ने यह घोषित किया है कि जाँच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री करने के लिए उनके पास दो माध्यम अर्थात असंबद्ध घरेलू अंतिम प्रयोक्ताओं को सीधे की गई बिक्रियां और वितरकों को की गई बिक्रियां। निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को तीन सरणियों से निर्यात किए हैं-

- क) स्वयं उत्पादित संबद्ध वस्तु की प्रत्यक्ष बिक्री;
- ख) स्वयं उत्पादित संबद्ध वस्तु का अपने असंबद्ध व्यापारियों अर्थात मित्सुई एंड कंपनी, कोरिया आरपी के जरिए निर्यात;
- ग) अन्य उत्पादकों अर्थात एस.के. पेट्रोकैमिकल, लोटे कैमिकल और सामनाम पेट्रोकैमिकल द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का निर्यात।

28. कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/ सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के दौरान कम्पनी ने कुल \*\*\* के आर डब्ल्यू मूल्य की कुल \*\*\* एमटी मात्रा के लिए अपने गैर-सहबद्ध पक्षकारों को इस सम्बद्ध वस्तु के \*\*\* घरेलू सौदे किए।

29. जाँच की अवधि के दौरान भारत को सम्बद्ध वस्तु के निर्यातों का संबंध है, हयोसंग कारपोरेशन की तीन सरणियाँ थीं— सीधे निर्यात, असम्बद्ध व्यापारिक कम्पनियों के माध्यम से निर्यात और अन्य कोरियाई उत्पादकों द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु का निर्यात। जाँच की अवधि के दौरान कम्पनी ने भारत को कुल \*\*\* के आर डब्ल्यू (\*\*\* यूएस डालर) मूल्य की \*\*\* एमटी सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया था। जाँच की अवधि के दौरान, कम्पनी ने अपनी एक असम्बद्ध व्यापारिक कम्पनी मित्सुई कारपोरेशन, जिसने वर्तमान जाँच में निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है, के माध्यम से इस सम्बद्ध वस्तु का भारत को कुल 'केआरडब्ल्यू' (\*\*\* यूएस डालर) मूल्य का \*\*\* एमटी का निर्यात भी किया था। इसके अतिरिक्त जाँच की अवधि के दौरान कम्पनी ने अन्य कोरियाई उत्पादकों अर्थात् एस. केकैमिकल्स, सामनाम और लोटेर द्वारा उत्पादित कुल \*\*\* के आर डब्ल्यू (\*\*\* यूएस डालर) मूल्य के \*\*\* एमटी सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया था। यद्यपि एस.के.पैट्रोकैमिकल्स ने वर्तमान जाँच से बाहर रहने का विकल्प दिया है, वहीं साम नाम और लोटेर ने वर्तमान जाँच रहने में निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के दौरान भारत को इस सम्बद्ध वस्तु के किए गए कुल \*\*\* एमटी निर्यातों में से, लगभग \*\*\*% निर्यात प्राधिकारी के समक्ष सत्यापित आंकड़ों का भाग नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, हयोसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी द्वारा इस सम्बद्ध वस्तु के किए गए निर्यातों की पर्याप्त मात्रा के बारे में सम्पूर्ण मूल्य श्रंखला के अभाव में, प्राधिकारी प्रतिवादी कम्पनी को व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत, हयोसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी के सम्बंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करना संगत नहीं माना जाता है और इसलिए प्राधिकारी हयोसंग कारपोरेशन कोरिया आरपी के लिए व्यक्तिगत सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं करते हैं।

#### मैसर्स सैमसंग पैट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी जिसे अब सैमसंग कैमिकल कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है

30. जाँच शुरूआत के पश्चात मैसर्स सैमसंग पैट्रोकैमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी की ओर से दिनांक 20 मई, 2014 में पत्र के तहत यह सूचित किया गया कि उक्त कंपनी का विलयन सैमसंग जनरल कैमिकल कम्पनी लिमिटेड, कोरिया आरपी के साथ हो गया है और इस विलयन के परिणामस्वरूप सैमसंग जनरल कैमिकल कंपनी लिमिटेड कोरिया आरपी अब संबद्ध वस्तु की उत्पादक कंपनी हो चुकी है। इस कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान कम्पनी द्वारा यह सूचना दी गई कि इसके एक प्रमुख शेयर धारक ने \*\*\* ग्रुप के साथ स्टाक खरीद करार कर लिया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने असंबद्ध पक्षकारों को \*\*\* के आर डब्ल्यू मूल्य की \*\*\* एमटी सम्बद्ध वस्तु की बिक्री की थी। जाँच की अवधि के दौरान, कम्पनी ने इस सम्बद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में ग्राहकों को प्रत्यक्षतः बिक्री की थी। केवल \*\*\* एमटी सम्बद्ध वस्तु की बिक्री एक सम्बद्ध पक्षकार \*\*\* को की गई थी। प्राधिकारी ने किए गए सौदों का माहवार विश्लेषण किया है और जाँच के सामान्य अनुक्रम का अनुप्रयोग किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुछ महीनों में लगभग सम्पूर्ण बिक्री, बिक्री लागत से कम कीमत पर की गई थे और इन महीनों में प्राधिकारी ने सहयोगकर्ता निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर लाभ अर्जन करने वाली घरेलू बिक्रियों पर कम्पनी द्वारा जाँच की अवधि के दौरान दावाकृत उचित सामयोजनों के पश्चात विचार किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने इस कम्पनी के लिए \*\*\* यूएस डालर प्रति एमटी सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

#### टैक्यांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी

31. निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर में कंपनी ने घोषणा की कि जाँच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री की उनकी तीन श्रेणियाँ थीं अर्थात् असंबद्ध अंतिम प्रयोक्ता को प्रत्यक्ष बिक्री, संबद्ध अंतिम प्रयोक्ता को सीधे बिक्रियाँ और असंबद्ध घरेलू व्यापारी के जरिए बिक्री। कम्पनी ने जाँच के दौरान भारत को निर्यात बिक्रियाँ प्रत्यक्षतः तथा असम्बद्ध विदेशी व्यापारी के जरिए भी की है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना की प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के दौरान, कम्पनी ने कुल \*\*\* के आर डब्ल्यू मूल्य के कूल \*\*\* एमटी मात्रा के \*\*\* घरेलू सौदे किए हैं। \*\*\* के आर डब्ल्यू मूल्य की कुल \*\*\* एमटी घरेलू बिक्री में से (\*\*\*%) की बिक्री सम्बद्ध पक्षकारों को की गई और प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह बिक्रियाँ आम्स्लेन्थ आधार पर की गई थी। प्राधिकारी ने सौदों का माहवार विश्लेषण किया है और जाँच के सामान्य अनुक्रम का प्रयोग किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुछ महीनों में लगभग सम्पूर्ण बिक्री, बिक्री लागत से कम पर की गई थी और इन महीनों के लिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर और लाभ के लिए 5% जोड़कर किया है। अन्य महीनों के सम्बंध में प्राधिकारी ने जाँच की अवधि के लिए कम्पनी द्वारा दावाकृत उचित समयोजन करने के पश्चात लाभ प्रदान कराने वाली घरेलू बिक्रियों पर विचार किया है। तदनुसार निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य \*\*\* यूएस डोलर प्रति एमटी है।

#### असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया आरपी के किसी भी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। कोरिया आरपी के सभी असहयोगकर्ता नियातकों/आयातकों के संबंध में प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण \*\*\* यूएस डालर/एमटी के रूप में करते हैं।

#### थाईलैंड के उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

33. थाईलैंड के निम्नलिखित संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है :

- क) इंडोरामा पैट्रोकेम लिमिटेड, थाईलैंड
- ख) टीपीटी पैट्रोकैमिकल्स पब्लिक लिमिटेड, थाईलैंड
- ग) इण्डोरामा पैट्रोकेम लिमिटेड, थाईलैण्ड

34. कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया। जांच की अवधि के दौरान, कम्पनी ने \*\*\*थाई बहट के लिए घरेलू बाजार में \*\*\*एमटी सम्बद्ध वस्तु की बिक्री की। कम्पनी द्वारा की गई कुल घरेलू बिक्रियों से से \*\*\*थाई बहट मूल्य की \*\*\*एमटी बिक्री को \*\*\*थाई बहट/प्रति एमटी की औसत दर सम्बद्ध पक्षकारों को की गई थी। प्राधिकारी ने सौदों का माहवार विश्लेषण किया है और जांच के सामान्य अनुक्रम का प्रयोग किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुछ महीनों में लगभग सम्पूर्ण बिक्री, बिक्री लागत से कम कीमत पर की गई थी और इन महीनों के लिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोग कर्ता निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर और आय के लिए उनमें 5% जोड़ किया गया है। अन्य महीनों के सम्बद्ध में, प्राधिकारी ने लाभ अर्जित करने वाले घरेलू बिक्रीयों पर जांच की अवधि के लिए कम्पनी द्वारा दावाकृत उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात विचार किया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने इस कम्पनी के लिए \*\*\*यूएसडी/प्रति एमटी सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

### टीपीटी पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लिमिटेड, थाईलैण्ड

35. कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया। जांच की अवधि के दौरान, कम्पनी ने \*\*\*थाई बहट के लिए घरेलू बाजार में \*\*\*एमटी सम्बद्ध वस्तु की बिक्री की। कम्पनी द्वारा की गई कुल घरेलू बिक्रीयों में से \*\*\*थाई बहट मूल्य की \*\*\*एमटी बिक्री को \*\*\*थाई बहट/प्रति एमटी की औसत पर सम्बद्ध पक्षकारों को की गई थी। प्राधिकारी ने सौदों का माहवार विश्लेषण किया है और जांच के सामान्य अनुक्रम का प्रयोग किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कुछ महीनों में लगभग सम्पूर्ण बिक्री, लागत से कम कीमत पर की गई थी और इन महीनों के लिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण सहयोगकर्ता निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर और आय के लिए उनमें 5% जोड़ कर किया गया है। अन्य महीनों के सम्बद्ध में, प्राधिकारी ने लाभ अर्जित करने वाले घरेलू बिक्रीयों पर जांच की अपधिके लिए कम्पनी द्वारा दावाकृत उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात विचार किया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने इस कम्पनी के लिए \*\*\*यूएस डी/प्रति एमटी सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैण्ड के किसी भी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। थाईलैण्ड के सभी असहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण \*\*\*यूएस डालर/एमटी के रूप में करते हैं।

### निर्यात कीमत कोरिया आरपी

#### एस. के पेट्रोकैमिकल इंक, कोरिया आरपी

37. निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का निर्यात अपनी दो अन्य कंपनियों अर्थात मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान तथा हयोसंग कारपोरेशन कोरिया आरपी वर्तमान जांच में एक अन्य प्रतिभागी कंपनी, के जरिए किया है। यद्यपि कम्पनी ने मित्सुबिशी कारपोरेशन जापान के माध्यम से \*\*\*एमटी सम्बद्ध वस्तु का निर्यात और हयोसंग कारपोरेशन कोरिया आरपी के माध्यम से \*\*\* एमटी सम्बद्ध वस्तु का निर्यात किया। निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करने के पश्चात एस. के. पेट्रोकैमिकल इंक, कोरिया आरपी. ने यह सूचना दी कि उन्होंने इस सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करना अब बंद कर दिया है और इसलिए उन्होंने वर्तमान जांच से अलग रहने का विकल्प दिया है। चूँकि एस के पेट्रोकैमिकल इंक, कोरिया आरपी ने इस जांच से अलग रहने का विकल्प दिया है, इसलिए प्राधिकारी इस कम्पनी के लिए व्यक्तिगत निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं करते हैं।

### मैसर्स हयोसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी

38. कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान कम्पनी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि हयोसंग ट्रेडिंग पीजी उस कम्पनी का केवल व्यापारिक प्रभाग है और हयोसंग कारपोरेशन द्वारा किए गए निर्यातों को इस व्यापारिक प्रभाग द्वारा किए गए निर्यातों से अलग नहीं किया जा सकता है। जांच की अवधि के दौरान हयोसंग कारपोरेशन को भारत को निर्यात की ३ सारणियाँ थीं प्रत्यक्षत निर्यात, असम्बद्ध व्यापारिक कम्पनियों के जरिए किए गए निर्यात और अन्य कोरियाई उत्पादकों द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु का निर्यात। जांच की अवधि के दौरान कम्पनी ने भारत को कुल \*\*\* केआरडब्ल्यू (\*\*\*यूएस डालर) मूल्य की \*\*\*एमटी सम्बद्ध वस्तु का प्रत्यक्षत: निर्यात किया था। जांच की अवधि के दौरान, इस कम्पनी ने अपनी एक असम्बद्ध कम्पनी मित्सुई कारपोरेशन, जिसने इस जांच में नियातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है, के जरिए कुल \*\*\* केआरडब्ल्यू (\*\*\* यूएसडालर) मूल्य के लिए भारत को \*\*\*एमटी सम्बद्ध वस्तु का निर्यात भी किया है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान इस कम्पनी ने एस.के. पेट्रोकैमिकल्स, साम नाम और लोटटे नामक कोरिया के अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु का \*\*\* केआरडब्ल्यू (\*\*\* यूएसडालर) मूल्य के \*\*\* एमटी का निर्यात भी किया है। एस. के. पेट्रोकैमिकल ने इस जांच से बाहर रहने का विकल्प दिया है, वहीं साम नाम और लोटटे ने इस जांच में नियातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान भारत को इस सम्बद्ध वस्तु के किए गए कुल \*\*\* एमटी निर्यातों में से लगभग \*\*\* प्रतिशत निर्यात प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए सत्यापित आंकड़ों का भाग नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, हयोसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी द्वारा किए गए इस सम्बद्ध वस्तु के निर्यातों की पर्याप्त मात्रा के सम्बंध में सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला का अभाव होने के कारण प्राधिकारी प्रतिवादी कम्पनी के लिए व्यक्ति गत मार्जिन का निर्धारण करने और व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी हयोसंग कारपोरेशन, कोरिया आरपी. के लिए व्यक्तिगत निर्यात कीमत और निर्यात मार्जिन का निर्धारण नहीं करते हैं।

**सैमसंग पेट्रोकैमिकल कम्पनी लिमिटेड, कोरिया आरपी जिसे अब सैमसंग जनरल कैमिकल कम्पनी लिमिटेड (उत्पादक) और सैमसंग सी एण्ड टी कोरिया आरपी (निर्यातक) के रूप में जाना जाता है।**

39. वर्तमान जाँच में, मैसर्स सैमसंग पेट्रोकैमिकल कम्पनी लिमिटेड, कोरिया आरपी (सैमसंग जनरल कैमिकल कम्पनी लिमिटेड के रूप में पुनर्नामित) द्वारा निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर मैसर्स सैमसंग सी एण्ड टी, कोरिया आरपी नामक अपने सम्बद्ध निर्यातक के साथ सम्बद्ध वस्तु के उत्पादक के रूप में दायर किया है। इस उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। जाँच की अवधि के दौरान सैमसंग जनरल कैमिकल कम्पनी लिमिटेड ने भारत को सम्बद्ध वस्तु का कुल \*\*\*यूएस डालर मूल्य का कुल \*\*\*एमटी मात्रा का निर्यात करने के लिए \*\*\*सौदे किये थे। जाँच की अवधि के दौरान भारत को किए गए कुल निर्यातों में से सैमसंग जनरल कैमिकल कम्पनी लिमिटेड ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को \*\*\*यूएस डालर प्रति एमटी की औसत कीमत पर सैमसंग सी एण्ड टी कोरिया आरपी के जरिए \*\*\*एमटी सम्बद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया था। सैमसंग जनरल कैमिकल कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपनी एक सम्बद्ध वस्तु की \*\*\*एमटी की अल्प मात्रा का निर्यात मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान जिसने वर्तमान जाँच में निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है, के जरिए भी किया गया है। मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान के जरिए किए गए निर्यातों की अल्प मात्रा (भारत को इसके कुल निर्यातों का लगभग \*\*\*%) पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने सैमसंग जनरल कैमिकल कम्पनी लिमिटेड (उत्पादक) और सैमसंग सी एण्ड कोरिया आरपी (निर्यातक) के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान के जरिए किए गए निर्यातों का अपवर्जन करके किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक और निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यथा दावाकृत और यथा सत्यापित, फैक्टरी बाह्यस्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए, (अन्तरदेशीय भाड़ा, प्रहस्तन प्रभार, सीमाशुल्क एवं ब्रोकरेज, समुद्री भाड़ा, बीमा, क्रेडिट व्यय पैकिंग प्रभार, बैंक प्रभार, शुल्क प्रतिअदायगी) समायोजन किया है तदनुसार, सैमसंग जनरल कैमिकल्स कम्पनी लिमिटेड (उत्पादक) और सैमसंग सी एण्ड टी, कोरिया आरपी (निर्यातक) के लिए फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का प्राधिकारी द्वारा निर्धारण \*\*\* यूएस डालर प्रति एमटी के रूप में किया है।

**ताइक्वांग इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड कोरिया आरपी**

40. वर्तमान जाँच में ताइक्वांग इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड, कोरिया आरपी द्वारा निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर भारत को सम्बद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक के रूप में दायर किया गया था। उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत कराए गए आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया। जाँच की अवधि के दौरान इस कम्पनी ने भारत को कुल \*\*\* यूएस डालर मूल्य के कुल \*\*\*एमटी मात्रा का भारत को निर्यात करने के लिए \*\*\*सौदा प्रत्यक्षतः किए थे जिनमें एक असम्बद्ध कम्पनी, मित्सुई कारपोरेशन के जरिए किए गए \*\*\*एम टी के निर्यात भी शामिल हैं। चूंकि असम्बद्ध व्यापारी के जरिए की गई निर्यात की मात्रा अमहत्पूर्ण है, इसलिए प्राधिकारी ने कम्पनी के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उन निर्यातों का अपवर्जन करके किया है। प्राधिकारी ने फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुँचने के लिए, निर्यातक द्वारा दावाकृत और शुल्क प्रति अदायगी के अपवाद सहित यथा—सत्यापित (अन्तरदेशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, क्रेडिट व्यय, बैंक प्रभार, प्रहस्तन, व्यय पैकिंग व्यय, सीमा शुल्क ब्रोकर शुल्क) का समायोजन किया। सत्यापन के दौरान कम्पनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारत को किए गए निर्यात के विरुद्ध कम्पनी द्वारा दावाकृत शुल्क प्रतिअदायगी का परिकलन सभी निर्यातों के लिए दावा की गई कुल राशि के आधार पर और किए गए सभी निर्यातों की मात्रा से भाग दिकर और भारत के निर्यात की मात्रा द्वारा गुणा करके किया गया है कम्पनी से पीटीए का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग किए गए कच्चे माल पर प्रदत्त आयात शुल्क का विवरण और भारत को किए गए निर्यात तथा अन्य देशों को किए गए निर्यातों पर दावा की गई प्रतिअदायगी की राशि और कोरियाई सीमा शुल्क प्रधिकारियों से वास्तविक रूप में प्राप्त राशि संगत दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। तथापि, कम्पनी ने भारत के किए गए निर्यातों के लिए दावाकृत प्रति अदायगी हेतु समर्थनकारी दस्तावेज सहित कोई दस्तावेज और इस दावे का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया। तदनुसार, ताइक्वांग इण्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड, कोरिया आरपी के लिए फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण दावा की गई शुल्क प्रति अदायगी की राशि का अपवर्जन करने के पश्चात \*\*\*यूएसडी प्रतिएमटी किया गया है।

**कोरिया आरपी के असहयोगकर्ता निर्यातक**

41. कोरिया आरपी के उन अन्य सभी निर्यातकों के संबंध में, जिन्हें असहयोगकर्ता के रूप में माना गया है, प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर \*\*\*यूएसडी डालर/एमटी के रूप में किया है।

**थाईलैंड**

42. थाईलैंड के निम्नलिखित संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जाँच में प्रत्युत्तर दायर किया है:

क) इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड, थाईलैंड

ख) टीपीटी पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लिमिटेड, थाईलैंड

**इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड थाईलैंड**

43. निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर में कम्पनी ने घोषित किया कि जाँच की अवधि के दौरान उसने भारत को, अपनी संबद्ध भारतीय कंपनी अर्थात मैसर्स इंडोरामा सिंथेटेक्स (आई) लिमिटेड को ही प्रत्यक्ष निर्यात किया है। उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया। जाँच की अवधि के दौरान इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड थाईलैंड ने भारत को कुल \*\*\*थाई बहट मूल्य की सम्बद्ध वस्तु के कुल निर्यातों में से \*\*\*एमटी का निर्यात, भारत में एक सम्बद्ध पक्षकार मैसर्स इण्डोरामा सिंथेटिक्स (इण्डिया) लिमिटेड को \*\*\*थाई बहट प्रति एम टी की औसत कीमत पर किए गए थे।

शेष \*\*\*एमटी सम्बद्ध वस्तु का निर्यात\*\*\* प्रति एमटी की औसत कीमत पर अन्य असम्बद्ध पक्षकारों को किया गया था। अन्य समायोजनों के अलावा आईआरपीएल ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए घटौती का दावा किया था। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार जॉच की अवधि के दौरान थाईलैंड की सरकार ने पीटीए के निर्यातों पर निर्यात प्रोत्साहन प्रदान किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातिक देशों की सरकारों द्वारा प्रदान किया गया और निर्यातिकों द्वारा दावा किया गया यह निर्यात प्रोत्साहन सम्बद्ध वस्तु का निर्यात करते समय निर्यातिक द्वारा उपगत किए गए व्यय का भाग नहीं होता है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य से निर्यातिक द्वारा दावा किए गए और यथा सत्यापित निर्यात आदेश प्रोत्साहन को छोड़कर। (समुद्री भाड़ा, अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा, टीएचसी प्रभार, सीमाशुल्क निकासी प्रभार, पैकिंग लागत, क्रेडिट लागत बैंक प्रभार) के लिए उचित समायोजन किए हैं और उसका \*\*\* यूएस डालर प्रति एमटी निर्धारण किया है।

### टीपीटी पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लिमिटेड, थाईलैंड

44. निर्यातिक प्रश्नावली प्रत्युत्र में कम्पनी ने घोषित किया कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तु का भारत को अपनी संबद्ध भारतीय कंपनी अर्थात इंडोरामा सिथंटिक्स (आई) लिमिटेड के जरिए प्रत्यक्ष निर्यात किया है। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना की प्राधिकारी द्वारा जॉच की गई। जॉच की अवधि के दौरान कम्पनी ने भारत को इस सम्बद्ध वस्तु की एमटी \*\*\*मात्रा का निर्यात \*\*\*यूएसडालर प्रति एम टी की औसत कीमत से किया था। अन्य समायोजनों के अलावा टीपीटी ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए घटौती का दावा किया था कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार जॉच की अवधि के दौरान थाईलैंड की सरकार ने पीटीए के निर्यातों पर निर्यात प्रोत्साहन प्रदान किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातिकों द्वारा दावा किया गया और निर्यातिक देशों की सरकारों द्वारा प्रदान किया गया यह निर्यात प्रोत्साहन सम्बद्ध वस्तु का निर्यात करते समय निर्यातिक द्वारा उपगत किए गए व्यय का भाग नहीं होता है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य से निर्यातिक द्वारा दावा किए गए और यथा सत्यापित निर्यात प्रोत्साहन को छोड़कर। (समुद्री भाड़ा, अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा, टीएचसी प्रभार, सीमाशुल्क निकासी प्रभार, पैकिंग लागत, क्रेडिट लागत बैंक प्रभार) उचित समायोजन किए हैं और उसका \*\*\* यूएस डालर प्रति एमटी निर्धारण किया है।

### थाईलैंड के असहयोगकर्ता निर्यातिक

45. थाईलैंड के अन्य सभी निर्यातिकों के संबंध में, जिन्हें असहयोगकर्ता के रूप में माना गया है, प्राधिकारी ने उनकी निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमावली के नियम 6(8) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार \*\*\*यूएस डालर प्रति एमटी के रूप में किया है।

### पाटन मार्जिन

46. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का परिकलन निम्नवत किया गया है।

क्रम सं.	निर्यात का माध्यम	उत्पादक का नाम	निर्यातिक	क्षति रहित कीमत यूसडी/एमटी	पहुंच कीमत यूसडी/एम टी	क्षति मार्जिन यूसडी/एमटी	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज -%
कोरिया आरपी आरपी . भारत								
1	कोरिया आरपी . भारत	सैमसंग जनरल कैमिकल कंपनी लिमिटेड	सैमसंग सी एण्ड टी	***	***	***	***	0 - 10
2	कोरिया आरपी . भारत	टैक्यांग इण्डस्ट्रियल कं., लि.	टैक्यांग इण्डस्ट्रियल कं., लि.	***	***	***	***	0 - 10
3	कोई	अन्य सभी उत्पादक	अन्य सभी निर्यातिक	***	***	***	***	5 - 15
थाईलैण्ड								
4	थाईलैण्ड-भारत	इंडोरामा पेट्रोकेम लि.	इंडोरामा पेट्रोकेम लि.	***	***	***	***	0 - 10
5	थाईलैण्ड-भारत	टीपीटी पेट्रोकैमिकल पब्लिक लि.	टीपीटी पेट्रोकैमिकल पब्लिक लि.	***	***	***	***	0 - 10
6	कोई	अन्य सभी उत्पादक	अन्य सभी निर्यातिक	***	***	***	***	5 - 15

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

**निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण**

47. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं:

- i. सम्बद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों में से एक कम्पनी, जिसने इस याचिका का समर्थन नहीं किया है, आई ओ सीएल की कीमत अन्य घरेलू उत्पादकों की कीमत से 4-10 प्रतिशत कम है। परन्तु आई ओ सी एल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आयातों के कारण कीमत में कमी होने दावा नहीं किया है। जहाँ आईओसीएल इस जॉच से बाहर रहा है, क्योंकि उसे लाभ हो रहा है, वहीं मित्शुबिशी और रिलायन्स यह दावा करते हैं कि उन्हें सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के कारण घाटा हो रहा है।
- ii. आर आई एल अपनी पीटीए क्षमता का 100 प्रतिशत से अधिक का विस्तार कर रहा है, जिससे इस तथ्य को बल मिलता है कि पीटीए का व्यवसाय अच्छा चल रहा है और उससे लाभार्जन हो रहा है। रिलायन्स और इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) दोनों का क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक था। आईओसी ने इस याचिका का न तो समर्थन किया और न ही जॉच में भाग लिया है।
- iii. आरआईएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि पेट्रोकैमिकल सेक्टर को 11.2 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत प्रचालन लाभ हुआ है जो कम्पनीवार लाभ की तुलना में बहुत अधिक है।
- iv. पीएक्स-पीटीए डेल्टा (पीटीए की कीमत और पीएक्स की लागत में अन्तर) में कमी होने के कारण एमसीआई को घाटा हुआ परन्तु आरआईएल और आईओसी को लाभ हुआ। याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि पीएक्स-पीटीए डेल्टा उत्तरजीविता हेतु विदेशी उत्पादकों के लिए कम से कम 150 डालर प्रति एम टी होना चाहिए। तथापि एमसीपीआई का पीएक्स-पीटीए डेल्टा (यूनिट पीटीए उत्पादन लागत-यूनिट पीक्स लागत) 253-279 डालर/प्रतिएमटी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एमसीपीआई जब तक अपनी लागत कम नहीं करता है तब तक वह विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है।
- v. आरआईएल ने पीएक्स डिवीजन में भारी लाभार्जन किया है परन्तु उसे पीटीए डिवीजन में घाटा हुआ है। आरआईएल पीएक्स के उत्पादन को पृथक लाभ केन्द्र के रूप में देखता है और पीएक्स की लागत को पीटीए की लागत जमा या बाजार कीमत आधार पर अन्तरित करता है। इसके परिणामस्वरूप, पीटीए की वास्तविक लागत में वृद्धि हो जाती है।
- vi. आरआईएल 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग का लाभ उठाता है और आई ओसीएल ने क्षति की अवधि और जॉच की अवधि में क्षमता उपयोग की न्यून दर का कारण अपनी क्षमता में अचानक विस्तार करना है और इसके संयंत्र2/चरण 2में सामने आई तकनीकी समस्यायें हैं। ऐसी स्थिति में, डीजीएडी को घरेलू उद्योग को संरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि केवल एक घरेलू उत्पादक (एमसीपीएल) के क्षमता उपयोग की दर कम है और वह भी इसकी उत्पादन सुविधाओं में समस्या और इसके क्षमता उपयोग में विस्तार के कारण हुई है।
- vii. घरेलू उद्योग ने विभिन्न करकों में संभावित गिरावट को सिद्ध नहीं किया है।
- viii. यह आरोप त्रुटिपूर्ण है कि वर्ष 2009-10 की तुलना में आयातों की मात्रा में समग्र वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 का समय वैशिक मंदी का समय था और उसे आधार वर्ष मानकर किया गया कोई भी विश्लेषण यथोर्थ नहीं होगा।
- ix. वर्ष 2010-11, 2011-12 और जॉच की अवधि में आयातों की मात्रा में कमी आई है उत्पादन के साथ-साथ खपत के सम्बंध में आयातों का प्रतिशत वर्ष के दौरान घटा है।
- x. घरेलू उद्योग मात्रा प्रभाव के कारण क्षति का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग अधिकतम क्षमता से प्रचालन करने के बावजूद बाजार की मांग को पूरा करने में असफल रहता है तो आयात होंगे।
- xi. आयातों के उत्तराई मूल्य में सतत एवं पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है।
- xii. घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं उसकी विक्री में भारी वृद्धि हुई है।
- xiii. एमसीपीआई ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखा एक पत्र में अपने संयंत्र में तकनीकी समस्या होने का दावा किया है, जिसके परिणामस्वरूप, उनका संयंत्र समुचित रूप से प्रचालन नहीं कर सका। इस कारण, उन्हें घटे हुए निर्यात दायित्व का लाभ मिल गया। आवेदक लाभ अर्जित करने लिए विभिन्न सार्वाधिक प्राधिकारियों के समक्ष अलग-अलग दावे नहीं कर सकता है। आरआईएल

और आईओसी ने पीटीए सुविधा को पूर्ण क्षमता से प्रचालन किया परन्तु एमसीपीआई तकनीकी समस्या के कारण आपना उत्पादन सामान्य नहीं कर सका।

xiv. एमसीपीएल के पूर्ण निष्पादन न कर पाने के लिए मुख्यकारण उसकी प्रचालनात्मक अक्षमता है, न कि आयात। एमसीपीएल, पीटीएके एक निर्यातक से सम्बद्ध होने के कारण यद्यपि इस याचिका में घरेलू उद्योग के रूप में शामिल होने के लिए पात्र होने के अर्ह नहीं है, फिर भी उसे वास्तविक क्षति सिद्ध करने के लिए शामिल किया गया, यद्यपि वह कथित पाठित आयातों के अलावा अन्य कारणों से अपनी पूर्णक्षमता से कार्य नहीं कर रहा है।

xv. एमसीपीएल का दूसरा संयंत्र तकनीकी खामी से जूझ रहा है। एमसीपीएल को न्यून क्षमता उपयोग, लगाई गई पूँजी पर न्यून प्रतिलाभ आदि से घाटा हो रहा है। एमसीपीएल के कथित कम निष्पादन के लिए चीन जन-गण से पीटीए के आयातों को उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है और प्राधिकारी को चाहिए कि वे क्षति विश्लेषण करते समय, एमसीपीएल द्वारा तकनीकी समस्याओं से सहन की गई क्षति को पृथक करें। एमसीपीएल को क्षति का प्रमुख कारण तकनीकी समस्या के कारण उनके संयंत्र के समक्ष उपस्थित समस्या है।

xvi. वर्ष 2010-11 से आयातों के बाजार हिस्सें में भारी कमी आई है।

xvii. वर्ष 2011-12 से जांच की अवधि तक बिक्री में वृद्धि उस अवधि में हुए उत्पादन में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है। इस मामले में यह तथ्य कि मालसूची में वृद्धि हुई है, परस्पर विरोधाभासी है।

xviii. उत्पादकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ। रोजमर्ग में वृद्धि हुई है। थोड़ी सी कमी एमसीपीआई के संयंत्र में तकनीकी खराबी के कारण आई है। संयंत्र वेतन में भी वृद्धि हुई है।

xix. पीटीए के घरेलू उत्पादकों द्वारा कीमत का निर्धारण संदर्भ कीमत पर आधारित है जो प्लैट्स द्वारा रिपोर्ट की गई चीन की सीएफआई है या आईसीआई एस द्वारा रिपोर्ट की गई सीएफआर सीएमपी है।

xx. एमपीसीएल, पीएक्स की कमी से पीड़ित है। और उसके लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। पीएक्स की कीमत में वृद्धि हो गई है परन्तु नापथा की कीमत में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, नापथा की कीमतों में वृद्धि, पीटीए की कीमतों में वृद्धि के समान ही थी। तीन में से दो घरेलू उत्पादक नापथा से पीएक्स का उत्पादन करते हैं और वे पीटीए का उत्पादन करने के लिए इसकी खपत करते हैं। इसलिए उत्पादन, लागत गैर क्षतिकारी कीमत, लाभ/हानि और आयक का निर्धारण करने के लिए वास्तविक उत्पादन लागत पीएक्स के लिए ग्रहण की जानी चाहिए न कि किसी अनुमानिक कीमत को।

xxi. एमसीपीआई को उसी वर्ष से घाटा होना प्रारम्भ हो गया जिस वर्ष से उसने अपनी क्षमताओं में विस्तार किया। एमसीपीआई ने वर्ष 2010 के दौरान अपनी क्षमता में लगभग तीन गुना वृद्धि की जिसके कारण उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आ गई और उसके परिणामस्वरूप उसे घाटा हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि एमसीसीपीआई को स्टर्ट अप समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उसने अपने उत्पादन को अभी स्थिर नहीं किया है। इस पहलू की डीजीएडी द्वारा विस्तृत जांच की जानी चाहिए।

xxii. घरेलू उद्योग द्वारा विचार की गई विनिमय दर 54 है जबकि आरबीआई की चालू विनिमय दर 62.88 है। यदि प्रचलित विनिमय दर पर विचार किया जाता है तो कीमत अधोरेदन और कीमत अधोविक्रयण का स्तर कम हो जाएगा।

xxiii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (iv) में विशिष्ट क्षति से संबंधित आंकड़ों का 'पृथक अभिज्ञान' किए जाने की अपेक्षा की गई है क्योंकि केवल तीन ही घरेलू उत्पादक हैं और प्रत्येक उत्पादक की उत्पादन प्रक्रिया मिन है।

xxiv. आर आई एल के पीटीए उत्पादन के 66 प्रतिशत का उत्पादन ग्राही खपत के लिए होता है और यह आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।

xxv. कीमत और लागत में भारी उत्तर-चढ़ाव के कारण सभी आर्थिक पैरामीटरों (कीमत अधोरेदन, अधोविक्रयण, निग्रहण एवं अवमंदन सहित) की जांच मासिक आधार पर की जानी चाहिए।

xxvi. कीमत निग्रहण/अवमंदन के संदर्भ में, आर आई एल और एमसीपीआई की लागत में भारी अंतर है और उत्पादन लागत का साधारण संचयन विश्लेषण को विकृत कर देगा।

xxvii. सुविधा उपयोग, लाभप्रदायकता और सर्वार्थीत माल सूची को छोड़कर किसी भी आर्थिक पैरामीटर ने क्षति प्रदर्शित नहीं की है।

xxviii. एमसीपीआई ने आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है।

xxix. आर आई एल ने ग्राही खपत के संदर्भ में सम्पूर्ण मात्रा की सूचना प्रदान की है। आर आई एल ने प्रत्येक बाजार प्रखंड व्यापारी और ग्राही के लिए सूचना प्रदान नहीं की है।

xxx. पीटीए का विनिर्माण करने के लिए पैराक्सीलीन पीएक्स मुख्य फीडस्टाक है, पीटीए की क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2009–10 से 2012–13 की अवधि के दौरान पीएक्स उत्पादन में क्षमता संवर्धन कम हो गया। क्षमता संवर्धन और पीएक्स की आपूर्ति में कमी से पीएक्स की कीमतों में वृद्धि हुई, जिस कारण से पीटीए की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। पीटीए की बिक्री कीमत पर दबाव पीटीए की अधिक आपूर्ति होने के कारण आया इसलिए विनिर्माताओं के मार्जिन पर दबाव पड़ा।

xxxi. यदि डीजीएडी एमसीपीआई की तकनीकी समस्या के कारण उपगत संवर्धनात्मक उत्पादन लागत कारकों पर विचार करता है और आर आई एल द्वारा प्राप्त आन्तरिक लाभ पर विचार करता है तो कोई भारी क्षति मार्जिन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, आरआईएल, जो आधारभूत स्थिति से सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इस उत्पाद के विभिन्न स्तरों पर अन्तरण कीमत को अपनाता है। वास्तविक कीमत पर पहुँचने के लिए, प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर जुड़े लाभ की प्रक्रिया को अवतरित कर अपनाया है। अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए और तदनुसार वास्तविक लागत का परिकलन किया जाना चाहिए।

xxxii. डीजीएडी द्वारा प्रारम्भिक जांच परिणाम में आंकी गई आवेदकों की क्षमता गलत है। आवेदकों की क्षमता 3240000एमटी है न कि 3420000एमटी और जांच की अवधि के दौरान आवेदकों का क्षमता उपयोग 90% है, न कि 86%, जैसा कि डीजीएडी ने अपने प्रारम्भिक जांच परिणाम में अंकन किया है।

xxxiii. सम्बद्ध आयातों का आवेदकों पर मार्जिनल कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण प्रभाव के कारण कोई विपरीत कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है। जब कीमत अधोविक्रयण और कीमत अधोरदन लगभग बराबर हैं तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एनआईपी और एनएसआर भी लगभग समान ही होंगे। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग एनआईपी की लगभग बराबर कीमत पर बिक्री करने में सक्षम हो वहाँ यह कल्पना करना असम्भव है कि उद्योग को घाटा हो रहा है।

xxxiv. पीटीए की आयात कीमत भारत में घरेलू उत्पादन की बिक्री कीमत से अधिक है। कीमत अधोरदन का दावा न्यायोचित नहीं है। अतः कोई विपरीत कीमत प्रभाव नहीं है। घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री को क्षति नहीं हुई है। विपरीत कीमत प्रभाव और मात्रा प्रभाव के अभाव में कोई कारणात्मक सम्बंध नहीं है।

xxxv. आरआईएल का यह दावा कि उसे पीटीए की घरेलू विक्रियों से प्रचालन घाटा हुआ है क्योंकि वह पीएक्स की आन्तरिक अन्तरार्द्धीय कम्पनी अन्तरण कीमत का प्रयोग करता है जिसका याचिका में पीटीए की लाभप्रदता और उत्पादन लागत का परिकलन करने के लिए, मूल्य सम्बवतः अन्तरार्द्धीय बाजार कीमत पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप, पीएक्स संयंत्र को आन्तरिक लाभ हुआ वहीं पीटीए को आन्तरिक घाटा हुआ।

xxxvi. डीजीएडी द्वारा अनुमत नियोजित पूँजी पर 22 % प्रतिलाभ तर्कसंगत नहीं हैं।

xxxvii. क्षति विश्लेषण व्यापारियों को तथा ग्राही आपूर्ति दोनों के लिए प्रवृत्तियों का अलग-अलग एवं फिर संचयी विश्लेषण होना चाहिए। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण आर आई एल द्वारा ग्राही खपत की अनदेखी करके किया है।

xxxviii. जब आयातों में वर्ष 2010–11 में सर्वाधिक वृद्धि हुई तब आवेदक को अधिकतम लाभ हुआ। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 2009–10 और 2010–11 के लिए ऋणात्मक कीमत अधोरदन का आकलन किया है और जांच की अवधि में यह 0–10 % की रेंज में था। इसलिए आवेदक घरेलू उत्पादक को वर्ष 2011–12 के दौरान क्षति उपगत होने का कोई कारण ही नहीं है।

xxxix. उपर्युक्त प्रस्तुतिकरणों की पूर्वाधारणा के बिना, यह तर्क भी दिया जाता है कि अधिरोपित शुल्क और सम्बद्ध उत्पाद के उत्तराई मूल्य की तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि कीमत अधोविक्रयण/क्षतिमार्जिन नगण्य है अर्थात लगभग सभी मामलों में 4 % से कम है इससे पुनः यह संकेत मिलता है कि कीमत अधोरदन 2–3 % से कम की रेंज में होनाचाहिए।

xl. गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए लाभ, नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह का निर्धारण भी असाधारण व्यय और लागत का अपवर्जन करने के पश्चात तथा सर्वोत्तम उपयोग प्रणाली अपनाकर किया जाना चाहिए।

xli. पीएक्स की कीमतों में वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान भारी वृद्धि हुई जबकि नापथा की कीमतों में उस दर पर वृद्धि नहीं हुई जिस दर पर वृद्धि पीएक्स की कीमतों में हुई थी। तथापि नापथा की कीमत में वृद्धि पीटीए की कीमत में हुई वृद्धि के अनुरूप थी। इसलिए आरआईएल वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान लगाई गई पूँजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ और क्षति की सूचना नहीं दे सकता है।

xlii. एमसीपीएल की कोयले की आपूर्ति करने हेतु निश्चित संविदा नहीं है, जिसका इसके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसे क्षति कारित करता है।

xliii. एमसीपीएल ने आपने संयंत्र की स्थापना उसके उपयोगकर्ताओं से काफी दूर की है और सम्बद्ध वस्तु के परिवहन पर इसके द्वारा व्यय की गई राशि इसे अप्रतिस्पर्धी बनाता है। इसलिए क्षति के एक कारक के रूप में भाड़े की निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने उपरोपण विश्लेषण में जाँच की जानी चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए।

xliv. मांग में वृद्धि होने के बाबजूद घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा स्थिर बना रहा। मांग में घरेलू उद्योग के स्थिर बाजार हिस्से और सम्बद्ध देशों से आयात के बीच कोई संबंध नहीं है।

xlv. एमसीपीएल ने पीएक्स (कच्चे माल) की खरीद अपने सम्बद्ध पक्षकार से काफी उच्च कीमतों पर की है निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वह एमसीपीएल द्वारा दर्शाई गई कीमत को नामजूर कर दें और गैर क्षतिकारी कीमत की रचना करने के लिए उस न्यून कीमत को अपनाएं जिस पर निर्यातक पीएक्स का अधिप्रापण करते हैं।

xlvi. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार गैर क्षतिकारी कीमत की संगणना करने के लिए क्रेडिट लागत और भाड़ा लागत से सम्बंधित समायोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अन्तर्गत प्रावधान की गई सांविधिक क्रियापद्धति के विपरीत है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के खण्ड 4 (VIII) (ख) में यह भी संपुष्टि की गई है कि गैर-क्षतिकारी कीमत फैक्टरी बाह्य स्तर पर होती है और गैर-क्षतिकारी कीमत का आकलन करते समय विनिमाण के पश्चात होने वाले खर्चों जैसे कमीशन, डिस्काउंट, बाहर ले जाने पर भाड़ा आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आवेदकों का दावा अस्वीकार्य है।

xlvii. घरेलू उद्योग का यह दावा अनुप्रयुक्त है कि भाड़ा लागत को गैर-क्षतिकारी कीमत में जोड़ा जाना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्तराई कीमत से गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना करते हैं। समान स्तर पर तुलना करने के उद्देश्य से फैक्टरी बाह्य स्तर पर गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण और पत्तन स्तर पर उत्तराई मूल्य का निर्धारण किया जाता है। दोनों ही मामलों में घरेलू परिवहन लागत को जोड़ा नहीं जाता है।

xlviii. किसी सम्भावित क्षति और सम्बद्ध देशों से पीटीए के आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि आयातों में वृद्धि और कीमत प्रभाव का कोई खास महत्व नहीं है और कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।

xlix. एमसीपीआई आन्तरिक समस्याओं और पीटीए की आपूर्ति के अभाव के कारण अपनी उत्पादन सुविधा का प्रचालन नहीं कर सका। आपूर्ति में कमी के अन्तराल के अनुपूरक के रूप में आयात किए गए थे। इसलिए आयातों एवं घरेलू उद्योग को कठित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

i. सम्बद्ध देशों से पीटीए के आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति कारित नहीं हुई है। क्षमता उपयोग, लाभप्रदता और मालसूची को छोड़कर कोई भी अन्य आर्थिक पैरामीटर वास्तविक क्षति का संकेत नहीं प्रदर्शित करता है। मांग और बाजार हिस्से की प्रवृत्ति भी कारणात्मक सम्बंधों का अभाव प्रदर्शित करता है। यद्यपि घरेलू बिक्रीयों और मांग दोनों में ही वृद्धि हुई है, तथापि आयातों में कमी आई है।

ii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक को क्षति विश्लेषण से पृथक कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान जाँच में कीमत या मात्रा प्रभाव नहीं है। आवेदकों द्वारा दावा किया गया घाटा प्राथमिकता: पारिश्रमिक की उच्च लागत, लाभ एवं आयातों के बीच सम्बंध का अभाव, क्षमता में अवांछित वृद्धि, जिसके कारण पारिश्रमिक लागत उच्च हुई, आयातों और लाभ के बीच सम्बंधों का अभाव, एमसीपीएल द्वारा सहन की गई तकनीकी समस्या, कच्चे माल पीएक्स की कमी, रूपये के अवमूल्यन, पुनर्चक्रित पीटीए का प्रयोग आदि के कारण हुआ है।

iii. यद्यपि घरेलू बिक्रीयों और मांग दोनों में वृद्धि हुई परन्तु आयातों में कमी आई। इससे यह भी अभिव्यक्त होता है कि सम्बद्ध आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक सम्बंधों का अभाव है जिसे आवेदक द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। आवेदकों को होनेवाला घाटा मुख्यतः एमसीपीएल की उच्च पारिश्रमिक लागत, अवांछित क्षमता विस्तार, अस्थिर प्रचालन और उनके संयंत्र में अक्सर होने वाली खराबी और आयातों में कमी होने के बाबजूद लाभ में गिरावट के कारण हुआ है, न कि पाटन के कारण।

### घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

48. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं और प्राधिकारी ने उन्हें संगत माना है:-

i. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न कारकों में संभावित गिरावट को सिद्ध नहीं किया है, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की वास्तविक स्थिति की जाँच कर रहे हैं और यदि कोई क्षति प्रदर्शित नहीं होती है तो संभावित कारक संगत रहता है।

ii. यह तथ्य असंगत है कि आधार वर्ष मंदी का काल था, क्योंकि क्षति का दावा कीमत पर आधारित है, न कि मात्रा पैरामीटर पर। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 में आयात पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक थे।

- iii. वर्ष 2010–11 के पश्चात आयात मात्रा में गिरावट आई क्योंकि एमसीपीआई ने संस्थापित नई क्षमता से उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। तथापि, लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर अर्जन के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में वर्ष 2010–11 के पश्चात वास्तविक रूप से गिरावट हुई।
- iv. इस संबंध में कि घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर प्रचालन करने के बावजूद भी घरेलू मांग को पूरा करने में समक्ष नहीं हो रहा है, घरेलू उद्योग ने पाटन के विपरीत कीमत प्रभाव का दावा किया है।
- v. प्रत्युत्तरदाता पक्षकारों द्वारा किए गए दावे के अनुसार यद्यपि आयात कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि आयातों की सीआईएफ कीमत और अवसारित कीमत में वृद्धि कच्चे माल की लागत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम है और कीमत निग्रहण हुआ है।
- vi. इस तर्क के संबंध में कि एमसीपीआई ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखे एक पत्र में अपने संयंत्र में तकनीकी समस्या होने का दावा किया है, यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने कीमत का दावा किया है न कि मात्रा क्षति का।
- vii. इक तर्क के संबंध में कि एमसीपीआई ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखे पत्र एक पत्र में तकनीकी समस्या का दावा किया है घरेलू उद्योग ने कीमत का दावा किया है, कि मात्रा क्षति का।
- viii. इस तर्क के संबंध में कि अन्य घरेलू उत्पादकों के संयंत्र अपनी 100 प्रतिशत क्षमता से अधिक प्रचालन कर रहे हैं। और इसलिए न्यून क्षमता उपयोग का दावा नहीं किया जा सकता है, घरेलू उद्योग ने कीमत क्षति का दावा किया है, न कि मात्रा क्षति का।
- ix. इस तर्क के संबंध में कि वर्ष 2010–11 के पश्चात से आयातों के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है, घरेलू उद्योग ने कीमत क्षति का दावा किया है, न कि मात्रा क्षति का।
- x. प्रतिवादी पक्षकार ने यह दावा किया है कि वर्ष 2011–12 से जांच की अवधि में बिक्री में वृद्धि उसी अवधि के दौरान हुई उत्पादन में वृद्धि की तुलना से अधिक है और इसलिए मालसूची में वृद्धि हो ही नहीं सकती है। घरेलू उद्योग ने कीमत, न कि मात्रा क्षति, का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि, इसके उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कम थी, जिसके कारण माल सूची में बढ़ोत्तरी हुई।
- xi. उत्पादकता, रोजगार और वेतन के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने इनके कारण क्षति का दावा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, नियमों में विशिष्ट: यह उल्लेख नहीं है कि क्षति सभी पैरामीटरों के संबंध में होनी चाहिए।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह वृद्धि दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई।
- xiii. प्रतिवादी पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि आवेदक, यद्यपि उन पर सीमा शुल्क लागू नहीं था, फिर भी, संदर्भ कीमत का अनुमानिक 5.583 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क प्रभारित कर रहे हैं और यह कि, चूंकि कीमतें यूएस डालर में हैं, इसलिए रूपए में आई प्रपाती गिरावट के कारण उन्हें अनुचित लाभ हो रहा है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया गया कीमत तंत्र आयात समानता पर आधारित है। इसलिए अतिरिक्त, रूपए के अवमूल्यन का भी उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ा होगा। प्राधिकारी की यह एक सुस्थिरित परम्परा रही है कि वह जांच की अवधि के दौरान प्रचलित विनियम दर के आधार पर निर्धारण करते हैं।
- xiv. यद्यपि जांच की अवधि के दौरान मलेशिया से आयात निर्धारित सीमा से कम थे, इसलिए मलेशिया के निर्यातक और याचिकाकर्ताओं में से किसी एक के बीच संबंध होने की बात असंगत हो जाती।
- xv. एमपीसीएल को पीएक्स की कमी के कारण क्षति सहन करनी नहीं पड़ रही है, जैसा कि प्रतिवादी पक्षकार ने दावा किया है। इसका विपरीत मात्रा प्रभाव पड़ना चाहिए, परन्तु उसका दावा घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया है।
- xvi. थाइलैण्ड से आयात में सम्पूर्ण गिरावट होने और कोरिया से आयातों में मामूली वृद्धि होने के मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सभी देशों से किए जाने वाले आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन किया जाना चाहिए। थाइलैण्ड से आयातों में गिरावट कोरिया में हुई आयातों की वृद्धि के कारण आई है।
- xvii. इस तर्क के संबंध में कि पुनर्चक्रित सामग्री, जैसे पी ई टी बोतलें, की ओर अन्तरित होने के कारण मांग में कम वृद्धि हुई है, यह कहा जा सकता है कि मांग में ऐसा कोई संकुचन अथवा खपत की प्रणाली में ऐसा को परिवर्तन नहीं हुआ जिसके कारण घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ा हो।

**xviii.** इस दावे के संबंध में कि भारतीय रिजर्व बैंक की चालू विनिमय दर 62.88 है, जबकि जांच की अवधि के दौरान विनिमय दर 55.67 थी और यह वह दर थी जिसे घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया गया था।

**xix.** क्षति की रिपोर्टिंग के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद कर समाहर्तालय से जानकारी मंगाने के संबंध में यह कहा जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी की यह अपेक्षा नहीं है।

**xx.** प्रतिवादी पक्षकार ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(iv) की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की है कि उसमें “पृथक अभिज्ञान” की जरूरत है। अनुबंध-II(iv) में एक ऐसी विधि का प्रावधान किया गया है जहां समान उत्पाद के उत्पादन से संबंधित सूचना, जैसे उत्पादक को लाभ और बिक्री, को अलग से अभिज्ञान नहीं किया जा सकता है। अनुबंध-II(iv) प्राधिकारी को आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद की तुलना में व्यापक उत्पाद समूह के उत्पादन के संबंध में सूचना पर विचार करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसमें समान उत्पाद भी शामिल हों। यह विभिन्न उत्पादकों की पृथक क्षति विश्लेषण को शामिल नहीं करता है।

**xxi.** यह दावा कि आर आई एल के पीटीए उत्पादनन का 66% उत्पादन ग्राही खपत के लिए होता है और यह आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, इससे पृथक विश्लेषण न्यायोचित नहीं बन जाता है। आर आई एल ने ग्राही उत्पादन को शामिल करते हुए और ग्राही उत्पादन को शामिल न करते हुए दोनों रूपों में सूचना प्रदान कर दी है।

**xxii.** इक तर्क के संबंध में कि पीएक्स, पीटीए डेल्टा में कमी होने के कारण एमसीपीआई को घाटा हुआ परंतु आर आई एल और आई औ सी को लाभ हुआ, यह कहा जा सकता है कि लाभ में गिरावट को भी क्षति माना जाता है।

**xxiii.** यह तर्क कि चूंकि घरेलू उद्योग को बाजार हिस्सा 80% से अधिक है, इसलिए कोरिया के उत्पाद भारत में बाजार कीमतों को अग्रसर नहीं कर सकते पिछले तर्क का खण्डन करता है जिसमें यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का अनुसरण किया गया है।

**xxiv.** यह तर्क कि आर आई एल और एम सी पी आई की संचयी उत्पादन लागत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे विश्लेषण विकृत हो जाएगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर समग्र रूप से विचार किया जाना है।

**xxv.** यह दावा कि एमसीपीआई को पीएक्स-पीटीए डेल्टा (पीटीए की कीमतों और पीएक्स की लागत के बीच अन्तर) 253-279 डालर/एमटी है, जो दर्शाता है कि एमसीपीआई, जब तक अपनी लागत में कटौती नहीं करता है तब तक वह, विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, तथ्यतः गलत है।

**xxvi.** यह दावा कि आर आई एल को पीएक्स प्रभाग में भारी लाभ हुआ परन्तु पीटीए प्रभाग में उसे घाटा हुआ, पिछले दावे का खण्डन करता है कि आरआईएल की लागत चून है और एमसीपीआई को क्षति हो रही है। प्राधिकारी को ग्राही इनपुटों पर विचार उनकी बाजार कीमतों के अनुरूप करना चाहिए।

**xxvii.** कुछ पैरामीटरों द्वारा क्षति न दर्शाए जाने के संबंध में, घरेलू उद्योग पर पाटन का विपरीत प्रभाव कीमत अधोरदन, कीमत नियन्त्रण/अवमंदन, माल सूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर अर्जन जैसे पैरामीटरों के संबंध में पड़ा है।

**xxviii.** मालसंचयी के संबंध में यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को, मांग-आपूर्ति में भारी अंतर के बाबजूद, बढ़ती मालसूची का सामना करना पड़ा।

**xxix.** इस तर्क के संबंध में कि आरआईएल और आईओसी ने पीटीए सुविधा का प्रचालन पूर्ण क्षमता के साथ किया परंतु एमसीपीआई अपने उत्पादन को सामान्य नहीं बना सकी क्योंकि उसके समक्ष तकनीकी समस्या थी, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में मात्रा क्षति का दावा नहीं किया गया है।

**xxx.** इस तर्क के संबंध में कि एससीपीआई ने अपने वास्तविक उत्पादन में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 100 % से अधिक वृद्धि की है। तथापि वर्तमान मामले में मात्रा क्षति का दावा नहीं किया गया है। उत्पाद में इतनी अधिक वृद्धि होने के बाबजूद घरेलू उद्योग के लाभ में प्रपाती गिरावट आई है।

**xxxi.** प्रतिवादी पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि आरआईएल और आईओसी ने जांच की अवधि में सर्वोत्तम क्षमता उपयोग प्राप्त किया है इसलिए तीनों उत्पादकों के क्षमता उपयोग का औसत निकालना भ्रामक है। किसी भी मामले में मात्रा क्षति का दावा नहीं किया गया है।

**xxxii.** प्रत्यक्षकार ने दावा किया है कि आरआईएल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्थीकार किया है कि पेट्रोकैमिकल सेक्टर को 11.2% और 8.2% का प्रचालन लाभ हुआ है जो कंपनी के व्यापक लाभ से काफी अधिक है। घरेलू उद्योग को क्षति का दावा संबंधित उत्पाद के लिए किया जाता है ना कि सेक्टर के लिए समग्र रूप से।

**xxxiii.** आरआईएल द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के संबंध में कंपनी ने कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड के अनुसार सूचना प्रदान कराई है।

**xxxiv.** प्रत्युत्तरदाता पक्षकार ने दावा किया है कि आईओसी की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि पेट्रोकैमिकल सेक्टर की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान घाटे से लाभ की ओर सुधार हुआ है और इसे यह लाभ इसलिए हुआ क्योंकि वह पीएक्स का उत्पादन और उसका उपयोग करता है। घरेलू उद्योग कि लिए क्षति का दावा संबद्ध उत्पाद के लिए किया जाता है, न कि समग्र सेक्टर के लिए। इसके अतिरिक्त, ऐसी क्षति घरेलू उद्योग के लिए देखा जाना अपेक्षित है और न कि आईओसीएल के लिए देखना।

**xxxv.** प्रत्युत्तरदाता पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि संबद्ध आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को यह क्षति आयातों द्वारा कारित कीमत अधोरदन कीमत निग्रहण/अवमंदन आदि के कारण हुई है।

**xxxvi.** निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी और सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रारम्भिक जांच परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध तथा पाटनरोधी शुल्क की जरूरत स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी निर्यातक ने सुनवाई के समय यह प्रस्तुत किया था प्रारम्भिक जांच परिणाम में निर्धारित पाटनमार्जिन और तद्वारा पाटन की स्वीकृति में कुछ छोटी-छोटी तथ्यात्मक त्रुटियाँ हैं।

**xxxvii.** क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के सम्बंध में विधि के अन्तर्गत कोई विधिक निर्धारण नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल परम्परा और प्रक्रिया के अनुरूप ही क्षति मार्जिन का निर्धारण पाटनरोधी शुल्क की ऐसी प्रमात्रा के रूप में निर्धारण करने के लिए, जो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, आयातों के उत्तराई मूल्य और गैर-क्षतिकारी कीमत के बीच अन्तर के रूप में करते हैं। प्रारम्भिक जांच परिणाम में निर्धारित क्षति मार्जिन बहुत कम है और यह दर्शाती है कि इस समय अपनाई गई क्रियपद्धति निम्नलिखित कारणों से उचित तुलना नहीं करती हैं।

**xxxviii.** प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग और विदेशी प्रदायकों के बीच क्रेडिट अवधि में अन्तर पर ध्यान नहीं दिया है। घरेलू उद्योग इस वस्तु की बिक्री अधिकांशतः घरेलू बाजार में ‘नकद प्रदाय’ के भुगतान की शर्त पर कर रहा है। इसके विपरीत विदेशी उत्पादक 180 दिनों तक का व्याज मुक्त ऋण देने की पेशकश कर रहे हैं। चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया ऋण और विदेशी उत्पादकों द्वारा पेशकश किया गया ऋण मिन्ह है, इसलिए गैर-क्षतिकारी कीमत की ऋण अवधि में अन्तर के लिए दोनों में से किसी का विधिवत समायोजन करने के पश्चात आयातों के उत्तराई मूल्य से किया जाना अपेक्षित है।

**xxxix.** घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना आयातों के उत्तराई मूल्य से करते समय घरेलू उद्योग की भाड़ा लागत की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भाड़ा लागत का समायोजन करना अपेक्षित है।

**xl.** चूंकि पीटीए संयंत्र पेट्रोरसायन संयंत्र होने के कारण, उच्च प्रचालन दरों पर चलना अपेक्षित होते हैं। उच्च प्रचालन दर कोई पसन्द नहीं होती है बल्कि व्यवसाय की मजबूरी होती है। उत्पादक के पास केवल एक ही विकल्प रहता है कि वह अपने उत्पाद का अधिकतम सीमा तक उत्पादन को और उत्पादक की बिक्री बाजार कीमतों पर करना। इसलिए, भारतीय संदर्भ में, जहाँ बाजार बहुत विशाल है। (आपूर्तियों की तुलना में मांग अधिक है), उत्पादकों को बाजार कीमतों का अनुसरण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इसके परिणामस्वरूप, पाटन का प्रभाव मात्रा के रूप में दृष्टिगोचर नहीं होगा बल्कि विपरीत कीमत प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है।

**xli.** भारतीय बाजार में कई देशों के निर्यातक इस सम्बद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वह घरेलू उद्योग को संचयी क्षति का आकलन संचयी रूप से करें।

**xlii.** ऐसी स्थिति में जहाँ आयात अनिवार्य हो, वहाँ विदेशी उत्पादकों के लिए कीमतों का निग्रहण करने का कोई कारण नहीं होता है। विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध अत्यधिक अनप्रयुक्त क्षमता उन्हें अपने उत्पाद की भारतीय बाजार में आक्रामक बिक्री करने को बाध्य कर रही है। किसी विदेशी उत्पादक या व्यापारी द्वारा अपनी कीमतों में कमी करने की स्थिति में या तो भारतीय उत्पादकों को आयात कीमतों में हुए परिवर्तनों के अनुरूप अपनी कीमतों में परिवर्तन करना होता है या व्यापारी की पुनर्विक्री के अनुरूप अपनी कीमतें निर्धारित करनी होती हैं अथवा याचिकार्ता के पास आड़े ही नहीं हो पाते हैं।

**xliii.** उपभोक्तागण दोनों स्रोतों—विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों द्वारा पेशकश की गई कीमतों की तुलना करते हैं और यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि आयातित उत्पाद की कीमतें सस्ती हैं तो उपभोक्तागण अपने आर्डर या तो विदेशी उत्पादकों को

देते हैं या घरेलू उद्योग से यह उम्मीद करते हैं कि वह अपनी कीमत कम करे। इसलिए कीमत अधोरदन का निर्धारण उपभोक्ताओं द्वारा दोनों कीमतों की तुलना करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति पर विवार करने के पश्चात किया जाना चाहिए।

**xliv.** एक याचिकाकर्ता नामशः एमसीसी पीटीए की उत्पादन सुविधा हल्दिया में अवस्थित है। तथापि, कम्पनी को अपने उत्पाद की बिक्री उन उपभोक्ताओं को करनी पड़ती है जो देश के पश्चिमी या उत्तरी भाग में हैं। चूँकि आयातक/उपभोक्तागण आयातित और घरेलू कीमतों की तुलनाला उनको आई लागत के आधार पर करते हैं, इसलिए एमसीसी को ऐसी कीमत की पेशकश करनी होती है जो उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाली कीमत आयातित उत्पाद की कीमतों से तुलनीय हो। इसलिए एमसीसी फैक्ट्री से उपभोक्ताओं तक भाड़ा लागत वहन करता है। अतः घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना आयातों की उत्तराई कीमत से उसमें घरेलू उद्योग के मामले में अन्तर्गत भाड़ा लागत जोड़कर करना चाहिए।

**xlv.** घरेलू उद्योग पर पहले से ही पहुँचायी जा रही वास्तविकक्षति के अलावा सम्बद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग को गम्भीर या वास्तविक क्षति की चुनौती भी उत्पन्न कर रहे हैं।

**xlvi.** घरेलू उद्योग को क्षति पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के बाद भी जारी रही क्योंकि पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा इतनी कम थी कि वह पाटन का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

**xlvii.** ग्राही खपत में लाभ/हानि, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी पवाह असंगत होते हैं और वे गुमराह करने वाले भी हो सकते हैं। ग्राही खपत में कीमत पैरामीटरों के रूप में क्षति का सुनिश्चयन करना और भी कठिन होता है। घरेलू उद्योग विभिन्न उत्पादों अलग-अलग रिकार्ड अनुरक्षित कर सकता है और नहीं भी रख सकता है।

**xlviii.** घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग पर कीमतों के विपरीत प्रभाव का दावा किया है। जहाँ तक सर्वोर्धितक्षमता के कारण उच्चनियत कीमत का संबंध है, एमसीपीआई ने अपनी क्षमता में वर्ष 2010–11 में वृद्धि की थी परन्तु घरेलू उद्योग को क्षति का दावा जांच की अवधि का है जो वर्ष 2012–13 है। इसलिए सर्वोर्धित नियत लागत का तर्क उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सर्वोर्धित क्षमता के परिणामस्वरूप उच्च नियत लागत पर विचार नहीं किया और सकारात्मक क्षति मार्जिन का निर्धारण कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि सर्वोर्धित क्षमता के कारण उच्च नियत लागत को पृथक किया जाता है तब भी घरेलू उद्योग को भारी क्षति मौजूद रहती है। एमसीपीआई को क्षमताओं में वृद्धि करने के बाद भी लाभ हुआ है। एमसीपीआई को तत्पश्चात लाभ में भारी गिरावट सहन करनी पड़ी और जांच की अवधि में उसे घाटा हुआ जिससे प्रत्यक्षतः यह स्पष्ट होता है कि एमसीपीआई को जो क्षति हुई है वह क्षमता सर्वधन के कारण नहीं हुई है।

**xlix.** यह तर्क कि चीन और ई यू के लिए क्षति मार्जिन 0–10% था और इसलिए यह सही नहीं है कि इन देशों से आयातों पर संस्तुत शुल्क समान रेंज में होना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माह-दर-माह आधार पर तुलना की है जब कि हितबद्ध पक्षकारों ने भारि औसत आधार पर तुलना की हैं।

**i.** पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद कर प्राधिकारियों को सूचित किए गए मूल्यांकन का सत्यापन करे और यह जांच करे कि क्या याचिकाकर्ताओं ने कम उत्पाद शुल्क प्रभारित किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत प्रचालन कर रहे हैं। उन्हें विशिष्ट दायित्व सौंपे गए हैं। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सौंपे गए दायित्वों से विपरीत होने को कोई कारण नहीं है।

**ii.** प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की सतत जांच की है। केवल ऐसी स्थिति में ही जब, क्षति अवधि के दौरान का वास्तविक निष्पादन घरेलू उद्योगों को क्षति प्रदर्शित नहीं करता है तभी प्राधिकारी विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के सम्बन्ध में सम्भावित स्थिति की जांच करेंगे। वास्तव में जांचकर्ता प्राधिकारी सम्पूर्ण विश्व में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की जांच करते हैं और उसके आधार ही अपना निर्णय लेते हैं।

**iii.** यह तथ्य पूर्णतया असंगत है कि वर्ष 2009–10 वैश्विक मंदी का काल था। किसी भी हाल में क्षति का दावा कीमत पैरामीटरों पर आधारित है अर्थात् कीमत आधोरदन या कीमत निग्रहण/अवमंदन, लाभ में कमी, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट। क्षति का दावा उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग गिरावट पर आधारित नहीं है। वर्ष 2009–10 में पिछले दो वर्षों की तुलना में आयातों में भारी वृद्धि हुई थी। यह तर्क दिया गया कि वर्ष 2009–10 में यह आयात मंदी के कारण अधिक थे, इसका आशय केवल यह है कि उसके पश्चात भी तो आयात उच्चतर बने रहे। यदि यह तर्क दिया जाता है कि वर्ष 2009–10 में आयात मंदी की स्थिति के कारण न्यूनतर रहे तो यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–10 में आयात विगत वर्ष की तुलना में अधिक हुए थे।

**liii.** विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह रिकार्ड कर सकते हैं कि आई ओ सी एल ने अपनी उत्पादन सुविधा को अस्थायी रूप से बंदकर दिया है और आर आई एल ने आपूर्ति में कमी कर दी है और इसकारण से घरेलू आपूर्ति कम हो गयी और अनुप्रवाही उद्योगों का उत्पादन बनाए रखने के लिए आयातों में वृद्धि हुई। यह नोट किया जा सकता है

कि याचिकाकर्ताओं ने लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह जैसे पैरामीटरों के सम्बंध में विपरीत कीमत प्रभाव का दावा करण से नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री पर विपरीत कीमत प्रभाव का दावा इस कारण से नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता अपने उत्पाद की बिक्री आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करके कर रहे थे और अपनी कीमते आयात कीमतों के समान करके कर रहे थे और इसलिए याचिकाकर्ता अपने उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम रहे।

iv. जहाँ तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का सम्बद्ध है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और उसकी बिक्री में भारी वृद्धि हुई है, यह नोट किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने यह दावा नहीं किया है कि आयातों ने घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद की बिक्री करने से निवारित कर रखा हैवास्तव में याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि उनके पास अपने उत्पादन की बिक्री करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। विगत में किए प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किया जा सकता है।

v. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा गलत है कि आयातों के कारण न्यून क्षमता उपयोग हुआ क्योंकि अन्य घरेलू उत्पादकों के संयंत्र 100 % से अधिक क्षमता से प्रचालन कर रहे हैं, यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी से क्षति का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है न कि अन्य घरेलू उत्पादकों पर। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने लाभ, नकदीप्रवाह, निवेश पर प्रतिलाभ आदि जैसे पैरामीटरों पर आयातों के विपरीत प्रभाव का दावा किया है।

vi. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा एमसीपीआई द्वारा क्षमताओं में वृद्धि किए जाने के कारण अनवरत बना रहा तथापि, अधिक उत्पादन करने और अधिक बिक्री करने के बाद भी लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में इतनी तेजी से कमी आई की एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि यह सभी पैरामीटर पहले वाली स्थिति के अनुरूप ही ऋणात्मक बने रहे।

vii. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्तराई मूल्य और बिक्री कीमत की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011–12 में कीमत अधोरदन जांच की अवधि में हुए कीमत अधोरदन की तुलना में कम होना चाहिए और इसलिए इस अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा क्षति सहन किए जाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन किए जाने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इतनी गिरावट आई कि वह घाटे में परिवर्तित हो गयी। पीएक्स और पीटीए में गिरते अन्तर से यह स्पष्ट होता है कि देश में इस उत्पाद का पाटन बढ़ रहा है, जिसमें जांच की अवधि के पश्चात और भी अधिक तीव्रता आ गयी। चूंकि हितबद्ध पक्षकार यह मानते हैं कि यह एक सामान्य अवधि थी, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाले लाभ के इस स्तर को लाभ के तर्कसंगत स्तर के रूप में मान्यता प्रदान करे। घरेलू उद्योग स्वतः ही आयातों के विपरीत नहीं है। घरेलू उद्योग पाटित कीमतों पर आयात के विरुद्ध है।

viii. जब हितबद्ध पक्षकार यह मानते हैं कि क्षति मार्जिन न्यून/नगण्य है, तो याचिकाकर्ता यह समझने और सराहने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी विता आपत्ति पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के विपरीत है। पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा क्षतिमार्जिन से अधिक नहीं है। उनके द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार ही यह क्षति मार्जिन न्यून या यहाँ तक कि नगण्य भी है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार कीमत अधोरदन की मौजूदगी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं।

ix. जब हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि कीमत अधोरदन, क्षति मार्जिन तथा गैर-क्षतिकारी कीमत और एनएसआर के बीच अन्तर न्यून/नगण्य है तो याचिकाकर्ता यह समझने और सराहने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी चिंता/ आपत्ति पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के विपरीत है। पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा क्षतिमार्जिन से अधिक नहीं है। इसके अपिरिक्त, यदि एनआईपी और एनएसआर तुलनीय हैं और अधोरदन न्यून है तो पुनः इसका आशय यह होता है कि उपभोक्ताओं की नजरों में पाटनरोधी शुल्क की मात्रा न्यून/नगण्य है। इन हालातों में, उपभोक्ताओं को पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने के विरुद्ध अपनी चिंता अभियक्त नहीं करनी चाहिए थी।

x. उपयोक्ता एसोसिएशन सहमत है कि आयात कीमत का ग्राही खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्षति विश्लेषण का उद्देश्य घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन करना होता है। यदि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पाटित आयातों का प्रभाव ग्राही खपत पर नहीं पड़ता है तो प्राधिकारी को यह मैकेनिकल अभ्यास करना अपेक्षित नहीं था। हितबद्ध को उसके लिए औचित्य स्थापित करना चाहिए।

xi. यह गलत मान लिया गया है कि आर आई एल द्वारा ग्राही रूप से उपयोग किया गया पीटीए पर आयात कीमतों का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। आर आई एल अपने उत्पाद प्रचालन आम्स लैंग्थ पर करता है और अन्तरण कीमतें वह बाजार कीमतें हैं जिस पर आर आई एल घरेलू बाजार में आपूर्ति करता है।

xii. घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों पर विचार करते हुए किया जाना अपेक्षित है। अनुबंध-III के बल गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए है। यह इंगित करना संगत है कि कई देश तो क्षति मार्जिन का भी निर्धारण नहीं करते हैं जबकि भारत के अलावा अन्य किसी भी देश में गैर-क्षतिकारी कीमत जैसी कोई विधि नहीं है। यह देश आर्थिक पैरामीटरों पर विचार घरेलू उद्योग के वित्तीय रिकार्डों के आधार पर करते हैं।

**lxiii.** विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आवेदक यद्यपि सीमा शुल्क के अध्यधीन नहीं है फिर भी वह संदर्भ कीमत के 5.583% की दर पर उसे प्रभारित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि चूँकि कीमतें यूएस डालर में हैं, इसलिए वे रूपये के प्रपाती अवमूल्यन का अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इससे पुनः यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई कीमत निर्धारण नीति आयात अनुरूपता तथा देश में इस उत्पाद के पाटनके कारण लाभ निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ के सम्बंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पर आधारित है। आयातः समता पर पहुँचने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उन विभिन्न लागतों व्ययों पर विचार किया जाता है जिन्हें उपभोक्ताओं द्वारा उस उत्पाद का आयात करने पर (खपत तक) उपगत किया जाता है और घरेलू उद्योग को आयातित उत्पादों के उपभोक्ताओं को खपत स्थल पर उत्तराई लागत को ध्यान में रखते हुए कीमतें निर्धारित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जहाँ तक रूपये के अवमूल्यन का प्रश्न है उपभोक्ता एसोसिएशन ने चुनिन्दा रूप से रूपये के अवमूल्यन और पीटीए की कीमतों पर इसके प्रभाव पर विचार किया है। उपभोक्ता उद्योग ने बड़ी आसानी से रूपये के अवमूल्यन के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर पड़े विपरीत प्रभाव और उपभोक्ताओं के स्वयं अपने उत्पादों पर उसके अनुकूल प्रभाव की अनन्देखी कर दी है। यह नहीं कहा जा सकता है कि रूपये के अवमूल्यन का केवल पीटीए की कीमतों पर ही प्रभाव पड़ा है और उसका पीटीए के उत्पादकों की उत्पादन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त इस अवमूल्यन से अनुप्रयाही उद्योग की काफी हद तक रक्षा हुई है। किसी भी हाल में निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह सुस्पष्ट प्रक्रिया है कि वह जांच की अवधि के दौरान प्रचलित विनियम दर और घरेलू उद्योग के वास्तविक रिकार्डों के आधार पर निर्धारण करते हैं। यह भी उल्लेख किया जाता है कि रूपये के इस कथित अवमूल्यन के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। जैसा कि इस अवधि के दौरान लाभ तथा निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट द्वारा स्पष्ट हो जाता है। इससे यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि यदि रूपये का अवमूल्यन नहीं हुआ होता तो घरेलू उद्योग को दावाकृत यह क्षति और भी अधि होती है। अतः घरेलू उद्योग को यह जावा कृत क्षति रूपये में अवमूल्यन होने के बावजूद हुई है।

**lxiv.** विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में 1550/- रूपये प्रति एमटी की वृद्धि कर दी है और वे उपयोक्ताओं की कीमत पर लाभ अर्जन करने का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने सितम्बर 2014 तक के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जो, लाभ की तो बात ही छोड़ दीजिए, घरेलू उद्योग को निरन्तर वित्तीय घाटा प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में, जांच की अवधि के पश्चात यह पाटन और भी अधिक हो गया जैसा कि पीएक्स और पीटीए की कीमतों के बीच अन्तर से देखा जा सकता है। घरेलू उद्योग की कीमत में इजाफा वास्तव में उस वृद्धि से कम है जो जांच की अवधि की स्थिति तक पहुँच जाने के लिए पर्याप्त नहीं है और वर्ष 2009–10, 2010–11 की स्थिति तक पहुँचने की बात ही छोड़ दें।

**lxv.** यह तर्क कि आर आई एल अपनी क्षमता में 100% विस्तार कर रहा है जिससे यह बल मिलता है कि पीटीए के व्यवसाय में अच्छी आमदनी हो रही है और यह कथन गलत है कि उत्तराई मूल्य में निरन्तर एवं पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है। याचिकार्कर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच परिणाम का उल्लेख करते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार इस उत्पाद के दीर्घावधिक आउटलुक कर विचार करते हुए किया जाता है। केवल इस तथ्य का कि इस समय बाजार को पाटन के कारण क्षति सहन करनी पड़ रही है, आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग के संघटक कोई नया निवेश करने से बचेंगे और वह भी ऐसी स्थिति में जब किदेश में इस उत्पाद के लिए मांग एवं आपूर्ति में भारी अन्तर है। आर आई एल ने वर्ष 2014–15 की तीसरी तिमाही और वर्ष 2015–16 की दूसरी तिमाही में मौजूदा क्षमता में विस्तार करने की योजना तब बनाई थी जब इस विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता काफी बेहतर थी। वास्तव में, इससे पुनः यह स्पष्ट होता है कि इस विचाराधीन उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना उन निवेशों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है जिसकी घरेलू उद्योग ने पहले ही योजना बना ली थी।

**lxvi.** उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार इस उत्पाद के दीर्घावधिक आउटलुक कर विचार करते हुए किया जाता है। केवल इस तथ्य का कि इस समय बाजार को पाटन के कारण क्षति सहन करनी पड़ रही है, आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग के संघटक कोई नया निवेश करने से बचेंगे और वह भी ऐसी स्थिति में जब किदेश में इस उत्पाद के लिए मांग एवं आपूर्ति में भारी अन्तर है। जहाँ तक आर आई एल द्वारा एकाधिकारकरण का सम्बंध है विरोधकर्ता पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से आर आई एल को एकाधिकार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, कोई साक्ष्य न तो प्रदर्शित किया है और न ही प्रदान कराया है। केवल समन्वित सुविधा रखने मात्र से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि एकाधिकार वादी स्थिति सृजित हो गयी है।

**lxvii.** यह तर्क निराधार है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से रिलायन्स की अधिपत्य वाली स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ होगी। आर आई एल 80 से अधिक उत्पादों का व्यवसाय करता है और उसके लगभग 24000 कर्मचारी हैं। इस कम्पनी ने अपने व्यवसाय को 4 भिन्न सेगमेंटों में विभाजित किया है जिनमें 40 भिन्न व्यवसाय से अधिक व्यवसाय हैं। इसके प्रचालनों के आकार पर विचार करते हुए विभिन्न व्यवसायों के स्पष्टतः परिभाषित उत्तरदायित्व हैं। इस उत्पाद का अन्तरण बाजार कीमतों से जुड़ी कीमतों पर एक व्यवसाय सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में अन्तरित किया जाता है। अतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के विपरीत, उपयोक्ताओं की पाटित आयातों तक पहुँच इन उपयोक्ताओं को अनुचित लाभ अर्जित करा रही है। यद्यपि आर आई एल के लिए पीटीए का मूल्य अनुप्रयाही उत्पादों के लिए उच्चतर था वहीं उपयोक्ताओं के लिए यह न्यूनतर था। अतः, विचाराधीन उत्पाद का पाटन न केवल आर आई एल की व्यापारी बाजार को क्षति कारित कर रहा था बल्कि अनुप्रयाही उत्पादों को भी क्षति हो रही थी। अधोलिखित तालिका वह कीमत प्रदर्शित करती है जिस पर आर आई एल ने अपनी ग्राही खपत को अन्तरित किया और व्यापारी बाजार में

पीटीए की बिक्री की। यह स्पष्ट है कि आर आई एल के अनुप्रवाही उत्पादों को भारत में पीटीए का पाटन होने के कारण भारी क्षति हुई।

**Ixviii.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि रिलायन्स ने बीपी कैमिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी (बीपीसीएम) में 100 % पण अवाप्त किया है और पीटीए का कच्चा माल जो मलेशिया भेजा गया वही पीटीए में सम्पर्वित कर दिया गया और उसी का भारत में पुनः आयात किया गया तथा उसकी बिक्री की गई यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से आयात नगण्य थे। चूँकि मलेशिया से आयात न्यूनतम है, इसलिए याचिकार्ता कम्पनियों में से किसी एक याचिकार्ता कम्पनी के मलेशिया के उत्पाद के साथ कोई सम्बंध होने को मुद्दा पूर्णतया असंगत हो जाता है। यह इगित करना भी संगत है कि आरआईएल द्वारा मलेशियाई कम्पनी को पीएक्स की बिक्री की गई और उस मलेशियाई कम्पनी ने भारतीय बाजार में पीटीए की बिक्री की। इससे किसी भी कम्पनी को कोई लाभ नहीं हुआ।

**Ixix.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्यात उपयोक्ता के क्षमता उपयोग में कमी आई हैं और पीटीए का प्रयोग करते हुए बने अन्तिम उत्पाद के आयातों में बढ़ोत्तरी हुई है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकार्ताओं ने इस पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए आवेदन पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों के साकारात्मक साक्षयों के आधार पर दायर किया है। जहाँ तक अनुप्रवाही उत्पादों के आयातों में वृद्धि होने का सम्बंध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण जुलाई 2014 में किया गया था, जब कि भारतीय बाजार में अनुप्रवाही उत्पादों के आयात काफी लम्बे समय से हो रहे थे। इसलिए, पीटीए के इन आयातों को पाटनरोधी शुल्क पर उपरोपित करना गलत है।

**Ixx.** प्रचालन क्षति पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति के अलावा और कुछ नहीं है। प्रचालन नकदी प्रवाह में कमी होना घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के कारण ही आई है। वास्तव में, नियमावली में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नकदी प्रवाह पर इन पाटित आयातों के वास्तविक एवं सम्भावित ऋणात्मक प्रभावों की जांच करे। हितबद्ध पक्षकार सहमत है कि घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह को क्षति हुई। विदेशी मुद्रा घाटा कच्चे माल के प्रदायकों को भुगतान किए गए धन के अलावा और कुछ नहीं है। यदि विनियम को दर में सुधार के कारण यह राशि उच्चतर होती तो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी उसी अनुपातिक सीमा तक उच्चतर होती। यह वह मामला नहीं है जहाँ घरेलू उद्योग ने पूर्व-निर्धारित कीमतों पर आर्डर लिए हों और फिर कच्चे माल की खरीद की हो और इस कच्चे माल पर अतिरिक्त लागत वहन की हो। यह वह मामला है जहाँ घरेलू उद्योग ने पहले कच्चे माल की खरीद की, उसके लिए अधिरोपण के समय प्रचलित और पहले डेबिट की गई राशि के बीच अन्तर का भुगतान विनियम उतार-चढ़व के रूप में किया और अपने उत्पाद की बिक्री उस दर पर की जो बिक्री के समय प्रचलित विनियम दर के अनुरूप थी।

**Ixxi.** घरेलू उद्योग इस तथ्य का विरोध नहीं करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वह क्षति कारित करने वाले अन्य कारकों की जांच करें। तथापि, यह दावे परिमाणात्मक सूचना पर आधारित होने चाहिए, न कि केवल अभिकथनों पर।

**Ixxii.** एमसीपीआई प्रविधि के सम्बंध में दिए गए तर्क पूर्णतया निराधार हैं। लाभप्रदता में गिरावट पाटन के कारण आई है, न कि किसी अन्य कारक के कारण। वास्तव में, यदि एमसीपीआई के क्षमता उपयोग पर तर्क संगत ढंग से विचार किया जाता है तो यह दर्शाएगा कि कम्पनी को भारी वित्तीय घाटा हुआ होगा। वास्तव में, याचिकार्ताओं द्वारा विगत में किए गए प्रस्तुतिकरणों के अनुसार, पीएक्स की उस कीमत पर विचार करते हुए, जो जांच की अवधि के दौरान से प्रचलित है, पीटीए का कोई भी उत्पादक यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री पर भारत में या वैश्विक रूप से कोई लाभार्जन हो रहा है।

**Ixxiii.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि क्षति के लिए पारिश्रमिक लागत में अनुपातिक वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकार्ताओं ने इस आधार पर होने वाली क्षति का दावा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली में विशेष रूप से ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति सभी पैरामीटरों में दृष्टिगत होनी चाहिए। जांच की अवधि के दौरान प्रति यूनिट परिश्रमिक लागत में कमी आई थी वहीं लाभप्रदता में प्रपाती गिरावट हुई थी, इससे यह स्पष्ट होता है कि जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में गिरावट उत्पादन की प्रति यूनिट परिश्रमिक लागत में वृद्धि होने के कारण हुई है।

**Ixxiv.** यह तर्क गलत है कि वर्ष 2010–11 में किए गए क्षमता विस्तार के कारण नियत लागत में वृद्धि हुई और लाभप्रदता में कमी आई। क्षमता में वृद्धि करने से वर्ष 2010–11 में लाभ में मामूली सी गिरावट आई थी। उसके पश्यात घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में प्रपाती गिरावट हुई और घरेलू उद्योग की क्षमता का समान स्तर रहने के बावजूद वित्तीय घाटा उठाना पड़ा। वास्तव में जांच की अवधि में, जहाँ क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई, वहीं क्षति में और अधिक प्रपाती गिरावट आ गई।

**Ixxv.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि एमसीपीआई द्वारा सामना की गई तकनीकी समस्या के कारण उन्हें घटी हुई निर्यात प्रतिबद्धता प्रदान की गई, यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन ने उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री करने से वंचित किया है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के विपरीत कीमत प्रभाव का दावा किया है।

**Ixxvi.** यह तर्क निराधार है कि आईओसीएल की कीमतें अन्य घरेलू उत्पादकों की कीमतों की तुलना में 4–10% कम हैं और आवेदकों को आई ओ सी एल की न्यूनतर कीमतों के कारण कीमत प्रभाव सहन करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि उपभोक्ता अपनी कीमतों की बेंचमार्किंग आई ओ सी एल द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतों के आधार पर करते हैं। वास्तव में अधिकांश उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन द्वारा किया जाता है और इसलिए यह एसोसिएशन इस बात के प्रति पूर्णतया: जागरूक होगी की उसके सदस्य भारतीय बाजार में पीटीए की खरीद कैसे कर रहे हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रमिक करने और वर्तमान जांच को अवरुद्ध करने का प्रयास करने के लिए पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन द्वारा किये गये यह एक अन्य गम्भीर प्रयास का उदाहरण है।

**Ixxvii.** प्रयोक्ता एसोसिएशन ने इसके साथ ही यह तर्क भी दिया कि घरेलू उद्योग की कीमतें आई ओ सी एल की कीमतों से प्रभावित हैं और उनकी बेंचमार्किंग सीएफआर चीन की कीमतों द्वारा की जाती है। इससे स्पष्टतः यह प्रदर्शित होता है कि एसोसिएशन द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयात आई ओ सी आई एस या प्लॉट्स द्वारा घोषित कीमतों के आसपास कीमतों पर होते हैं। पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन का यह तर्क नहीं है कि आयात उन कीमतों पर नहीं किए हैं जो आई ओ सी आई एस या प्लॉट्स द्वारा निर्धारित होती हैं। इस प्रकार आई ओ सी आई एस द्वारा रिपोर्ट की गई सी एफ आर चीन कीमतें या प्लॉट्स द्वारा रिपोर्ट की गई सी एफ आर चीन कीमतें और कुछ नहीं बल्कि वह कीमतें होती हैं जो आयात किए जाने के लिए निर्धारित की जाती हैं और उस अवधि में निर्धारित की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया आई ओ सी आई एस/प्लॉट्स में रिपोर्ट की गई कीमतों की तुलना उन कीमतों से करें जिन पर प्रतिवादी निर्यातकों ने भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया था।

**Ixxviii.** चूँकि पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन प्रयोक्ताओं के हितों को प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इस एसोसिएशन को कम से कम इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि इसके सदस्य घरेलू उद्योग के साथ अपनी कीमतों की बेंचमार्किंग इन प्लॉट्स अथवा आई ओ सी आई एस कीमतों पर क्यों करते हैं। इस तर्क में स्पष्टतः इन दो परिस्थितियों में से कोई स्थिति आशयित होती है – (क) प्रयोक्ताओं ने प्रयोक्ता एसोसिएशन को उस तथ्य से भी अवगत नहीं कराया है जिन तथ्यों प्रयोक्ता घरेलू और आयातित स्रोतों से इस सामग्री की खरीद कर रहे हैं। अथवा (ख) प्रयोक्ता एसोसिएशन इस तथ्य के प्रति जागरूक है परन्तु निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष विकृत तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास उन्हें भ्रमित करने और जांच की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने के लिए किया है। इससे यह भी स्पष्टतः प्रदर्शित होता है कि प्रयोक्ता एसोसिएशन ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को यथार्थ सूचना नहीं दी है। प्रयोक्ता एसोसिएशन यह स्वीकार करती है कि घरेलू उद्योग ने अपने कीमतों का निर्धारण आई ओ सी आई एस/प्लॉट्स में उल्लिखित कीमतों के आधार पर किया है। चूँकि उपभोक्ताओं द्वारा यह आयात इन कीमतों की आई ओ सी आई एस/प्लॉट्स में उल्लिखित कीमतों के रूप में विचार करते हुए कर रहे हैं; इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर उन कीमतों का प्रभाव है जिन पर भारत में आयात किए जा रहे हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमतों का निर्धारण आई ओ सी आई एस या प्लॉट्स में उल्लिखित कीमतों के आधार पर करते हुए कर रहे हैं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतों की तुलना कर सकते हैं। यदि उपभोक्तागण यह पाते हैं कि आई ओ सी आई एस प्लॉट्स में रिपोर्ट की गई कीमतें घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत की गई कीमतों से कम हैं तो उपभोक्ताओं को यह प्रयोक्ता एसोसिएशन कीमतों पर इस उत्पाद का आयात कर लें।

**Ixxix.** घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया गया कीमत निर्धारण तत्र आयात समानता पर आधारित है। आयात समानता पर पहुँचने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उन विभिन्न व्ययों/लागत पर विचार किया जाता है जो इस उत्पाद का आयात करने पर (खपत स्थल तक) उपभोक्ताओं द्वारा उपगत किया जाता है और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें मजबूरन आयातित उत्पाद के लिए खपत स्थल तक उपभोक्ता की उत्तराई कीमत को ध्यान में रखकर निर्धारित करना पड़ता है। यदि इस एसोसिएशन की चिंता यह है कि घरेलू उद्योग आयात कीमतों में सीमा शुल्क न जोड़ें और उसे अपने उत्पाद की विक्री सी आई एफ लागत कीमतों पर करनी चाहिए और घरेलू उद्योग सीमाशुल्क प्रभारित करके अतिरिक्त लाभ कमा रहा है, तो यह वास्तव में एक हास्यास्पद स्थिति होगी। यह देश में न केवल एक सुस्थापित व्यवसाय स्थिति है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों का निर्धारण आयात कीमतों तथा आधारभूत सीमाशुल्क पर विचार करते हुए करता है वर्हीं प्रयोक्ता एसोसिएशन यह नहीं कह सकता है कि उनकी कीमतों की बेंचमार्किंग सी आई एफ आयात कीमतों पर की जाती है। यह तर्क उस प्रयोजन को ही निष्क्रिय कर देता है जिस प्रयोजन से भारत सरकार और विश्व के अन्य देशों की सरकारें सीमा शुल्क का निर्धारण करती हैं तथा उस ढंग के विपरीत है जिस तरीके से व्यवसाय उद्योग इनका उपयोग करते हैं।

**Ixxx.** विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पी एक्स की कीमतों में वृद्धि हुई है, हालांकि नापथा की कीमतों में वृद्धि पीएक्स की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है। परन्तु नापथा की कीमतों में यह वृद्धि पीटीए की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप थी। तीन घरेलू उत्पादकों में से दो घरेलू उत्पादक नापथा से पी एक्स का उत्पादन करते हैं और इसका उपयोग पीटीए का उत्पादन करने के लिए करते हैं। इसलिए, वास्तविक उत्पादन लागत पर विचार पीएक्स की लागत को ध्यान में रख कर करना चाहिए न कि उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य नोशनल कीमत पर। गैर क्षतिकारी कीमत, लाभ/हानि और प्रतिलाभ, आदि पर। इन तर्कों के विपरीत याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल पीएक्स है। इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए नापथा कच्चा माल नहीं है। इस तरह का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कराया गया है कि पीटीए के उत्पादक अपनी कीमतों की बेंचमार्किंग न तो नापथा की कीमतों के अनुरूप करते हैं और न ही वैश्विक रूप से, नापथा की कीमतें पीटीए की कीमतों की बेंचमार्किंग करती हैं पीटीए की कीमतों की बेंचमार्किंग

पीएक्स की कीमतों के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, संगत विधिक अपेक्षा यह है कि क्या इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण होगा या यह उन कीमतों को बढ़ने से रोकेगा जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती। ऐसी स्थिति में जहाँ पीएक्स की कीमतों में संगत अवधि में वृद्धि हुई है, वहाँ प्रत्येक उत्पादक की तटस्थ प्रत्याशा यही होगी कि बिक्री कीमतों में वृद्धि की जाए।

**Ixxxii.** उपभोक्ता एसोसिएशन ने रूपये के अवमूल्यन और पीटीए की कीमतों पर इसके प्रभाव पर चुनिन्दा रूप से विचा किया है उपभोक्ता उद्योग ने बड़ी सुविधाजनक ढंग से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, उत्पाद की बिक्री कीमत और उत्पाद की आयात कीमत पर रूपये के अवमूल्यन के प्रभाव की अनदेखी की है। यह नहीं कहा जा सकता है कि रूपये के अवमूल्यन का पीटीए के आयात पर या पीटीए की कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ा। रूपये का अवमूल्यन हो या उन्नयन उसका कच्चे माल और परिष्कृत उत्पाद दोनों पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी हाल में, प्राधिकारी की यह एक सुस्थापित प्रक्रिया है कि वह निर्धारण की कार्रवाई जांच की अवधि के दौरान प्रचलित विनियम दर के आधार पर करते हैं। जैसा कि इस अवधि के दौरान लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट से स्पष्ट होता है।

**Ixxxiii.** विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मांग में मन्थर वृद्धि इस तथ्य के कारण आई है कि कतिपय प्रयोक्ताओं ने पुनर्चक्रीकृत सामग्री, जैसे पीईटी बोतलें, जो ताजे पीटीए का प्रतिस्थानी है, का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि विधिक अपेक्षा यह है कि क्या मांग में कोई संकुचन हुआ है और क्या विचाराधीन उत्पाद के खपत के प्रतिमान में कोई परिवर्तन हुआ है। खपत के प्रतिमान में परिवर्तन संगत है क्योंकि खपत के प्रतिमान में इस परिवर्तन से देश में इस उत्पाद की मांग में गिरावट आई हो, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग आदि में गिरावट आई हो। जहाँ तक इन अपेक्षाओं का सम्बंध है, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि इस उत्पाद के लिए देश में मांग के सकारात्मक वृद्धि हुई और इसलिए उस विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में संकुचन घरेलू उद्योग क्षति कारित करते के लिए उत्तरदायी कारकों में सक एक कारक नहीं है। इस विचाराधीन उत्पाद के सम्बंध में खपत के प्रतिमान में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बढ़ती मांग से स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है। अतः यह तथ्य कि पुनर्चक्रीकृत उत्पाद का प्रयोग बढ़ा है, इस मालमें पूरी तरह से सारहीन है।

**Ixxxiv.** विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस दावे के प्रभाव के रूप में कोई सूचना प्रदान नहीं किया है कि एमपीसीएल को विद्युत की खपत के कारण घाटा हो रहा है क्योंकि (i) कोयले की आपूर्ति के लिए कोई निश्चित संविदा नहीं की गई, (ii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उर्जाप्रणाली के लिए क्लीयरेंस की जरूरत में परिवर्तन होता रहा है। यह तर्क एक दूसरे के विरोधाभावी है। क्योंकि एसोसिएशन ने यह तर्क दिया है कि एमसीपीआई को (क) तकनीकी कारकों, (ख) पीएक्स की आपूर्ति, (ग)कोयले की आपूर्ति के कारण घाटा हुआ है। सर्वोपरि, हो सकता है कि इन सभी कारकों का कम्पनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा हो। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के पाठन के कारण घरेलू उद्योग के लाभ में भारी कटाव हुआ है।

**Ixxxv.** विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने त्रुटिपूर्ण ढंग से यह तर्क दिया है कि एमसीपीएल को अपने कच्चे माल का परिवहन करने के लिए भारी भाड़ा लागत व्यय करना पड़ता है। जहाँ तक घरेलू उद्योग को क्षति और उसके निर्धारण का सम्बंध है, घरेलू उद्योग के समग्र रूप से आंकड़े और एमसीपीआई के लिए प्रधक रूप से आंकड़े दोनों ही लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में प्रपाती गिरावट दर्शाते हैं। एमसीपीआई के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कम्पनी को पहले लाभार्जन हो रहा था और जांच की अवधि में उसको वित्तीय घाटा हुआ। समान अवस्थापनीय स्थिति में, यदि कम्पनी को पहले लाभ हो रहा था और अब घाटा हो रहा है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम्पनी के निष्पादन में यह गिरावट अवस्थापनात्मक स्थिति के कारण नहीं आई है बल्कि पाटित आयातों के कारण हुई है। जब एमसीपीआई के संयंत्र की संकल्पना की गई थी तो यह सुन्नात था कि यह संयंत्र उसी जगह पर होगा जहाँ यह अभी स्थित है। इस संयंत्र को काफी समय तक लाभार्जन हुआ था।

**Ixxxvi.** यह तर्क निराधार है कि यह याचिका आरआईएल द्वारा सुनियोजित क्षमता विस्तार से संरक्षण प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। यह याचिका जांच की अवधि अर्थात् 2012–2013 के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा इस आधार पर सहन की गई क्षति पर आधारित है कि भारी मात्रा में पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को क्षति जांच की अवधिमें सम्बद्ध देशों से उत्पाद के पाठन के कारण हुई है और उन्होंने अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क की संस्तुति की जिसका अधिरोपण वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। अतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया तर्क निराधार है।

**Ixxxvii.** यह तर्क गलत है कि आवेदकों ने अपनी कीमतों में वृद्धि उस भाड़े के आधार पर की है जिसका उन्होंने भुगतान नहीं किया है। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर उन कीमतों का प्रभाव है जिन पर आयात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, तथ्यों से स्पष्टतः यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को निरन्तर क्षति हो रही है। अतः वह कीमत जिस पर घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री कर रहा है, उस उत्पाद की उत्पादन लागत को वसूल करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

और घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा है। चूँकि यह कीमतें आयात कीमतों द्वारा प्रभावित होती हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं।

**Ixxxviii.** यह तर्क गलत एवं निराधार है कि घरेलू उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के पश्चात अपनी कीमतों में और अधिक वृद्धि कर दी है और वे घरेलू उपयोक्ताओं की लागत पर लाभार्जन करना चाहते हैं। घरेलू उद्योग को निरन्तर वित्तीय घाटा हो रहा है। इसप्रकार, वह कीमत, जिसपर घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री कर रहा है, उस उत्पाद की उत्पादन लागत को पुनः प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है और घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा है। चूँकि यह कीमतें आयात कीमतों से प्रभावित होती हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि आयातों से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है।

**Ixxxix.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि आई ओसी एल और आर आई एल जैसे घरेलू उत्पादक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर भारी लाभ अर्जित कर रहे हैं, याचिकार्कर्ता यह प्रस्तुतिकरण करते हैं कि उन उत्पादकों को छाड़कर जिनके पास अपनी निजी ग्राही पीएक्स हैं और जो पीएक्स का अन्तरण पीटीए की लागत से कम मूल्य पर कर रहे हैं, किसी भी वैशिक उत्पादक को लाभ का अर्जन नहीं हो रहा है किर भी कम्पनी को अपने लाभ में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है और यह घाटा भी नियमावली के अन्तर्गत क्षति के बराबर ही है। जहाँ तक आई ओ सी का सम्बंध है, चूँकि यह कम्पनी “घरेलू उद्योग” का भाग नहीं है, इसलिए यह मुद्दा पूरी तरह से असंगत है। यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि आई ओ सी के लाभ में कमी नहीं आई है आर आई एल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बड़े सुरक्षित ढंग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आई ओ सी के लाभ में भी गिरावट आई है।

**XC.** विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से आर आई एल को अपनी पीटीए की कीमतों में बढ़ोत्तरी करने की अनुमति मिल जाएगी और इससे पालिएस्टर बाजार में प्रतिस्पर्धा का हनन होगा क्योंकि पालिएस्टर के अन्य उत्पादक पीटीए की उच्च कीमतों के कारण आर आई एल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। याचिकार्कर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि जाँच की अवधि में एमसीपीआई की व्यापारिक बिक्री आर आई एल की व्यापारिक बिक्री से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, कई ऐसे मामले हैं जहाँ पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया और जहाँ उत्पाद का उत्पादन भारत में केवल एक कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। ऐसा मामला होने पर, केवल यह तथ्य कि किसी एक कम्पनी का उत्पादन अधिक है, उस कम्पनी को संरक्षण प्राप्त करके की मांग करने निवारित नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक इस तथ्य का सम्बंध है कि आर आई एल इस उत्पाद तथा अनुप्रवाही उत्पाद दोनों ही उत्पादों का उत्पादन कर रहा है, परन्तु इससे स्थिति में किसी तरह का कोई अन्तर नहीं पड़ता है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, आर आई एल को इस समय अपने अनुप्रवाही उत्पादों में घाटा हो रहा है, क्योंकि भारत में उनके प्रतिस्पार्धियों की अनुचित रूप से कीमत निर्धारित पाटित आयातों तक पहुँच है।

**XCI.** पाटनरोधी शुल्क का महत्व और प्रयोजन पाटन को रोकना तथा समान अवसर प्रदान करना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल सृजित करना होता है। पीटीए के घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। यदि पीटीए उद्योग के से न्यून उपयोगिता अनुपात और प्रपाती कीमत प्रतिस्पर्धा का सामना करने की उम्मीद की जाती है तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि घरेलू उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराए जाए।

**XCII.** यह तर्क गलत है कि जाँच की शुरूआत के पश्चात आयातों में वृद्धि तकनीकी खराबी के कारण बाजार में मांग को पूरा करने में घरेलू उत्पादकों की असफलता के कारण हुई है। पीटीए और पीएक्स के बीच कीमत अन्तर में जाँच की अवधि के पश्चात कमी आई जिससे पाटन में तीव्रता आई। इस तर्क के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि मांग को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि जरूरत थी तो भी विदेशी उत्पादकों के समक्ष यह विवशता तो नहीं रही होगी कि पाटन में वृद्धि कर दी जाए।

**XCIII.** यह तर्क निराधार है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण सभी प्रमुख निर्यातक देशों के विरुद्ध आरआईएल का एकाधिकार नियंत्रण और आरआईएल की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन के सकारात्मक साक्ष्य और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने एक और तो यह उल्लेख किया है कि मलेशिया को शामिल नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर यह उल्लेख किया गया कि सभी प्रमुख निर्यातक देशों को शामिल किया गया है। स्पष्टतः, हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क अत्यधिक पक्षपातपूर्ण है। किसी भी हाल में, शुल्क का अधिरोपण केवल तभी किया जा सकता है जब उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा हो।

**XCIV.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि भारतीय उत्पादकों के समान ही कोरियाई उत्पादक भी अपनी कीमतों का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर करते हैं और कोई कीमत अधोरदन नहीं हुआ है, याचिकार्कर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि पाटन का निर्धारण करने के लिए यह पूर्णतया असंगत है कि निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किए गए हों। केवल सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत ही संगत है। सामान्य मूल्य को नियमावली के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है और तदनुसार ही उसका निर्धारण होना होता है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने ग्राम्यकारी जाँच परिणाम में सकारात्मक कीमत अधोरदन का निर्धारण किया है। नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह निर्धारित करें कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं, अथवा, क्या आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का बाजार में नियमावली/आवंटन कर रहे हैं। अतः, ऐसी स्थिति में जहाँ घरेलू उद्योग की कीमतें भी आयात कीमतों के समान ही हैं, वहाँ यह नियमावली/आवंटन कीमत नियमावली/आवंटन प्रभाव हुआ है।

**xcv.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि आर आई एल और आई ओ सी एल को भारी स्तर तक लाभ हुआ है, याचिकार्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि संगत विधिक अपेक्षा यह है कि क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना है या कीमत में वृद्धि होने को रोकना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती। ऐसी स्थिति में जहाँ पीएक्स की कीमतों में संगत अवधि के दौरान वृद्धि हो रही है, वहाँ हरेक उत्पादक की स्वाभाविक प्रत्याशा यही होती है कि अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की जाए। तथापि, घरेलू उद्योग कीमत निग्रहण के परिणामस्वरूप अपनी कीमत में उस अनुपात में वृद्धि नहीं कर सका जिस अनुपात में उसकी लागत में वृद्धि हुई थी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उसकी लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अनुपात में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में पीएक्स के कारण लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अनुपात में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ।

**xcvi.** हितबद्ध पक्षकारों ने दो तर्क दिये हैं यह कि जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क स्वयं ही यह दर्शाते हैं कि (क) घरेलू उद्योग द्वारा इस समय सहन किया गया कीमत अधोरदन और कीमत निग्रहण पाटन के कारण हुआ है, (ख) यद्यपि घरेलू उद्योग को इससे पहले लाभ हो रहा था तथापि जांच की अवधि में इसको भारी घाटा हो रहा था जो देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण ही हुआ है।

**xcvii.** घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन की बिक्री करने से नियारित किया है और उसके उत्पादन को क्षति हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने एक ऐसे तर्क का अनुमान लगाया जिसे घरेलू उद्योग ने किया ही नहीं था। घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के विपरीत कीमत प्रभाव का दावा किया है। घरेलू उद्योग उसके द्वारा उत्पादित किए गए सभी उत्पाद की बिक्री तब तक करने में सक्षम था जब तक उसके द्वारा प्रस्तुत कीमतों आयातों की उत्तराई कीमतों से तुलनीय रहीं। अतः घरेलू उद्योग पर पाटन का विपरीत प्रभाव कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण/अवमंदन, मालसूची, लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों के सम्बंध में पड़ा है।

**xcviii.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि आर आई एल ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में पेट्रो रसायन सैक्टर में प्रचालन लाभ स्वीकार किया है और आर आई एल को पीटीए के आयातों से क्षति नहीं हुई है, याचिकार्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई आधार नहीं है कि यह मुख्यतः इसलिए हुआ है कि आर आई एल ने उत्पादन लागत का आन्तरिक अन्तर्राक्षरण कीमत का प्रयोग किया है। इसलिए इन परिकलनों से यह प्रदर्शित हुआ है कि आर आई एल के पीएक्स संयंत्र को पीटीए के अन्य उत्पादकों को बिक्री करके तथा इसकी अपने पीटीए संयंत्र को बिक्री से लाभ हुआ और आर आई एल के पीटीए संयंत्र को पालिएस्टर के अन्य उत्पादकों को की गई बिक्री पर घाटा हुआ है। यह परिकलन भ्रामक हैं और वास्तव में यह परिकलन भारतीय जीएपी के अनुसार किया जाना चाहिए था। घरेलू उद्योग को सम्बद्ध उत्पाद के लिए क्षति का दावा किया गया है, न कि इस सैक्टर को समग्र रूप से। यद्यपि आर आई एल को अपने अनुप्रवाही उत्पादों में पीटीए का मूल्य उच्च था, वहीं उपभोक्ताओं के लिए यह न्यूनतर था। अतः, इस विचाराधीन उत्पाद का पाटन न केवल आर आई एल की व्यापारिक बाजार को क्षति करित कर रहा है, बल्कि इसके अनुप्रवाही उत्पादों को भी क्षति हो रही हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम्पनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों के आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त, आर आई एल ने यह दावा नहीं किया है कि उसे घाटा हुआ है आर आई एल से सम्बंधित आंकड़े देखे जा सकते हैं।

**xcix.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि एमसीपीआई को हुए घाटे का मुख्य कारण उत्पादन की मात्रा कम होना है यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमसीपीआई को होने वाले घाटे के लिए उत्पादन की अल्प मात्रा ही एक कारण नहीं है, जैसा कि उत्पादन में वृद्धि तथा लाभ में गिरावट से सिद्ध होता है। कम्पनी को कम उत्पादन पर लाभ हुआ और अधिक उत्पादन करने पर घाटा हुआ।

**C.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि चूंकि क्रूड आयल, नापथा, पीएक्स और पीटीए की बाजार कीमतों का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर की जाती है इसलिए वैशिक अर्थव्यवस्था और मांग/आपूर्ति की स्थिति इस कीमत में हुए उच्चावचन के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक हैं, यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि वर्तमान जांच पीटीए के आयातों के विरुद्ध शुरुकी गई है और पैराक्सीलीन जो पीटीए की प्रमुख कच्चामाल है, की कीमत और सम्बंधित उत्पाद ही संगत और निर्धारक कारक है। क्रूड आयल तथा नापथा की बाजार कीमतों इस जांच से संगत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, पाटन के लिए कारण वर्तमान प्रयोजन हेतु संगत नहीं हैं। केवल पाटन का तथ्य ही संगत है। निर्दिष्ट प्राधिकारी पेट्रोरसायन उद्योगों के सम्बंध में जांच नहीं कर रहे हैं।

**ci.** यह तर्क कि पीटीए की कीमतों का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर किया जाता है जिसकी घोषणा दैनिक या साप्ताहिक रूप से की जाती है, पाटन का निर्धारण करने के लिए पूरी तरह से असंगत है। केवल सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत ही संगत है। सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमानुसार किया जाता है और तदनुसार ही उसका निर्धारण किया जाना है। केवल इस तथ्य का आशय “पाटन न होना” नहीं हो जाता है कि निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किए गए हैं।

**cii.** आर आई एल की बिक्री मात्रा प्राधान्य की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेती है। वास्तव में एमसीपीआई की बिक्री मात्रा आर आई एल की बिक्री मात्रा से अधिक है। इसके अतिरिक्त, सभी पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतों आयात कीमतों से जुड़ी होती हैं। किसी भी पक्षकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि एमसीपीआई की कीमतें आर आई एल की कीमतों से जुड़ी हैं। यह तर्क भ्रामक है और तथ्यतः गलत है।

**Ciii.** पीटीए के आयातों में प्रारम्भिक जांच परिणाम के पश्चात भारी वृद्धि हुई है। जांच की शुरुआत के पश्चात पाटन में तीव्रता आई है। कम कीमतों पर भारी आयात के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादों की मांग में कमी आई और मालसूची का संचयन हुआ।

**Civ.** जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ उसकी लाभप्रदता में वृद्धि हुई है इसलिए कोई कारणात्मक सम्बंध स्थापित नहीं हो पाया है, याचिकार्ता यह प्रस्तुतिकरण करते हैं कि यह गलत है। आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि जैसे आयातों में वृद्धि हुई वैसे-वैसे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई।

**CV.** यह तर्क गलत है कि एमसीपीएल को पीएक्स के अभाव के कारण घाटा हो रहा है। एसोसिएशन ने एक रथान पर यह तर्क दिया है कि एमसीपीआई तकनीकी समस्या के कारण अपना उत्पादन नहीं कर सका, वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि एमसीपीआई को पीएक्स के कारण घाटा हो रहा है। एसोसिएशन ने सभी तरह के भ्रामक और विरोधाभाषी अभिकथन किए हैं। एमसीपीआई को पीएक्स के अभाव के कारण घाटा नहीं हो रहा है। यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि कच्चे माल की उपलब्धता घरेलू उद्योग को क्षति का कारण कैसेबन गई। वास्तव में कच्चे माल की उपलब्धता का उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ना चाहिए था। याचिकार्ता ने यह दावा नहीं किया है कि इस विचाराधीन उत्पादन के पाटन से घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन और उसकी बिक्री करने से किस तरह निवारित किया गया।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

49. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में जांच की कार्रवाई के दौरान घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए प्रस्तुतिकरणों की जांच एवं उनका समाधान निम्नलिखित किया गया है :

(क) जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि आईओसीएल, जिसने इस याचिका का समर्थन नहीं किया है, की कीमतें अन्य घरेलू उत्पादकों की कीमतों की तुलना में 4-10 प्रतिशत कम हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईओसीएल ने वर्तमान जांच में आवेदकों का न तो समर्थन किया है और न ही उसका विरोध किया है और इसलिए उसे पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है। वर्तमान जांच में आवेदक घरेलू उत्पादक अर्थात् एमसीपीआई और आरआईएल पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं। इसलिए, पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी को केवल घरेलू उद्योग के संबंध में जांच करना और क्षति निर्धारित करना अपेक्षित है।

(ख) जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि आर आई एल द्वारा अपनी पीटीए की क्षमता में विस्तार करना उसकी खुशहाल और लाभप्रद रिथित की परिचायक है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन क्षमता में विस्तार करने का निर्णय सामान्यतः बाजार में संभावित मांग की प्रत्याशा द्वारा शासित होता है। इसलिए व्यवसाय के ऐसे निर्णयों को उद्योग को होने वाली क्षति के आभाव के संकेत के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

(ग) जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि आर आई एल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर को 11.2 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत का प्रचालन लाभ हुआ जो कम्पनी के व्यापक लाभ की तुलना में बहुत अधिक था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण सम्बंधित उत्पाद के लिए किया जाना अपेक्षित होता है न कि सम्पूर्ण सेक्टर के लिए समग्र रूप से। आर आई एल एक बहु-उत्पाद कम्पनी होने के कारण कम्पनी का समग्र रूप से निष्पादन कम्पनी द्वारा एक उत्पाद में सहन की जा रही क्षति की संकेत नहीं हो सकती है।

(घ) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीएक्स-पीटीए डेल्टा में कमी होने के कारण एमसीपीआई को घाटा हुआ, परंतु आरआईएल और आईओसी को लाभ हुआ, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादित संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत भिन्न हो सकती हैं, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि एमसीपीआई को इस घाटा के लिए पीएक्स के स्तर से संबद्ध वस्तु का विनिर्णय करना ही क्षति का एक मात्र कारण है। इसके अतिरिक्त, आरआईएल को भी संबद्ध वस्तु में कम लाभ का सामना करना पड़ा है।

(ङ) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि आरआईएल पीएक्स उत्पादन को पृथक लाभ केंद्र के रूप में मानता है और पीएक्स की लागत को लागत प्लस और बाजार कीमतों के आधार पर पीटीए को अंतरित कर देता है जिससे पीटीए की वास्तविक लागत बढ़ जाती है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III और डीजीएडी में संगत परम्परा के अनुसार किया है।

(च) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि डीजीएडी द्वारा घरेलू उद्योग को तब संरक्षण नहीं प्रदान करना चाहिए जब केवल एक घरेलू उत्पादक (एमसीपीएल) की क्षमता उपयोग की दर कम हो और वह भी अपने क्षमता विस्तार और अपनी उत्पादन सुविधा की समस्या के कारण, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच में क्षति का विश्लेषण घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से किया जाना अपेक्षित होता है न कि किसी व्यक्तिगत घरेलू उत्पादक के लिए। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में क्षति की समस्या लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर प्रतिलाभ आदि पर आयातों के विपरीत प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई है। जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि एमसीपीआई को अपने संयंत्र में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो क्षति का वास्तविक कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक तथ्य है कि एमसीपीआई को अपने संयंत्र में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा है, परंतु उसे ही क्षति का एकमात्र कारक नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते समय इन कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखा गया।

(छ) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न कारकों में सम्भावित क्षति को सिद्ध नहीं किया है। इस सम्बंध में, यह नोट किया जाता है कि एसा केवल एकमात्र ऐसी रिथित में ही होता है जहाँ क्षति अवधि के दौरान वास्तविक निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति नहीं दर्शाता है, प्राधिकारी को विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के सम्बंध में सम्भावित स्थिति की जांच करना अपेक्षित है।

(ज) यह आरोप लगाया गया कि वर्ष 2009–10 वैश्विक मंदी का समय था और उसे आधार वर्ष मानकर किया गया कोई भी विश्लेषण अयथार्थ होगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति मुख्यतः कीमत पैरामीटरों पर आधारित है और इसलिए वैश्विक मंदी का आरोपित प्रभाव पूर्णतया असंगत है।

(झ) जहाँ तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि एमसीपीआई ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखे एक पत्र में उत्पादन की तकनीकी समस्या के बारे में दावा किया है और उसने घटे हुए निर्यात दायित्व का लाभ उठाने का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक तथ्य है कि एमसीपीआई को अपने संयंत्र में तकनीकी समस्या हुई थी, परन्तु केवल उसे ही क्षति के रूप में निर्विचित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एमसीपीआई ने यह दावा किया है कि लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर प्रतिलाभ आदि जैसे पैरामीटरों पर आयात का विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते समय इन कारोंके प्रभाव को ध्यान में रखा गया है।

(ञ) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि एमसीपीआई को उसके संयंत्र में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा था जो कि क्षति का वास्तविक कारण है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह एक तथ्य है कि एमसीपीआई को अपने संयंत्र में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा था परन्तु उसे ही क्षति के एकमात्र कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने सम्बंध देशों से आयातों के विपरीत कीमत प्रभाव का दावा किया है न कि मात्रा प्रभाव का।

(ट) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि पीटीए के घरेलू उत्पादकों द्वारा कीमतों का निर्धारण संदर्भ कीमत के आधार पर किया गया है जो आई सी आई एस द्वारा रिपोर्ट की गई सीएफआर/सीएमपी कीमतों पर और पीएलएटीटीएक द्वारा रिपोर्ट किए गए सीएफआर चीन कीमतों हैं और उनका आयातों से कोई संबंध नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे स्रोतों द्वारा घोषित की गई कीमतें घरेलू बिक्री कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उत्पादकों हेतु बेंचमार्क कीमत के रूप में कार्य तो कर सकती हैं। तथापि, पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत, क्षति एवं कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए संबंद्ध देशों से वास्तविक अवसारित कीमत संगत होती है, जिसकी घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से तुलना करने पर, वह क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए आधार बनती है।

(ठ) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के विपरीत एमपीसीएल को पीएक्स की कमी के कारण घाटा सहन करना पड़ रहा है और इसलिए पीएक्स के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत, लाभ/हानि और प्रतिलाभ का निर्धारण करने के लिए उत्पादन की वास्तविक लागत नापथा के स्तर से ली जानी चाहिए, न कि किसी अनुमानिक लागत से ली जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति कीमत प्रभाव के कारण नहीं है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा संबंद्ध वस्तु के उत्पादन पर प्रभाव के डालने वाले किसी कच्चे माल का अभाव संगत नहीं है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि संबंद्ध वस्तु के लिए पीएक्स प्रमुख कच्चा मान है, न कि नापथा।

(ड) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि एमसीपीआई को उसी वर्ष से घाटा होना प्रारम्भ हो गया जिस वर्ष से उसने अपनी क्षमताओं में विस्तार किया था और उसका यह कार्य घाटे में परिणत हो गया, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एमसीपीआई ने अपनी क्षमता का विस्तार वर्ष 2010–11 में किया था और यह वह वर्ष था जब उद्योग को लाभ हुआ है। इसलिए, यह तर्क तथ्यतः गलत है।

(ढ) जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि मौजूदा मुद्रा विनिमय दर 62.88 है और यदि 54 के बजाय प्रचलित विनिमय दर पर विचार किया जाता है तो कीमत अधोरदन और कीमत अधेविक्रयण के स्तर का उपशमन हो जाएगा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जॉच में जॉच की अवधि के दौरान प्रचलित विनिमय दर ही संगत होती है, न कि मौजूदा विनिमय दर।

(ण) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि प्रत्येक घरेलू उत्पादक के लिए पृथक क्षति विश्लेषण अपेक्षित होता है क्योंकि उनकी उत्पादन प्रक्रिया भिन्न होती है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अनुसार क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से करना होता है।

(त) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि आर आई एल के पीटीए उत्पादन के 66 प्रतिशत की खपत ग्राही रूप से होती है और वह आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण केवल घरेलू बिक्रीयों के लिए किया गया है। उपर्युक्त को देखते हुए व्यापारी और ग्राही आपूर्ति के लिए प्रथक-प्रथक क्षति विश्लेषण की जरूरत, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है, नहीं पड़ती है।

(थ) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि कीमत और लागत में व्यापक उतार-चढ़ाव के कारण सभी आर्थिक पैरामीटरों (कीमतों अधोरदन, अधेविक्रयण, निग्रहण और अवमंदन सहित) जांच मासिक आधार पर की जानी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण मासिक आधार पर किया गया है।

(द) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि आर आई एल और एमसीपीआई की लागत में भारी अन्तर है और उत्पादन लागत का साधारण संचयन विश्लेषण को विकृत कर देगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति का विश्लेषण समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए किया जाना अपेक्षित होता है न कि विखिण्डत ढंग से।

(ध) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि पीटीए की बिक्री कीमत पर दबाव पी एक्स की कम आपूर्ति होने और पीटीए की अधिक आपूर्ति होने के कारण है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आयातों के मात्रा प्रभाव के कारण क्षति का दावा नहीं किया है। इसलिए, प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति का अभाव और सम्बद्ध वस्तु की अधिक आपूर्ति करके घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन पर प्रभाव डालने का तर्क संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त यह तर्क कि भारत में पीटीए की अधिक आपूर्ति हो रह है तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि भारत में मांग-आपूर्ति की तुलना में अधिक है।

(न) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि आरआईएल का यह दावा कि उसे पीटीए की घरेलू बिक्री से प्रचालन घाटा पीएक्स की आन्तरिक अन्तरा-कम्पनी अंतरण कीमत के कारण हुआ है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना का सत्यापन किया गया है और उस पर घरेलू उद्योग के अन्य संघटकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित आंकड़ों/सूचना के साथ भरोसा किया गया है।

(प) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि डीजीएडी ने नियोजित पूँजी पर 22% प्रतिलाभ की अनुमति दी है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियोजित पूँजी पर 22% प्रतिलाभ प्रदान करना डीजीएडी की संगत प्रक्रिया के अनुरूप है।

(फ) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि जब वर्ष 2010-11 में आयात बढ़कर चरम पर पहुँच गए थे, तब आवेदक को अधिकतम लाभ हुआ था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए ऋणात्मक कीमत अधोरदन का आकलन किया है और जाँच की अवधि कि लिए इसकी रेंज 0-10% है। इसलिए, आवेदक घरेलू उत्पाद को वर्ष 2011-12 के दौरान कोई घाटा उपगत होने का कोई कारण ही नहीं था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अन्तिम जाँच परिणाम में किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः स्पष्ट है। सत्यापित सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग को जाँच की अवधि के दौरान घाटा हुआ और कीमत अधोविक्रयण सकारात्मक है।

(ब) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए लाभ, नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह का निर्धारण असाधारण व्ययों एवं लागत का अपवर्जन करके तथा सर्वोत्तम उपयोगिता तरीका अपनाकर करना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोध नियमावली के अनुबंध-III और डीजीएडी की संगत प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है।

(भ) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-7-13 के दौरान पीएक्स की कीमतों में भारी वृद्धि हुई जब कि नापथा की कीमतों में उसी दर पर वृद्धि नहीं हुई जिस दर पर वृद्धि पीएक्स की कीमतों में हुई थी। तथापि, नापथा की कीमतों में वृद्धि पीटीए की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप थी। इसलिए आरआईएल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान लगाई गई पूँजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ और क्षति होने की बात नहीं कह सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तथ्य कि पैराक्सीलीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतों में वृद्धि नापथा की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण उनकी लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में या उससे भी अधिक वृद्धि कर दी, वर्तमान जाँच के लिए पूर्णतया असार है क्योंकि सम्बद्ध वस्तु पीटीए है न कि नापथा या पीएक्स।

(म) जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि एमसीपीएल की कोयले की आपूर्ति के लिए कोई ठोस संविदा नहीं है, जिसका उसकी उत्पादन लागत पर विपरीत प्रभाव पड़ा, और उसे क्षतिहुई, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने अपने उपर्युक्त दावे के समर्थन में कोई साक्षात्कृत सूचना प्रदान नहीं कराई है। एमसीपीआई ने दावा किया है कि आयातों को विपरीत प्रभाव लाभ, नकदी प्रवाह, निवेश पर प्रतिलाभ आदि जैसे पैरामिटरों पर पड़ा है।

(य) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एमसीपीएल ने अपने संयंत्र की स्थापना प्रयोक्ताओं से अत्यधिक दूर के एक स्थान पर की है और सम्बद्ध वस्तु पर उसके द्वारा व्यय की जा रही परिवहन लागत ने उसे अप्रतिपर्धी बना दिया है। इसलिए, भाड़े की जाँच क्षति के एक कारक के रूप में की जानी चाहिए और इस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने विश्लेषण करते समय विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसी जगह संयंत्र रहते हुए कम्पनी को पहले लाभ हो रहा था और जाँच की अवधि में उसे वित्तीय घाटा होने लगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को उसी रूप में देखा जाना चाहिए जिस रूप में वह मौजूद है, न कि आदर्श स्थिति के रूप में।

(कक) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मांग में वृद्धि होने के बावजूद भी स्थिर बना रहा। मांग में घरेलू उद्योग के स्थिर बाजार हिस्से और सम्बद्ध देशों से आयात के बीच में कोई सम्बंध नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पक्षपातहीन व्यापार के लिए पात्र बनने हेतु सम्पूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अधिदेशित नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग इस बढ़ी हुई मांग को पूरा के लिए अपनी क्षमता में विस्तार कर रहा है।

(ख्ख) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एमसीपीएल ने पीएक्स (कच्चे माल) का अधिग्रापण एक सम्बद्ध पक्षकार से अत्यधिक उच्च कीमतों पर किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को एमपीसलएल द्वारा दर्शाई गयी इन कीमतों को नामंजूर कर देना चाहिए और एनआईपी की संरचना करने के लिए उस न्यून कीमत को अपनाना चाहिए जिस पर निर्यातक अधिग्रापण करते हैं प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-III तथा डीजीएडी की संगत प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है।

(गग) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि गैर-क्षतिकारी कीमत की संगणना करने के लिए आवेदकों द्वारा अनुरोध की गई क्रेडिट लागत और भाड़ा लागत से सम्बंधित समायोजनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में दिए गए हैं। और वर्तमान जाँच में गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए उनका ही अनुसरण किया गया है।

(घघ) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि आवेदकगण, यद्यपि वे सीमाशुल्क के अध्यधीन नहीं हैं फिर भी वे घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री करते समय ग्राहकों से 5.583 प्रतिशत प्रभारित करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा अपनाया जाने वाला यह कीमत निर्धारण तंत्र आयात सममुल्यता पर आधारित है।

(डड) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि पीटीए चिप्स के कुछ प्रयोक्ताओं ने पाली इथायलीन टैरेफ्थालेट (पीईटी) बाटल्स जैसे पुनर्चक्रित सामग्री का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है, जो ताजे पीटीए का एक स्थानापन्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तर्क निराधार है क्योंकि संबद्ध वस्तु के लिए मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है।

(चच) घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा दिया जा रहा क्रेडिट अलग-अलग है, इसलिए गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना आयातों के उत्तराई मूल्य से, क्रेडिट अवधि में अन्तर का उपर्युक्त ढंग से समायोजन करने के पश्चात, की जानी चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत की संगणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III और डीजीएडी की संगत प्रक्रिया के अनुरूप की गई है।

(छछ) जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भाड़ा लागत का समायोजन किया जाना अपेक्षित है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली और डीजीएडी की संगतप्रक्रिया के अनुरूप किया गया है।

(जज) जहाँ तक पीटीए प्रयोक्ता एसोसिएशन के इस अनुरोध का सम्बंध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए क्या उत्पाद कर कम प्रभारित किया गया है याचिकाकर्ताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद कर को प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्टों का सत्यापन करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 4 के अन्तर्गत यह अधिदेशित नहीं है कि कम उत्पाद शुल्क प्रभारित किए जाने की जांच की जाए।

### संचयी आकलन

50. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जबवह यह निर्धारित करें कि:-

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुरिटकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (या अधिक) है या जहाँ अलग-अलग अन्य देशों से निर्यात तीन प्रतिशत से कम है और जहाँ आयात समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक होते हैं, और
- ख. आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के महेनजर आयातों के प्रभावों का संचयी निर्धारण उचित है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (क) भारत में संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों से पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा व्यक्तिगत रूप से आयातों की कुल मात्रा से 3 प्रतिशत से अधिक है।
- (ग) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से किए गए निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं।

52. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विचार करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों के कारण होने वाली क्षति का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा।

53. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति विश्लेषण में उन कारकों की जांच करना शामिल होगा जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हों "....पाठित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्राभाव को शामिल करते हुए सभी कारकों पर विचार किया जाता है।...." कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाठित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों का अन्यथा भारी निग्रहण हुआ है अथवा उनकी कीमतों में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उन सभी कारकों पर पाटनरोधी नियमावली जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभदायकता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि।

### घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों का मात्रा प्रभाव

- (क) मांग एवं बाजार हिस्सा

54. प्राधिकारी ने, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, मांग और भारत में इस उत्पाद की स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्त्रोतों से आयात जोड़ के रूप में परिभाषित किया है। इस तरह आकलित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
मांग	एमटी	3456617	3952141	3876427	4096498
रुझान	अनुक्रमणिका	100	114	112	119
सम्बद्ध देशों से आयात	एमटी	308102	618818	511137	586986
रुझान	अनुक्रमणिका	100	201	166	191
अन्य देशों से आयात					
चीन जन. गण.	एमटी	-	5262	6490	3368
ईयू	एमटी	6881	1272	5390	11374
अन्य	एमटी	159505	119018	71896	46230
कुल	एमटी	166386	125552	83776	60972
रुझान	अनुक्रमणिका	100	75	50	37
घरेलू उद्योग कि बिक्री (ग्राही खपत सहित)	एमटी	2454129	2760771	2739514	2906540
रुझान	अनुक्रमणिका	100	112	112	118

अन्य उत्पादकों कि बिक्री	एमटी	528000	447000	542000	542000
रुझान	अनुक्रमिका	100	85	103	103

### i. मांग में बाजार हिस्सा

55. भारत में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से की जांच विभिन्न स्त्रोतों से आयात तथा घरेलू उद्योग की बिक्री पर विचार करते हुए की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का हिस्सा स्थिर बना रहा जबकि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2009–10	2010–11	2011–12	जांच की अवधि
संबद्ध देशों से आयात	%	8.91	15.66	13.19	14.33
ईयू और चीन सहित अन्य देशों से आयात	%	4.81	3.18	2.16	1.49
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	71.00	69.86	70.67	70.95
अन्य उत्पादों की बिक्री	%	15.28	11.31	13.98	13.23

### आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

56. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा निम्नलिखित है:

विवरण		यूनिट	2009–10	2010–11	2011–12	जांच की अवधि
मात्रा	संबद्ध देश	एमटी	308102	618818	511137	586986
	ईयू और चीन सहित अन्य देश कुल आयात	एमटी		166386	125552	83776
आयात में बाजार हिस्सा	संबद्ध देश	%	474488	744370	594914	647958
	अन्य देश	%	64.93	83.13	85.92	90.59

57. उपयुक्त तालिका से यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

### उत्पादन के संबंध में आयातों का हिस्सा

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के आयात में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:

विवरण	यूनिट	2009–10	2010–11	2011–12	जांच की अवधि
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	308102	618818	511137	586986
घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	2454835	2754659	2753708	2931680
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में सम्बद्ध देशों से आयात	%	12.55	22.46	18.56	20.02

### इ. क्षमता एवं क्षमता उपयोग

59. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2009–10	2010–11	2011–12	पीओआई
क्षमता एमटी	एमटी	2,595,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000
उत्पादन	एमटी	2,454,835	2,754,659	2,753,708	2,931,680
क्षमता उपयोग	%	95	81	81	86

60. यह देखा जाता है कि मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष में गिरावट आई है:

### च. उत्पादन

61. घरेलू उद्योग के उत्पादन ऑकड़े निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं:

विवरण	यूनिट	2009–10	2010–11	2011–12	जांच की अवधि
उत्पादन	एमटी	2454835	2754659	2753708	2931680
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	112	119
मांग	एमटी	3456617	3952141	3876427	4096498
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	112	119
मांग के संबंध में उत्पादन	प्रतिशत	71.02	69.70	71.04	71.57

62. प्रेक्षण किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षमात में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है।

छ. बिक्री मात्रा

63. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2009–10	2010–11	2011–12	जांच की अवधि
घरेलू बिक्री (ग्राही खपत सहित)	एमटी	2454129	2760771	2739514	2906540
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	112	118
माग	एमटी	3456617	3952141	3876427	4096498
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	112	119
माग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	प्रतिशत	71.00	69.86	70.67	70.95

64. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि प्रतिशत के रूप में यह वृद्धि स्थिर बनी रही।

झ. घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों का कीमत प्रभाव

65. जहां तक कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या पाठित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादन की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत अधोरदन हुआ है। अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। इस विष्लेशन के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (सीओपी), भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारी (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से हुए आयातों की उत्तराई लागत के साथ की गई है।

i. कीमत अधोरदन

66. निवल बिक्री प्राप्ति की गणना भुगतान किए गए भाडे और करों की कटौती करने के बाद की गई है। आयातों के उत्तराई मूल्य की गणना लागू उपकर सहित 1 प्रतिशत हैडलिंग प्रभार तथा लागू मूल सीमाशुल्क का संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य में जोड़कर की गई है। आयातों के उत्तराई मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई थी और यह पाया गया था कि “प्रतिशत अवधि अधोरदन हुआ। जांच की अवधि सहित सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से कीमत अधोरदन ऋणात्मक रहा है। इस सम्बंध में प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस प्रस्तुतिकरण को नोट करते हैं कि वे अपनी वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री “नकदी पर सुपर्दगी” के आधार पर कर रहे हैं वहीं विदेशी उत्पादक 180 दिनों तक का व्याज मुक्त क्रेडिट देने की पेशकश कर रहे हैं, इसलिए प्राधिकारी द्वारा संगणित उत्तराई मूल्य घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्राप्ति और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत से तुलनीय नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह दावा भी किया है कि घरेलू उद्योग की कीमत की आयातों की उत्तराई कीमत से तुलना करते समय घरेलू उद्योग की भाड़ा लागत की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। प्राधिकारी ने सम्बद्ध वस्तु के उत्तराई मूल्य का निर्धारण पत्तन-बाह्य स्तर पर किया है और घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण सुरक्षापित प्रक्रिया के अनुसार फैक्टरी-बाह्य स्तर किया है।

	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
सम्बद्ध देश					
आयातों की उत्तराई कीमत	रुपये/एमटी	47016	54115	63191	65056
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	115	134	138
निवल बिक्री कीमत	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	103	138	145
कीमत अधोरदन	रुपये/एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत अधोरदन	%	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत अधोरदन रेंज	%	(5 – 15)	(5 – 15)	(0 – 10)	(0 – 10)
कोरिया आरपी					
आयातों की उत्तराई कीमत	रुपये/एमटी	47226	52738	62904	64936
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	133	138
निवल बिक्री कीमत	रुपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	103	138	145
कीमत अधोरदन	रुपये/एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत अधोरदन	%	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत अधोरदन रेंज	%	(5 – 15)	(5 – 15)	(0 – 10)	(0 – 10)

	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
थाईलैण्ड					
आयातों की उत्तराई कीमत	रूपये/एमटी	46731	55602	63405	65246
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	119	136	140
निवल बिक्री कीमत	रूपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	103	138	145
कीमत अधोरदन	रूपये/एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत अधोरदन	%	(***)	(***)	(***)	(***)
कीमत अधोरदन रेंज	%	(5 - 15)	(10 - 20)	(0 - 10)	(0 - 10)

### ii. कीमत अधोविक्रयण

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्षति रहित कीमत की गणना की गई है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा निकालने के लिए उसकी तुलना संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण पाटनरेधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया गया है। विष्लेशण से यह पता चलता है जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य क्षति रहित कीमत से कम था जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	यूनिट	कोरिया	थाईलैण्ड	सम्बद्ध देश
गैर-क्षतिकारी कीमत(बल्क)	रूपये/एमटी	***	***	***
गैर-क्षतिकारी कीमत(पैकड़)	रूपये/एमटी	***	***	***
गैर-क्षतिकारी कीमत(भारित औसत)	रूपये/एमटी	***	***	***
उत्तराई कीमत(जांच की अवधि)	रूपये/एमटी	64936	65246	65056
कीमत अधोविक्रयण	रूपये/एमटी	***	***	***
अधोविक्रयण	%	***	***	***
अधोविक्रयण रेंज	%	0-10	0-10	0 - 10

### iii. कीमत निग्रहण/अवमंदन

68. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटित आयातों के प्रभाव से भारत में समान वस्तु की कीमतों का अवमंदन हुआ है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रूपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	116	164	180
बिक्री कीमत	रूपये/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	138	145
आयातों की उत्तराई कीमत (संबद्ध देश)	रूपये/एमटी	47016	54115	63191	65056
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	115	134	138

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बिक्री लागत 2009-10 में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 180 हो गई है, बिक्री कीमत इसी अवधि के दौरान 100 बढ़कर केवल 145 हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्तराई कीमत जो आधार वर्ष में 100 आधार बिन्दु हो गई। यह दर्शाता है कि पाटित आयातों के कारण कीमत निग्रहण हुआ और घरेलू उद्योग अपनी कीमतों के उस अनुपात में वृद्धि करने में समर्थ नहीं था जिस अनुपात में लागत में वृद्धि हुई थी।

## घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

### i. लाभ/हानि

69. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है।

विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	2011–12	जांच अवधि
लाभ	रु./लाख	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	(39)	(117)
नकद	रु./लाख	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	2	(60)
नियोजित पैंजी पर प्रतिलाभ	प्रतिशत	***	***	(***)	(***)
नियोजित पैंजी पर प्रतिलाभ	अनुक्रमित	100	120	(35)	(110)

70. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है। आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अवधि के दौरान नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आई है।

### ii. नकदी प्रवाह

71. घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह की स्थिति पर पाठन के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने नकद लाभ में प्रवृत्तियों की जांच की है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ के बारे में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	2011–12	जांच अवधि
नकद लाभ	रु./लाख	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	125	2	(60)

यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के नकद लाभ में वर्ष 2011–12 से गिरावट आई है।

### iii. मालसूची

72. घरेलू उद्योग के पास मालसूची में उतार–चढ़ाव निम्नानुसार रहा है:

विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	2011–12	जांच अवधि
औसत स्टॉक	एमटी	4,747	3,634	3,554	11,069
बिक्री दिवसों की संख्या के रूप में स्टॉक	दिन	***	***	***	***

यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची में वृद्धि हुई है।

### iv. उत्पादकता

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान उसमें वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	2011–12	जांच अवधि
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	7014	7870	7868	8376

### v. रोजगार और मजदूरी

74. निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि आधार वर्ष की तुलना में समूची क्षति अवधि के दौरान रोजगार के स्तर में मामूली वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
रोजगार	सं०	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	107	105	104
मजदूरी	रु. / लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	152	174	175

#### vI. पाटन की मात्रा

75. उस सीमा, जहां तक पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, के संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा से यह पता चलता है कि सम्बद्ध देशों के सम्बंध में निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

#### vii. वृद्धि

76. प्राधिकारी अधोलिखित तालिका से यह नोट करते हैं कि उत्पादन, घरेलू बिक्री, लाभ/हानि, निवेश पर प्रतिलाभ आदि के सम्बंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि में वर्ष 2010-11 में प्राप्त वृद्धि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2009.10	2010.11	2011.12	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	12.21	(0.03)	6.46
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	12.49	(0.77)	6.10
बिक्री लागत	%	-	16.20	41.06	9.64
बिक्री कीमत	%	-	12.07	22.92	5.28
प्रति यूनिट लाभ / हानि	%	-	-14.41	-134.98	-158.54
नियोजित पूँजी पर प्रति लाभ	%	-	16.64	-127.89	-228.91

#### viii. पूँजी निवेश उगाहने की क्षमता

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के संघटकों में से एक संघटक विविध वस्तु के उत्पादन में अंतर्गत है तथा पूँजी उगाहने की क्षमता क्षति विश्लेषण का कारक नहीं है। इसके अतिरिक्त, अन्य संघटक घरेलू उद्योग बीआईएफआर में हैं:

#### ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

78. सम्बद्ध देशों तथा अन्य देशों की आयात कीमत, लागत ढाँचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले पाटित आयातों के अलावा करकों आदि की जांच करने से यह प्रदर्शित होता है कि सम्बद्ध देशों से आयातिक सामग्री की उत्तराई मूल्य घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोविक्रयण हो रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि इस सम्बद्ध वस्तु के लिए मांग में जांच की अवधि सहित सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है। अतः घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रभाव कारक सम्बद्ध देशों से पाटित सम्बद्ध वस्तु के आयातों का उत्तराई मूल्य है।

#### ज. वास्तविक क्षति के संबंध में निष्कर्ष

79. उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के हुए पाटित आयातों में समग्र रूप में और भारत में सम्बद्ध वस्तु की खपत एवं उत्पादन की तुलना में संगत रूप से वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का मामूली अधोरदन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, परन्तु बिक्री कीमत में यह वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं थी। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण कर रहे थे और उन कीमतों को बढ़ने से रोक रहे थे जो पाटित आयातों के अभाव में अन्यथा भारी मात्रा में बढ़ी होती। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह जाता है कि इस उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन में भी वृद्धि हुई मांग में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं थी। परिणामतः मांग एवं क्षमता में वृद्धि बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि नहीं हुई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आई। लगाई गई पूँजी पर अर्जन और नकद लाभ ने भी लाभ के समान ही प्रवृत्ति दर्शाई। लगाई गई पूँजी पर अर्जन और नकद लाभ दोनों ने जांच की अवधि के दौरान ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है कीमत पैरामीटरों के सम्बंध में वृद्धि ने घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव प्रदर्शित किया है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ट. कारणात्मक संबंध एवं अन्य कारक

80. घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री तथा कीमत निग्रहण/कीमत न्यूनीकरण के प्रभावों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के कारण होने वाली वास्तविक क्षति, आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की मौजूदगी की जांच करने के बाद भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार में सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मापदंण्डों की जांच की गई है ताकि यह देखा जा सके कि क्या पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। तदअनुसार, निम्नलिखित मापदंण्डों की जांच की गई है:—

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

81. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से इतर देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा नगण्य रही है। अतः, अन्य देशों से हुए आयातों के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी।

(ख) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिवंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

82. विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिवंधात्मक व्यवहारों और उनके बीच प्रतिस्पर्धा का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

(ग) मांग में कमी अथवा खपत के प्रतिमान

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान इस उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में कमी के कारण नहीं हुई थी।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास

84. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रौद्योगिकी में हुए किसी खास परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

85. घरेलू और निर्यात बाजार के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन को पृथक किया गया है। अतः निर्यात निष्पादन में आई कोई संभावित गिरावट होने वाली किसी क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

86. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट प्रदर्शित की है।

87. पूर्वोक्त से प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के अलावा अन्य कारकों की वजह से होने वाली क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है।

(छ) कारणात्मक संबंध की पुष्टि करने वाले कारक

88. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में अधितम गिरावट आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि निम्नलिखित आधारों पर की जाती है:

(i) देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और खपत के संबंध में एवं संगत रूप से एवं समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

(ii) क्षति अवधि के दौरान उत्पादन बिक्री लागत बढ़ती रही तथापि बिक्री कीमत में हुई यह वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई।

(iii) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का निग्रहण कर रहे थे और कीमतों को जिससे पाटित आयातों के अभाव में भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती।

(iv) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी हुई। लगाई गई पूंजी पर आवक और नकद लाभ ने भी लाभ के समान ही प्रवृत्ति दर्शाई। पाटित आयातों के कारण नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आवक दोनों में जांच की अवधि के दौरान ऋणात्मक वृद्धि हुई।

(v) लाभ, आर और आई और नकदी प्रवाह के संगंध में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई है।

89. इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

(d) **क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन**

90. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण यथासंशोधित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध दशों से हुए आयातों की उत्तराई मूल के साथ की गई है।

क्रम सं.	निर्यात का माध्यम	उत्पादक का नाम	निर्यातक	क्षति रहित कीमत यूसडी/एमटी	पहुंच कीमत यूएसडी/एमटी	क्षति मार्जिन यूएसडी/एमटी	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेज -%
1.	कोरिया आरपी - भारत	सैमसंग जनरल कैमिकल कंपनी लि.	सैमसंग सीएंडटी	***	***	***	***	0 - 10
2.	कोरिया आरपी - भारत	टैक्यांग इंडस्ट्रियल्स कंपनी लि.	टैक्यांग इंडस्ट्रियल कंपनी लि.	***	***	***	***	0 - 10
3.	कोई	अन्य सभी उत्पादक	अन्य सभी निर्यातक	***	***	***	***	0 - 10
4.	थाईलैंड - भारत	इंडोरामा पेट्रोकेम लि.	इंडोरामा पेट्रोकेम लि.	***	***	***	***	0 - 10
5.	थाईलैंड - भारत	टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक लि.	टीपीटी पेट्रोकेमिकल्स पब्लिक लि	***	***	***	***	0 - 10
6.	कोई	अन्य सभी उत्पादक	अन्य सभी निर्यातक	***	***	***	***	0 - 10

(d) **प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ**

91. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियाँ/प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं—

i. प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रकटन विवरण तथ्यों एवं विधि की अयथार्थ समालोचना पर आधारित है। इससे प्रतिवादियों द्वारा किए गए कई प्रस्तुतिकरणों पर विचार नहीं किया गया है। उदाहरणर्थ, प्रतिवादियों ने यह प्रस्तुतिकरण किया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को एमसीपीएल द्वारा सामना की जा रही सभी स्वीकृत तकनीकी समस्याओं के आलोक में सभी आर्थिक प्राचलों पर विचार करना चाहिए। परन्तु प्राधिकारी ने उक्त प्रस्तुतिकरण पर और उद्घृत किए गए विधिशास्त्र पर कोई ध्यान नहीं दिया।

ii. आवेदक घरेलू उत्पादकों का यह तर्क गलत है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्राधिकारी किसी जाँच को तब तक समाप्त “नहीं” करेंगे “जब तक” वह यह निर्धारित नहीं करते हैं कि पाटित आयातों की वास्तविक “और” सम्भावित मात्रा “न्यूनतम” है।

iii. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह उल्लेख किया है कि क्षति मार्जिन और-कीमत अधोविक्रयण का माहवार निर्धारण किया गया है। इस माहवार निर्धारण की संकीर्ण रेज के निर्धारण का इस प्रकटन विवरण में खुलासा किया जाना चाहिए था। प्राधिकारी को सी आई एफ मूल्य से संगत समायोजन युक्त उत्तराई मूल्य के वास्तविक परिकलन का भी खुलासा करना चाहिए था।

iv. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में, खासकर साम नाम के निदेशकों, गैर-क्षतिकारी कीमतों आदि के विवरण से सम्बंधित सूचना के सम्बंध में भारी गोपनीयता वरती है। यद्यपि साम नाम के निदेशकों के विवरण का प्रकटन न करने से आवेदक घरेलू उत्पादकों का आधार प्रभावित होता है, वहीं गैर-क्षतिकारी कीमत के विवरण/क्रियापद्धति का प्रकटन न करने से प्राधिकारी द्वारा निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत की मात्रा के सम्बंध में सन्देह उत्पन्न होता है।

v. एमसीपीएल के संयंत्र 2 की त्रुटिपूर्ण उत्पादन प्रविधि का ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते वक्त ध्यान नहीं रखा है। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि मांग में बाजार हिस्सा, उत्पादन के सम्बंध में आयातों का हिस्सा, क्षमता उपयोग का निर्धारण, बिक्रियों का निर्धारण आदि करते समय ध्यान नहीं रखा गया है। इस त्रुटिपूर्ण उत्पादन प्रविधि के कारण हुई क्षति को कथित पटित आयातों सहित अन्य कारणों पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी का प्रकटन विवरण में प्रेक्षण त्रुटिपूर्ण है कि प्रविधि में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं हुई है। यह एक स्वीकृत रिथ्ति है कि एमसीपीएल ने संयंत्र 2 की स्थापना क्षति अवधि के दौरान की थी और इस संयंत्र में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी के कारण उसे क्षति हो रही है।

vi. प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या घरेलू उद्योग के ब्याज मुक्त ऋण और भाड़ा लागत सम्बंधी तर्क को गैर-क्षतिकारी कीमत की संगणना करते समय स्वीकार किया गया या अस्वीकार कर दिया गया, केवल यह कह देना कि सुस्थापित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, पर्याप्त नहीं है।

vii. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है क्योंकि न तो मात्रा क्षति हुई है और नहीं कीमत अघोरदन हुआ है।

viii. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि एमसीपीएल को तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तब प्राधिकारी तर्क संगत रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि इस तकनीकी समस्या के कारण उत्पादकता पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा।

ix. यह एक स्वीकृत रिथ्ति है कि आवेदक घरेलू उत्पादक और आईओसीएल अपने समस्त उत्पादन की बिक्री करने में सक्षम हैं और 100% से अधिक क्षमता उपयोग (एमसीपीएल के एक संयंत्र-II को छोड़कर, जो त्रुटिपूर्ण उत्पादन प्रविधि का प्रयोग करता है) प्राप्त करने के पश्चात भी अपना समस्त उत्पादन बेचने में समर्थ हैं। आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि सम्बद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं ने कभी कीमत कम करने के लिए आवेदक घरेलू उत्पादकों पर कोई स्थिर दबाव डाला हो। वास्तव में, प्रयोक्तागण हमेशा अपनी कीमतों का निर्धारण करने में आवेदक घरेलू उत्पादकों के अधिदेश का अनुपालन करते हैं। आवेदक घरेलू उत्पादकों ने प्रयोक्ता उद्योग पर उनके द्वारा थोपे गए कीमत निर्धारण फार्मूला के आधार पर भारी लाभ अर्जित किया है। तथापि, जाँच की अवधि के दौरान ही परिवर्तित परिस्थितियों के कारण आवेदक घरेलू उत्पादकों की लाभप्रदता में (एमसीपीएल के संयंत्र-II के सम्बंध में के सिवाय) मामूली सी गिरावट आई थी। आवेदक घरेलू उत्पादक बिक्रियों के सौदों की क्षति के सम्बंध में भी कोई साक्ष्य रिकार्ड में दर्ज कराने में असफल रहें हैं।

x. अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पहले भी आवेदक घरेलू उत्पादकों ने एक बार पुनः प्रयोक्ताओं पर अपनी वस्तु की कीमत निर्धारण का एक अन्य फार्मूला अपनाने का दबाव डाला ताकि आवेदक घरेलू उत्पादकों की लाभप्रदता में पर्याप्ततः वृद्धि हो सके। आयात केवल मांग एवं आपूर्ति के बीच के अन्तर को ही पूरा करने के लिए ही तब किए गए थे जब आवेदक घरेलू उत्पादक सम्बद्ध वस्तु की अनुसूचित आपूर्ति को पूरा करने में असफल रहे थे। आयातों की मात्रा घरेलू उत्पादकों द्वारा की गई आपूर्ति में कभी को पूरा करने के लिए ही की गई थी। इससे यह सिद्ध होता है कि आयातों और आवेदक घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

xi. सम्बद्ध वस्तु के उपयोगकर्ताओं का दूर-दूर तक ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि सम्बद्ध वस्तु का आयात करके आवेदक घरेलू उत्पादकों को क्षति पहुँचाई जाए। अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात आवेदक घरेलू उत्पादकों तथा आई ओसीएल दोनों ने ही सम्बद्ध वस्तु की कीमतों में वृद्धि कर दी थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 17 (xi) में प्रतिवादियों के प्रस्तुतिकरण को गलत ढांग से नोट किया है। यह प्रस्तुत किया गया कि आर आई एल 'सहित' 'प्रत्येक' उत्पादक ने अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि कर दी थी। पीटीए की कीमतों में वृद्धि करने के पश्चात बाह्य उपयोगकर्ताओं से यह निवेदन किया गया था कि आर आई एल ने पीटीए के अन्तिम उत्पादों की कीमत में वृद्धि नहीं की है और इस कारण पीटीए के उपयोगकर्ताओं और अनुप्रवाही उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

xii. इसके अतिरिक्त, एमसीपीएल को क्षति इसलिए हुई क्योंकि वह अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहा था। एमसीपीएल ने अपने संयंत्र की स्थापना एक ऐसे स्थान पर की है जो अन्य घरेलू उत्पादकों की तुलना में अलाभकर है और इसी कारण से वह अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहा। एमसीपीएल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है।

इसके परिणामस्वरूप उपयोक्ता को यदि वह सम्बद्ध वस्तु का अधिप्रापण अन्य घरेलू उत्पादकों से करने के बजाय एमसीपीएल से करते हैं, तो भारी भाड़ा लागत वहन करनी पड़ती है।

**xiii.** किसी भी हाल में, एमसीपीएल की उत्पादन लागत बहुत अधिक है और वह सम्बद्ध उत्पाद के उपयोक्ताओं से उसकी पुनर्प्राप्ति करने में सक्षम नहीं है, इसलिए एमसीपीएल घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा में असफल रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण एमसीपीएल को इस तथ्य के अलवा भी क्षति हो रही है कि उसकी उत्पादन तकनीकी त्रुटिपूर्ण है।

**xiv.** निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1 यूएस डालर = आई एन आर 54.65/- की विनियम दर अपनाई है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इसके उत्तरवर्ती रूप से आई एन आर का भारी अवमूल्यन हुआ और विनियम दर घटकर 1यूएस डालर= आईएन आर 62/- हो गई जो अब एक स्थाई तत्व बन चुका है। विनियम दर में इस परिवर्तन से पाटन/क्षति के प्रभाव का उपशमन हो गया है और इससे घरेलू उद्योग के लिए लाभप्रद स्थिति सृजित हुई है। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वे पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश न करें।

**xv.** प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट है कि माहवार भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना माहवार निर्यात कीमत से की गई और फिर अन्तिम पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए अन्य भारित औसत का पुनः अनुप्रयोग किया गया। प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने के अनुरोध किया गया कि किस विधिक प्रावधान के अन्तर्गत इस क्रियापद्धति का अनुपालन किया गया है।

**xvi.** दो उत्पादकों की भारित औसत संशोधित लागत के आधार पर गैर-क्षतिकारी कीमत को प्राधिकारी द्वारा गोपनीय के रूप में नहीं रखा जा सकता है।

**xvii.** हयोसंग के आंकड़ों का नामंजूर कर देना और उसे केवल इस आधार पर कि ‘मूल्य श्रंखला अपूर्ण’ है, व्यक्तिगत मार्जिन न प्रदान करने का कोई विधिक आधार नहीं है। हयोसंग को व्यक्तिगत मार्जिन किसी तृतीय पक्षकार द्वारा सहयोग के अभाव में अथवा एस. के. पेट्रोकैमिकल द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को स्वयं सत्यापन न करने के इस अपने कृत्य के कारण प्रदान न करना पूर्णतया अनधिपात्रित है और प्राधिकारी का मनमाना व्यवहार है।

**xviii.** डीजीसी आई एण्ड एस के संव्यवहार-गर आयात आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालना सही है कि चीन जन.गण और ईयू से सम्बद्ध वस्तु के न्यूनतम आयात हुए हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. ईयू को सही ही सम्बद्ध देशों के दायरे और अभिग्राय से अपवर्जित कर दिया है और इन देशों से सम्बंध में जॉच को पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार खारिज कर दिया है।

92. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियों/प्रस्तुतिकरण किए गए हैं।

- i.** चीन और ईयू के सम्बंध में जॉच को पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं करना चाहिए क्योंकि नियम में यह उल्लेख है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी जॉच को तब तक समाप्त “नहीं” कर सकते हैं “जब तक” कि यह निर्धारित नहीं हो जाता है कि पाटित आयातों की मात्रा वास्तविक “और” संभावित रूप से न्यूनतम है।
- ii.** प्रतिवादी निर्यातकों की आयात कीमत सर्वोत्तम ‘उपलब्ध तथ्य’ सूचना इस कारण से नहीं है कि वह किसी विशिष्ट निर्यात से सम्बंधित है और इसका “किसी अन्य ऐसे निर्यातक” से कोई सम्बंध नहीं है जिनके लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण ‘किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक’ अथवाअसहयोगकर्ता निर्यातक’ की श्रेणी के अन्तर्गत किया जाता है। इसलिए अवशिष्ट पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण भारतीय सीमाशुल्क के आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए।
- iii.** याचिकाकर्ताओं को प्रकटन किए गए गैर-क्षतिकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड की कार्य शील पूँजी का निर्धारण मौजूदा देयताओं से ब्याज वहन करने वाली क्रेडिट खरीद का अपवर्जन करके किया गया है। ब्याज वहन करने वाली क्रेडिट खरीद कार्यशील पूँजी का भाग नहीं बन सकती है। कार्यशील पूँजी का निर्धारण मौजूदा परिसम्पत्तियों से मौजूदा देयताओं को घटाकर किया जाता है। घटाई गयी मौजूदा परिसम्पत्तियों व्यवसाय उद्यमों को प्राप्त ब्याज मुक्त निधियों/ उपलब्ध क्रेडिट हैं और इस सीमा तक, किसी व्यवसाय उद्यम को निधियों (और इन निधियों पर उपगत लागत) परिनियोजित करना अपेक्षित नहीं होता है। यह वह कारण है कि ब्याज मुक्त निधियों/ ऋणों को मौजूदा देयताओं के रूप में माना जाता है और कार्यशील पूँजी का निर्धारण करने के लिए उन्हें मौजूदा परिसम्पत्तियों से घटाया जाता है। तथापि, यदि वर्तमान देयताओं में कोई ब्याज युक्त ऋण होता है तो कार्यशील पूँजी का निर्धारण करने के लिए वर्तमान देयताओं का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। जहाँ किसी कम्पनी की ब्याज युक्त ऋण खरीद होती है तो इन ब्याज युक्त क्रेडिट दाताओं को जी एपी और लेखाकरण मानकों के अनुसार क्रेडिट दाताओं में शामिल कर लिया जाता

है। तथापि, चूंकि कम्पनी ने इसकी लागत का भुगतान किया है, इसलिए उसे कार्यशील पूँजी का निर्धारण करने के लिए वर्तमान देयताओं से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।

- iv. निर्धारित क्षति मार्जिन अनुपयुक्त है और इस कारण से उसका कम उल्लेख किया गया है कि गैर-क्षतिकारी कीमत और आयात के बीच तुलना अनुचित है क्योंकि दोनों ही आंकड़े समान स्तर पर नहीं हैं। क्षति मार्जिन बिल्कुल कम है और यह दर्शाता है कि अपनाई गई क्रियापद्धति से इस मार्जिन का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच ऋण अवधि में अन्तर को ध्यान में नहीं रखा गया। क्षति मार्जिन का परिकलन इस क्रेडिट लागत पर विचार करते हुए किया जाना अपेक्षित है।
- v. प्राधिकारी ने उस क्रियापद्धति का प्रकटन नहीं किया है जिसका अनुप्रयोग विदेशी उत्पादकों की उत्पादन लागत, अपनाई गई लागत के तत्वों और अपनाई गई क्रिया पद्धति का निर्धारण करने के लिए किया गया है। प्राधिकारी ने इस बात का भी प्रकटन नहीं किया है कि उन्होंने विदेशी उत्पादकों की उत्पादन लागत की तर्क संगतता के बारे में स्वयं को किस तरह संतुष्ट किया है।
- vi. गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण उपयुक्त नहीं है और वह पाटन विधि के प्रयोजन और आशय के विपरीत है और इसलिए वर्तमान मामले में निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत को उपरिमुखी संशेधित करने की जरूरत है।
- vii. प्राधिकारी को क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत में उत्पाद शुल्क जोड़ना चाहिए। केवल यह तथ्य कि, उत्पाद शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क केन्द्रीय रूप से वैट योग्य है, यह निर्धारित करने के लिए पूर्णतया अपर्याप्त है कि क्या गैर-क्षतिकारी कीमत में उत्पाद शुल्क जोड़ना और आयात कीमत में सीमा शुल्क जोड़ना चाहिए। यदि गैर-क्षतिकारी कीमत में उत्पाद कर नहीं जोड़ा जाता है और आयातों की उत्तराई कीमत में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को नहीं जोड़ा जाता है तो क्षति मार्जिन का अनुपातिक रूप से कम आकलन हो पाता है।
- viii. घरेलू उद्योग के मामले में परिवहन लागत, लागत एक भारी हिस्सा होती है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की उत्तराई कीमत की तुलना परिवहन लागत को जोड़ने के पश्चात ही की जानी चाहिए।
- ix. रिलायंस ने अपने नए पीटीए संयंत्र में, जिसकी उत्पादन क्षमता 1.15 मिलियन एमटी/ प्रतिवर्ष है, वाणिज्यिक उत्पादन करना पहले से ही प्रारंभ कर दिया है। तर्कसंगत लाभ प्रदान करते समय इन निवेशों के वर्तमान मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए।
- x. लगायी गयी पूँजी का निर्धारण अचल परिस्मृतियों के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए करना चाहिए। निवल अचल परिस्मृतियों का अनुकूलन अत्यधिक अनुचित है।
- xi. घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति की वास्तविक सीमा का निर्धारण करने के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत के साथ आयात कीमत की तुलना उचित स्तर पर की जानी चाहिए। गैर-क्षतिकारी कीमत और आयात कीमत पर विचार उससे जुड़े मालभाड़े का अपवर्जन या समावेशन किए जाने के पश्चात किया जाना चाहिए। उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत, उससे जुड़े मालभाड़े को शामिल किए बिना, की तुलना आयातों की उत्तराई कीमत से, उससे जुड़े मालभाड़े को जोड़ने के पश्चात करना, उचित तुलना नहीं होगी और घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गयी क्षति का सकल कम आकलन होगा।
- xii. नियमों में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी फैक्टरी बाह्य स्तर पर गैर-क्षतिकारी कीमत पर विचार करें। बिक्री कर, उत्पाद कर, डिस्काउंट, कमीशन, फैक्टरी बाह्य स्तर पर देय होते हैं और इसलिए यह तथ्य कि क्षति मार्जिन का निर्धारण फैक्टरी बाह्य स्तर पर किया जा रहा है, का आशय यह नहीं है कि बिक्री कर और उत्पाद शुल्क को जोड़ा नहीं जा सकता है।
- xiii. घरेलू पीटीए की बिक्री नकद रूप से करता है जबकि, जाँच के अधीन सम्बद्ध देशों से पीटीए की आपूर्ति \*\*\* दिनों से \*\*\* दिनों तक की अवधि के लिए व्याज रहित क्रेडिट पर की जाती है। यह महत्वपूर्ण लागत है क्योंकि भारत में 12 प्रतिशत व्याज है। भारत में पीटीए के प्रयोक्ता, घरेलू उद्योग के साथ लेनदेन करते बक्त हमेशा सौदा करने के लिए इस व्याज, मुक्त क्रेडिट के मूल्य का परिकलन करते हैं और न्यूनतम कीमतों का उदाहरण देते हैं। उद्योग को क्षति का निर्धारण करते समय इस पर विचार किया जा सकता है।

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अधिकांश विवरण प्रस्तुतिकरण उनके पिछले विवरणों की पुनरावृत्ति ही है। तथापि, संगत माने गए प्रकटन पश्चात विवरणों की जाँच निम्नवत की गई है:

### उत्पादकों/निर्यातकों/आयाताकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों की जाँच

- i. यह तर्क कि प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रकटन विवरण तथ्यों की गलत धारणा पर आधारित है और यह विधिविरुद्ध है तथा इसमें कोई दम नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जाँच की कार्रवाई के दौरान प्रोद्भवित अनिवार्य तथ्यों का विश्लेषण लागू विधि के अनुरूप किया गया है और उसकी आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन योग्य साक्ष्यों के साथ परिपूर्णी की गई है तथा उसका अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया गया है। इस जाँच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों की संगत समझी गई सीमा तक जाँच की गई है और उनका इस अन्तिम जाँच परिणाम में समाधान कर दिया गया है।
- ii. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में, खासकर सामनाम के निदेशकों के ब्यौरों से सम्बंधित सूचना के बारे में, गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के सम्बंध में भारी गोपनीयता वरती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई अगोपनीय सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध करा दी गई है गैर-क्षतिकारी कीमत घरेलू उद्योग के लिए व्यवसाय संवेदनशील सूचना होती है और इसलिए उसे सुरक्षापित परम्परा के अनुरूप गोपनीय के रूप में माना गया है।
- iii. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को माहवार क्षति मार्जिन और कीमत मार्जिन की संकीर्ण रेंज का तो कम से कम प्रकटन करना चाहिए था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच की अवधि के लिए दौरान उक्त निर्धारणोंकी रेंज प्रतिशत का प्रकटन, प्राधिकारी की संगत परम्परा के अनुरूप कर दिया गया है। प्राधिकारी पुनः नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की रेंज का माहवार विवरण देना, न तो व्यवहार्य है और न ही ऐसी प्रक्रिया है।
- iv. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प. प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र-II में त्रुटिपूर्ण उत्पादन तकनीक का, ऐसा प्रतीत होता है कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते वक्त और क्षति विश्लेषण करते वक्त ध्यान नहीं रखा गया है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप कम्पनी द्वारा अपने नये संयंत्र में सामना की गई तकनीकी समस्याओं के कारण हुए घाटे को ध्यान में रख कर किया गया है।
- v. प्रकटन पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया है कि प्रकटन विवरण में प्राधिकारी का यह प्रेक्षण कि घरेलू उद्योग को प्रविधि में परिवर्तन के कारण क्षति नहीं हुई है इस दृष्ट के सम्बंध में गलत है कि एमसीपीआई के संयंत्र-II में त्रुटिपूर्ण उत्पादन प्रविधि के कारण घरेलू उद्योग को कारित क्षति हुई है; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मौजूदा प्रौद्योगिकी में चूक को नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह सत्य है कि मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र-II में कुछ कमियों के कारण कम्पनी को क्षति हुई थी परन्तु सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के पाटन ने इस क्षति को और भी अधिक बढ़ा दिया था।
- vi. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने उनके द्वारा जबरदस्ती थोपे गए कीमत निर्धारण फार्मूला के आधार पर भारी लाभ अर्जित किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों द्वारा अपनाया गया कीमत निर्धारण फार्मूला अन्तर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण फार्मूला के अनुरूप ही है।
- vii. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड ने अपने संयंत्र की रक्षापना एक ऐसे स्थान पर की है जो अन्य घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों के स्थान से अधिक अलाभकर जगह पर है और इस कारण से ही वे अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी संयंत्र की स्थापना के स्थान अथवा उससे जुड़े लाभ/अलाभ क्षति विश्लेषण के लिए पाटनरोधी विधि के अन्तर्गत संगत नहीं है। सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई क्षति को वर्तमान जाँच परिणाम में स्पष्टकर दिया गया है।
- viii. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड को क्षति सहन करनी पड़ रही है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्रस्तुतिकरण के सम्बद्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। जाँच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी के समक्ष यह सिद्ध करने के लिए कोई संगत साक्ष्य नहीं दिया गया कि घरेलू उद्योग को वास्तविक रूप से क्षति घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है, न कि पाटन के कारण।
- ix. जहाँ तक इस तर्क का सम्बंध है कि विनिमय दर में परिवर्तन ने पाटन के प्रभाव का पहले ही प्रशमन कर दिया है और इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि

कि यह सम्पूर्ण जॉच पीओआई आंकड़ों पर आधारित है और जॉच की अवधि के पश्चात की अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों, जैसे विनिमय दर में परिवर्तन की प्राधिकारी द्वारा पाटनराधी उपायों की सिफारिश के लिए कोई संगतता नहीं है।

**X.** जहाँ तक भारित औसत पाटन मार्जिन का कार्य करने के लिए विधिक आधार से सम्बंधित तर्क का सम्बंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब माहवार अभ्यास किया जाता है तो माहवार सामान्य मूल्य की तुलना, माहवार पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए माहवार निर्यात कीमत से की जाती है। तत्पश्चात जॉच की अवधि के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने भारित औसत माहवार-पाटन मार्जिन की संगणना संगत प्रक्रिया के अनुरूप की है।

**xii.** जहाँ तक हयोसंग के इस तर्क का सम्बंध है उनके आंकड़ों की अस्वीकृति तथा उनको व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान करने की इस आधार पर मनाही करना बिना किसी आधार के है कि मूल्य श्रंखला अपूर्ण है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मुद्दे की इस जॉच परिणाम में विस्तार से जॉच पहले ही की जा चुकी है। उत्पादकों (एस के पेट्रोकैमिकल्स, सामनाम और लोट्टे) तथा हयोसंग (निर्यातक) के बीच मूल्य श्रंखला इस कारण से टूट गई है कि जॉच की अवधि के दौरान भारत को सम्बद्ध वस्तु का भारी मात्रा में निर्यात हुआ है क्योंकि उक्त उत्पादकों ने सहयोग नहीं किया है।

**xiii.** जहाँ तक इस प्रस्तुतिकरण का सम्बंध है कि प्राधिकारी के यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ब्याज मुक्त ऋण एनआईपी की गणना करने के लिए भाड़ा लागत के मुद्दे पर घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया तर्क स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया; प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच परिणाम में अंयत्र उल्लिखित कारणों से घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है।

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड के द्वितीय संयंत्र के क्षति अवधि के दौरान गैर-स्थिरीकरण के कारण प्राधिकारी को क्षतिविश्लेषण उनके द्वितीय संयंत्र के निष्पादन पर विचार किए बिना करना चाहिए था, ताकि द्वितीय संयंत्र के प्रचालन में सामने आई तकनीकी समस्याओं के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति, यदि कोई हो, का अपवर्जन किया जा सके। इसलिए प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड के द्वितीय संयंत्र के निष्पादन पर इसकी क्षमता के \*\*\*% की दर से विचार करते हुए किया है जैसा कि गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए किया गया था। निम्नलिखित तालिका प्रमुख अर्थिक पैरामीटरों के सम्बंध में घरेलू उद्योग को नोशनल निष्पादन को दर्शाती है मात्रा कि कम्पनी के द्वितीय संयंत्र ने जॉच की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान बिना किसी तकनीकी समस्या के प्रचालन किया हो।

क्रम. सं.	विवरण	यूनिट	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13 (जॉच की अवधि)
1.	क्षमता	एमटी	25,95,000	34,20,000	34,20,000	34,20,000
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	132	132	132
2.	उत्पादन	एमटी	25,03,093	32,26,130	33,20,442	32,97,251
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	129	133	132
3.	क्षमता उपयोग	%	96	94	97	96
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	98	101	100
4.	घरेलू बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	172	177	178
5.	ग्राही खपत	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	98	99	96
6.	बिक्री लागत	रुपये / एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	163	180
7.	बिक्री कीमत	रुपये / एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	138	145
8.	लाभ / हानि	रुपये / एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	(17)	(68)
9.	कर पूर्व लाभ / हानि	रुपये / लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	171	-28	-111
10.	अवमूल्यन	रुपये / लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	213	210	216
11.	ब्याज	रुपये / लाख	***	***	***	***

क्रम. सं.	विवरण	यूनिट	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13 (जॉच की अवधि)
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	274	233	249
12.	नकद लाभ/ हानि	रुपये/ लाख	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	170	8	–59
13.	कर और ब्याज पूर्व लाभ/ हानि	रुपये/ लाख	***	***	(***)	(***)
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	173	–22	–104
14.	लगाई गई पूँजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	(***)	(***_
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	168	–23	–100

उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जॉच की अवधि में सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जॉच की अवधि के दौरान स्थिर बना रहा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत दोनों में ही वृद्धि हुई है तथापि बिक्री कीमत में हुई वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वर्ष 2011–12 से और जॉच की अवधि में भारी घाटा उपगत हुआ। इसी तरह, लगाई गई पूँजी पर प्रतिलाभ वर्ष 2009–10 में 100 आधार बिन्दु से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 168 हो गया, फिर इसमें वर्ष 2011–12 में –23 बिन्दुओं की कमी आई और जॉच की अवधि में यह –100 बिन्दु हो गया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का संघटक बनने वाले एक घरेलू उत्पादक सम्बद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण जॉच की अवधि के दौरान अपनी संम्पूर्ण परिवर्ती लागत को कवर नहीं कर सके। इसलिए, प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग को हाँने वाली क्षति उत्पादकों में से एकद्वारा अपने नए संयंत्र में आई तकनीकी समस्या के कारण हुई है, सही नहीं है।

### घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियों की जॉच

- जहाँ तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का सम्बंध है कि यद्यपि जॉच की अवधि में चीन से आयातों की मात्रा न्यूनतम मानी गई है, तथापि, प्राधिकारी को आयातों की सम्भावित मात्रा पर विचार करना चाहिए (जो ३ प्रतिशत से अधिक है) और इसलिए उसे चीन के विरुद्ध जॉच को खारिज नहीं करना चाहिए, प्राधिकारी पुनः यह उल्लेख करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधान पर्याप्ततः यह स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक आयात या सम्भावित आयात कुल आयातों का ३ प्रतिशत से कम होने पर, जॉच को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के सम्बंध में असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ डीजीसीआई एण्ड एस आयात आंकड़ों के अनुरूप न्यूनतम कीमत पर विचार करना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीजीसीआई एण्ड एस आयात आंकड़े सहयोगकर्ता निर्यातकों तथा अन्य असहयोगकर्ता निर्यातकों द्वारा किए गए पीटीए के आयातों का अलग—अलग विवरण प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए प्राधिकारी इस सम्बंध में घरेलू उद्योगों के अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि असहयोगकर्ता निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(८) में उल्लिखित शर्तों तथा डीजीएडी की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है, जिसमें सहयोगकर्ता निर्यातकों के माहवार आंकड़ों सहित, आंकड़े शामिल हैं।
- घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के सम्बंध में कि मैसर्स एमसीसीपीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित पैराक्सीलीन की खरीद करने के लिए प्राप्त किए गए व्याज युक्त ऋण को भी शामिल किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कम्पनी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से पैराक्सीलीन का आयात क्रेडिट लागत पर करती रही है और कच्चे माल की लागत में क्रेडिट लागत भी शामिल होती है। मैसर्स एमसीसी पीटीए इण्डिया कार्प प्राइवेट लिमिटेड की क्रेडिट लागत और वास्तविक लागत के एक भाग के रूप में विदेशी विनियम अन्तर के प्रभाव सहित सम्पूर्ण लागत पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, उसने अपनी लेखापरीक्षित लेखाओं में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त क्रेडिट को मौजूदा देयताओं के रूप में प्रदर्शित किया है। चूँकि प्रधिकारी ने गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए कम्पनी (ऋण लागत और विनियम दर परिवर्तन सहित) द्वारा तथा दावाकृत पीएक्स की लागत पर विचार किया है, घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है कि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त व्याज युक्त ऋण को मौजूदा देयताओं से हटा दिया जाये। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने निवल कार्यशील पूँजी का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-३ के अनुसार मौजूदा परिस्मत्तियों और मौजूदा देयताओं के बीच अन्तर के रूप में किय है। इसलिए प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा इस सम्बंध में किए गए प्रस्तुतिकरण स्वीकार्य नहीं हैं।
- घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण के सम्बंध में कि क्षति मार्जिन का निर्धारण घरेलू उद्योग और निर्यातक द्वारा अनुमत क्रेडिट अवधि में अन्तर को ध्यान में रखते हुए व्याज लागत पर विचार करते हुए करना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन का निर्धारण गैर-क्षतिकारी कीमत और आयातों के उत्तराई मूल्य के अन्तर के रूप में किया गया है। उत्तराई मूल्य का निर्धारण प्रधिकारी की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार करनिर्धार्य मूल्य और लागू सीमा शुल्क एवं उपकर पर विचार करके किया गया है, वहीं गैर-

—क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अन्तर्गत निर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। इस तुलना में घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा अनुमत क्रेडिट अवधि में अन्तर के प्रभाव को ग्राह्य नहीं किया गया है।

v. घरेलू उद्योग के इस तर्क के सम्बंध में कि प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों की यथार्थता के बारे में किस तरह संतुष्टि की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन लागत (कच्चे माल, उपयोगी वस्तुओं, उपरिशीर्षी आदि) बिक्री और सामान्य प्रशासन व्यय, और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत अन्य व्ययों/आय का उनकी लेखा परीक्षित लेखाओं से और कम्प्यूटरीकृत लेखाकरण प्रणाली से संगत समझी गई सीमा तक सत्यापन किया है।

vi. घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण के सम्बंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पाद का परिवहन उपभोक्ता की फैक्ट्री/वेयरहाउस तक करने पर उपगत भाड़े को गैर-क्षतिकारी कीमत में शामिल करना चाहिए अथवा उसे सम्बद्ध वस्तु के आयातों के उत्तराई मूल्य से घटा दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्तराई मूल्य का निर्धारण पत्तन स्तर पर और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण फैक्ट्री बाह्य स्तर पर क्रमशः सुरक्षापित प्रक्रिया और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुरूप किया गया है। इस लिए घरेलू उद्योग द्वारा उनकी फैक्ट्रीयों से उपभोक्ता के परिवहन पर व्यय पर विचार किया गया है।

vii. जहाँ तक घरेलू उपयोग के इस तर्क का सम्बंध है कि प्राधिकारी को क्षति मार्जिन करने के लिए उत्पादकर, बिक्री कर डिस्काउंट, कमीशन आदि को घरेलू उद्योग कि गैर-क्षतिकारी कीमत में और आयातों में प्रतिसंतुलनकरी शुल्क को जोड़ना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के सम्बंध में उठाए गए कुछ मुद्दे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जब तक इस सम्बंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है, तब तक प्राधिकारी को अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धान्तों का ही अनुपालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा इस मामले में गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है।

#### ४. निष्कर्ष

94. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए प्रस्तुतिकरणों और इस जांच परिणाम में प्राधिकारी के समक्ष यथा दर्ज रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी इस जांच परिणाम में निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(क) संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का पाटन हुआ है।

(ख) विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देशों से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(ग) यह वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

#### ५. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

96. प्रयोक्ता सेक्टर द्वारा अभिव्यक्त की गई यह चिंता कि पीटीए पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुप्रवाही उद्योगों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यह एक दूरगमी तथ्य है और इसका सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। 2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत की रेंज में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का अनुप्रवाही उत्पादों जैसे पी एफवाई और पीएसएफ की उत्पादन लागत में 2-3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने का न्यूनतम लागत प्रभाव पड़ेगा। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं की तुलना में घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर सुनित करेगा और पीटीए के अन्तिम प्रयोक्ता, जिन्हें इस अनुचित व्यापार प्रक्रिया से लाभ हुआ था, उन्हें अब कच्चे माल के लिए अपाटित/उचित कीमतों का भुगतान करना होगा।

97. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादक के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर, तब जब पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण उस राशि तक सीमित रखा जाएगा जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में हास रुकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देशों से आया किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

#### ६. सिफारिशें

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी और पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी, नियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में यह जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटिट आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित है अतः प्राधिकारी सम्बद्ध देशों (कोरिया आरपी और थाईलैण्ड) से अधोलिखित वर्णित रूप और ढंग से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 36/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अनन्तिम शुल्क के अधिरोपण की अधिसूचना जारी होने की तारीख से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना आवश्यक समझते हैं और उसका अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोरामा पेट्रोकेम लिमिटेड, थाईलैंड और टीपीटी पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लिमिटेड, थाईलैंड संबद्ध कंपनियां हैं जो थाईलैंड में प्रचालन कर रही हैं और उन्होंने संबद्ध वस्तु का निर्यात भारत में अपने संबद्ध पक्षकारों अर्थात मैसर्स इण्डोरामा सिंथेटिक्स(इण्डिया) लिमिटेड को किया है। उनके संबंध को देखते हुए प्राधिकारी ने दोनों ही संबद्ध निर्यातकों के लिए भारित औसत आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है ताकि पाटनरोधी शुल्क के अंतिलंघन के दूर किया जा सके।

100. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने कि सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, सम्बद्ध देशों के मूल की अंथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर अनन्तिम शुल्क का अधिरोपण किए जाने की तारीख निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने की सिफारिश की जाती है।

#### शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई एमटी	मुद्रा यूरस डॉलर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	21973600	प्योरिफाइड ट्रैरेप्थैलिक एसिड	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	सैमसंग जनरल कैमिकल कंपनी लि.	सैमसंग सी एण्डटी	27.32	एमटी	यूरस डॉलर
2.	—वही—	—वही—	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	टैक्वांग इण्डस्ट्रियल कं. लि.	टैक्वांग इण्डस्ट्रियल कं. लि.	23.61	एमटी	यूरस डॉलर
3.	—वही—	—वही—	कोरिया आरपी	कोरिया आरपी	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 2 में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य संयोजन		78.28	एमटी	यूरस डॉलर
4.	—वही—	—वही—	कोरिया आरपी	जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है उनसे इतर कोई अन्य देश	कोई	कोई	78.28	एमटी	यूरस डॉलर
5.	—वही—	—वही—	जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है उनसे इतर कोई अन्य देश	कोरिया आरपी	कोई	कोई	78.28	एमटी	यूरस डॉलर
6.	—वही—	—वही—	थाईलैण्ड	थाईलैण्ड	इंडोरामा पेट्रोकेम लि.	इंडोरामा पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लि.	45.43	एमटी	यूरस डॉलर
7.	—वही—	—वही—	थाईलैण्ड	थाईलैण्ड	टीपीटी पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लि.	टीपीटी पेट्रोकैमिकल्स पब्लिक लि.	45.43	एमटी	यूरस डॉलर
8.	—वही—	—वही—	थाईलैण्ड	थाईलैण्ड	उपर्युक्त क्रम संख्या 6 से 7 में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य संयोजन		62.55	एमटी	यूरस डॉलर

क्रम सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तु विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई एमटी	मुद्रा यूएस डॉलर
9.	—वही—	—वही—	थाईलैण्ड	जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लाग है उनसे इतर कोई अन्य देश	कोई	कोई	62.55	एमटी	यूएस डॉलर
10.	—वही—	—वही—	जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है उनसे इतर कोई अन्य देश	थाईलैण्ड	कोई	कोई	62.55	एमटी	यूएस डॉलर

101. उपर्युक्त के अध्यधीन कोरिया आरपी और थाईलैण्ड के सम्बंध में दिनांक 19 जून, 2014 को समसंख्यक अधिसूचना के तहत अधिसूचित प्रारम्भिक जाँच परिणाम को एतदद्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

**द. आगे की प्रक्रिया**

102. इस संस्तुति से उत्पन्न केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत सीमाशुल्क, उत्पाद कर एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में, अपील दायर की जा सकती है।

जे के दादृ निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**Department of Commerce**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2015

**Final Findings**

**Subject :** Anti-dumping investigation concerning imports of 'Purified Terephthalic Acid' (PTA), originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Thailand.

**No.14/7/2013-DGAD:** - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

- Whereas M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd (MCPI), and M/s Reliance Industries Limited (RIL) (hereinafter also referred to as the applicants or domestic industry) jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules, for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Purified Terephthalic Acid (hereinafter also referred to as the subject goods or PTA), originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Thailand, alleging dumping and consequent injury and requested for levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the said countries.
- And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence, submitted by the applicant issued a public notice vide Notification No.14/7/2013-DGAD dated 8<sup>th</sup> October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the sub Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

4. And whereas, the Designated Authority having regard to the Act and the Rules, issued the preliminary findings vide Notification No.14/7/2013-DGAD dated 19<sup>th</sup> June 2014, recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the China PR, European Union, Korea RP and Thailand. Accordingly, the Central Government vide Notification No.36/2014-Customs dated 25<sup>th</sup> July, 2014 imposed provisional anti-dumping duties on imports of the subject goods, originating in or exported from the China PR, European Union, Korea RP and Thailand.

#### A. PROCEDURE

5. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- i. The Authority notified the Embassies/Representatives of China PR, European Union, Korea RP and Thailand in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
- ii. In addition to the provisions of Sub-Rule (5) of Rule 5 supra, the Government of Korea RP was informed through its Embassy in India about the receipt of the subject application as per provisions of Article 2.14 of Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and Korea RP.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 8<sup>th</sup> October, 2013 to the Embassies of China PR, European Union, Korea RP and Thailand in India, known producers/exporters from China PR, European Union, Korea RP and Thailand, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies/Representatives of China PR, European Union, Korea RP and Thailand in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- v. The Embassies/Representatives of China PR, European Union, Korea RP and Thailand in India were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from China PR, European Union, Korea RP and Thailand.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, European Union, Korea RP and Thailand in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - a. BP Zhuhai Chemical Co. Ltd, China PR
  - b. Xianglu Petrochemicals Co., Ltd, China PR
  - c. Jiaxing Petrochemical Co., Ltd., China PR
  - d. Zhejiang Yisheng Petrochemical Co., Ltd., China PR
  - e. Zhejiang Yuandong Petrochemical, China PR
  - f. Yisheng Dahua Petrochemical Co., Ltd. , China PR
  - g. Hengli Petrochemical, China PR
  - h. Jinan Shijitongda Chemical Co., Ltd., China PR
  - i. Samsung Total Petrochemical Company Ltd., Korea RP
  - j. Samsung Petrochemical Company Ltd., Korea RP
  - k. Hyosung Petrochemical, Korea RP
  - l. Hyosung Corporation, Korea RP
  - m. Taekwang Industrial Co., Ltd., Korea RP

n. Honam Petrochemical Corporation, Korea RP  
 o. Samyang Corporation, Korea RP  
 p. Samnam Petrochemical Co.,Ltd, Korea RP  
 q. SK Petrochemical, Korea RP  
 r. Lotte Chemical, Korea RP.  
 s. Indorama Petrochem Limited, Thailand  
 t. TPT Petrochemicals PCL.,Thailand  
 u. Siam Mitsui PTA Co., Ltd., Thailand  
 v. BP Chembel N.V., Belgium  
 w. Cepsa Quimica S.A, Spain  
 x. Lotte Chemical UK Ltd, United Kingdom  
 y. BP Chemicals Limited, United Kingdom  
 z. Artlant PTA, Portugal  
 aa. PKN Orlen SA, Poland

vii. The following producers/exporters from China PR, European Union, Korea RP and Thailand filed exporters questionnaire response in the prescribed format:

a. Indorama Petrochem Ltd., Thailand  
 b. TPT Petrochemicals Public Limited, Thailand  
 c. Samsung C&T Corporation, Korea RP  
 d. Samsung Petrochemical Co. Ltd., Korea RP now known as Samsung General Chemicals Co Ltd.  
 e. SK Petrochemical Inc, Korea RP (producer) along with Mitsubishi Corporation, Japan (exporter)  
 f. Taekwang Industrial Co Ltd, Korea RP  
 g. Hyosung Corporation, Korea RP  
 h. Zhejiang Yisheng Petrochemical Co., Ltd, China PR  
 i. Ningbo Hengyi Trading Co Limited, China PR

viii. The following producers/exporters from China filed Market Economy Treatment questionnaire response:

a. Zhejiang Yisheng Petrochemical Co. Ltd.  
 b. Ningbo Hengyi Trading Co. Ltd.  
 c. Yisheng Dahu Petrochemical Co. Ltd.  
 d. Hainan Yeshing Petrochemical Co. Ltd.

ix. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

a. Wellknown Polyester Ltd., Mumbai  
 b. JBF Industries Ltd., Mumbai  
 c. Alok Industries Ltd., Mumbai  
 d. Indo Rama Synthetics (India) Ltd., Gurgaon, Haryana  
 e. The Bombay Dyeing & Mfg. Compnay Ltd., Mumbai  
 f. Dhunseri Petrochem & Tea Ltd., Kolkata  
 g. Garden Silk Mills Ltd., Mumbai  
 h. Filatex India Ltd., New Delhi  
 i. Jindal Poly Films Ltd., New Delhi  
 j. Nakoda Ltd., Mumbai  
 k. Sumeet Industries Ltd., Surat  
 l. Raj Rayon Industries Ltd, Mumbai  
 m. Association of Synthetic Fiber Industry (ASFI), New Delhi.  
 n. PTA Users Association of India, New Delhi.

x. The following importers/users filed importer's questionnaire response in the prescribed format:

- Dhunseri Petrochem & Tea Ltd.
- Alok Industries Ltd.
- The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd.
- Jindal Poly Films Ltd.
- JBF Industries Ltd.
- Wellknown Polyesters Ltd.
- Indo-Rama Synthetics (India) Ltd.
- Sumeet Industries Ltd.

xi. Post-initiation, submissions have also been made by the domestic industry and the following other interested parties:

- Dhunseri Petrochem & Tea Limited
- Filatex India Ltd.
- Indo Rama Synthetics (India) Ltd.
- The Bombay Dyeing & Mfg Co Ltd.
- JBF Industries Ltd.
- Garden Silk Mills Ltd.
- Sumeet Industries Ltd.
- Alok Industries Ltd.
- Raj Rayon Industries Ltd.
- Jindal Polyfilms Ltd.
- Samsung Petrochemical Co., Ltd.
- Hyosung Corporation
- SK Petrochemical Co., Ltd.
- Taekwang Industrial Co., Ltd.
- Indorama Petrochem Ltd
- TPT Petrochemicals Public Limited Company.
- BP Chembel NV, EU
- BP Aromatics, EU.
- BP Zuhai Chemical Co Ltd, China PR
- Polyester Film industries Association
- PTA Users Association
- The Southern India Mill's Association (SIMA)
- Association of Synthetic Fibre Industry.
- Chemicals & Petrochemicals Manufacturers Association

xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xiii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI & S) to provide details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority has relied upon DGCI & S data in this final finding.

xiv. The petitioner had submitted the petition alleging dumping of the subject goods from China PR, European Union, Korea RP and Thailand relying upon imports data sourced from the DGCI & S. The Authority had relied upon the data provided by the petitioner while initiating the present investigation. Post initiation, the Authority also obtained transaction-wise imports data from the DGCI & S and issued the preliminary findings.

xv. Post preliminary findings, certain interested parties contended that export of subject goods from the European Union and China PR during the POI is less than 3% of the total imports of PTA into India and therefore, European Union and China PR should be excluded from the purview of the subject

countries. Consequently, the transaction wise DGCI & S data was reanalyzed and cross verified with the DG Systems data and it was noted that during POI the imports of the subject goods from European Union and China PR were found to be de minimis. In view of the above position and in terms of the provisions laid down under Rule 14 of Anti-dumping Rules, the Authority terminates the investigation in respect of imports of subject goods from China PR and European Union and continues the investigation in respect of the imports of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries).

- xvi. Without prejudice to the Authority's right to file SLP before the Hon'ble Supreme Court against the Judgment of the Hon'ble Delhi High Court dated 18.3.2015 in WP(C) No.744/2015 in the matter of San Disk International Ltd. Vs. The Designated Authority & Others, the non-confidential version of transaction-wise details of imports of the subject goods obtained from DGCI & S and relied upon in this final finding have been placed in the public file for inspection by the interested parties.
- xvii. The Non-injurious Price based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xviii. Information provided by the domestic industry and the cooperating producers/exporters were verified by the Authority to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding.
- xix. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is from 1<sup>st</sup> April 2012 to 31<sup>st</sup> March 2013 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 1<sup>st</sup> April 2009 to the end of the POI, i.e., 2009-10, 2010-11, 2011-12 and POI.
- xx. In accordance with Rule 6(6) of the Anti Dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all the known interested parties to present their views orally in a public hearing held on 19<sup>th</sup> November, 2014. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were advised to file written submission and rejoinder submission.
- xxi. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation and considered relevant have been examined and addressed by the Authority in this final finding.
- xxii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these disclosures on the basis of the facts available.
- xxiii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.
- xxiv. In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 28th March, 2015 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this final finding.

- xxv. \*\*\* in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxvi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$ = Rs. 54.65.
- xxvii. The Central Government in the Department of Revenue, Ministry of Finance extended the time limit for completion of the investigation and issue of final findings till 7<sup>th</sup> April, 2015 vide their Office Memorandum No. 354/95/2014-TRU dated 7<sup>th</sup> October, 2014.

#### **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

- 6. The Product under Consideration (PUC) in the present investigation is Purified Terephthalic Acid (PTA), including its variants - Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA). Purified Terephthalic Acid (PTA) is a white, free flowing crystalline powder, free from any visual contamination. Terephthalic Acid is an organic compound whose chemical formula is  $C_6H_4(COOH)_2$ . It sublimes at 402°C and is poorly soluble in water and alcohol. PTA is the primary raw material for the manufacturing of polyester chips which in turn is used in a number of applications in textiles, packaging, furnishings, consumer goods, resins and coatings. Since QTA, MTA and PTA are chemically the same product and further since they are interchangeably used, the scope of the product under consideration covers QTA and MTA as well. As claimed by the applicants, Di-Methyl Terephthalate (DMT) is chemically a different product and therefore not covered in the scope of the product under consideration. The product under consideration is classified under subheading 29173600 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.

#### **Submissions made by the Domestic Industry**

- 7. The submissions made by the domestic industry and considered relevant by the Authority with regard to product under consideration and like articles are as follows:

- i) The product under consideration in the present petition is Purified Terephthalic Acid, including its variants Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA) (hereinafter referred to as "the product under consideration" or "PTA"). PTA is a white, free-flowing crystalline powder free from any visual contamination. It is classified under subheading 29173600 of the Customs Tariff Act. Terephthalic acid is an organic compound whose chemical formula is  $C_6H_4(COOH)_2$ . It sublimes at 402°C and is poorly soluble in water and alcohols. PTA is a primary raw material in the manufacture of polyester chips which in turn has number of applications in textiles, packaging, furnishings, consumer goods, resins and coatings. MTA and QTA are chemically the same as PTA. The only difference between PTA, MTA and QTA is in the level of impurities present in the QTA and MTA. PTA, MTA & QTA are produced using the same production technology, plant & equipment, manufacturing process, raw materials. The three perform the same function. These fall under same customs classifications. The only difference in the three products is in the level of impurities. In fact, producer such as SK Chemical produces MTA, but literature states PTA.
- ii) Di-Methyl Terephthalate (DMT) is chemically different product than PTA. The production technology, manufacturing process, plant & equipment, raw materials, technical specifications of DMT and PTA are different. However, DMT and PTA are interchangeably used in some applications. However, DMT cannot replace/substitute PTA in all the applications. There is no production of DMT in India, nor there import of DMT in India. The present petition is for anti dumping duty on PTA (including its variants, MTA and QTA) and the petition has been filed by producers of PTA in India. DMT is in fact a product being phased out and PTA has substituted DMT. The product scope does not cover DMT, there being no imports into India and no production in India. Since QTA, MTA and PTA are chemically the same product and further

since they are interchangeably used, the scope of the product under consideration covers QTA and MTA as well.

**Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

8. No submissions have been made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article.

**Examination of the Authority**

9. The submissions made by the interested parties with regard to the scope of product under consideration and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- i. The product under consideration in the present investigation, as defined by the Authority in the initiation notification is Purified Terephthalic Acid (PTA), including its variants - Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) and Qualified Terephthalic Acid (QTA). The PUC is a white, free flowing crystalline powder, free from any visual contamination. Terephthalic Acid is an organic compound whose chemical formula is  $C_6H_4(COOH)_2$ . It sublimes at 402°C and is poorly soluble in water and alcohol. PTA is primary raw material in the manufacture of polyester chips which in turn is used in a number of applications in textile, packaging, furnishings, consumer goods, resins and coatings. Since QTA, MTA and PTA are chemically the same product and further since they are interchangeably used, the scope of the product under consideration covers QTA and MTA as well. The product under consideration is classified under subheading 29173600 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the present investigation.
- ii. As claimed by the applicants, Di-Methyl Terephthalate (DMT) is chemically a different product and therefore not covered in the scope of the product under consideration.
- iii. With regard to like article, Rule2(d) of the AD Rules provides as under: -

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

- iv. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The consumers importing the product under consideration have also purchased the same from the domestic industry. In view of the same, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as domestic like article to the product under consideration imported from subject countries in terms of the Rules.

**C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

**Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

10. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. IOCL, which is selling the subject goods at a price cheaper than the two applicant domestic producers and profitably operating its PTA plants at over 100% capacity utilization, has neither joined nor supported the petition. The present investigation should therefore be terminated forthwith.
- ii. MCC PTA India Corp. Private Limited (MCPI) is not qualified to be treated as part of the domestic industry under Rule 2(b), as by virtue of their share holdings, they are related to Mitsubishi Corporation, Japan, Mitsubishi Corporation India Pvt. Ltd., Marubeni Corporation, Japan, Samyang Corporation, Korea RP and Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. Korea RP.

- iii. MCC PTA India Corp. Private Limited (MCPI) is a 100% subsidiary of Mitsubishi Corporation, Japan (MC). Mitsubishi Corporation is engaged in exporting subject goods to India by procuring from the subject countries in the injury period. Mitsubishi Corporation India Pvt. Ltd. (MCPIL) imported these and sold them in India. Mitsubishi Corporation India Pvt. Ltd. (MCPIL) was also acting as a sales agent of MCC PTA India Corp. Private Limited (MCPI) in India.
- iv. Exporter (Mitsubishi Corporation-MC), importer (Mitsubishi Corporation India Pvt Ltd-MCPIL) and petitioner (MCC PTA India Corp. Private Limited-MCPI) are controlled by the Mitsubishi group and so MCPI is related to an exporter and importer of the subject goods.
- v. MC is a significant shareholder of MCC PTA India Corp. Private Limited (MCPI) and is forcing MCPI to appoint its wholly owned subsidiary, MCPIL, as its sales agent in order to earn profits.
- vi. Marubeni Corporation is a sale agent of MCPIL, shareholder of MCPIL and an importer of subject goods. A substantial quantity of the goods was imported/exported by Marubeni and MC. Therefore, MCPI is to be disqualified as domestic industry.
- vii. Sam Nam Petrochemical Co. Ltd., Korea is controlled by Mitsubishi Chemical Corporation, Japan (MCC) and Samyang Corporation, Korea as they together hold 80% of the shares of Sam Nam. MCC Japan is the largest shareholder (40%) in Sam Nam Petrochemical Co. Ltd and refers to it as a subsidiary. Therefore, MCC PTA India Corp. Private Limited (MCPI) and Samyang are related.
- viii. Mitsubishi Chemical Corporation holds 66% share in MCC PTA and 40% shares in Sam Nam Petrochemicals, Korea. The share held by MCC also signifies a significant control over MCC PTA and Sam Nam Petrochemical's operations and its executive decisions. Sam Nam Petrochemicals is one of the named exporters in the investigation, therefore, as per sub-clause (i)(b) of explanation to rule 2(b), the relationship between MCC PTA, MCC and Sam Nam Petrochemicals, Korea would clearly exclude MCC PTA from the definition of domestic industry.
- ix. Sam Nam Petrochemicals Co. Ltd is an exporter of the subject product from Korea RP. In Sam Nam, Mitsubishi Chemical Corporation, Japan and Samyang Corporation, Korea hold 40% share each, and the remaining 20% share is held by GS Caltex Korea. Since Mitsubishi Chemical Corporation, Japan is controlling both MCPL (domestic producer in India) and Sam Nam (exporter of the subject product from Korea RP), MCPL should be disqualified from being a constituent of the domestic industry.
- x. Mitsubishi Corporation, Japan and Marubeni Corporation, Japan, the related parties of MCC PTA India Corp. Private Limited, buy the subject product from Korea RP at low prices and export the same to India, creating a situation of positive injury margin for POI.
- xi. Mitsubishi Corporation, Japan and Samsung, Korea entered into a contract on 1<sup>st</sup> November, 2012 to purchase/sell 4000-5000 MT of PTA every month, all of which was destined to the Indian market. Thus, declaration made by MCC PTA India Corp. Private Limited that none of its related/affiliated companies have exported the subject goods to India, is false and misleading.
- xii. Imports from Malaysia have increased over the injury period. Reliance industries have acquired 100% stake in BP Chemicals (Malaysia) SdnBhd (BPCM). The raw material of PTA was sent by Reliance to Malaysia, converted to PTA and re-imported and sold in India.

**Submissions made by the Domestic industry**

11. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The fact that IOCL has not supported the present petition does not prevent the Authority from proceeding with the investigation. As per the AD Rules, the Designated Authority is only to examine whether (a) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (b) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. There is no legal requirement which prescribes that the Designated Authority should proceed with the initiation and investigations only if IOCL supports the present petition.
- ii. There is no basis for the argument that IOCL prices are cheaper than prices offered by constituents of the domestic industry. It is without basis that IOCL performance is not impacted by rising prices. IOCL prices are also governed by the import prices.
- iii. The shareholding pattern of MCC PTA Corp. India Pvt. Ltd (MCPI) is as given below:

SN	Shareholder	Shareholding
1	Mitsubishi Chemical Corp., Japan	66%
2	Mitsubishi Corporation	10%
3	Sojitz Corporation	8%
4	Marubeni Corporation	6%
5	Toyota Tsusho	5%
6	West Bengal Industrial Development Corp.	5%

- iv. One of the producers in Korea namely Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. is a joint venture company in Korea whose shareholding is given below:

SN	Shareholder	Shareholding
1	Samyang Corp, Korea	40%
2	G S Caltex, Korea	20%
3	Mitsubishi Chemical Corp., Japan	40%

- v. Mitsubishi Chemical Corporation, Japan holds 66% share in MCC PTA Corp. Pvt. Ltd. India and 40% share in M/s. Sam Nam Petrochemical Co. Ltd., Korea. Thus, MCC PTA Corp. Pvt. Ltd. India has no direct or indirect relationship with Samyang or GS Caltex. These are Korean companies.
- vi. Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. has \*\*\* Directors, out of whom \*\*\* each are nominated by \*\*\* and \*\*\*. One director is nominated by \*\*\*. Mitsubishi Chemical Corporation, Japan does not control Sam Nam Petrochemical Co. Ltd, Korea. The company, however, controls MCC PTA Corp. Pvt. Ltd. India. Mitsubishi Chemical Corporation is not in a position to give direction or otherwise control Sam Nam Petrochemical Co. Ltd., as it lacks majority shareholding.
- vii. Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. has sold \*\*\* MT PTA to one of the consumers in India during the period of investigation. Barring this, there is no export made by Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. to India over the injury period. Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. has given this material to \*\*\* as a trial product. \*\*\* is setting up a plant for production of \*\*\*MT per year \*\*\* (\*\*streams) in \*\*\* which is due for commercial production shortly. \*\*\*explored the possibility of buying PTA from Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. for this new plant. Therefore, the company purchased this material for testing the product produced by Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. Thus, this export by Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. was an exceptional transaction for technical consideration and not in the nature of regular exports by Sam Nam Petrochemical Co. Ltd.

viii. It is settled legal position that the Designated Authority has discretion under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. In any case, facts of the case clearly establish that both the petitioner companies should be considered eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

ix. There is no legal entity as Mitsubishi Group. Therefore, there is no question of any of the companies listed above being controlled by Mitsubishi Group. Further, MCPI is not controlled by Mitsubishi Corporation, nor MCPI controls Mitsubishi Corporation, nor MCPI and Mitsubishi Corporation are controlled by a third party. It cannot be said that MCPI and Mitsubishi Corporation are related party under the rules

x. As regards the arguments of opposing interested parties that Marubeni Corporation is a sale agent of MCPI, shareholder of MCPI and an importer of subject goods, the following Shareholding pattern of Marubeni is relevant for consideration:

Shareholding Pattern	
Financial Institutions	***%
Individual	***%
Domestic Entities	***%
Non-Domestic Entities	***%
Others	***%
Major Shareholders	
The Master Trust Bank of Japan Ltd.	***%
Japan Trustee Services Bank Ltd.	***%
Sompo Japan Insurance Inc.	***%
JP Morgan Chase Bank	***%
Japan Trustee Services Bank	***%
Meiji Yasuda Life Insurance Company	***%
Tokio Marine & Nichido Fire Ins. Co. Ltd.	***%
Mizuho Bank	***%
Barclays Securities Japan Ltd.	***%
Nippon Life Insurance Company	***%

xi. Thus, MCPI is not controlled by Marubeni Corporation, nor MCPI controls Marubeni Corporation, nor MCPI and Marubeni Corporation are controlled by a third party. It cannot be said that MCPI and Marubeni Corporation are related party under the rules.

xii. MCPI is not related to any importer or exporter of the product under consideration within the meaning of the Anti-dumping Rules as none of them directly or indirectly controls the other; neither MCPI nor exporters/importers are directly or indirectly controlled by a third person; nor MCPI & exporters/importers together directly or indirectly control a third person. Further, there are no grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.

xiii. With respect to the argument that Mitsubishi Corporation and Samsung entered into a contract on 1<sup>st</sup> November, 2012 to purchase/sell 4000-5000 MT of PTA every month, all of which was destined to the Indian market, Mitsubishi Corporation is not related to the MCPI and therefore none of the petitioners have any control over decisions of Mitsubishi Corporation to dump the product in India.

xiv. With respect to the argument that MCPI did not disclose its affiliation or explain why Mitsubishi Corporation exported substantially on a regular basis, MCPI is not related to the Mitsubishi Corporation and therefore it is not in a position to prevent Mitsubishi Corporation from selling the product in India.

xv. Imports from Malaysia are de-minimis and therefore, the issue of possible relationship of one of the petitioner company with one of the Malaysian producer becomes entirely irrelevant.

xvi. Petitioners have not imported the product under consideration in India from subject countries. They are not an importer of the product under consideration within the meaning of Rule 2(b). Petitioners are not related to an importer of the product under consideration in India. While MCC PTA Corp. Pvt. Ltd. India is not related to a producer/exporter in exporting countries, even if it is considered that the company is related to one of the producers in Korea i.e. M/s. Sam Nam Petrochemical Co. Ltd., M/s. Sam Nam Petrochemical Co. Ltd. is not a regular exporter of the product under consideration in Indian market. Therefore, both the petitioner companies should be considered eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

xvii. It is an established position of law that the Authority may, in its discretion, include a producer who is either related to the producer/exporter of the subject goods or imported the subject goods, within the scope of domestic industry. Therefore, even if it is considered that MCPI is related to the exporters of the product under consideration, the Designated Authority may exercise its discretion to consider MCPI as eligible domestic industry. The exports made by the company constitutes insignificant share in relation to total imports of the product under consideration, Indian production and consumption of the product under consideration in India. Therefore, in any case, these exports should not disentitle the company from being treated as domestic industry.

xviii. The argument that Mitsubishi Corporation Japan (MC) and Marubeni Corporation Japan are buying at low prices from Korea RP and exporting the same to Mitsubishi Corporation India Pvt Ltd and Marubeni India Pvt Ltd respectively, declaring a very low landed price, is baseless. Mitsubishi Corporation India Pvt Ltd and Marubeni India Pvt Ltd are not related to the domestic industry. Hence the domestic industry cannot be denied remedy due to any activities carried out by unrelated parties. It is also not established that export price to India is materially lower than the procurement price.

xix. On the one hand, PTA Users Association has pointed out at the non-participation of IOCL. On the other hand, the association has questioned why MCPI has participated as domestic industry, as RIL alone constitutes domestic industry. Any company who has suffered injury due to dumping of the product can approach Designated Authority for remedy.

xx. There is no legal basis to argue as to why MCPI is a part of domestic industry, unless positive evidence is shown to prove ineligibility of the company. MCPI's production alone constitutes a major share in Indian production and the Designated Authority may consider MCPI alone as the domestic industry under the Rules.

xxi. Petitioners constitute domestic industry under the Rules. Further, standing is governed by Rule 5(3) of AD Rules and the petitioners satisfy the same in the present case.

#### **Examination of the Authority**

12. The various submissions made by the interested parties with regard to the scope of domestic industry & standing and considered relevant by the Authority are examined as follows:

i) The Application has been filed by M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd (MCPI) and M/s Reliance Industries Limited (RIL) on behalf of the domestic industry. Apart from these two domestic producers, there is one more producer of PTA in India, namely Indian Oil Corporation Limited (IOCL). However, the said domestic producer of PTA has neither supported nor opposed the application. As per the information furnished in the application, the production of M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd and M/s Reliance Industries Limited accounts for more than 50% of Indian production of the like article. The applicants have declared that they have neither imported the product under consideration, nor any of their related parties in India have imported the product. It has been further declared that the applicants are not related to any of the importers of the subject goods in India or exporters of the subject goods from the subject countries. As per the Anti-dumping Rules, the Authority is required to examine whether (a) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (b) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. Thus, absence of support by IOCL is immaterial for the present investigation. The submissions made by the

opposing interested parties that IOCL is selling the subject goods at a price cheaper than the domestic industry and profitably operating its PTA plants at over 100% capacity utilization, have not been substantiated.

ii) As regards the submission of the interested parties that MCPI is not qualified to be treated as part of the domestic industry due to their relationship with exporters and/or importers, Authority notes that Rule 2(b) provides as follows

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”*

iii) On the basis of information available in the Wikipedia, the Authority notes that the Mitsubishi Group is a group of autonomous Japanese multinational companies covering a range of businesses which share the Mitsubishi brand, trademark, and legacy. Thus, question of relationship of MCPI with “Mitsubishi Group” directly or indirectly does not arise.

iv) Further, the Authority on the basis of information available in the website mitsubishi.com notes that "Mitsubishi" is a community that consists of a multitude of independent companies. The names of most - but not all - of those companies contain the word "Mitsubishi." And many of the companies use the three-diamond Mitsubishi mark. But none calls itself simply "Mitsubishi." Further, the same web based information states that such companies conduct their business activities independently and even compete with each other in many fields. But as they share the same founding management philosophy, they cooperate in areas of common interest, such as sporting, cultural events and public-interest activities. The companies established a Mitsubishi portal on the Internet, "mitsubishi.com", to provide a broad perspective on "Mitsubishi." But, as the said web based information conveys, such companies do not have a decision-making body that determines overall policy for the companies.

v) On the basis of the information furnished by the interested parties including domestic industry, Authority notes that the shareholding pattern of various parties with whom relationship of MCPI has been alleged are as follows –

a. Shareholding pattern of MCC PTA India Pvt. Ltd (MCPI):

Name	Shareholding (%)
Mitsubishi Chemical Corporation	66
Mitsubishi Corporation	10
Sojitz Corporation	8
Marubeni Corporation	6
Toyota Tsusho Corporation	5
West Bengal Industrial Development Corporation	5

b. Shareholding pattern of Mitsubishi Corporation India Pvt. Ltd:

Name	Shareholding (%)
Mitsubishi Corporation	100%

## c. Shareholding pattern of Mitsubishi Chemical Corporation:

Name	Shareholding (%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account)	***
Meiji Yasuda Life Insurance Company	***
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account)	***
Nippon Life Insurance Company	***
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	***
Takeda Pharmaceutical Company Limited	***
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.	***
The Bank of New York, Treaty JASDEC Account	***
Taiyo Life Insurance Company	***
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account )	***

## d. Shareholding pattern of Mitsubishi Corporation, Japan:

Name	Shareholding (%)
Financial Institutions	***
Foreign Companies	***
Individuals	***
Other Companies	***

## e. Shareholding pattern of Marubeni Corporation, Japan:

Shareholding Pattern	%
Financial Institutions	***
Individual	***
Domestic Entities	***
Non domestic entities	***
Others	***
Major Shareholders	
Name	Shareholding (%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	***
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	***
Sompo Japan Insurance Inc.	***
JP Morgan Chase Bank 380055	***
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)	***
Meiji Yasuda Life Insurance Company	***
Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Co., Ltd	***
Mizuho Bank, Ltd.	***
Barclays Securities Japan Ltd.	***
Nippon Life Insurance Company	***

f. Shareholding pattern of Sam Nam Petrochemical Co. Ltd, Korea RP.

SN	Shareholder	Shareholding
1	Samyang Corp, Korea	40%
2	G S Caltex, Korea	20%
3	Mitsubishi Chemical Corp., Japan	40%

vi) Authority further notes that related party under the Rules has been defined as follows –

- (i) *producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if,-*
  - a) *one of them directly or indirectly controls the other; or*
  - b) *both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or*
  - c) *together they directly or indirectly control a third person subject to the condition that are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.*
- (ii) *a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.*
- vii) Authority thus notes that two entities can be treated as related entities only if one of the above conditions is satisfied. The Authority notes that MCPI is related to Mitsubishi Chemical Corporation, Japan by virtue of the latter company holding majority share. However, Japan not being a subject country in the present investigation, such relationship has no relevance.
- viii) The Authority further notes that Sam Nam Petrochemical Co. Ltd, Korea, in which Mitsubishi Chemical Corporation, Japan is having significant share, has exported \*\*\* MT of subject goods to India during the POI. However, as submitted by the applicant, SamNam's export of subject goods to India during the POI is an exception and not a regular trading activity. Moreover, as stated by the applicant, the shareholding of Mitsubishi Chemical Corporation, Japan in SamNam Korea, cannot be considered as having controlling effect on the commercial activities of SamNam Korea without having majority representation in the board of directors.
- ix) The Authority notes that the exports made by SamNam Korea RP to India during the relevant period constitute merely \*\*\*% of the total imports from the subject countries and \*\*\*% of the total imports from Korea RP during the POI. Moreover, Korea RP is a subject country in the present investigation and the exports that may be made by SamNam Korea, despite being related party to the MCPI, will also be subjected to the anti-dumping measures. Therefore, no undue benefit will accrue to MCPI out of such relationship in case definitive anti-dumping measures are imposed.
- x) The Authority notes that Marubeni Corporation has insignificant shareholding in MCPI. Marubeni Corporation has a wholly owned subsidiary in India namely Marubeni India Pvt Ltd who have imported the product under consideration to India. However, the insignificant shareholding held by Marubeni Corporation in MCPI cannot be construed as having any material effect in the decision making process of MCPI.
- xi) As regards the contention that Mitsubishi Corporation, Japan and Marubeni Corporation, Japan are buying subject goods from Korea RP and selling in India through their related entities at low prices, the Authority notes that first of all these contentions are unsubstantiated. Moreover, Japan is a non-subject country in the present investigation.
- xii) As regards the contention that Mitsubishi Corporation, Japan and Samsung, Korea entered into a contract to purchase/sell 4000-5000 MT of PTA every month, all of which was destined to the Indian market, the Authority notes that the said contract, if any, is between two independent entities and such commercial arrangement has nothing to do with the status of the domestic industry in the present investigation.

xiii) As regards the contention that Reliance is engaged in converting raw material in its acquired Malaysian plant i.e. BP Chemicals (Malaysia) SdnBhd (BPCM) and re-importing the same to India, the Authority notes that Malaysia is not a subject country in the present investigation and therefore such imports have no relevance. Moreover, imports from Malaysia are de-minimis.

13. In view of the above position, the Authority notes that there is no justification for treating MCPI as an ineligible domestic industry. There are no grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship of MCPI with an exporter or importer was such as to cause the company to behave differently from non-related producers. Principal business of MCPI is production and not import/trading. Moreover, had there been any undue benefit accruing to MCPI out of any such relationship then Reliance Industry Ltd, who is the joint applicant, would not have opted to collaborate with MCPI in the present investigation. In view of the above, the Authority considers M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd as an eligible domestic producer constituting domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.

14. After detailed examination the Authority holds that M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd and M/s Reliance Industries Ltd account for a major proportion of the total domestic production of the subject goods during the POI and constitute domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti- dumping Rules.

#### **D. CONFIDENTIALITY**

##### **Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

15. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The Applicants have claimed excessive confidentiality, especially for information pertaining to the details of directors of Sam Nam. The claim of confidentiality by the Applicants for the details of the directors of Sam Nam is excessive and required to be struck down.
- ii. Authority has also allowed excessive confidentiality especially with reference to price related information, inventory etc.
- iii. Transaction-wise import data has also not been made available in the public file.

##### **Submissions made by the Domestic industry**

16. The submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The petitioner has claimed only such information as confidential, confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
- ii. The petitioner has provided sufficient non confidential version of the application. No interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.
- iii. With respect to the claim of confidentiality for the directors of Sam Nam, the fact that there is no control does not mean that the relevant information can be disclosed.
- iv. Information such as gross volume of exports to India, gross volume of sales in domestic market, production, sales, average price for exports to India have been claimed confidential by the respondent exporters. Indeed nothing is commercially sensitive in this information.
- v. Most of the exporters have not even provided indexed information even when information is capable of being summarized in an indexed form.

- vi. The interested parties have resorted to excessive confidentiality in the questionnaire response filed by them.
- vii. The non-confidential transaction-wise DGCI&S import data furnished to the Authority can be placed in the public file.

## **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

17. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- i. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

*Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that there is a quest for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

- ii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
- iii. Without prejudice to the Authority's right to file SLP before the Hon'ble Supreme Court against the Judgment of the Hon'ble Delhi High Court dated 18.3.2015 in WP(C) No.744/2015 in the matter of San Disk International Ltd. Vs The Designated Authority & Others, the non-confidential version of transaction-wise details of imports of the subject goods obtained from DGCI & S and relied upon in this final finding have been placed in the public file for inspection by the interested parties.

## **E. MISCELLANEOUS SUB MISSIONS**

### **Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

18. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to miscellaneous issues during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The initiation of subject investigation and the preliminary findings are bad in law due to grave deficiencies in the eligibility of the applicants, absence of price or profit injury to the applicants and the lack of a causal link between the subject imports and injury.

- ii. In the preliminary findings DGAD did not examine whether provisional duty is required to prevent injury during the course of the investigation. Without such a determination, DGAD should not have recommended imposition of provisional anti-dumping duty.
- iii. There is a huge demand supply gap in India. As against the total demand of 2179204 MT, domestic producers could supply only 1531245 MT. The entire PTA produced in the country is absorbed by the user industry, and only the shortfall in supply is met through imports. Since import of PTA is inevitable, imposition of anti-dumping duty is unwarranted.
- iv. PTA is the basic raw material for Polyester Filament, Staple Fibre, Polyester Film, etc which in turn are used in textiles, packing materials and PET Bottles. Imposition of Anti Dumping Duty on imports of PTA will lead to increase in the prices of PTA in the domestic market and also have adverse effect on the cost of production and marketability of downstream products. Imposition of anti-dumping duty on PTA would curb the production and export of downstream products and cause unemployment. After anti-dumping duty has been imposed, the whole textile industry is suffering due to more imports, less capacity utilisation and more unemployment.
- v. Imposition of antidumping duty on PTA and no antidumping duty on the final products would encourage the domestic buyers to import the final products instead of buying the same from India. As a result, it will not only drain the much required foreign exchange, but also the domestic producers of these import substitutable final products will suffer.
- vi. Since imports of Paraxylene are allowed at zero customs duty, no further protection should be provided to the PTA manufacturers in India. Otherwise, imposition of ADD on PTA would create an inverted duty structure in polyester sector. After imposition of ADD on PTA, the duty has gone up to 10% to 16% whereas the end products attract only 5% import duty. Due to such inverted duty structure, domestic textile industry has suffered in terms of more imports, increased costs of domestic produce, less capacity utilisation and unemployment.
- vii. After Anti-dumping Duty has been imposed on PTA, the capacity utilization of down-stream industries has come down by 10% due to increase of import of Polyester Staple fibre (PSF), Polyester Filament Yarns( PFY) and Polyester Chips and textiles exports from India has decreased.
- viii. RIL is an integrated refinery and chemical company producing PTA from crude oils. The imposition of anti-dumping duty would disadvantage other PET manufacturers and not RIL which has a captive PTA manufacturing facility.
- ix. However, MCCPI is producing PTA from purchased PX. In addition, PX price was significantly high due to supply shortage but PTA price hit the bottom. Accordingly, there should be significant cost difference between RIL and MCCPI and simple cumulation of COP will distort the result of price suppression analysis.
- x. The petitioners stated during the course of oral hearing that the imports of PTA increased after the initiation of the investigation particularly in April – June 2014. It is submitted that PTA users had no option but to increase imports to meet their requirement due to inability of domestic producers to supply. Further, IOCL's plant was completely shut down due to major breakdown for 45 days or more.
- xi. If the Applicants are claiming losses on sale of PTA, then the DGAD may seek information from the jurisdictional Central Excise Commissionerate regarding such losses which may have been reported by the applicants to them. But, the same does not seem to have been done. The non-consideration of this submission has violated the principles of natural justice.

xii. With the imposition of provisional anti-dumping duty on PTA, all the domestic producers, except RIL, have increased the price of PTA. The downstream polyester industry has been severely and unjustly impacted as the raw material cost (both domestic and imports) has increased by the amount of anti-dumping duty for all polyester producers except RIL. Thus, the imposition of anti-dumping duty to protect the alleged injury to PTA manufacturers has resulted in grave injury to the downstream polyester industry.

xiii. RIL enjoys preeminent position in domestic fibre intermediate market with 51% share in PTA market. RIL enjoys a dominant position in the downstream products as well. They also have embarked upon capacity expansion in PTA production. Imposition of ADD on imports of PTA will give RIL a monopolistic position in PTA and downstream products. Reliance has increased the PTA prices but not the prices of downstream products and thus engaged in predatory pricing.

xiv. The demand of subject product, fresh PTA, would have increased at a faster pace if certain users of PTA had not shifted to the use of recyclable material, such as PET bottles, which is a substitute for fresh PTA. Designated Authority is required to analyse how the demand may have grown if certain users of PTA had not shifted to the use of recyclable material.

xv. Subsequent to the imposition of provisional anti-dumping duty, imports of Polyester Filament Yarn (PFY) and Polyester Staple Fiber (PSF) have started increasing and cost of raw material for them increase, therefore, the user industry which was already working on suboptimal capacity of around 65% to 70% has further cut down their capacities by 10% in both Polyester Filament Yarn & Staple Fiber. Such reduction in capacity utilisation reduced the off take of PTA, which may have resulted in inventory, though not so admitted by the Respondents.

xvi. Analysis of post-POI data for determination of injury is completely unwarranted in the present investigation.

xvii. Merely because China has imposed anti-dumping duties on the imports of PTA from Korea and Thailand, it does not mean that exports are being shifted to India. The imposition of anti-dumping duty by another country cannot substitute the investigation which is to be undertaken by the DA. Mere existence of surplus capacities in these countries does not mean that the subject product would be dumped into other countries.

xviii. Retrospective imposition of anti-dumping duty is not sustainable under the law as the Designated Authority has already issued the PF. There is no history of dumping on the part of the exporters of the subject product, nor are the users aware of any dumping by the exporter concerned. The Applicant Domestic Industry is suffering injury due to its own intrinsic problems and not due to imports of the subject product. Praying for imposition of Anti-dumping Duty on the subject product with retrospective effect is only a tactic resorted by the Applicant Domestic Industry to mislead the Designated Authority and enjoy undue gain out of this.

xix. The Designated Authority is required to provide to the interested parties the basis on which raw imports data from DGCI&S is sought, the methodology followed to refine the transaction wise import data; the refined import data and its summary for the meaningful analysis and submission on such import data. The DA is requested to make available the information relied upon. The Authority is also requested to grant a hearing after the requested information is made available.

xx. The DA is requested to disclose the basis and evidences used to make adjustments in assessable value to reach the ex-factory export price for non-cooperating exporters.

xxi. The DA may also disclose all essential facts in the disclosure statement and grant an opportunity of hearing thereafter.

#### **Submissions made by the Domestic industry**

19. The miscellaneous submissions made by the domestic industry during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. None of the responding exporters have fully replied to the question with regard to valuation of Paraxylene. Further, only Samsung Petrochemicals and SK Petrochemicals have affiliated companies who are producing Paraxylene and supplying to these companies.
- ii. Questionnaire responses are grossly deficient; the authority should reject the same at least for the purpose of preliminary findings.
- iii. Questionnaire responses by the exporters does not make it clear how the producer concerned has produced and supplied the goods to a trading company who has eventually supplied the goods to India.
- iv. With respect to the argument that PX supply shortage and low capacity utilisation of its downstream industry will give RIL an advantage, the purpose of anti-dumping duties is to allow healthy competition.
- v. The contention that initiation of investigation is bad in law due to lack of standing of the Applicants and also absence of injury and a causal link, is baseless. The applicants have standing under the rules. The petition contains sufficient evidence of dumping causing injury to the domestic industry to justify initiation of investigations.
- vi. The entire current market situation is because of significant unutilized capacities in subject countries and significant capacity additions in China. With the massive fresh capacity additions in China in last 2-3 years, the current demand/consumption of PTA globally is far less than the current global capacities, thus resulting in significant surplus capacities with the producers in Korea and Thailand. The Korean and Thai producers have capacities for PTA production far in excess of their domestic market demand. The surplus production was earlier being exported largely to China. However, imposition of anti-dumping duty by China on one hand and massive capacity additions in China on the other hand have led to significant loss of market for the Korean and Thai producers. Faced with significant market loss, the producers in these countries are now looking for other market opportunities to utilize their capacities.
- vii. The movements in the prices of PTA closely follow those in the cost of the major raw material, para-xylene. The price difference between PX and PTA (known as “delta” in the business) should at the least be US\$ 150 per MT as the bare minimum. However, global producers have been experiencing shrinking margins of PX and PTA and consequently, PTA producers globally are suffering huge financial losses.
- viii. The Indian industry is in the process of enhancing capacities in view of the demand-supply gap in the Country. This involved significant capital expenditure by the company.
- ix. Petitioners are not against imports per se. In a situation where the imports are inevitable, it wouldn't be prudent for any business entity to aggressively sell at cheap price, when it is a very well known fact that the goods can be sold at reasonable prices in the market as the demand is more than the capacity with the domestic producers.

- x. Thus, when the imports are inevitable; there is no reason for the foreign producers to depress the prices for the product in the Indian market, that too discriminately for the Indian market. The only plausible explanation is the surplus capacities with the foreign producers. The surplus unutilized capacities with the foreign producers are forcing them to sell their product aggressively in the Indian market. China has imposed anti-dumping duties on imports of PTA from Korea and Thailand. As a result, exporters from Korea and Thailand have started diverting exports of PTA to the Indian market. During the last two years, the domestic industry has suffered losses to the extent of Rs. 5 Crore per day.
- xi. After imposition of the provisional ADD, PTA user industry is maliciously misrepresenting the facts about the impact of the ADD on the downstream industries. The exports of manmade fibre and textiles have gone up contrary to the contention of the opposite interested parties.
- xii. There has been a continuous fall in the prices of filament yarn which has helped in growth of manmade fabrics production and exports. PSF is also sold at very low prices in India. It is therefore wrong to say that ADD on PTA has affected the industries manufacturing yarn and fabric. Instead, the surge in imports of PSF and PFY from China PR is affecting the Indian downstream industries of manmade fibre. In order to stop China from ruining the PSF and PFY Industry, the Customs Duty on these products should be increased from 5% to 10%.
- xiii. Since the imposition of anti dumping duties the price of PTA and other raw material are falling. The prices of downstream fibre, yarn or fabric are not affected by imposition of anti dumping duties. In fact the Indian domestic PTA and MEG prices, the basic raw materials for polyesters, have moved in tandem with the international prices, unaffected by the ADD.
- xiv. Polyester filament yarn is 3/4th of the total polyester consumed in the country by downstream yarn and weaving industry and Indian Producers are selling Filament yarn at below the landed prices of china with negative EBITDA.
- xv. The imports of manmade fibre from china is impacting the downstream yarn and fabric industry as India impose duty on these tariff lines while China impose 18% custom duty.
- xvi. The PTA user association is misrepresenting the facts that imposition of anti dumping duties has affected thousands of downstream yarn and fibre units. Polyester fibre is used only in 30-35 spinning mills for making polyester Yarn. There are 105 spinning mills in India using polyester to blend with other fibres in making Polyester Cotton and polyester Viscose yarn. Therefore only 150 downstream mills are using polyester.
- xvii. There are around 300 mills located in India producing polyester fabric in fragmented section. These mills are affected by cheaper imports from china. Thus claim of PTA user association to mention thousands of downstream units is incorrect.
- xviii. There is massive dumping in a relatively short period and injury to the domestic industry is aggravating. Designated Authority should consider retrospective imposition of anti dumping duty.
- xix. The opposing interested parties argued that since all polyester producers purchase PTA at international market prices, imposing anti-dumping duty will create a price disadvantage to the Indian polyester industry. The argument is without any basis and irrelevant for the present purpose. The significance and purpose of anti-dumping duty is to provide a level-playing field to the domestic industry by preventing dumping, while allowing for healthy competition. If PTA is purchased at international market price and still is at dumped levels, it would mean that the foreign producers are dumping the product. If such dumping is causing injury, anti dumping duty is required to be imposed.

xx. In fact, while developed economies such as USA and developing countries such as China are imposing anti dumping duty upto the margin of dumping, the Indian law restricts it to injury margin and India has now invented the least duty rule by introducing the concept of NIP. In fact, while both major countries, Korea and Thailand Govt. considers that dumping should be condemned by imposing anti dumping duty upto the margin of dumping, the exporters wish that the Govt. of India does not impose anti dumping duty even upto the margin of injury!

xxi. Further, it is not established how imposition of anti dumping duty will create a price disadvantage to the Indian polyester industry. Since the anti-dumping duties are imposed on non-discriminatory basis, it would have no discriminatory impact on any particular producer of polyester. As far as competitiveness of Indian polyester producers in global market is concerned, anti-dumping duty in any case will not apply for imports under duty exemption Scheme.

xxii. The contention that Designated Authority should carry out individual as well as combined examination of applicants has no legal basis. There is no legal requirement for such analysis either in AD Act or Rules or no such practice is adopted by the Designated Authority or any investigation authorities in other countries.

xxiii. The fact that there is absence of control does not imply that there is no sensitivity in the information. For instance, a person/party holding 5% shareholding in a company is not clearly able to control the company. It, however, does not imply that the person cannot seek some information from the company concerned which is otherwise not public domain information.

xxiv. It has been argued by the opposing interested parties that Designated Authority has violated Article 7 of WTO ADA as he has not examined the issue whether provisional duty is required to prevent injury during the course of the investigation; the petitioners submit that the preliminary findings at para 105 clearly demonstrate need for imposition of provisional duty.

xxv. It has been argued by the opposing interested parties that imposition of anti-dumping duty will result in an unduly high burden on the Indian users and various downstream industries which depend on the subject product as a raw material. They have further argued that imports of PSF and PFY have increased by approx 80%-130% in last 6 months. In this regard, the domestic industry submits that it has been amply demonstrated that injury has been caused by dumping of the product under consideration from subject countries. The Indian manufacturers of product under consideration cannot be allowed to suffer because of some apprehensions of the interested parties without any document corroborating their claims. Further, the association has extensively contended that the injury margin in the present case is quite low. Such being the case, petitioners fail to understand and appreciate how the anti dumping duty would cause unduly high burden. In fact, anti dumping duty has taken away unfair advantages gained by the consumers due to access to dumped imports. However, the consumers cannot demand access to material at dumped prices particularly when the same is causing injury to the domestic industry.

xxvi. It has been argued by opposing interested parties that the entire product of PTA in India is absorbed and only the shortfall in supply is met through imports. They have further argued that due to the imposition of ADD the importers are forced to increase the cost in a market where there is already a shortage of PTA. The petitioners submit that they had inventory close to \*\*\* MT in October, 2014. In a situation when the domestic industry is unable to dispose off their inventories, the statement of the importers that they are importing because of non-availability of the material in India does not hold good and is factually incorrect. The fact that the consumption in India is higher than the capacities with the Indian producers may justify imports per se. The same however does not justify dumping. There is no reason/occasion for the foreign suppliers to resort to dumping to meet Indian demand.

xxvii. As regards the contention that there is significant demand supply gap and even if the domestic industry work at 100% capacity utilization, it cannot meet the demand. Imports are inevitable, domestic industry submits that if the foreign producers wish to meet the requirements of Indian customers for the product under consideration, they can very well do so by selling the product at fair prices and not at dumped prices. Dumping does not justify meeting the requirement of the domestic industry.

xxviii. The imports from China and Europe are not de-minimis. It is possible that some material was exported by exporters in Korea, Thailand or some other countries to China and Europe and the material was however not cleared in China and Europe and the same was transshipped to India. In such a situation, these imports should be considered as Chinese or European imports.

xxix. Even if the volume of imports from China and European Union in the POI is considered as de-minimis, the same does not imply that the investigation must be terminated in respect of China as well as European Union. In such a situation, Rule 14 provides consideration of both actual and potential imports. If actual import is de-minimis, the Authority should consider potential import.

### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

20. Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined as follows:

- i. The contention of the opposing interested parties that the initiation of investigation is bad in law due to lack of standing of the Applicants and also absence of injury and causal link is without any basis. The present final finding is self explanatory in this regard.
- ii. As regards the argument by the opposing interested parties that Authority has not examined the issue whether provisional duty is required to prevent injury during the course of the investigation, the Authority notes that the preliminary findings at para 105 establishes the need for imposition of provisional duty.
- iii. As regards the contention that there is huge demand supply gap in India and since import of PTA is inevitable, imposition of anti-dumping duty is unwarranted, the Authority notes that there is no legal provision mandating the domestic industry to meet the entire demand in the country. Further, given a situation of fair play, the domestic industry would be in position to meet the entire demand in the country within its capacity. Moreover, the domestic industry is in the process of expanding its capacity commensurate with the demand in India. Once that is achieved and fair play is ensured through imposition of anti-dumping duty, the domestic industry would be in a position to meet the entire domestic demand.
- iv. As regards the contention that PTA is the basic raw material for many downstream products and imposition of anti-dumping duty on imports of PTA will escalate the cost of production of such products, having adverse effect on their marketability and viability, the Authority notes that the object of imposing anti-dumping measure to is to rectify unfair trade practices and to redress its injurious effect by providing level playing field to domestic industry. The concern of the opposing interested parties that imposition of anti-dumping duty on the imports of PTA would adversely affect production of downstream industries is farfetched and premature. The imposition of provisional ADD ranging from 2% to 11% may have a cost push effect of about 2 – 3% on the cost of production of PFY and PSF. Thus, considering the quantum of the provisional antidumping duties imposed, the impact on the cost of production of the products of the downstream industries is not much. The end users of PTA, who have been benefitting out of dumping, would now have to pay for the raw materials at undumped/fair prices. Moreover imposition of anti-dumping measures does not prevent imports.

- v. As regards the contention that imposition of antidumping duty on PTA and no antidumping duty on the final products would lead the domestic buyers to import the final products and consequently drain the foreign exchange reserves of the country, the Authority notes that the objective of imposing anti-dumping measures is to create a level playing field for the domestic industry against the unfair trade practices of dumping.
- vi. As regards the contention that since import of Paraxylene, the main raw material for PTA, is allowed at zero customs duty, no further protection should be provided to the PTA manufacturers in India, the Authority notes that imposition of anti-dumping duties are intended to protect domestic industry against dumping. Factoring duty free raw materials, if any, has no relevance in the determination of anti-dumping measures.
- vii. As regards the contention that imposition of ADD on PTA would create an inverted duty structure, the Authority notes that the Basic Customs Duty (BCD) on PTA as well as downstream products is the same i.e. 5% before as well as after the imposition of AD duty on PTA. Since imposition of ADD is to offset the unfair advantage gained by the importers of PTA, it cannot be considered as part of BCD. Therefore, the contention of opposing interested parties that imposition of ADD on PTA would create an inverted duty structure is not correct.
- viii. The contention that imposition of anti-dumping duty would disadvantage other PET manufacturers and not RIL which has a captive PTA manufacturing facility, the Authority notes that the final finding concerning injury to the domestic industry on account of dumping of the subject goods from the subject countries is self explanatory. However, it is obvious that the industries having backward integration will have certain cost advantage vis-a-vis others not having such facilities. The Authority further notes that injury to the domestic industry is required to be analysed for domestic industry as a whole and not in a segmental manner.
- ix. As regards the contention that DGAD may seek information from the jurisdictional Central Excise Commissionerate regarding losses claimed by domestic industry on sales of PTA, the Authority notes that the injury analysis has been done on the basis of verified data.
- x. As regards the contention that imposition of anti-dumping duty on imports of PTA would give RIL a monopolistic position and enable RIL to engage in predatory pricing to the detriment of other similar producers, the Authority notes that such a situation is hypothetical. Imposition of anti-dumping duty does not bar imports. The objective of imposing anti-dumping measures is to create a level playing field for the domestic industry against the unfair trade practices of dumping. However, in the event of such a situation, the affected parties can approach the Competition Commission.
- xi. The Authority further notes that the argument that imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods would accrue undue advantage to domestic Industry is presumptuous. Anti-dumping investigations are based on facts and the law mandates analysis and assessment of magnitude of dumping and consequent injurious effect on the domestic industry. The Authority further notes that the antidumping rules provide for imposition of suitable and adequate anti-dumping measure to provide a fair and level playing field to the domestic industry vis-à-vis dumping.
- xii. As regards the contention that the demand of PTA would have increased at a faster pace if certain users of PTA had not shifted to the use of recyclable material, such as PET bottles, the Authority notes that the contention has no relevance to the determination of dumping, injury and causal link.
- xiii. The contention of the opposing interested parties that imposition of anti-dumping duty on the imports of PTA has resulted in more imports, less capacity utilisation and more unemployment in textile sector, the Authority notes that the opposing interested parties have not furnished any substantiated evidence to support their contention that the textile industry has been affected only due to imposition of antidumping duty on PTA.

xiv. The contention of the opposing interested parties that mere existence of surplus capacities in subject countries does not mean that the subject product would be dumped into other countries, the Authority notes that facts and analysis of the instant investigation in this final finding is self-explanatory. The favourable market situation in India coupled with global surplus production is a major attraction for the producers of PTA in the subject countries suffering from surplus capacities.

xv. As regards the contention of the opposite interested parties that the DA is required to make available the transaction-wise imports data obtained from the DGCI&S including the refined data and its summary, the Authority notes that without prejudice to the rights of Designated Authority to file SLP before the Hon'ble Supreme Court challenging the judgment dated 18.03.2015 of the Hon'ble High Court of Delhi pronounced in the matter of SanDisk International vs. Designated Authority, the Authority has placed the non-confidential version of the transaction-wise DGCI&S import statistics of subject goods in the public file. As regards the contention of the opposite interested parties to have access to the refined data and its summary, the Authority notes that the interested parties can examine the DGCI&S import data placed by the Designated Authority in the public file and file necessary submissions.

xvi. As regards the contention of the opposite interested parties that hearings should be granted by the Authority at the stage of providing transaction-wise imports data as well as post-disclosure, the Authority notes that an opportunity of oral hearing has already been provided to the interested parties on 19th November, 2014 and the written submissions including rejoinders made by the interested parties post oral hearing as well as the submissions made during the course of this investigation by the interested parties, including submissions made post-disclosure statement, and considered relevant have been examined and addressed in this final finding.

xvii. The domestic industry has argued that the imports from China PR and European Union (EU) are not de-minimis as per the import data obtained by them from the DGCI&S. In this regard, the Authority notes that at the time of issuing the preliminary finding the transaction-wise imports data obtained by the Authority from DGCI&S was relied upon. While analysing the said data at the stage of preliminary finding, the Authority had considered the country code given in the DGCI&S data under the field name “cntry\_org” as Country of Origin and accordingly determined the volume of imports during POI for the subject countries. Accordingly, the volume of imports from China PR and EU during POI was determined as 22160 MT and 27896 MT respectively, which was considered to be above de minimis level.

Subsequent to the issue of the preliminary finding, some of the interested parties argued that the volume of imports from China PR and EU was below de-minimis as per the import data available in the website of the Department of Commerce. The Authority, therefore, sought clarifications from DGCI&S about the mismatch in the data provided by them to the domestic industry as well as the data hosted on the website of Department of Commerce.

The DGCI&S has informed on 26<sup>th</sup> March, 2015 that the transaction wise import data provided to the domestic industry during July, 2013 was provisional in nature as at that point of time, the complete data for 2012-13 was not available. DGCI&S further informed that due to some software glitches, the country of consignment, IEC No., etc., had been erroneously posted for some of the bills of entries and the same were rectified subsequently. As a result, there were major changes in the country-wise distribution of commodities imported in the year 2011-12 and 2012-13. Thereafter, the revised data was hosted on the website of Department of Commerce.

Further clarification was sought from DGCI&S on 26<sup>th</sup> March, 2015 on the exact reasons why there was discrepancy in the November 2103 data of 2012-13, and the recent clarification of DGCI&S as stated above.

DGCI&S, vide their communication dated 27.3.2015 informed that the country codes appearing under the field name (cntry\_org) contains unvalidated data and does not represent Country of Origin. It has further informed that the data appearing under the field name “cntry\_code” provides validated data

which should be used for generating country-wise imports. The clarification given by DGCI&S in this regard is as follows:

*"It seems while generating the data relating to total imports from China and EU, DGAD had considered the country codes appearing under the field name "cntry\_org". Since this field contains un-validated data, the data appearing under the field name "cntry\_code" (which provides the validated country codes) was to be used for generating the country-wise totals. The variation (discrepancy) in the 2 sets of figures is only because of selecting the un-validated field (cntry\_org) in place of the validated field (cntry\_code). Had the appropriate field (cntry\_code) been selected there would not have been any variation (discrepancy) in the total quantity numbers for China and EU as forwarded in November 2013 and clarified in March 2015.*

*It may also be mentioned that DGCI&S does not receive any data from Customs relating to imports by country of origin. This was also clarified in the mail dated 18.03.15 from DGCI&S.*

*The reasons for discrepancy between the data provided to the domestic industry in July 2013 and that provided to DGAD had been briefly indicated in our mail dated 26.03.15. We may further clarify that the EDI data received from ICEGATE (Customs) comes in two parts. For each Bill of Entry (for import) there is a master record containing information like Country of consignment, IEC (importer exporter code), gross weight etc., and one or more item records containing information on item imported, quantity, value etc.*

*At the first stage of processing the item and master records are merged. If for one BE (Bill of Entry) there are 4 item records and one master record there will be four merged records with the master information repeated in all the four.*

*For this merging process, the item and master records are matched by the BE no. and BE date. The BE no., which were of 6-digits earlier increased to 7-digits. Since the DGCIS database had provisions for 6-digit BE number, the 7-digit nos. got truncated by 1-digit resulting in the same BE no. for two or more otherwise distinct 7-digit BE nos. For example two BEs with no. 1234567 and 1234568 got truncated to the same BE no. 123456. This affected the matching process and the master information which contains country of consignment code, IEC code, gross weight etc. had been erroneously posted for those BEs in which the first 6-digits are the same (as in the example above).*

*Since there was no provision in the software for generation of error message on account of such exceptions, it took quite some time for DGCIS to locate the errors. However the software was rectified as soon as the error was detected. As a result import data for 2011-12 and 2012-13 had been revised as far as master information is concerned. This affected the country wise numbers.*

*The data that was forwarded to DGAD in November 2013 was generated from the revised dataset."*

Therefore, in the interest of justice, fair play and correct analysis, it is incumbent upon the Authority to amend the volume of imports from China PR and EU as mentioned in the preliminary findings and reflect the correct position in the final findings. A mistake apparent on record has to be corrected in the interest of justice. The Authority, therefore, concludes that the volume of imports from China PR and EU considered in this final finding, is below de minimis level.

xviii. The domestic industry has argued that even if volume of imports from China in the POI is considered as de-minimis, the Authority shall not terminate the investigation and rather should consider the potential imports. In this regard, the Authority notes that the potential position is a subject of review investigations to analyse and establish the likelihood of dumping and injury and not for fresh Anti-dumping investigations. As per Annexure II of the Anti-dumping rules, while determining the injury in a fresh anti-dumping investigation, the Designated Authority is required to conduct an objective analysis of the volume of imports of subject goods from the subject country during the POI and their impact on the domestic industry to examine causal link. Rule 14 of the Anti-dumping Rules inter alia provides that the investigation shall be terminated if the volume of dumped imports, actual or potential,

from a particular country accounts for less than 3% of the imports of the like product. The reading of the Rules makes it clear that the investigation should be terminated when either the actual imports or the potential imports account for less than 3% of total imports and therefore the argument of the domestic industry that when the actual dumped imports are de minimis, the potential imports should also be considered before taking a decision for terminating the investigation is not correct. Further, the arguments of the domestic industry that it is possible that some material was exported by exporters in Korea, Thailand or some other countries to China and Europe and the same might have been transhipped to India is mere conjecture and unsubstantiated.

## **F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

### **Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

21. Various submissions made by the interested parties with regard to Normal value, export price and dumping margin and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- i. Due to fluctuation of raw material and PTA prices, the ordinary course of trade (viability/COP) test (80:20) and dumping margin/injury margin, if applied based on average cost for the POI, would be totally erroneous and illogical. For proper comparison between cost and price, viability test is to be applied on a monthly basis and dumping margin calculated for every month. Adopting one cost based on average for the POI for applying viability test (80:20) will lead to skewed results.
- ii. PTA is traded and sold to different categories of customers (end users and distributors). If sales are made to distributor, exporter incurs less distribution cost.
- iii. The subject goods are exported as packed and as bulk. Cost of different types of packing should be neutralized both in cost of production and domestic sales while applying the viability test.
- iv. PTA prices are determined by international market prices which are announced by chemical market price information websites. RIL having predominant market share determines its sales price according to international market price plus import duty and import related expenses. MCPI and IOC follow RIL's prices. Korean producers also determine export price on the basis of international price. Since ICIS announces prices on a weekly basis, monthly average weekly price can be calculated only after month-end closing of the shipment. Therefore, Korean producers apply tentative price and make a settlement on a monthly basis. Import price from Korea is almost the same as average monthly price issued by ICIS, PLATTS and PCI after considering ocean freight and payment term differentials. Domestic market price in Korea is also determined based on international market price. Therefore, dumping by Korea is incorrect.
- v. Hyosung Trading PG is not a separate company, but only a division of Hyosung Corporation. The Trading PG purchased the subject product from other producers like S.K. Petrochemical, Samnam Petrochemical and Lotte Petrochemical and exported to India during the POI. Hyosung Corporation procures the subject product from other producers since more than half of consumed internally and the balance is not sufficient to meet the global demand.
- vi. Hyosung Corporation's production of subject product is essentially of higher purity. The Trading PG mainly purchases and sells the MTA (Medium Quality Terephthalic Acid) to meet the specified demand of the Indian Customers.
- vii. S.K. Petrochemical is not a related party of Hyosung Corporation. Due to huge capacity expansion in China, S.K. Petrochemical could not compete and therefore closed down. Hence S.K. Petrochemical will not further participate in the investigation.
- viii. Article 6.10 of the WTO Anti-Dumping Agreement places an obligation upon the investigating authority to determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer.

DGAD should determine a separate margin of dumping and recommend a separate rate of duty for Indorama Petrochem Limited, Thailand and TPT Petrochemicals Public Limited Company, Thailand.

- ix. Rejection of the exports data furnished by Zhejiang Yisheng Petrochemical Co Ltd on the ground of insignificant volume is illegal and erroneous.
- x. The volume of the imports from China PR being minuscule could not have caused injury to the domestic industry.
- xi. Denial of market economy treatment to Zhejiang Yisheng Petrochemical Co Ltd and its related associates is erroneous as they have furnished sufficient evidence that they operate under market economy condition.

#### **Submissions made by the Domestic Industry**

22. Submissions made by the domestic industry with regard to Normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. With respect to the claim that market prices of crude oil, naphtha, PX and PTA are determined based on international market price and global economy and demand/supply condition are the main factors for price fluctuation, it is submitted that the present investigation is against imports of PTA and therefore the price fluctuations of Paraxylene, being the major raw material and PTA itself are relevant for the present investigation and not other cited factors.
- ii. With respect to the claim that RIL has the predominant market share and the other producers follow its price, in fact sales volumes of RIL do not constitute predominant position. The responding party concedes that MCPI prices are linked to import prices and not RIL prices. Even RIL prices are linked to import prices.
- iii. The claim that import price from Korea is almost the same as average monthly price issued by ICIS, PLATTS and PCI, after considering ocean freight and payment term differentials, shows that the Korean producers have followed international prices in exports to India and have not considered their domestic prices and cost of production. Thus if domestic prices are higher and such domestic prices are profitable, it establishes dumping by the Korean producers/exporters.
- iv. The claim that the domestic market price in Korea is also determined based on international market price does not prove that the exporters are not selling the product in India at dumped prices. If domestic market price in Korea is also the same as the international market price, it implies that the Korean producers are suffering financial losses, considering the prevailing PX prices during the relevant period.
- v. Questionnaire responses do not make it clear how the producer concerned has produced and supplied the goods to a trading company who has eventually supplied the goods to India. Whether the sales channels declared in the EQ responses are complete or there are still more, should be got clarified from the respondent exporters.
- vi. The dumping margin determined by the Authority in the preliminary findings is grossly low.
- vii. Any price which does not represent comparable price in the ordinary course of trade for the like article when meant for consumption in the exporting country cannot be taken for determination of normal value. Considering Paraxylene (PX) price and conversion costs, all producers in the subject countries are suffering losses. The selling price of the product in the domestic market of subject countries are not in the ordinary course of trade for the reason that the said price does not permit recovery of cost of production in the domestic market. Therefore, the prices prevailing in subject countries cannot be adopted for determination of Normal Value.

- viii. PX price paid by MCPI and Korean companies cannot be materially different. There could be three sources of Paraxylene for the responding producers - (a) own production; (b) procurement from related party; (c) procurement from unaffiliated parties. In case the procurement is from an unaffiliated party, the procurement price must be comparable to the prevailing prices in the international market. In case a producer has purchased Paraxylene from affiliated supplier, then also the purchase price must confirm to the price prevailing in the international market.
- ix. The foreign producer is required to provide the following information in case any material is purchased from related supplier or captively produced:
  - a. the basis of pricing of the material considered
  - b. how exporter considers that the pricing considered is reflective and representative of a fair market price
  - c. provide purchase prices from independent parties for an identical or comparable input product.
  - d. provide cost of production of the item procured captively or from an affiliated supplier.
- x. Designated Authority is required to consider whether the procurement prices from an affiliated supplier is representative of market values.
- xi. None of the foreign producers of PTA for whom the Designated Authority has determined individual dumping margin and ADD are having their own Paraxylene production. Such being the case, the consumption price reported by them should conform to the international prices as reported in the trade journals. The authority should examine the same by corroborating the consumption/purchase price with the prices reported in the trade journals.
- xii. Normal value determination cannot be restricted to producer concerned. In a situation where about majority of the market is being supplied by imported goods and further in a situation where the domestic producer is selling about 80-90% of its domestic sales to an affiliated company and remaining 10-20% (which forms hardly 3-5% of total sales of the product under consideration), and further in a situation where the domestic producer is selling the product at a price which is 30-40% below the market price, moot question that arises for consideration is why the producer is selling the product at such a low prices. It is evident that such sales transactions do not represent comparable prices in the ordinary course of trade.
- xiii. Designated Authority is not bound to adopt the cost of production of the exporter without satisfaction whether the same reasonably reflect the cost associated with production and sale of the product under consideration. For conducting a fair and proper comparison, the Authority is requested to modify the cost of production in respect of PX prices.
- xiv. Injury to the domestic industry has continued even after imposition of anti dumping duty because of low quantum of anti dumping duty which is not sufficient to counteract dumping.
- xv. Petitioners are not against imports per se. In a situation where the imports are inevitable, it wouldn't be prudent for any business entity to aggressively sell at cheap price, when it is a very well known fact that the goods can be sold at reasonable prices in the market as the demand is more than the capacity with the domestic producers.
- xvi. Thus, when the imports are inevitable; there is no reason for the foreign producers to depress the prices for the product in the Indian market, that too discriminately for the Indian market. The only plausible explanation is the surplus capacities with the foreign producers. The surplus unutilized capacities with the foreign producers are forcing them to sell their product aggressively in the Indian market.

- xvii. There is massive dumping in a relatively short period and injury to the domestic industry is aggravating. Designated Authority should consider retrospective imposition of anti dumping duty.
- xviii. None of the WTO Member countries have granted market economy status to Chinese producers on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph 8(3). Therefore, none of the Chinese companies should be granted MET and normal value for China should be constructed in terms of Rule 7 of the AD Rules.
- xix. As regards the issue concerning insignificant volume of exports made by Zhejiang Yisheng and its associates, it is submitted that the exporter must establish how its prices are representative of the prevailing prices. For instance, a party cannot claim individual dumping margin based on sample sales.
- xx. As regards the contention that the volumes of the imports from China PR are minuscule and could not have caused injury to the domestic industry, it is submitted that the volume of imports from China PR is above de minimis and is sufficient to cause injury to the domestic industry.

#### **Examination of the Authority**

23. Since in this investigation, China PR and EU have been excluded from the purview of the subject countries for the reasons explained in Para 19(xvii) above, the Authority does not consider it relevant to examine the issues concerning these countries. However, the submissions made by the interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin in respect of the subject countries in this investigation (Korea and Thailand) are addressed by the Authority as follows:

- i. As regards the contention that due to fluctuation of raw material and PTA prices, the ordinary course of trade test and determination of dumping margin/injury margin should be made on a monthly basis, the Authority has done month wise analysis.
- ii. As regards the contention that when sales are made to distributors, exporter incurs less distribution cost and the same should be taken in to account while determining export price, the Authority notes that the export price in respect of cooperating exporters has been determined in terms of verified data and relevant rules.
- iii. As regards the contention that the subject goods are exported in packed and bulk forms and therefore cost of different types of packing should be neutralized both in cost of production and domestic sales while applying the viability test, the Authority notes that the normal value and the non-injurious price are determined in terms of the laid down rules and as per prevailing practice in the DGAD.
- iv. As regards the contention that since market prices of crude oil, naphtha, PX and PTA are determined based on international market price, global economy and demand/supply condition are the main factors for price fluctuation, the Authority notes that the present investigation is against imports of PTA and therefore the price fluctuations of Paraxylene, being the major raw material and PTA are relevant for the present investigation and not other cited factors.
- v. The opposite interested parties have contended that dumping by Korea is factually incorrect as Korean producers determine sales price on the basis of international prices so as RIL as well as MCPI and IOC, the Authority notes that as per the Anti-dumping Law, actual dumping margin is calculated as the differential between the Normal Value of the subject goods and the actual export prices of the subject goods at ex-factory level. If the normal value is more than the export price, dumping margin is positive irrespective of the fact that export price has been determined by the exporter on the basis of international price.

#### **G. Determination of Normal Value**

##### **Determination of Normal Value for producers and exporters in Korea RP and Thailand**

##### **Determination of Normal Value for producers and exporters in Korea RP**

24. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:

(i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

(ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

- (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (b) *The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of exporter there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

#### **Korea RP**

25. The following producers/exporters from Korea RP have filed exporter's questionnaire response:

- a. SK Petrochemical Inc, Korea RP (producer) along with Mitsubishi Corporation, Japan (exporter)
- b. Hyosung Corporation, Korea RP
- c. Samsung Petrochemical Co. Ltd., Korea RP now known as Samsung General Chemicals Co Ltd (producer) and Samsung C&T Corporation, Korea RP (exporter).
- d. Taekwang Industrial Co Ltd, Korea RP (producer/exporter)

#### **SK Petrochemical Inc, Korea RP.**

26. In the present investigation, SK Petrochemical Inc, Korea RP (producer) had filed exporter's questionnaire response along with Mitsubishi Corporation, Japan (exporter). In the exporter's questionnaire response, SK Petrochemical Inc declared that they have only one channel of domestic sale and sold the subject goods in the domestic market directly to the customers in the POI. It has been further declared that the Company sold the product concerned in the domestic market to both end-users and distributors; however, there is no difference in sales process depending on the class of the customer. From the exporters questionnaire response the Authority notes that the Company has exported substantial volume of the subject goods to India during the POI through two other companies namely Mitsubishi Corporation, Japan and Hyosung Corporation, Korea RP, another respondent Company in the present investigation. The Company exported \*\*\* MT of subject goods through Mitsubishi Corporation, Japan and \*\*\* MT of subject goods through Hyosung Corporation, Korea RP. Subsequent to the filing of exporter's questionnaire response, SK Petrochemical Inc. Korea RP informed that they have stopped production of the subject goods and opted out of the present investigation. Since, SK Petrochemical Inc. Korea RP opted out of the present investigation; the Authority does not consider it necessary to determine normal value for the Company.

#### **M/s Hyosung Corporation, Korea RP**

27. In the exporters questionnaire response the Company declared that during the POI they had two channels of sales in domestic market viz; sales made directly to unrelated domestic end-users and sales made to distributors. From the exporters questionnaire response the Authority notes that the Company has made exports to India during the POI through three channels :-

- a. Direct exports of self produced subject goods,
- b. Exports of self produced subject goods through unrelated traders namely Mitsui & Co, Korea RP,

c. Exports of subject goods produced by other producers namely SK Petrochemical, Lotte Chemical and Samnam Petrochemical.

28. The data/information furnished by the Company was verified by the Authority. The Authority notes that during the POI, the Company made \*\*\* domestic transactions of subject goods to non-affiliated parties for a total quantity of \*\*\*MT for a total value of KRW \*\*\*.

29. As regards exports of subject goods to India during the POI, Hyosung Corporation has 3 channels – direct exports, exports through unrelated trading companies and export of subject goods produced by other Korean producers. During the POI, the Company directly exported to India \*\*\* MT of subject goods for a total value of KRW \*\*\* (USD \*\*\*). During the POI, the Company also exported \*\*\* MT of subject goods to India for a total value of KRW \*\*\* (USD \*\*\*) through Mitsui Corporation, an unrelated trading company, which has not filed exporter's questionnaire response in the present investigation. Further, during the POI, the Company exported \*\*\* MT of subject goods worth of KRW \*\*\* (USD \*\*\*) produced by other Korean producers namely S.K. Petrochemicals, Sam Nam and Lotte. While S.K. Petrochemicals opted out of the present investigation, Sam Nam and Lotte have not filed exporter's questionnaire response in the present investigation. The Authority notes that out of the total export of \*\*\* MT of subject goods made to India during the POI, about \*\*\*% of the exports are not a part of the verified data before the Authority. Consequently, in the absence of the complete value chain in respect of substantial volume of exports of subject goods made by Hyosung Corporation, Korea RP, the Authority is not in a position to determine and grant individual margins to the respondent Company. Under the above stated circumstances, determination of normal value concerning Hyosung Corporation, Korea RP is not considered to be relevant and therefore, the Authority does not determine individual normal value for Hyosung Corporation, Korea RP.

**Samsung Petrochemical Co. Ltd., Korea RP now known as Samsung General Chemicals Co Ltd**

30. Post initiation, vide letter dated 20<sup>th</sup> May, 2014 M/s Samsung Petrochemical Co. Ltd., Korea RP informed that the company has been merged with Samsung General Chemical Co Ltd, Korea RP and consequent upon the merger, Samsung General Chemical Co Ltd Korea RP became the producer of the subject goods. The data/information furnished by the Company was verified by the Authority. During verification, it was informed by the Company that its major shareholders entered into Stock Purchase Agreement with \*\*\* Group. The Authority notes that during the POI the company sold \*\*\* MT of subject goods to unaffiliated parties amounting to KRW \*\*\*. During the POI, the Company sold the subject goods in the domestic market directly to the customers. Only \*\*\* MT of subject goods were sold to \*\*\*, a related party. The Authority has made month-wise analysis of the transactions and applied Ordinary course of Test. The Authority also notes that in some of the months, almost entire sales were below the cost of sales and in such months the Authority has determined the normal value based on the data made available by the cooperating exporter and adding 5% towards profit. In respect of other months, the Authority has considered the profit making domestic sales after due adjustments claimed by the Company for the POI. Thus, the Authority has determined the normal value for the Company as US\$ \*\*\*per MT.

**Taekwang Industrial Co Ltd, Korea RP**

31. In the exporters questionnaire response the Company declared that during the POI they had three channels of sales in domestic market viz; direct sales to unrelated end user, direct sales to related end user and indirect sales through unrelated domestic trader. The Company made export sales to India during the POI directly as well as through unrelated foreign traders. The data/information furnished by the Company was verified by the Authority. The Authority notes that during the POI, the Company made \*\*\* domestic transactions for a total quantity of \*\*\* MT for a total value of KRW \*\*\*. Out of the total domestic sales, \*\*\*MT (\*\*\* %) for a value of KRW \*\*\* was sold to related parties and the Authority notes that such sales were made at arm's length basis. The Authority has made month-wise analysis of the transactions and applied Ordinary course of Test. The Authority also notes that in some of the months, almost entire sales were below the cost of sales and in such months the Authority has determined the normal value based on the data made available by the cooperating exporter and adding 5% towards profit. In respect of other months, the Authority has considered the profit making domestic sales after due adjustments claimed by the Company for the POI. Accordingly, the normal value determined works out to \*\*\*US\$ per MT.

**Normal Value for Non Cooperative exporters**

32. The Authority notes that no other exporter/producer from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Korea RP, the Authority has determined the normal value on the basis of best available information as \*\*\*US\$/MT.

**Determination of Normal Value for producers and exporters in Thailand**

33. The following related producers/exporters from Thailand have filed exporter's questionnaire response.

- a. Indorama Petrochem Ltd, Thailand
- b. TPT Petrochemicals Public Limited, Thailand

**Indorama Petrochem Ltd, Thailand**

34. The data/information furnished by the Company was verified by the Authority. During the POI, the Company sold \*\*\*MT of subject goods in the domestic market for Thai Baht \*\*\*. Out of the total domestic sales made by the Company, \*\*\*MT valuing Thai Baht \*\*\*was made to related parties at an average price of \*\*\*Thai Baht/MT. The average sales price to the unrelated parties was \*\*\*Thai Baht/MT. The Authority has made month-wise analysis of the transactions and applied Ordinary course of Test. The Authority also notes that in some of the months, almost entire sales were below the cost of sales and in such months the Authority has determined the normal value based on the data made available by the cooperating exporter and adding 5% towards profit. In respect of other months, the Authority has considered the profit making domestic sales after due adjustments claimed by the Company for the POI. Thus the Authority has determined the normal value for the Company as US\$ \*\*\*per MT.

**TPT Petrochemicals Public Limited, Thailand**

35. The data/information furnished by the Company was verified by the Authority. During the POI, the Company made \*\*\*MT of domestic sales valued at Thai Baht \*\*\*. Out of the total domestic sales made by the Company, \*\*\*MT worth of Thai Baht \*\*\*was made to related parties at an average price of \*\*\*Thai Baht/MT. The average sales price to the unrelated parties was \*\*\*Thai Baht/MT. The Authority has made month-wise analysis of the transactions and applied Ordinary course of Test. The Authority also notes that in some of the months, almost entire sales were below the cost of sales and in such months the Authority has determined the normal value based on the data made available by the cooperating exporter and adding 5% towards profit. In respect of other months, the Authority has considered the profit making domestic sales after due adjustments claimed by the Company for the POI. Thus, the Authority has determined the normal value for the Company as US\$ \*\*\*per MT.

**Normal Value for Non Cooperative exporters**

36. The Authority notes that no other exporter/producer from Thailand has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/ producers in Thailand, the Authority has determined the normal value on the basis of best available information as US\$\*\*\*per MT.

**EXPORT PRICE****Korea RP****SK Petrochemical Inc, Korea RP.**

37. From the exporters questionnaire response the Authority notes that the Company has exported substantial volume of the subject goods to India during the POI through two other companies namely Mitsubishi Corporation, Japan and Hyosung Corporation, Korea RP, another respondent Company in the present investigation. The Company exported \*\*\* MT of subject goods through Mitsubishi Corporation, Japan and \*\*\* MT of subject goods through Hyosung Corporation, Korea RP. Subsequent to filing of Exporter's questionnaire response, SK Petrochemical Inc. Korea RP informed that they have stopped production of the subject goods and opted out of the present investigation. Since, SK Petrochemical Inc. Korea RP opted out of the present investigation, the Authority does not determine individual export price for the Company.

**M/s Hyosung Corporation, Korea RP**

38. The data/information furnished by the Company was verified by the Authority. During the verification it was acknowledged by the Company that Hyosung Trading PG is merely a trading division of the Company and the exports by Hyosung Corporation cannot be separated from the exports made by its trading division. During the POI, Hyosung Corporation has 3 channels of exports to India – direct exports, exports through unrelated trading

companies and export of subject goods produced by other Korean producers. During the POI, the Company directly exported to India \*\*\*MT of subject goods for a total value of KRW \*\*\* (USD \*\*\*). During the POI, the Company also exported \*\*\* MT of subject goods to India for a total value of KRW \*\*\* (USD \*\*\* ) through Mitsui Corporation, an unrelated trading company, which has not filed exporter's questionnaire response in the present investigation. Further, during the POI, the Company exported \*\*\* MT of subject goods worth of KRW \*\*\* (USD \*\*\* ) produced by other Korean producers namely S.K. Petrochemicals, Sam Nam and Lotte. While S.K. Petrochemicals opted out of the present investigation, Sam Nam and Lotte have not filed exporter's questionnaire response in the present investigation. The Authority notes that out of the total export of \*\*\* MT of subject goods made to India during the POI, about \*\*\*% of the exports are not a part of the verified data before the Authority. Consequently, in the absence of the complete value chain in respect of substantial volume of exports of subject goods made by Hyosung Corporation, Korea RP, the Authority is not in a position to determine and grant individual margins to the respondent Company. In view of the above position, the Authority does not determine individual export price and margins for Hyosung Corporation, Korea RP.

**Samsung Petrochemical Co. Ltd., Korea RP now known as Samsung General Chemicals Co. Ltd. (producer) and Samsung C&T, Korea RP (exporter)**

39. In the present investigation, exporters questionnaire response was filed by M/s Samsung Petrochemical Co. Ltd., Korea RP (renamed as Samsung General Chemical Co. Ltd.) as the producer of subject goods along with its related exporter namely M/s Samsung C&T, Korea RP. The data/information furnished by the producer and the exporter was verified by the Authority. During the POI, Samsung General Chemical Co. Ltd. made \*\*\* transactions of exports of subject goods to India for the total quantity of \*\*\*MT and value of US\$ \*\*\*. Out of the total exports to India during the POI, Samsung General Chemical Co Ltd exported \*\*\*MT of subject goods to India during the POI through Samsung C&T, Korea RP at an average price of US\$ \*\*\*per Mt. A small volume of \*\*\* MT of subject goods was also exported by Samsung General Chemical Co. Ltd. through Mitsubishi Corporation, Japan, an unrelated company, which has not filed exporter's questionnaire response in the present investigation. Considering the insignificant (about \*\*\*% of its exports to India) volume of exports made through Mitsubishi Corporation, Japan, the Authority has determined the net export price for Samsung General Chemicals Co. Ltd. (producer) and Samsung C&T, Korea RP (exporter) excluding the exports made through Mitsubishi Corporation, Japan. The Authority has made adjustments (inland freight, handling charges, customs and brokerage, ocean freight, insurance, credit expenses, packing expenses, bank charges, duty drawback) as claimed by the producer and the exporter in their questionnaire responses and as verified in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Samsung General Chemicals Co. Ltd. (producer) and Samsung C&T, Korea RP (exporter) has been determined by the Authority as US\$ \*\*\*per MT.

**Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP**

40. In the present investigation, exporter's questionnaire response was filed by Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP as the producer/exporter of subject goods to India. The data/information furnished by the producer and the exporter was verified by the Authority. During the POI, the Company made \*\*\*Transactions of exports to India for the total volume of \*\*\*MT for a total value of USD \*\*\* directly including exports of \*\*\*MT through an unrelated trader namely Mitsui Corporation. Since the volume of exports through unrelated trader is insignificant, the Authority determined the net export price for the Company by excluding the same exports. The Authority made adjustments (inland freight, ocean freight, credit expenses, bank charges, handling expenses, packing expenses, customs broker fees) as claimed by the exporter and as verified with the exception of duty drawback in order to arrive at the net export price at ex-factory level. During the verification, it was explained by the Company that the duty drawback claimed by the Company against its exports to India was calculated based on the total amount claimed for the entire exports and divided by the quantity of entire exports made and multiplied by the quantity of exports to India. The company was requested to provide a statement showing the details of import duty paid on the raw materials used in the manufacture of PTA and the amount of drawback claimed on exports to India and exports to other countries and the amount actually received from Korean Customs Authority along with relevant documents. However, the Company has not provided the details along with supporting documents for the drawback claimed for the exports to India and the basis for such claim. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP has been determined by the Authority as US\$ \*\*\*per MT after excluding the claim on duty drawback.

**Non-cooperative Exporters From Korea RP**

41. In respect of all other exporters from Korea RP who are treated to be non-cooperative, the Authority has determined their net export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules as US\$ \*\*\*per MT.

**Thailand**

42. The following related producers/exporters from Thailand have filed exporter's questionnaire response in the present investigation:

- c. Indorama Petrochem Ltd, Thailand
- d. TPT Petrochemicals Public Limited, Thailand

**Indorama Petrochem Ltd, Thailand**

43. In the exporters questionnaire response the Company declared that during the POI they had made only direct exports to India to their related Indian Company namely M/s Indo Rama Synthetics (I) Ltd. The data/information furnished by the producer and the exporter was verified by the Authority. During the POI, Indorama Petrochem Ltd, Thailand exported totally \*\*\* MT of subject goods to India valued at Thai Baht \*\*\*. Out of the total exports, \*\*\*MT of subject goods valuing Thai Baht \*\*\* were exported to M/s Indo Rama Synthetics (I) Ltd, a related party in India at the average price of Thai Baht \*\*\*per MT. The balance \*\*\*MT of subject goods were exported to other unrelated parties at an average price of \*\*\*per MT. Apart from other adjustments, IRPL claimed deduction towards export incentive. As per the information furnished by the Company, during the POI, Government of Thailand provided export incentives on the exports of PTA. The Authority notes that such export incentives granted by the Governments of exporting countries and claimed by the exporters do not constitute part of the expenses incurred by the exporter while exporting the subject goods. In view of this position, the Authority made due adjustments (ocean freight, inland freight, THC charges, customs clearance charges, packing cot, credit cost, bank charges) with the exception of export incentive claimed by the exporter and as verified in order to arrive at the net export price at ex-factory level and determined the same at \*\*\*US\$ per Mt.

**TPT Petrochemicals Public Limited, Thailand**

44. In the exporters questionnaire response the Company declared that during the POI they had made only direct exports to India to their related Indian Company namely M/s Indo Rama Synthetics (I) Ltd. The data/information furnished by the Company was verified by the Authority. During the POI, the Company exported \*\*\* MT of subject goods to India during POI at an average price of \*\*\*US\$ per Mt. Apart from other adjustments, TPT claimed deduction towards export incentive. As per the information furnished by the Company, during the POI, Government of Thailand provided export incentives on the exports of PTA. The Authority notes that such export incentives provided by the Government of exporting countries and claimed by the exporters do not constitute part of the expenses/income incurred by the exporter while exporting the subject goods. The Authority made due adjustments (ocean freight, inland freight, THC charges, customs clearance charges, packing cot, credit cost, bank charges) with the exception of export incentive as claimed by the Company and as verified in order to arrive at the net export price at ex-factory level and determined the same at \*\*\*US\$ per Mt.

**Non-cooperative Exporters From Thailand**

45. In respect of all other exporters from Thailand who are treated to be non-cooperative, the Authority has determined their net export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules as US\$ \*\*\*per MT.

**DUMPING MARGIN**

46. Considering the Normal Values and Net Export Prices determined above, the Dumping Margins are calculated as below:

S. No.	Channel of Export	Name of producer	Exporter	Normal value US/MT	Net Export price US\$/MT	Dumping margin US\$/MT	Dumping margin %	Dumping margin Range %
<b>Korea RP</b>								
1	Korea RP-India	Samsung General Chemical Co. Ltd.	Samsung C&T	***	***	***	***	0 - 10
2	Korea RP-India	Taekwang Industrial Co. Ltd.	Taekwang Industrial Co. Ltd.,	***	***	***	***	0 - 10
3	Any	All Other Producers	All Other Exporters	***	***	***	***	5 - 15
<b>Thailand</b>								
4	Thailand - India	Indorama Petrochem Ltd.	Indorama Petrochem Ltd.	***	***	***	***	0 - 10
5	Thailand - India	TPT Petrochemicals Public Limited	TPT Petrochemicals Public Limited	***	***	***	***	0 - 10
6	Any	All Other producers	All Other Exporters	***	***	***	***	5 - 15

**H. INJURY AND CAUSAL LINK****Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties**

47. The following submissions with regard to injury and causal link have been made by the opposite interested parties and considered relevant by the Authority:

- i. The price of IOCL, one of the domestic producers of the subject goods which have not supported the petition, is lower than the other domestic producers by 4-10%. But, IOCL has not claimed decline in profits due to imports in its annual report. While IOCL has stayed out of the investigation as they are making profits, Mitsubishi and Reliance claim that they are making losses on account of dumped imports of subject goods from the subject countries.
- ii. RIL is expanding its PTA capacity by more than 100% which reinforces the fact that PTA business is doing extremely well and is profitable. The capacity utilization of both Reliance and Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) was more than 100%. IOC has neither participated nor supported the petition.
- iii. RIL in Annual Report admitted the petrochemical sector realized 11.2% and 8.2% of operating profit which were significantly above company-wide profit.
- iv. Due to the PX PTA delta (difference between PTA price and cost of PX) decreasing, MCPI incurred losses but RIL and IOC achieved profits. The petitioners claim that the PX-PTA delta should be at least \$150/MT for foreign producers to survive. However, MCPI's PX-PTA delta (unit PTA production cost-unit PX cost) is 253-279 \$/MT. This shows MCPI cannot compete with foreign producers unless it reduces its costs.
- v. RIL made significant profit in PX division but losses in PTA division. RIL treats PX production as a separate profit centre and transfers cost of PX to PTA at cost plus or market price basis. This results in inflating the actual cost of PTA.

- vi. RIL has been enjoying more than 100% capacity utilization, and IOCL has also been achieving consistently high rates of capacity utilization in the period of injury and POI. The only domestic producer who is struggling is MCPL, and the reason behind its low rate of capacity utilization is the sudden capacity expansion undertaken by MCPL, and the technical problems experienced in its Plant 2/Phase 2. In such a situation, DGAD should not grant protection to the domestic industry when only one domestic producer (MCPL) has a low rate of capacity utilization and that too because of its capacity expansion and problems in its production facilities.
- vii. The domestic industry has not established potential decline in various factors.
- viii. The allegation that there is an absolute increase in volume of imports as compared to 2009-10 is erroneous. 2009-10 was a time of global recession and any analysis with the same as base year, is inaccurate.
- ix. The volume of imports has decreased over 2010-11, 2011-12 and the POI. The percentage of imports in relation to production as well as consumption has undergone a sharp decline over the years.
- x. The domestic industry cannot claim injury due to volume effect because it is inevitable that there will be imports when the domestic industry is operating at maximum capacity but still cannot fulfill the demands of the market.
- xi. The landed value of imports has exhibited a consistent and substantial increase.
- xii. The sales and production of the domestic industry have undergone a substantial increase.
- xiii. MCPI has claimed technical problems in their plant in the letter to the Ministry of Environment, as a result of which, the plant couldn't operate properly. Because of this, they got benefit of reduced export obligation. The applicant cannot make different claims before different statutory authorities to reap benefits. RIL and IOC operated PTA facility at full capacity but MCPI could not normalize its production because of technology problem.
- xiv. Operational inefficiency and not imports the root cause of MCPL's sub-par performance. MCPL, though not qualified to be eligible to join the Domestic Industry for this petition being related to an exporter of PTA, was included to prove material injury though it has been operating below full capacity suffering for reasons other than alleged dumped imports.
- xv. MCPL's 2<sup>nd</sup> plant had been suffering from technical defect. MCPL may have suffered from losses, low capacity utilization, low return of capital etc. The said under performance by MCPL cannot be attributed to the imports of PTA from China PR and the Authority ought to have segregated the alleged injury caused due to technical problems faced by MCPL at the time of conducting the injury analysis. The real cause of injury to MCPL is problems to their plant due to technical snags.
- xvi. From 2010-11 onwards, the market share of imports has declined substantially.
- xvii. Increase in sales from 2011-12 to POI is more than the increase in production for the same period. In which case, the fact that inventories have increased is contradictory to the same.
- xviii. There is no adverse impact on productivity. Employment has undergone an increase. The slight decrease is due to the MCPI plant having technical problems. Wages paid have also increased.

- xix. Fixation of prices by domestic producers of PTA is based on reference price which is CFR CMP reported by ICIS or CFR China reported by Platts and is independent of imports.
- xx. MCPL is suffering due to shortage of PX. And that cannot be attributed to imports. Price of PX has increased but that of Naphtha did not increase at the same rate. However, the increase in price of Naphtha was commensurate with increase in price of PTA. Two of the three domestic producers produces PX from Naphtha and consume it to produce PTA. Therefore actual cost of production should be taken for PX and not any notional price for determination of cost of production, NIP, profits/loss, and return.
- xxi. MCCPI started incurring losses from the year it expanded its capacities. MCCPI enhanced its capacities by almost three times during 2010, which resulted in decline in their capacity utilisation and in turn resulted into losses. This clearly establishes that MCCPI has been facing start up problems and has not stabilised its production. This aspect must be examined by the DGAD in detail.
- xxii. Exchange rate considered by Domestic industry is 54 whereas as per RBI current exchange rate is 62.88. If prevailing exchange rate is considered, the level of price undercutting and price underselling would be eliminated.
- xxiii. Annex II (iv) of Anti-dumping Rules requires 'separate identification' of specific injury related data since there are only three domestic producers and each producer has a different production process.
- xxiv. 66% of RIL's PTA production is captively consumed and does not compete with imports.
- xxv. All economic parameters (including price undercutting, underselling, depression and suppression) should be examined on monthly basis due to wide fluctuation in price and cost.
- xxvi. In the context of price suppression/depression, there is a significant difference between the costs of RIL and MCPI and simple cumulation of COP will distort the analysis.
- xxvii. None of the economic parameters show injury except facility utilization, profitability and inventory build-up.
- xxviii. MCPI increased actual production by more than 100% during the POI as compared with the base year.
- xxix. RIL has provided complete volume information with regard to captive consumption. RIL has not provided information for each market segment – merchant and captive.
- xxx. Paraxylene (PX) is the main feedstock for manufacture of PTA, there has been significant addition in PTA capacity. During the period 2009-10 to 2012-13, the capacity addition in PX production has trailed. The lack of capacity addition and supply of PX has driven the prices of PX which in turn have raised the cost of production of PTA. The pressure on the sales price of PTA is on account of oversupply of PTA, therefore, creating pressures on margin of the manufacturers.
- xxxi. If DGAD takes into account the incremental production cost factors incurred by MCPI's technical problems and internal profit realized by RIL, there would be no significant injury margin. Further, RIL producing the subject goods from basic stage adopts transfer price at various stages of the products. To arrive at the real cost, profit added at each stage of process should be excluded and the actual cost worked out accordingly.

- xxxii. The capacity of the Applicants estimated by DGAD in the preliminary findings is incorrect. The capacity of the Applicants is 3240000 MT and not 3420000MT and capacity utilization of the Applicants during the POI is 90% and not 86% as estimated by the DGAD in the preliminary findings.
- xxxiii. There is no adverse price effect of the subject imports on the Applicants due to marginal price undercutting and underselling effect. When price undercutting and underselling are almost the same, then it is inferred that both NIP and NSR are almost the same as well. In a situation where the domestic industry is able to sell at a price almost equal to NIP, it is impossible to imagine that the industry is suffering injury at the same time.
- xxxiv. Import price of the PTA is higher than the selling prices of domestic producer of India. Claim of Price undercutting is not justified. Thus there is no adverse price effect. Production and sales of the domestic producers have not suffered an injury. In the absence of the adverse price effect and volume effect there is no causal link.
- xxxv. RIL's claim that it made operating losses from PTA domestic sales is because it used internal intra-company transfer price of PX, which presumably was valued at international market price, to calculate COP and profitability of PTA in the Petition. Consequently, PX plant had internal profit but PTA had internal losses.
- xxxvi. 22% return on capital employed, allowed by DGAD, is not reasonable.
- xxxvii. The injury analysis should be of trends for both merchant as well as captive supply separately and then cumulatively. However, the Designated Authority has carried out injury analysis ignoring the captive consumption by RIL.
- xxxviii. When imports increased to its peak in 2010-11, the Applicant generated maximum profits. Designated Authority has estimated negative price undercutting for 2009-10 and 2010-11 and in the 0-10% range for POI. Therefore, there was no reason for Applicant Domestic Producer to incur losses during 2011-12.
- xxxix. Without prejudice to the above submissions, it is also contended that by comparing the duties imposed and landed value of the subject product, it is apparent that price underselling/injury margin is negligible, i.e. less than 4% in almost all the cases. This further indicates that price undercutting would be in the range of less than 2-3%.
- xl. For determining NIP, profit, return on capital employed and cash flow must also be determined after excluding extraordinary expenses and costs and adopting best utilisation method.
- xli. The price of PX increased substantially during 2011-12 and 2012-13 while the price of naphtha did not increase at the rate in which prices of PX increased. However, the increase in prices of Naphtha was commensurate with increase in prices of PTA. Therefore, RIL cannot report loss and negative return on capital during 2011-12 and 2012-13.
- xlii. MCPL has no firm contract for coal supply, which has an adverse effect on its cost of production, causing injury.
- xliii. MCPL has established its plant far away from the users and transportation cost incurred by it on the subject goods make it uncompetitive. Therefore, freight as a factor of injury must be investigated and considered by the Designated Authority in its attribution analysis.

- xliv. The market share of the Domestic Industry has remained static in spite of increase in demand. There is no connection between Domestic Industry's static market share in demand and the import from subject countries.
- xlv. MCPL procured PX (raw material) at substantially high prices from the related party. Designated Authority should reject such price shown by MCPL and adopt the low price at which the exporters procured PX for constructing NIP.
- xlvi. The adjustments relating to credit cost and freight cost for the computation of NIP requested by the Applicants cannot be granted as it is against the methodology statutorily provided under Annexure III to the AD Rules. Clause 4(vii)(b) of Annexure III to the AD Rules also affirms that NIP is at the ex-factory level, and post manufacturing expenses such as commission, discount, freight outward etc shall not be considered while assessing the NIP. Applicants' claim is inadmissible.
- xlvii. The claim of the Domestic Industry that freight cost should be adjusted in the non-injurious price is inappropriate. Designated Authority makes a comparison of Non-injurious Price with landed value. In order to make comparison at same level, Non-injurious Price at ex-factory level is worked out and landed value is worked out at port level. In both the cases domestic transport cost is not added.
- xlviii. There is no causal relationship between any possible injury and imports of PTA from subject countries as the increase of import volume and price effect is insignificant and there is no material injury.
- xlix. MCCPI could not operate its production facility due to internal problems and caused shortage of PTA supply. Imports were made as a supplement to fill supply shortage. Thus there is no causal link between imports and alleged injury to the domestic industry.
  - l. PTA imports from the subject countries did not cause material injury to the domestic industry. None of the economic parameters, except facility utilization, profitability and inventory, show indications of material injury. The demand and market share trends also exhibit the absence of a causal link. While there was an increase in both domestic sales and demand, there was a reduction in imports.
  - li. As per Annexure II to the AD Rules, any factors other than dumped imports should be segregated from the injury analysis. There is no price or volume effect in the present investigation. The claimed losses of the Applicants are primarily on account of High wage cost, absence of link between profits and imports, unwanted increase in capacity resulting in increase in costs, Technical problems suffered by MCPL, Shortage of raw material PX, depreciation of rupee, use of recycled PTA etc.
  - lii. While there was an increase in both domestic sales and demand, there was a reduction in imports. This also demonstrates the absence of a causal link between the subject imports and any injury which may have been sustained by the Applicants. The losses of the Applicants are primarily on account of MCPL's high wage cost, unwanted capacity expansion, unstable operation and frequent breakdown of its plant and fall in profits despite fall in imports, and not dumping.

**Submissions made by domestic industry**

48. The following submissions with regard to injury and causal link have been made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:

- i. With respect to the argument that the domestic industry has not established potential decline in various factors, the Authority is examining the actual position of the domestic industry and it is only if this shows no injury then the potential factor becomes relevant.
- ii. The fact that the base year was during the recession is irrelevant as the claim of injury is based on price and not volume parameters. Further, imports in 2009-10 were in fact significantly higher as compared to preceding year.
- iii. The import volume has declined after 2010-11 because of commencement of production at the new capacities installed by MCPI. However, the performance of the domestic industry materially deteriorated in respect of profits, cash flow and return on investment after 2010-11.
- iv. With respect to the domestic industry not being able to meet demand even while operating at full capacity, the domestic industry has claimed adverse price effect of dumping.
- v. While import prices have increased, as claimed by the responding party, the increase in the CIF and landed price of import is far lower than the increase in raw material cost and there is price suppression.
- vi. With respect to the argument that the sales and production of the domestic industry have undergone a substantial increase, the domestic industry has claimed price and not volume injury.
- vii. With respect to the argument that MCPI has claimed technical problems in their plant in the letter to the Ministry of Environment, the domestic industry has claimed price and not volume injury.
- viii. With respect to the argument that the other domestic producers' plants are operating at more than 100% capacity and so low capacity utilization cannot be claimed, the domestic industry has claimed price and not volume injury.
- ix. With respect to the argument that from 2010-11 onwards, the market share of imports has declined substantially, the domestic industry has claimed price and not volume injury.
- x. The responding party claimed that increase in sales from 2011-12 to POI is more than the increase in production for the same period and so inventories cannot have increased. The domestic industry has claimed price and not volume injury. Further, increase in sales of the domestic industry was lower than increase in production, which led to increase in inventories.
- xi. With respect to productivity, employment and wages, the petitioners have not claimed injury on account of these. Further, the rules don't specify that injury be in respect of all parameters.
- xii. With respect to capacity expansions by the domestic industry, these were made with a long term outlook.
- xiii. The responding party argued that the applicants, though not subject to customs duty, are claiming customs duty notionally at 5.583% of the reference price and that, as prices are at USD, they are getting unjustified benefit of steep depreciation of rupee. This shows that the pricing mechanism followed by the domestic industry is based on import parity. Further the depreciation of the rupee would also have impacted the cost of production. It is established practice of the authority to proceed with determination based on exchange rate prevailing during period of investigation.
- xiv. Since imports from Malaysia were below prescribed limits during the investigation period, the issue of a relationship between one of the petitioners and a Malaysian exporter becomes irrelevant.
- xv. MPCL is not suffering due to shortage of PX, as claimed by the responding party. This would have caused adverse volume effects, which have not been claimed by the domestic industry.

- xvi. With respect to the issue of absolute decline in imports from Thailand and marginal increase in imports from Korea, the domestic industry requested that a cumulative assessment be made of the effect of all subject country imports on the domestic industry. Decline in imports from Thailand is due to increase in imports from Korea.
- xvii. With respect to the argument that there has been a depressed increase in demand due to a shift to recycled material such as PET bottles, there has been no contraction of demand or change in the pattern of consumption that has affected the domestic industry.
- xviii. With respect to the claim that as per RBI current exchange rate is 62.88, the exchange rate during the POI was 55.67, which was what was adopted by the domestic industry.
- xix. With respect to the Designated Authority seeking information from Central Excise Commissionerate regarding reporting of losses, this is not required of the Authority under the Anti-dumping Rules.
- xx. The responding party has incorrectly interpreted the Annex II (iv) of Anti-dumping Rules requirement of 'separate identification'. Annexure II (iv) provides for a situation where information concerning the production of the like product, such as producers' profits and sales, cannot be separately identified. Annexure II(iv) allows the authority to consider information concerning production of a broader product group than the like product produced by the domestic industry, which includes the like product, in evaluating the effect of imports. It does not deal with the separate injury analysis of different producers.
- xxi. The claim that 66% of RIL's PTA production is captively consumed and does not compete with imports does not justify a separate analysis. RIL has already provided information including and excluding captive production.
- xxii. With respect to the argument that due to the PX PTA delta decreasing, MCPI incurred losses but RIL and IOC achieved profits, decline in profits is also considered injury.
- xxiii. The argument that because the domestic industry's market share is more than 80%, Korea producers cannot lead market price in India contradicts the previous argument that international prices were followed.
- xxiv. The argument that cumulating cost of production of RIL and MCPI cannot be done as it will distort analysis cannot be accepted since the performance of the domestic industry as a whole has to be considered.
- xxv. The claim that MCPI's PX-PTA delta (difference between the PTA price and cost of PX) is 253-279 \$/MT which shows MCPI cannot compete with foreign producers unless it reduces its costs is factually incorrect.
- xxvi. The claim that RIL made significant profit in PX division but losses in PTA division contradicts the previous claim that RIL's costs are low and MCPI is suffering injury. The Authority should consider captive inputs at their market prices.
- xxvii. With respect to some parameters not showing injury, adverse effect of dumping on the domestic industry is in respect of parameters such as price undercutting, price suppression/depression, inventories, profit, cash flow and return on investment.
- xxviii. With respect to inventories, the domestic industry was faced with rising inventories despite significant demand-supply gap.
- xxix. With respect to the argument that RIL and IOC operated PTA facility at full capacity but MCPI could not normalize its production because of technology problem, volume injury has not been claimed in the present case.
- xxx. With respect to the argument that MCPI increased actual production by more than 100% during the POI as compared with the base year, volume injury has not been claimed in the present case. Despite such increase in production, profits of the domestic industry steeply declined.

- xxxii. The responding party has argued that RIL and IOC have achieved best capacity utilizations in the POI so averaging capacity utilization of the three producers is misleading. Volume injury has not been claimed in any case.
- xxxiii. The responding party has claimed that RIL in Annual Report admitted the petrochemical sector realized 11.2% and 8.2% of operating profit which were significantly above company-wide profit. The injury to the domestic industry is claimed for the product concern and not for the sector as a whole.
- xxxiv. With respect to the information provided by RIL, the company has provided information as per the records kept by the company.
- xxxv. The responding party claimed IOC's Annual Report shows profitability of the petrochemical sector improved from loss to profit in the POI and the realized profits since it produces and uses PX. The injury to the domestic industry is claimed for the product concern and not for the sector as a whole. Further, such injury is required to be seen for domestic industry and not for IOCL.
- xxxvi. The responding party has stated that there was no sharp increase in subject imports. Injury to the domestic industry is because of price undercutting, price suppression/depression caused by the imports.
- xxxvii. PF issued by the designated authority and implemented by Govt., establishes dumping, injury, causal link and the need for anti dumping duty. Further, the responding exporters at the time of hearing submitted that the dumping margin determined in the preliminary findings contains minor factual errors, thereby acknowledging dumping.
- xxxviii. There is no legal prescription under the law with regard to determination of injury margin. Only as a matter of convention and practice, the Designated Authority determines injury margin as the difference between non injurious price and landed price of imports in order to determine the quantum of anti-dumping duties which would be sufficient to address injury to the domestic industry. The injury margin determined in the preliminary findings is quite low and shows that the methodology adopted at present does not constitute fair comparison for the following reasons.
  - xxxix. Authority has not taken in to account the difference in credit period between domestic industry and foreign suppliers while determining injury margin. The domestic industry is largely selling the goods in the domestic market offering payment terms as "cash against delivery". As opposed to this, the foreign producers have been offering interest free credit of up to 180 days. Since the credit offered by the domestic industry and foreign producers are different, the non-injurious price is required to be compared with landed price of imports after appropriately adjusting any one of the two for the difference in the credit period.
  - xli. Freight cost of the domestic industry has been completely ignored while comparing the domestic industry price with landed price of imports. Freight cost is required to be adjusted for determination of injury margin.
  - xlii. PTA plants, being petrochemical plant, are required to run at high operating rates. High operating rate is not a choice but a business compulsion. The only choice with the producers is to produce to the maximum extent and sell the product at the market price. Thus, even in Indian context where the market is huge (demand is more than supplies), the producers have no choice but to follow the market price. Consequently, the impact of dumping would not be visible in terms of volumes but would be found in respect of adverse price effect.
  - xliii. Exporters from a number of countries are dumping subject goods in the Indian market. Designated authority should cumulatively assess injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries.
  - xlii. In a situation where the imports are inevitable, there is no reason for the foreign producers to depress the prices. The surplus unutilized capacities with the foreign producers are forcing them to sell their product aggressively in the Indian market. In a situation of reduction in the prices either by the foreign producers or by traders, either the Indian producers must realign their prices with the changes in the import prices or traders' resale prices, or the petitioners must lose orders.

xliii. The consumers compare the prices offered by two sources—foreign producers and domestic producers and if they find that the price of imported product is lower, the consumers would either place orders on the foreign producers, or would expect the domestic industry to reduce the prices. Therefore, the price undercutting must be determined after considering the methodology that is followed by the consumers in comparing the two prices.

xliv. Production facility of one of the petitioners, namely, MCC PTA is located at Haldia. The company has to however sell the consumers who are either in the western or northern part of the country. Since the importers/consumers compare the imported and domestic price on the basis of cost to them, MCC has to offer a price where the consumers find its prices comparable to the imported product price. Thus, MCC bears the freight cost from factory to the consumers. Therefore, the selling price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports after including the freight cost involved in case of domestic industry.

xlv. In addition to the material injury already inflicted on the domestic industry, imports from subject country are posing threat of material injury to the domestic industry.

xlvi. Injury to the domestic industry has continued even after imposition of anti dumping duty because of low quantum of anti dumping duty which is not sufficient to counteract dumping.

xlvii. Profit/loss, return on investment and cash flow in captive consumption can be irrelevant and could even be misleading. Injury in the captive consumption in terms of price parameters may even be difficult to be ascertained. Domestic industry may or may not maintain separate records of different products.

xlviii. The domestic industry has claimed adverse price effects of imports on the domestic industry. As regards increase in high fixed cost due to enhanced capacity, MCPI has increased capacity in the year 2010-11 and but the claim of the injury to the domestic industry is during period of investigation, which is 2012-13. Hence the argument of increased fixed cost does not hold good. Further, while determining Non Injurious Price, the Designated Authority has not considered high fixed cost resulting due to enhanced capacity and determined positive injury margin. This shows that even when the high fixed cost due to enhanced capacities is segregated, there exists significant injury to the domestic industry. MCPI earned profits after increase in capacities. MCPI suffered severe decline in profits thereafter and suffered losses in POI, which directly establishes that the losses to MCPI are not due to capacity enhancement.

xlix. The contention that Injury margin for imports from China and EU was 0-10% and therefore duty recommended from imports of these countries should be of same range is incorrect. The Designated Authority has done month by month comparison, whereas the interested party has done weighted average comparison.

l. PTA User Association requested the authority to verify the valuation reported by the petitioners to the Central Excise Authorities and examine whether the petitioners have undercharged excise duty. The Designated Authority is operating under Rule 4 of the AD Rules and has been entrusted with specific duties. There is no reason for the Designated Authority to deviate from the entrusted responsibilities.

li. The authority has been consistently examining actual performance of the domestic industry over the injury period. It is only in a situation where actual performance over the injury period does not show injury to the domestic industry that the authority shall examine potential situation with regard to various economic parameters. In fact, the investigating authorities globally examine actual performance of the domestic industry over the injury period and make their determination on the basis of the same.

lii. The fact that 2009-10 was a time of global recession is entirely irrelevant. In any case, the claim of injury is largely based on price parameters i.e. price undercutting or price suppression/depression; decline in profits, cash flow and return on investment. The claim of injury is not based on decline in production, sales and capacity utilization. There was significant increase in imports in 2009-10 as compared to previous two years. If it is contended that imports in 2009-10 were higher due to recession, it only implies that imports thereafter are still higher. If it is contended that imports in 2009-10 were lower due to recession, it would be seen that imports in 2009-10 were in fact significantly higher as compared to preceding year.

- liii. The opposite interested parties have argued that Designated Authority may take on record that IOCL has temporarily shut down its production facilities and RIL cut down the supply and hence domestic supply was reduced and imports increased to sustain the production of downstream industries. It may be noted that the petitioners have claimed adverse effect of dumped imports on parameters such as profits, return on investment and cash flow. Petitioners have not claimed adverse effect on production, capacity utilisation and sales for the reason that the petitioners are selling the product in competition to imports and after aligning their prices to import prices and therefore the petitioners are able to sell the product.
- liv. As regards the argument of opposing interested parties that sales and production of domestic industry has undergone substantial increase, it may be noted that the Petitioners have not claimed that imports have prevented the domestic industry from selling the product. In fact, petitioners have extensively contended that they have no option but to sell the product. Submissions made earlier are relied upon.
- lv. As regards the contention that the claim of petitioners that low capacity utilization is due to imports is incorrect since other domestic producers' plants are operating at more than 100% capacity, it is submitted that Designated Authority is required to consider domestic industry and not other domestic producers for assessment of injury. Further, the domestic industry has claimed adverse effects of imports on the parameters such as profits, cash flows, return on investment, etc.
- lvi. Market share of the domestic industry has remained constant because of addition of capacities by MCPI. However, even after producing and selling more, the profits, return on investment and cash flows have reduced drastically to a situation that all these parameters have become negative from a situation of positive earlier.
- lvii. The opposing interested parties argued that keeping in view the trends of landed value and selling price the price undercutting in 2011-12 would be even lower than in POI and hence no reason for domestic industry suffering losses in this period. It is submitted that the profitability of the domestic industry declined to significant losses due to dumping resorted by foreign producers. Declining difference between PX and PTA establishes the increasing dumping of the product in the Country, which intensified after the POI. Since the interested parties concede that this was a normal period, the Designated Authority may kindly grant this level of profits to the domestic industry as a reasonable level of profits. The domestic industry is not against imports per se. The domestic industry is against imports at dumped prices.
- lviii. When the interested parties concede that the injury margin is low/negligible, petitioners fail to understand and appreciate their concern/objection against imposition of anti dumping duty. The quantum of anti dumping duty is not higher than injury margin. By their own argument, such injury margin is low or even negligible. Further the interested parties are not disputing the presence of price undercutting.
- lix. When the interested parties concede that the price undercutting, injury margin and difference between NIP and NSR is low/negligible, petitioners fail to understand and appreciate their concern/objection against imposition of anti dumping duty. The quantum of anti dumping duty is not higher than injury margin. Further, if the NIP and NSR are comparable and undercutting is low, it again implies that the quantum of anti dumping duty is low/negligible in the eyes of the consumers. In such a case, the consumers should not be raising any concern against imposition of anti dumping duty.
- lx. The User Association agrees that the captive consumption is not affected with the import price. The purpose of injury analysis is to assess the impact of dumped imports on the domestic industry. If it is admitted fact that the impact of dumped imports is not onto captive consumption, the authority is not required to carry out the mechanical exercise. The interested parties must establish a justification for the same.
- lxi. It is wrongly assumed that PTA captively consumed by RIL are unaffected by impact of price of imports. RIL operates its products at arm's length and transfer prices are market prices at which RIL supplies in domestic market.

lxii. Injury to the domestic industry is required to be determined considering financial records of the company. Annexure-III is only for determination of NIP. It is relevant to point out that several countries do not even determine margin of injury, while none of the countries other than India has a law such as NIP. All these countries consider economic parameters on the basis of financial records of the domestic industry.

lxiii. The opposing interested parties contended that Applicants though not subject to customs duty are charging the same at 5.583% of the reference price. Further, it has been argued by them that as prices are at USD, they are getting unjustified benefit of steep depreciation of rupee. This further establishes that the pricing mechanism followed by the domestic industry is based on import parity and deterioration in performance of the domestic industry in respect of profits, return on investment and cash profits is because of dumping of the product in the Country. In order to arrive at import parity, various expenses/cost that the consumers shall incur (upto consumption point) in importing the product are considered by the domestic industry and the domestic industry forced to fix the prices keeping in mind this landed cost to the consumer at consumption point for the imported product. As regards depreciation of rupee, the consumer association has selectively considered the depreciation rupee and its impact on PTA prices. The consumer industry has conveniently ignored the adverse impact of depreciation of rupee on the cost of production of domestic industry and its favourable impact on the consumers own product. It cannot be said that depreciation of rupee impacted only PTA prices and has not impacted the cost of production of the PTA producers. Further, the depreciation has protected the downstream industry to higher extent. In any case, it is established practice of the authority to proceed with determination based on exchange rate prevailing during period of investigation and actual records of the domestic industry. It is also pointed out that despite these alleged rupee depreciation; the domestic industry has suffered injury, as established by the decline in profits and return on investment during this period. This at the least establishes that had the Rupee not depreciated, the injury to the domestic industry would have been higher. Thus, the claimed injury to the domestic industry is despite the Rupee depreciation.

lxiv. The opposing interested parties contended that with imposition of anti-dumping duty, the domestic industry has increased its price by Rs1550/MT and they are resorting to profiteering at the cost of users. The domestic industry has provided data upto Sept., 2014 which shows continued financial losses, leave aside profiteering. In fact, dumping got intensified after the POI, as would be observed from the difference between PX and PTA prices. The price increase by the domestic industry is in fact lower than what is necessary to reach back the situation of the POI, leave aside reaching the situation of 2009-10 and 2010-11.

lxv. The contention that RIL is expanding capacities by 100% which reinforces that PTA business is doing extremely well and landed value, has shown consistent and substantial increase, is incorrect. The petitioner refers and relies on the preliminary findings by Designated Authority. Further Capacity expansions are made by the industry considering long term outlook of the product. The mere fact that the market is at present suffering from dumping does not mean that the constituents of the domestic industry will shy away from making fresh investments that too in a situation where there is significant demand supply gap for the product in the country. RIL planned the present capacity expansion in Q3 2014-15 and Q2 of 2015-16, the year when the profitability of the product under consideration was far better. In fact, this further establishes that the dumping of the product under consideration is causing injury to the domestic industry and imposition of anti dumping duty is vital to protect the investments that were planned earlier by the domestic industry.

lxvi. Capacity expansions are made by the industry considering long term outlook of the product. The mere fact that the market is at present suffering from dumping does not mean that the constituents of the domestic industry will shy away from making fresh investments that too in a situation where there is significant demand supply gap for the product in the country. As regards monopolization of RIL, the opposing parties have not demonstrated or provided any evidence in order to establish that RIL will enjoy monopoly status on imposition of anti-dumping duty. Mere having integrated facility does not tantamount to monopolization.

lxvii. The contention that Imposition of ADD will further strengthen the dominant position of Reliance is without basis. RIL deals with more than 80 products and employs around 24,000 persons. The company has divided its business into about 4 different segments comprising of more than 40 different businesses. Given the size of its operations, there are clearly defined responsibilities with different businesses. The product is transferred from

one business segment to other segment at prices linked to market prices. Thus, contrary to the argument of the interested parties, access to dumped imports to the consumers was causing unfair advantage to these consumers vis-à-vis. While value of PTA for RIL was higher in downstream products, the same was lower for the consumers. Thus, the dumping of the product under consideration has been causing injury not only to the merchant market of RIL, but also in the downstream products. Table below shows the price at which RIL has transferred its captive consumption and has sold PTA in merchant market. It is evident that the downstream products of RIL were significantly disadvantaged because of dumping of PTA in India.

lxviii. As regards the contention that Reliance has acquired 100% stake in BP Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd (BPCM) and raw material of PTA was sent to Malaysia converted to PTA and re-imported and sold in India, it is submitted that imports from Malaysia were negligible during the injury period. Since imports from Malaysia are de-minimis the issue of possible relationship of one of the petitioner company with one of the Malaysian producer becomes entirely irrelevant. It is also relevant to point out that PX was sold by RIL to the Malaysian company and the Malaysian company sold PTA in Indian market. This resulted in no advantage to either company.

lxix. As regards the contention that after imposition of anti-dumping duty, capacity utilization in the user industry has declined and imports of final product using PTA has increased, it is submitted that the petitioners filed the application for imposition of anti-dumping duty on the positive evidence of dumping, injury and causal link. As regard increase in imports of downstream products, it is submitted that the anti-dumping duty was imposed only in July 2014, whereas the imports of the downstream products is entering the Indian market since long. Hence, it is incorrect to attribute such imports on anti-dumping duty of PTA.

lxx. Operating losses are nothing but injury due to dumped imports. Shortage in operating cash flows is the effect of dumped imports on the domestic industry. In fact, the Rules require the Designated Authority to examine actual and potential negative effects of dumped imports on cash flow. The interested parties concede that the domestic industry's cash flows suffered. Foreign exchange loss is nothing but the amount paid to the raw material suppliers. In case the amount is higher because of improvement in exchange rates, the selling price of the domestic industry is also higher to the proportionate extent. It is not a case where the domestic industry first took order at a pre-determined price then bought raw materials and suffered additional costs on such raw materials. It is a case where the domestic industry first bought the raw material, accounted for the same as per exchange rate prevailing at the time of procurement, accounted for the difference between actual payment and amount earlier debited as exchange fluctuation and sold the product at the rates which corroborates the exchange rate prevailing at the time of sales.

lxxi. The domestic industry does not dispute that the Designated Authority should examine other factors causing injury. However, such claims should be based on quantitative information and not mere statements.

lxxii. The arguments with regard to MCPI technology are totally without basis. The decline in profitability is because of dumping and not because of any other factor. In fact, even if capacity utilization of MCPI is considered at reasonable level, it would show that the company would have suffered significant financial losses. In fact, as submitted by the petitioners earlier, considering the prices of PX that have been prevailing since POI, no producer of PTA can claim that it is earning profits on production and sales of the product under consideration - whether in India or globally.

lxxiii. As regards the contention that injury may also be attributable to disproportionate increase in wage cost, it is submitted that the petitioners have not claimed injury on this account. Further, AD Rules do not specify that injury to the domestic industry should be visible in respect of all parameters. While wage cost per unit of production declined in POI, profitability steeply deteriorated, thus establishing that the decline in profits in POI is not because of increase in incidence of wage cost per unit of production.

lxxiv. The contention that capacity expansion in 2010-11 led to high fixed cost and reduced profitability, is not correct. Increase in capacity led to only a marginal decline in profits in 2010-11. Thereafter, profitability of the domestic

industry steeply declined and the domestic industry suffered financial losses despite same level of capacity. In fact, in POI, whereas capacity utilization increased, losses further declined steeply.

lxxv. As regards the contention that due to technical problems suffered by MCPI, reduced export obligation was allowed to them, it is submitted that domestic industry has not claimed that the dumping of the product under consideration has prevented them from selling the product. Rather, domestic industry has claimed adverse price effects of dumped imports.

lxxvi. The contention that prices of IOCL are lower than the other domestic producers by 4-10% and the applicants are suffering price effect due to lower prices of IOCL, is baseless. Petitioners submit that there is no evidence provided by the PTA User Association that the consumers benchmark their prices to the prices offered by IOCL. In fact, majority of the consumers are being represented by PTA User Association and therefore, the association should be well aware how its members are buying PTA in Indian market. This is another example of serious efforts being made by PTA User Association in misleading the Designated Authority and making efforts to impede the present investigations.

lxxvii. The Users Association simultaneously contended that the domestic industry's prices are impacted by IOCL prices and also benchmarked by CFR China prices. This clearly shows contradictory and inconsistent arguments by the association. Imports of the product under consideration occur around prices declared in ICIS or Platts. It is not the argument of PTA Users Association that the imports are not made around the prices reported in ICIS or Platts. Thus, the CFR China prices reported by ICIS or CFR China prices reported by Platts is nothing but the prices which are benchmarked at which imports can be and were made in that period. The Designated Authority may kindly compare the prices reported in ICIS/Platts with the price at which responding exporters have exported the product to India.

lxxviii. Since PTA Users Association is representing the interests of the users, the association should at the least be aware why its members are benchmarking their prices with the domestic industry on the basis of these Platts or ICIS prices. The argument clearly implies either of the two situations – (a) the users have not even informed the Users Association of the facts in which these users are buying material from domestic and imported sources, OR, (b) the users association is aware of the facts, but has attempted to present distorted facts before the Designated Authority in an attempt to create confusion and impede the process of investigations. This also clearly shows that the Users Association is not with clean hands before the Designated Authority. The User Association concedes that the domestic industry has fixed its prices on the basis of prices mentioned in ICIS/Platts. Since the imports are being made by the consumers considering these prices mentioned in ICIS/Platts, it follows that domestic industry prices are impacted by the prices at which imports are being made in India. Thus, the reasons for domestic industry to fix its prices based on prices mentioned in ICIS or Platts is the fact that the consumers consider these prices as the prices at which they can import the product and compare the prices offered by the domestic industry. If the consumers find that the prices reported in ICIS/Platts are lower than the prices quoted by domestic industry, the consumers have an option of importing the product at the prices mentioned in ICIS/Platts.

lxxix. The pricing mechanism followed by the domestic industry is based on import parity. In order to arrive at import parity, various expenses/cost that the consumers shall incur (upto consumption point) in importing the product are considered by the domestic industry and the domestic industry forced to fix the prices keeping in mind this landed cost to the consumer at consumption point for the imported product. If the concern of the association is that the domestic industry should not add customs duty to the import price, should sell the product at CIF import prices and the domestic industry is making extra profits by charging customs duty, this is really laughable at the least. Not only it is established business situation in the Country that the domestic industry fixes its prices considering the import price and basic customs duty, the user association cannot say that their prices are benchmarked to CIF import prices. The argument defeats the very purpose for which the Govt. of India and Governments globally fixes customs duty and way these are utilized by business enterprises.

lxxx. The opposing interested parties argued that price of PX have increased however price of Naphtha did not increase at the rate of increase in PX. But Increase in price of Naphtha was commensurate with increase in

price of PTA. Two of the three domestic producers produce PX from Naphtha and consume it to produce PTA. Therefore actual cost of production should be taken for PX and not any notional price for determination of cost of production, NIP, profits/loss, and return. As against these arguments, the petitioners submit that the raw material involved for production of the product under consideration is PX. Naphtha is not the raw material involved for production of the product under consideration. There is no evidence provided that producers of PTA benchmark their prices to Naphtha prices, nor globally, Naphtha prices benchmark the PTA prices. PTA prices are benchmarked on PX prices. Further, the relevant legal requirement is whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree. In a situation, where prices of PX have been increasing over the relevant period, natural expectation of every producer is to increase the selling prices.

- Ixxx. The consumer association has selectively considered the depreciation rupee and its impact on PTA prices. The consumer industry has conveniently ignored the impact of depreciation of rupee on the cost of production of domestic industry, selling price of the product and import price of the product. It cannot be said that depreciation of rupee impacted selectively either PTA prices or PTA costs. Whether the Rupee appreciates or depreciates, the same impacts both the raw materials and finished product. In any case, it is established practice of the authority to proceed with determination based on exchange rate prevailing during period of investigation. Despite these alleged rupee depreciation; the domestic industry has suffered injury, as established by the decline in profits and return on investment during this period.
- Ixxxii. The opposing interested parties have argued that the depressed increase in demand is due to the fact that certain users have shifted to use of recycled material such as PTE bottles which is a substitute of fresh PTA. The petitioners submit that the legal requirement is whether there is a contraction in demand and whether pattern of consumption of the product under consideration has undergone a change. Change in pattern of consumption is relevant, as this change in pattern of consumption might have led to decline in demand for the product in the Country, which might have in turn resulted in decline in domestic industry's sales, production, capacity utilization, etc. As far as these requirements are concerned, petitioners submits that there was positive growth in the demand for the product in the country and therefore contraction in demand for the product under consideration was not one of the factors for injury to the domestic industry. Pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone a significant change. This is clearly established by rising demand. Thus, the fact that use of recycled product has increased is entirely immaterial in the present case.
- Ixxxiii. The opposing interested parties have not provided any information to substantiate the claims that MCPL is suffering losses on account of power consumption as (i) no firm contract for coal supply (ii) there has been change in clearance requirements for energy systems by State Pollution Control Board. The argument is baseless. Further, the arguments are contradictory in as much as the association has contended that MCPI has suffered due to (a) technical factors, (b) PX supplies, (c) coal supply. Above all, all these factors could have impacted production of the company. Petitioners have however claimed that the dumping of the product under consideration has led to significant erosion in profits of the domestic industry.
- Ixxxiv. The opposing interested parties have wrongly argued that MCPL is incurring substantial cost on freight in transporting raw material for its manufacture of raw material which increased its cost of production. As far as injury to the domestic industry and its determination is concerned, the data relating to domestic industry as a whole and separately for MCPI both shows steep decline in profits, cash flows and return on investment. MCPI data shows that the company was earning profits earlier and suffered financial losses in the POI. With the same locational situation, if the company was earlier earning profits and now suffering losses, it must be concluded that the deterioration in performance of the company is not because of locational situation but because of dumped imports. When the plant of MCPI was conceived, it was well known that the plant will be at its present location. The plant was earning profits for quite some time.
- Ixxxv. The argument that the petition has been initiated to seek protection for planned capacity expansion by RIL is baseless. The petition is based on the injury suffered by the domestic industry during POI i.e., 2012-13 on the grounds that significant dumped imports have caused injury to the domestic industry. The Designated Authority after analysis of all the arguments of the domestic industry and other interested parties came to the conclusion

that the domestic industry has suffered injury due to dumping of product from subject countries in the POI and recommended provisional anti-dumping duty which was imposed by Ministry of Finance. Hence, the argument of the interested parties is baseless.

lxxxvi. As regards the argument that there has been no volume injury, the petitioners submit that the preliminary finding issued by the authority establishes adverse price effects of imports on the domestic industry.

lxxxvii. The argument that the applicants have increased their prices based on the freight which is not paid by them, is incorrect. There is no dispute that the domestic industry prices are influenced by the price at which the imports can be made. Further, the facts clearly show that the domestic industry is continuing to suffer losses. Thus, the price at which the domestic industry is selling the product is insufficient to recover the cost of production of the product and the domestic industry is suffering financial losses. Since these prices are influenced by the import prices, it must be considered that the imports are causing injury to the domestic industry.

lxxxviii. The argument that the Domestic Producers have further increased the price of PTA after the imposition of ADD and are trying to seek profit at the cost of domestic users is incorrect and baseless. The domestic industry is continuing to suffer financial losses. Thus, the price at which the domestic industry is selling the product is insufficient to recover the cost of production of the product and the domestic industry is suffering financial losses. Since these prices are influenced by the import prices, it must be considered that the imports are continuing to cause injury to the domestic industry.

lxxxix. As regards the contention that the domestic producers IOCL and RIL are making huge profits on year on year basis, the petitioners submit that except for the producers who have their own captive PX and who are transferring PX at less than its value in PTA costs, none of the global producers are earning profits. Further, though RIL is not suffering financial losses, the company has faced significant decline in profits which also tantamount to injury under the Rules. As regards IOC, since the company is not part of “domestic industry”, the issue is entirely irrelevant. It has not been shown that the profits of IOC have not declined. Given the situation of RIL, it can be safely concluded that IOC profits have also declined.

xc. The opposing interested parties argued that imposition of ADD will allow RIL to raise the price of PTA and will also kill the competition in the Polyester market as the other polyester producers will no longer be able to compete with RIL due to high price of PTA. The petitioners submitted that in the POI, merchant sales of MCPI were higher than RIL. Further, there are several cases where anti dumping duty has been imposed and where the product is being produced only by one company in India. Such being the case, the mere fact that production of one company is higher does not bar the company from seeking protection. As regards the fact that RIL is producing both the product and downstream products, the same does not vitiate the position any way. Contrary to the argument of the interested parties, RIL is at present at a disadvantaged position in downstream products, as their competitors in India are having access to unfairly priced dumped imports.

xcii. The significance and purpose of anti-dumping duty is to maintain a level-playing field and prevent dumping, while allowing for healthy competition. The domestic industry of PTA is suffering material injury due to presence of dumped imports. If PTA industry is expected to face low utilization ratio and steep price competition, it is all the more important to provide the industry with level playing field.

xciii. The argument that increases in imports after the initiation of investigation was due to failure of domestic producers to satisfy the market demands due to technical reasons is incorrect. The price difference between PTA and PX declined further after the POI, which establishes intensified dumping. Assuming for sake of argument that there was increased need for imports to meet the demand that could not have been compulsion with the foreign producers to intensify dumping.

xciiii. The argument that anti-dumping duty is imposed against all main exporting countries to ensure monopoly control and enrich RIL is baseless. Anti-dumping duty is imposed on the basis of positive evidence of dumping and consequent injury to the domestic industry. Further, the interested parties have stated on one hand that Malaysia has not been included and on the other hand has stated that all major exporting countries have been

included. Evidently, the arguments of the interested parties are highly biased. In any case, duty can be imposed only if the product is being exported at dumping prices.

xciv. As regards the argument that like the Indian producers, Korean producers determine their prices on the same international market price, and there is no price undercutting, petitioners submit that it is entirely irrelevant for determination of dumping that the exports have been made at the international prices. Only normal value and export price alone are relevant. The normal value has been defined under the Rules and has to be determined accordingly. Further the Designated Authority has determined positive price undercutting in its preliminary findings. The Rules require the authority to determine whether the imports were undercutting the prices of the domestic industry in the market, OR, whether imports were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry in the market. Thus, in a situation where the domestic industry prices are the same as import prices, it is proved beyond doubt that the imports are forcing the domestic industry to sell at a price which led to suppressing/depressing effect.

xcv. As regards the argument that both RIL and IOC have marked significant levels of profits, the petitioner submits that the relevant legal requirement is whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree. In a situation, where prices of PX have been increasing over the relevant period, natural expectation of every producer is to increase the selling prices. However, the domestic industry is unable to increase its prices in proportion to increase in cost resulting in price suppression. The selling price of the domestic industry has not increased in proportion to the increase in the costs. Further, the domestic industry has not been able to increase its prices in proportion to the increase in costs on account of PX.

xcvi. The interested parties have contended both that the imports have declined in POI and that the imports have increased in POI. The argument of the interested parties itself shows that (a) the price undercutting and price suppression suffered by the domestic industry at present is due to dumping, (b) even when the domestic industry was earlier earning profits, it was suffering severe losses in the POI, which is due to dumping of the product in the Country.

xcvii. The domestic industry has not claimed that the dumping of the product under consideration has prevented the domestic industry from selling the product and its production has suffered. Interested parties have assumed an argument which the domestic industry has not at all made. The domestic industry has claimed adverse price effects of dumped imports on the domestic industry. The domestic industry is able to sell whatever they produce so long as the prices offered by the domestic industry are comparable to the landed price of imports. Thus, adverse effect of dumping on the domestic industry is in respect of parameters such as price undercutting, price suppression/depression, inventories, profit, cash flow and return on investment.

xcviii. As regards the argument that RIL admitted operating profits in its annual report in petrochemical sector and RIL was not injured by the PTA imports, the petitioners submit that the argument of the interested party does not have any basis. It is mainly because in the calculation of COP and profitability RIL has used internal intra-company transfer price of PX. Thus, the calculations showed RIL's PX Plant to have undergone profit by sales to other PTA producers and its sales to own PTA Plant, and RIL's PTA Plant made loss from sales to other polyester producers and from internal sales to its own polyester plants. This calculation is misleading and in actuality it should have been done in accordance to the Indian GAAP. The injury to the domestic industry is claimed for the product concern and not for the sector as a whole. While value of PTA for RIL was higher in downstream products, the same was lower for the consumers. Thus, the dumping of the product under consideration has been causing injury not only to the merchant market of RIL, but also in the downstream products. Designated Authority is required to proceed based on records maintained by the company. Further, RIL has not claimed that it has suffered losses. Data relating to RIL may be seen.

xcix. As regards the contention that low production volume was one of the reasons for financial losses of MCCPI, it is submitted that low production volume was not one of the reasons for financial losses of MCPI, as is established by the increase in production and decline in profits. Company earned profits with lower production and suffered losses with higher production.

c. As regards the contention that since market prices of crude oil, naphtha, PX and PTA are determined based on international market price, global economy and demand/supply condition are the main factors for price fluctuation, it is submitted that the present investigation is against imports of PTA. And price of Paraxylene, being the raw material of PTA and the product concerned alone are the relevant and determining factors. The market prices of crude oil and naphtha are irrelevant to the present investigation. Further, reasons for dumping are not relevant for the present purpose. Only the fact of dumping is relevant. The Designated Authority is not conducting a study on petrochemical industries.

ci. The contention that PTA prices are determined by international market prices which are announced on a daily or weekly basis is entirely irrelevant for determination of dumping. Only normal value and export price alone are relevant. The normal value has been defined under the Rules and has to be determined accordingly. Mere fact that the goods have been exported at international prices does not mean “no dumping”.

ii. The sales volumes of RIL do not constitute predominant position. In fact, sales volumes of MCPI were higher than RIL. Further, all parties concede that domestic industry prices are linked to import prices. No party has established that MCPI prices are linked to RIL prices. The argument is misleading and factually incorrect.

iii. The imports of PTA have substantially increased post preliminary findings. Dumping has intensified after initiation of investigations. Significant increase in imports at reduced prices has led to decline in demand of the domestic industry product and accumulated inventories.

civ. As regards the contention that there is no causal link, since volume of imports increased so also profitability, the petitioners submit that it is incorrect. The data proves that as imports increased, profitability of the domestic industry declined.

cv. The contention that MPCL is suffering due to shortage of PX and not due to imports, is incorrect. At one place association has contended that MCPI could not produce due to technical problem, at other place, the association has contended that MCPI is suffering due to PX. The association has resorted to all sorts misleading or contradictory statements. MCPI is not suffering due to shortage of PX. It is not established how availability of raw material is a cause of injury to the domestic industry. In fact, availability of raw material would have adversely impacted production and capacity utilization. The petitioner has not claimed that dumping of the product under consideration prevented the domestic industry from producing and selling the product.

#### **Examination of the Authority**

49. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below:

- a. As regards the submission that price of IOCL, who have not supported the petition, is lower than the other domestic producers by 4-10%, the Authority notes that IOCL has neither supported nor opposed the applicants in the present investigation and therefore cannot be construed as domestic industry under the Anti-dumping Rules. The applicant domestic producers in the present investigation i.e. MCPI and RIL constitute domestic industry under the Anti-dumping Rules. Therefore, in terms of the provisions laid down under the Anti-dumping Rules, the Authority is required to investigate and determine injury in respect of the domestic industry only.
- b. As regards the contention that expansion of PTA capacity by RIL is indicative of their healthy and profitable position, the Authority notes that the decision for expansion of capacity of production is generally governed by prospective demand in the market. Therefore, such business decision cannot be interpreted as indicative of absence of injury to an industry.
- c. As regards the contention that RIL in Annual Report admitted the petrochemical sector realized 11.2% and 8.2% of operating profit which were significantly above company-wide profit, the Authority notes that injury to the domestic industry is required to be analysed for the product concern and not for the

sector as a whole. RIL being a multi-product company, performance of company as whole cannot be indicative of the injury being suffered by the company in one of the products.

- d. It has been contended by the opposing interested parties that due to the PX PTA delta decreasing, MCPI incurred losses but RIL and IOC achieved profits, the Authority notes that cost of production of subject goods produced through different technologies may differ, but that does not mean that the handicap suffered by MCPI due to manufacturing the subject goods from the stage of PX is the sole cause of injury. Moreover, RIL is also faced with declining profits in the subject goods.
- e. As regards the submission that RIL treats PX production as a separate profit centre and transfers cost of PX to PTA at cost plus or market price basis inflating the actual cost of PTA, it is noted that the Authority has determined the NIP based on the accounts maintained by the domestic industry and in accordance with Annexure III of the Rules and established practices of DGAD.
- f. As regards the submission that DGAD should not grant protection to the domestic industry when only one domestic producer (MCPL) has a low rate of capacity utilization and that too because of its capacity expansion and problems in its production facilities, the Authority notes that in anti-dumping investigation the injury analysis is required to be conducted for domestic industry as a whole and not for individual domestic producers. Moreover, in the present investigation, the crux of the injury is on account of adverse effects of imports on profits, cash flows, return on investment, etc. As regards the submission that MCPI suffered technical problems in their plant which is the real cause of injury, the Authority notes that it is a fact that MCPI suffered technical problems in their plant, but that cannot be interpreted as the only cause of injury. Further, while determining NIP, the impact of such factors has been taken into account.
- g. The opposing interested parties have contended that the domestic industry has not established potential decline in various factors. In this regard, it is noted that only in a situation where actual performance over the injury period does not show injury to the domestic industry, the authority is required to examine potential situation in respect of various economic parameters.
- h. It has been alleged that 2009-10 was a time of global recession and any analysis with the same as base year, is inaccurate. The Authority notes that the injury is largely based on price parameters and therefore alleged impact of global recession is entirely irrelevant.
- i. As regards the contention of the opposing interested parties that MCPI has claimed technical production problems in their letter to the Ministry of Environment and claimed the benefit of reduced export obligation, the Authority notes that it is a fact that MCPI suffered technical problems in their plant, but that cannot be interpreted as the only cause of injury. Moreover, MCPI has claimed adverse effects of imports on the parameters such as profits, cash flows, return on investment, etc. Further, while determining NIP, the impact of such factors has been taken into account.
- j. As regards the submission that MCPI suffered technical problems in their plant which is the real cause of injury, the Authority notes that it is a fact that MCPI suffered technical problems in their plant, but that cannot be interpreted as the only cause of injury. Moreover, the domestic industry has claimed adverse price effect of the imports from the subject countries and not volume effect.
- k. As regards the submission that fixation of prices by domestic producers of PTA is based on reference price which is CFR CMP reported by ICIS or CFR China reported by Platts and is independent of imports, the Authority notes that the prices announced by such sources do act as a benchmark for the domestic producers while determining their domestic selling prices. However, under the Anti-dumping Rules, for establishing injury and causal link, what is relevant is the actual landed price from the subject countries, which compared with the non-injurious price of the domestic industry, forms the basis for determination of injury margin.

1. As regards the submission that unlike other domestic producers MPCL is suffering due to shortage of PX and therefore actual cost of production should be taken for PX from the stage of Naphtha and not any notional price for determination of cost of production, NIP, profits/loss, and return, the Authority notes that claimed injury to the domestic industry is not on account of volume effect. Therefore, shortage of major raw materials impacting production of subject goods by the domestic industry is not relevant. The Authority further notes that PX and not Naphtha is a major raw material for the subject goods.
- m. As regards the contention that MCPI started incurring losses from the year it expanded its capacities and in turn resulted into losses, the Authority notes that MCPI has expanded its capacity in the year 2010-11 and this was the year when the industry has earned profits. Therefore, the argument is factually incorrect.
- n. As regards the contention that current exchange rate is 62.88, and if prevailing exchange rate is considered instead of 54, the level of price undercutting and price underselling would be eliminated, the Authority notes that in anti-dumping investigation the exchange rate prevailing during POI is relevant and not the current exchange rate.
- o. As regards the submission that separate injury analysis is required for each domestic producer as they have different production processes, the Authority notes that as per the Anti-dumping Rules, injury is required to be determined for the domestic industry as a whole.
- p. As regards the submission that 66% of RIL's PTA production is captively consumed and does not compete with imports, the Authority notes that the injury analysis has been done only for domestic sales. In view of the above, the need for conducting injury analysis for merchant and captive supply separately, as claimed by some of the interested parties, does not arise.
- q. As regards the submission that all economic parameters (including price undercutting, underselling, depression and suppression) should be examined on monthly basis due to wide fluctuation in price and cost, the Authority notes that dumping margin and injury margin have been ~~are~~ determined on monthly basis.
- r. As regards the submission that there is a significant difference between the costs of RIL and MCPI and simple cumulation of COP will distort the analysis, the Authority notes that injury to the domestic industry is required to be analysed for domestic industry as a whole and not in a segmental manner.
- s. As regards the submission that the pressure on the sales price of PTA is on account of under supply of PX and oversupply of PTA, the Authority notes that the domestic industry has not claimed injury on account of volume effect of imports. Therefore, shortage of major raw materials and over supply of subject goods impacting production of subject goods by the domestic industry is not relevant. Moreover, the contention that PTA is in over supply in India is not factually correct since the demand in India is more than the supply.
- t. As regards the submission that RIL's claimed operating losses from PTA domestic sales is on account of internal intra-company transfer price of PX, the Authority notes that the data/information furnished by the Company has been verified and the same has been relied upon along with the verified data/information furnished by the other constituent domestic industry.
- u. As regards the submission that 22% return on capital employed, allowed by DGAD, is not reasonable, the Authority notes that granting 22% return on capital employed is a consistent practice in the DGAD.
- v. The opposite interested parties argued that when imports increased to its peak in 2010-11, the Applicant generated maximum profits. Designated Authority has estimated negative price undercutting for 2009-10 and 2010-11 and in the 0-10% range for POI. Therefore, there was no reason for Applicant Domestic Producer to incur losses during 2011-12. The Authority notes that the injury analysis in this final

finding is self explanatory. As per the verified information, the domestic industry has suffered losses during the POI and positive underselling.

- w. The opposite interested parties argued that for determining NIP, profit, return on capital employed and cash flow must be determined after excluding extraordinary expenses and costs and adopting best utilisation method, the Authority notes that NIP for the domestic industry has been determined as per Annexure III of the Anti-dumping Rules and as per consistent practice in the DGAD.
- x. The opposite interested parties argued that the price of PX increased substantially during 2011-12 and 2012-13 while the price of naphtha did not increase at the rate in which prices of PX increased. However, the increase in prices of Naphtha was commensurate with increase in prices of PTA. Therefore, RIL cannot report loss and negative return on capital during 2011-12 and 2012-13. The Authority notes that the fact that Paraxylene producers have increased their prices in proportion to or more than their cost increases due to increase in naphtha prices is entirely immaterial for the present investigation as the subject goods is PTA and neither naphtha nor PX.
- y. As regards the contention that MCPL has no firm contract for coal supply, which has an adverse effect on its cost of production, causing injury, the Authority notes that the opposing interested parties have not provided any information to substantiate this above claim. MCPI has claimed adverse effects of imports on the parameters such as profits, cash flows, return on investment, etc.
- z. The opposite interested parties argued that MCPL has established its plant far away from the users and transportation cost incurred by it on the subject goods make it uncompetitive. Therefore, freight as a factor of injury must be investigated and considered by the Designated Authority in its attribution analysis. The Authority notes that the company was earning profits earlier and suffered financial losses in the POI with the same locational situation. Moreover, domestic industry must be seen as it exists and not under ideal situation.
- aa. The opposite interested parties argued that the market share of the Domestic Industry has remained static inspite of increase in demand. There is no connection between Domestic Industry's static market share in demand and the import from subject countries. The Authority notes that the domestic industry is not mandated to meet the entire domestic demand for becoming eligible for fair trade. Moreover, the domestic industry is in the process of expanding its capacity to meet the increased demand.
- bb. The opposite interested parties argued that MCPL procured PX (raw material) at substantially high prices from the related party. Designated Authority should reject such price shown by MCPL and adopt the low price at which the exporters procured PX for constructing NIP. The Authority notes that NIP has been determined as per Annexure III of the Rules and as per consistent practice in the DGAD.
- cc. The opposite interested parties argued that the adjustments relating to credit cost and freight cost for the computation of NIP requested by the Applicants cannot be allowed. The Authority notes that the detailed guideline for computation of NIP is laid down under Annexure III of the AD Rules and the same has been adopted while determining NIP in the present investigation.
- dd. As regards the submission that applicants, though not subject to customs duty, are charging the same at 5.583% from the customers while selling the subject goods in the domestic market, the Authority notes that as stated by the domestic industry, such pricing mechanism followed by the domestic industry is based on import parity.
- ee. As regards the submission that certain users of PTA Chips have shifted to use of recycled material such as Poly Ethylene Terephthalate (PET) bottles which is a substitute of fresh PTA, the Authority notes that such argument is baseless as there is no contraction in demand for the subject goods.
- ff. The domestic industry argued that since the credit offered by the domestic industry and foreign producers are different, the non-injurious price is required to be compared with landed price of imports

after appropriately adjusting the difference in the credit period. The Authority notes that NIP for the domestic industry has been computed as per Annexure III of the Anti-dumping Rules and as per consistent practice in the DGAD.

- gg. As regards the contention that freight cost is required to be adjusted for determination of injury margin, the Authority notes that injury margin has been determined by the Authority as per the Anti-dumping Rules and consistent practice in the DGAD.
- hh. As regards the request of the PTA User Association that the Designated Authority should verify the valuation reports submitted by the petitioners to the Central Excise Authorities to establish whether there is any undercharging of excise duty, the Authority notes that under Rule 4 of the Anti-dumping Rules, it is not mandated to conduct investigations regarding undercharging of excise duty.

#### **Cumulative Assessment**

50. Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

51. The Authority notes that:

- a) The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
- b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
- c) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

52. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.

53. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-dumping Rules.

#### **Volume Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

##### **a) Demand and market share**

54. Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Demand	MT	3456617	3952141	3876427	4096498
Trend	Index	100	114	112	119
Imports from Subject Countries	MT	308102	618818	511137	586986
Trend	Index	100	201	166	191
<b>Imports From Other Countries</b>					
China PR	MT	-	5262	6490	3368
EU	MT	6881	1272	5390	11374
Others	MT	159505	119018	71896	46230
Total	MT	166386	125552	83776	60972
Trend	Index	100	75	50	37
Sales of Domestic Industry (Including captive consumption)	MT	2454129	2760771	2739514	2906540
Trend	Index	100	112	112	118
Sales of Other producer	MT	528000	447000	542000	542000
Trend	Index	100	85	103	103

#### i) Market Share in Demand

55. Considering imports from various sources and sales of the domestic industry, market share of subject imports in demand in India was examined. The Authority notes that the share of domestic industry has remained static despite increase in demand, whereas share of dumped imports from subject countries increased substantially during the POI as compared to the base year.

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Imports from Subject Countries	%	8.91	15.66	13.19	14.33
Import from Other Countries including China & EU	%	4.81	3.18	2.16	1.49
Sales of Domestic Industry	%	71.00	69.86	70.67	70.95
Sales of Other producer	%	15.28	11.31	13.98	13.23

#### Import volume and market share

56. The volume of imports of the subject goods from the subject countries is as under:-

Particulars		Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Volume	Subject Countries	MT	308102	618818	511137	586986
	Other countries including China & EU	MT	166386	125552	83776	60972
	Total imports	MT	474488	744370	594914	647958
Market Share in Imports	Subject Countries	%				
	Other countries	%	64.93	83.13	85.92	90.59

57. It is observed from the above table that imports from subject countries increased significantly during the POI as compared to the base year.

**Share of imports in relation to production**

58. Authority notes that the imports from subject countries have increased in relation to the production of the domestic industry, as is evident from the following table:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Imports from Subject Countries	MT	308102	618818	511137	586986
Production of domestic industry	MT	2454835	2754659	2753708	2931680
Imports from subject countries in relation to production of domestic industry.	%	12.55	22.46	18.56	20.02

e) **Capacity & capacity utilization**

59. Capacity and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Capacity MT	MT	2,595,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000
Production	MT	2,454,835	2,754,659	2,753,708	2,931,680
Capacity utilization	%	95	81	81	86

60. It is observed that capacity utilization of the domestic industry declined during POI as compared to the base year, despite increasing demand.

f) **Production**

61. Production data of the domestic industry is given in the following table:-

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	MT	2454835	2754659	2753708	2931680
Trend	Index	100	112	112	119
Demand	MT	3456617	3952141	3876427	4096498
Trend	Index	100	114	112	119
Production in relation to Demand	%	71.02	69.70	71.04	71.57

62. It is observed that production of the domestic industry has increased due to increase in capacity.

g) **Sales volume**

63. Sales volume of the domestic industry is given in the following table:

	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Domestic sales (Including captive consumption)	MT	2454129	2760771	2739514	2906540
Trend	Index	100	112	112	118
Demand	MT	3456617	3952141	3876427	4096498
Trend	Index	100	114	112	119
Market Share of domestic industry in Demand	%	71.00	69.86	70.67	70.95

64. It is observed from the above table that sales of the domestic industry have increased during the POI as compared to the base year. However, in percentage terms, it remained static.

### **I. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

65. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

#### **i. Price Undercutting**

66. The net sales realization has been arrived after deducting outward freight and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty including applicable cess to the CIF value of subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry and it was found that the price undercutting from the subject countries is negative during the entire injury period including POI. In this connection the Authority notes the submission of the domestic industry, that while they are selling the goods in the domestic market on “cash against delivery”, the foreign producers have been offering interest free credit of up to 180 days, the landed value computed by the Authority is not comparable with the net sales realization of the domestic industry and the non-injurious price determined by the Authority. The domestic industry has also claimed that the freight cost of the domestic industry has been completely ignored while comparing the domestic industry price with landed price of imports. The Authority has determined the landed value of the subject goods at ex-port level and the net sales realization of the domestic industry at ex-factory level as per its established practice.

	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
<b>Subject Countries</b>					
Landed price of imports	Rs./MT	47016	54115	63191	65056
Trend	Index	100	115	134	138
Net Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	138	145
Price Undercutting	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting	%	(***)	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting Range	%	(5 – 15)	(5 – 15)	(0 – 10)	(0 – 10)
<b>Korea RP</b>					
Landed price of imports	Rs./MT	47226	52738	62904	64936
Trend	Index	100	112	133	138
Net Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	138	145
Price Undercutting	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting	%	(***)	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting Range	%	(5 – 15)	(5 – 15)	(0 – 10)	(0 – 10)
<b>Thailand</b>					
Landed price of imports	Rs./MT	46731	55602	63405	65246
Trend	Index	100	119	136	140
Net Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	138	145

Price Undercutting	Rs./MT	(***)	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting	%	(***)	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting Range	%	(5 – 15)	(10 - 20)	(0 – 10)	(0 – 10)

### ii. Price Underselling

67. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules. The analysis shows that during the POI the landed value of subject imports were below the non-injurious price of the domestic industry as can be seen from the table below.

Particulars	Unit	Korea	Thailand	Subject countries
Non-injurious price (Bulk)	Rs./MT	***	***	***
Non-injurious price (Packed)	Rs./MT	***	***	***
Non-injurious price (Wt. Average)	Rs./MT	***	***	***
Landed price (POI)	Rs./MT	64936	65246	65056
Price underselling	Rs./MT	***	***	***
Underselling	%	***	***	***
Underselling - Range	%	0-10	0-10	0 - 10

### iii. Price suppression/depression

68. The Authority examined whether the effect of the dumped imports was to depress the prices of the like article in India, or prevent price increases which would have otherwise occurred.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	116	164	180
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	138	145
Landed price of imports (Subject countries)	Rs./MT	47016	54115	63191	65056
Trend	Index	100	115	134	138

It may be seen from the table above that the cost of sales has increased from 100 to 180 from 2009-10 to POI, the selling price increased only from 100 to 145 during the same period. The Authority also notes that the landed prices have increased from 100 basis points in base year to 138 basis points during the POI. This shows that the prices were suppressed on account of dumped imports and the domestic industry was not able to increase its prices in proportion to increase in costs.

### Economic parameters of the domestic industry

#### i. Profit/Loss

69. The profitability of the domestic industry is given in the following table;

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Profit	Rs./Lacs	***	***	(***)	(***)
Trend	Index	100	114	(39)	(117)
Cash Profit	Rs./Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	125	2	(60)
Return on Capital Employed	%	***	***	(***)	(***)
Trend	Index	100	120	(35)	(110)

70. It is seen from the above table that profitability of the domestic industry declined significantly during the POI as compared to the base year. Cash profits as well as return on investment have also declined in the POI as compared to base year as well as the previous year.

**ii. Cash Flow**

71. The Authority has examined the trends in cash profits in order to examine the impact of dumping on cash flow situation of the domestic industry. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cash profits	Rs./Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	125	2	(60)

It is seen that the cash profits of the domestic industry declined from 2011-12.

**iii. Inventories**

72. Inventories with the domestic industry moved as follows;

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Average Stock	MT	4,747	3,634	3,554	11,069
Stock as no. of days sale	Days	***	***	***	***

It is noted that inventories with the domestic industry increased in the POI as compared to the base year as well as the previous year.

**iv. Productivity**

73. The Authority notes that productivity of the domestic industry has increased during the POI as compared to base year.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
Productivity per day	MT	7014	7870	7868	8376

**v. Employment and Wages**

74. It is seen from the table below that the employment level has increased during the POI marginally as compared to the base year.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	107	105	104
Wages	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	152	174	175

**vi. Magnitude of Dumping**

75. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margins determined in respect of the subject countries are above de-minimis.

**vii. Growth**

76. The Authority notes from the table below that growth of the domestic industry in respect of production, domestic sales, profit/loss, ROI, etc have declined during the POI as compared to the growth achieved in 2010-11.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Production	%	-	12.21	(0.03)	6.46
Domestic Sales Volume	%	-	12.49	(0.77)	6.10
Cost of Sales	%	-	16.20	41.06	9.64
Selling Price	%	-	12.07	22.92	5.28
Profit/(Loss) per unit	%	-	-14.41	-134.98	-158.54
Return on Capital Employed	%	-	16.64	-127.89	-228.91

**viii. Ability to raise capital investment**

77. The Authority notes that one of the constituent of the domestic industry is involved in production of multiple goods and ability to raise capital is not a factor for injury analysis. Further, the other constituent domestic industry has been referred to BIFR.

**ix. Factors Affecting Domestic Prices**

78. The examination of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price underselling in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is the landed value of the imports of dumped subject goods from subject countries.

**J. CONCLUSION ON MATERIAL INJURY**

79. In view of the above, the Authority concludes that the dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India. However, imports of the subject goods from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry in the market marginally. Further, while cost of production kept increasing over the injury period, the increase in selling price was not in proportion to the increase in cost of production. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increase that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is found that though demand for the subject goods increased significantly, the production and sales of the domestic industry has not increased in proportion to the increase in demand. Resultantly, the domestic industry did not increase its market share despite increase in capacity and demand. Profitability of the domestic industry declined. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Both return on capital employed and cash profits marked negative growths in POI. Growth in respect of price parameters shows an adverse impact on the domestic industry. It is thus concluded that the domestic industry has suffered material injury.

**K. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS**

80. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. Accordingly, the following parameters have been examined:-

**(a) Volume and prices of imports from third countries**

81. During POI, imports of the subject goods from countries other than the subject countries have been insignificant in volume. Therefore, the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

**(b) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

82. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

**(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption**

83. The Authority notes that demand for the product showed significant increase during the injury period and also during POI. The Authority thus concludes that injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

**(d) Development in Technology**

84. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

**(e) Export performance of Domestic Industry**

85. Performance of the domestic industry has been segregated for domestic and export market. Therefore, any possible decline in export performance is not a cause of injury to the domestic industry.

**(f) Productivity of the Domestic Industry**

86. Productivity of the domestic industry has increased during the POI. However, profitability of the domestic industry showed decline.

87. From the foregoing, the Authority concludes that there is no evidence of injury being caused due to any other factor other than the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**L. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK**

88. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated over the injury period. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- i The dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India.
- ii While the cost of production/sales kept increasing over the injury period, the increase in selling price was not in proportion to the increase in cost of production/sales.
- iii The imports were suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increase that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports.

- iv Profitability of the domestic industry declined. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Both return on capital employed and cash profits marked negative growths in POI on account of dumped imports.
- v The financial performance of the domestic industry has deteriorated in respect profit, return on capital employed and cash flow, due to dumped imports.

89. Thus the Authority concludes that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

#### **M. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN**

90. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules, as amended. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries.

S. No.	Channel of Export	Name of producer	Exporter	Non Injurious Price USD/MT	Landed price USD/MT	Injury margin US\$/MT	Injury margin %	Injury margin Range %
1	Korea RP-India	Samsung General Chemical Co Ltd	Samsung C&T	***	***	***	***	0 - 10
2	Korea RP-India	Taekwang Industrial Co Ltd	Taekwang Industrial Co Ltd,	***	***	***	***	0 - 10
3	Any	All other Producers	All other Exporters	***	***	***	***	0 - 10
4	Thailand- India	Indorama Petrochem Ltd	Indorama Petrochem Ltd	***	***	***	***	0 - 10
5	Thailand- India	TPT Petrochemicals Public Limited	TPT Petrochemicals Public Limited	***	***	***	***	0 - 10
6	Any	All other producers	All other Exporters	***	***	***	***	0 - 10

#### **N. Post Disclosure Comments**

91. The following are the post-disclosure comments/submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties:

- i. The Disclosure Statement issued by the Authority is based on incorrect appreciation of facts and law. It does not take into account many of the submissions made by the respondents. For example, the respondents had submitted that Designated Authority is bound to determine all the economic factors in light of the admitted technical problem faced by MCPL. But, the Authority brushed aside the said submission and also the cited jurisprudence.
- ii. Contention of the applicant domestic producers that in terms of Rule 14 of AD Rules, the Designated Authority shall “not” terminate an investigation “unless” it determines that the volume of dumped imports, actual “and” potential, is de-minimis”, is incorrect.
- iii. The Authority has stated in the disclosure statement that injury margin and price underselling have been determined month wise. A narrow range of such month-wise determinations should have

been disclosed in the disclosure statement. The Authority should also have disclosed the actual calculation of the landed value with the relevant adjustments from the CIF value.

- iv. The Authority has exercised confidentiality in the disclosure statement, especially regarding information pertaining to the details of directors of Sam Nam, determination of NIP etc. While non-disclosure of details of directors of Sam Nam affects the standing of the applicant domestic producers, non-disclosure of details/methodology of NIP casts doubt about the magnitude of the NIP arrived at by the Authority.
- v. The faulty production technology in the Plant II of MCPL does not seem to have been taken care of by the Designated Authority while determining NIP. Further, the impact of the said factor does not seem to have been taken care of while computing market share in demand, share of imports in relation to production, determination of capacity utilization, determination of sales, etc. Injury due to such faulty production technology cannot be attributed to any other cause including the alleged dumped imports. The observation of the Authority in the disclosure statement that changes in technology have not caused injury to the domestic industry is incorrect. It is an admitted position that MCPL established Plant II during injury period and in such Plant, it is facing a number of technical problems and due to that it is suffering.
- vi. The Authority is required to clarify whether the domestic industry's contention on the issue of interest free credit and freight cost for the computation of NIP was accepted or rejected; merely stating that the established practice was followed is insufficient.
- vii. The domestic industry is not suffering any injury as there is no volume injury and price undercutting is negative.
- viii. It is an admitted position that MCPL suffers technical problems. The Authority cannot then logically conclude that such technical problem has not affected productivity.
- ix. It is an admitted position that the Applicant Domestic Producers as well as IOCL are able to sell whole of their production and even after achieving more than 100% capacity utilisation (except one plant II of MCPL which uses faulty production technology). No evidence has been produced by the Applicant Domestic Producers to establish that the users of the subject goods ever made any sustained pressure on the Applicant Domestic Producers to reduce the prices. In fact, the users always followed the dictate of the Applicant Domestic Producers in fixation of prices. The Applicant Domestic Producers earned huge profits based on the pricing formula forced by them on the user industry. However, only during POI due to changed circumstances, there was slight reduction in profitability of Applicant Domestic Producers (except in relation to Plant II of MCPL). The Applicant Domestic Producers also failed to place on record any evidence regarding loss of transactions for sales.
- x. Even before imposition of provisional anti-dumping duty, the Applicant Domestic Producers once again forced the users to adopt another formula of pricing the goods, so that the profitability of the Applicant Domestic Producers increased sufficiently. The imports have taken place only to fill the gap in demand and supply where the Applicant Domestic Producers failed to commit for scheduled supply of the subject goods. The quantity of import was never more than the shortfall in supply by the domestic producers. This proves that there is no causal link between imports and injury to the Applicant Domestic Producers.
- xi. The users of the subject goods do not have any intention remotely to cause any injury to the Applicant Domestic Producers by importing the subject goods. After imposition of provisional anti-dumping duty, the Applicant Domestic Producers as well as IOCL have increased the price of the subject goods. The Designated Authority has incorrectly noted the submission of the Respondents in para 17 (xii) of the Disclosure Statement. It was submitted that "every" producer "including" RIL increased the selling prices. It was submitted after increasing the price of PTA to

its outside users, RIL has not increased the prices of final products of PTA and due to that the users and down-stream of PTA suffering adversely.

- xii. Further, MCPL suffered injury due to its failure to stand in competition with other domestic producers. MCPL has established the Plant at a disadvantageous place in comparison to other domestic producers and due to this reason they fail to compete with other domestic producers. MCPL is situated in Eastern part of India. This results in payment of higher freight cost by the users, if they procure the subject goods from MCPL instead of from other domestic producers.
- xiii. In any case, MCPL has higher cost of production and is not able to recover from the users of the subject product; therefore, MCPL fails in inter-se competition among the domestic producers. This proves that due to inter-se competition among the domestic producers, MCPL is suffering injury apart from the fact that it has the faulty production technology.
- xiv. The Designated Authority has adopted exchange rate as 1 USD = INR 54.65. It is an undisputed fact that there is a huge devaluation of INR subsequently and the exchange rate is hovering as 1 USD=INR 62 which is becoming a permanent feature. Such change in the exchange rate has already eliminated effect of dumping/injury and provided a very beneficial situation for the Domestic Industry. Therefore, the Designated Authority may not recommend the imposition of anti-dumping duty.
- xv. It is apparent from the disclosure statement that month-wise weighted average normal value is compared with month-wise export price and then another weighted average is further applied to arrive at the final dumping margin. The Authority is requested to clarify under which legal provision such methodology adopted.
- xvi. NIP based on weighted average revised cost of two producers cannot be kept as confidential by the Authority.
- xvii. Rejection of Hyosung's data and refusal to grant it an individual margin on the ground of an "incomplete value chain" is without any legal basis. It is wholly unwarranted and arbitrary for the Authority to decline to grant Hyosung individual margins either due to lack of cooperation of third parties or due to its own act of not verifying the data submitted by SK Petrochemical.
- xviii. The Authority's conclusion on the basis of the transaction-wise imports data of DGCI&S that imports of subject goods from China PR and EU are de minimis is correct. The Authority has therefore correctly excluded China PR and EU from the scope and purview of the subject countries and terminated the investigation in respect of these countries in terms of Rule 14 of AD Rules.

92. The following are the post-disclosure comments/submissions made by the domestic industry:—

- i. The investigation should not be terminated in respect of imports from China and EU in terms of Rule 14 of AD Rules as the Rule states that the Designated Authority shall "not" terminate an investigation "unless" it determines that the volume of dumped imports, actual "and" potential, is de-minimis".
- ii. The import price of the responding exporters is not the best "facts available" information for the reason that it relates to a particular exporter and does not pertain to "any other exporters" for whom dumping margin and injury margin is determined under the category in "any other exporter/producer" or "non cooperating exporters". Therefore, determination of residual dumping margin and injury margin should be based on Indian customs data.

- iii. It is evident from the NIP figures disclosed to the petitioners that the working capital of MCC PTA India Corp Pvt Limited has been determined without excluding interest bearing credit purchase from the current liabilities. Interest bearing credit purchases cannot form part of working capital. The working capital is determined by deducting current liabilities from current assets. The current liabilities deducted are interest free funds/credits available to the business enterprises and to this extent, a business enterprise is not required to deploy funds (and incur a cost on such funds). It is for this reason that interest free funds/credits are treated as current liabilities and deducted from current assets in order to determine working capital. However, if current liabilities include any interest bearing loans, the same should be excluded from the current liabilities for determining working capital. Where a company has interest bearing credit purchases, such interest bearing creditors are included in creditors in accordance with GAPP and accounting standards. However, because, the company has paid a cost for it, this should be excluded from the current liabilities for determination of working capital.
- iv. The injury margin determined is inappropriate and understated for the reason that the comparison between NIP and import price is unfair, as the two figures are not at the same level. The injury margin is quite low and shows that the methodology adopted does not constitute fair comparison for the reason that difference in credit period between domestic industry and foreign suppliers not taken into account while determining injury margin. The injury margin is required to be calculated considering the credit cost.
- v. The Authority has not disclosed the methodology that has been applied for determination of cost of production of foreign producers, the elements of cost adopted and the methodology applied. The Authority has also not disclosed how it has satisfied itself about the reasonableness of the cost of production of the foreign producers.
- vi. Determination of non-injurious price is inappropriate and is against the object and intent of the dumping law and therefore, the NIP determined in the instant case is required to be revised upwards.
- vii. Authority must add excise duty to the domestic industry's non injurious price and countervailing duty on the imports for determining injury margin. The mere fact that excise duty and countervailing duty are cenvatable is wholly insufficient to decide whether excise duty should be added to the non injurious price and the customs duty should be added to the import price. If excise duty is not added to the non injurious price and countervailing duties is not added to the landed price of imports, the injury margin is proportionately understated.
- viii. Transportation cost forms a significant portion of the cost in case of domestic industry. The selling price and non injurious price of the domestic industry should be compared with the landed price of imports only after adding the transportation costs.
- ix. Reliance has already commenced commercial production in their new PTA plant having a capacity of 1.15 million MT/annum. The present value of these investments should be considered while granting reasonable profits.
- x. Capital employed should be determined considering present value of fixed assets. Adoption of net fixed assets is highly inappropriate.
- xi. The comparison of import price with non injurious price should be at fair level to determine actual extent of injury suffered by the domestic industry. The non injurious price and import price should be considered after either including or excluding associated freights. A comparison of non injurious price of the domestic industry without including associated freight with landed price of

imports after adding associated freights will not constitute a fair comparison and would lead to gross under estimation of the injury suffered by the industry.

xii. The rules provide that the Designated Authority shall consider non injurious price at ex-factory level. Sales tax, excise duty, discounts, commission are payable at ex-factory level and therefore the fact that injury margin is being determined at ex-factory level does not imply that the sales tax and excise duty cannot be added.

xiii. The domestic industry sells PTA on cash, whereas exports from subject countries under investigation supply PTA with an interest free credit period ranging from \*\*\* days to \*\*\* days. This is a significant cost as interest in India is at 12%. The users of PTA in India while negotiating with the domestic industry always calculate a value of this interest free credit to bargain and extract a lower price. This may be considered while determining injury to the industry.

#### **Examination by the Authority**

93. The Authority notes that most of the post-disclosure comments made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post-disclosure comments considered relevant are examined as below:

#### **Examination of comments made by the Producers/Exporters/Importers/Other Interested Parties**

- i. The contention that the Disclosure Statement issued by the Authority is based on incorrect appreciation of facts and law is devoid of any merit. The Authority notes that the essential facts that emerged during the course of this investigation were analyzed with the applicable law and corroborated with verifiable evidence to the extent deemed necessary and disclosed to the interested parties. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent considered relevant, have been examined and addressed in this final finding.
- ii. As regards the contention that Authority has exercised excessive confidentiality in the disclosure statement, especially regarding information pertaining to the details of directors of Sam Nam, determination of NIP, etc, the Authority notes that the non-confidential information furnished by the various interested parties have been made available in the public file. The non-injurious price is business sensitive information for the domestic industry and therefore treated as confidential in line with the established practices.
- iii. As regards the contention that the Designated Authority should have disclosed at least the narrow range of the month-wise injury margin and dumping margin, the Authority notes that the range percentage of the said determinations for POI as a whole were disclosed in the disclosure statement as per its consistent practice. The Authority further notes that it is neither the practice nor feasible to provide the month-wise range of dumping and injury margins.
- iv. As regards the contention that the faulty production technology in the Plant II of M/s MCC PTA India Corp. Pvt Ltd., does not seem to have been taken care of by the Designated Authority while determining NIP and conducting injury analysis, the authority notes that the NIP has been determined in terms of Annexure III of the AD Rules after taking in to account the loss of production due to technical problems faced by the Company in its new plant.
- v. Post-disclosure, interested parties contented that Authority's observation in the disclosure statement that changes in technology have not caused injury to the domestic industry is incorrect in the face of injury suffered by the domestic industry on account of faulty production technology in the Plant II of MCPI, the Authority notes that a fault in the existing technology cannot be interpreted as an introduction of new technology. It is true that snags in Plant II of M/s MCC PTA India Corp. Pvt Ltd have caused injury to the Company, but dumping of subject goods from the subject countries has aggravated the injury.

- vi. As regards the contention that the Applicant Domestic Producers earned huge profits based on the pricing formula forced by them on the user industry, the Authority notes that the pricing formula adopted by the domestic producers is in line with the international pricing formula.
- vii. As regards the contention that M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. has established the Plant at a disadvantageous place in comparison to other domestic producers and due to this reason they failed to compete with other domestic producers, the Authority notes that location of a plant and its associated advantages/disadvantages are not relevant under the anti-dumping law for injury analysis. The injury on account of dumping of subject goods from the subject countries has been established in the present finding.
- viii. As regards the contention that due to inter-se competition among the domestic producers, M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. is suffering injury, the Authority notes that the submission is unsubstantiated. During the course of the investigation, nothing relevant was brought before the authority to establish that injury to the domestic industry is actually on account of inter-se competition among the domestic producers and not due to dumping.
- ix. As regards the contention that the change in the exchange rate has already eliminated the effect of dumping and therefore Authority may not recommend the imposition of anti-dumping duty, the Authority notes that the entire investigation is based on POI data and post POI developments like changes in exchange rates have no relevance for recommendation of anti-dumping measures by the Authority.
- x. As regards the contention concerning the legal basis for undertaking weighted average dumping margin, the Authority notes that when a month-wise exercise is done, month-wise normal value is compared with month-wise export price to work out month-wise dumping margin. Thereafter, in order to determine the dumping margin for the POI as a whole, the Authority has computed the weighted average of the dumping margins by considering the month-wise exports as per the consistent practice.
- xi. As regards the contention of Hyosung that rejection of their data and refusal to grant them individual margin on the ground of an “incomplete value chain” is without any legal basis, the Authority notes that the issue has already been examined in detail in this finding. The value chain between the producers (SK Petrochemicals, SamNam and Lotte) and Hyosung (exporter) has been broken for a significant volume of exports of subject goods to India during the POI as the said producers have not cooperated.
- xii. As regards the submission that the Authority should clarify whether the domestic industry’s contention on the issue of interest free credit and freight cost for the computation of NIP was accepted or rejected; the Authority notes that for the reasons stated elsewhere in this finding, the request of the domestic industry in this regard has not been accepted.
- xiii. Some of the interested parties have submitted that due to non-stabilisation of the 2<sup>nd</sup> plant of M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. during the injury period, the Authority should have done injury analysis without taking into account the performance of their 2<sup>nd</sup> plant so that injury, if any, suffered by the

domestic industry on account of the technical problems faced in operation of the 2<sup>nd</sup> plant is excluded. The Authority has, therefore, made the injury analysis by considering the performance of the 2<sup>nd</sup> plant of M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. @ \*\*\*% of its capacity as was considered for determining NIP. The following Table gives the notional performance of the domestic industry in terms of the major economic parameters had the second plant of the Company operated without any technical problems during the injury period including the POI.

S. No.	Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (POI)
1	Capacity	MT	25,95,000	34,20,000	34,20,000	34,20,000
	Trend	Index	100	132	132	132
2	Production	MT	25,03,093	32,26,130	33,20,442	32,97,251
	Trend	Index	100	129	133	132
3	Capacity utilisation	%	96	94	97	96
	Trend	Index	100	98	101	100
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	172	177	178
5	Captive Consumption	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	98	99	96
6	Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	114	163	180
7	Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	112	138	145
8	Profit/loss	Rs./MT	***	***	(***)	(***)
	Trend	Index	100	100	(17)	(68)
9	Profit/loss before tax	Rs./lakhs	***	***	(***)	(***)
	Trend	Index	100	171	-28	-111
10	Depreciation	Rs./lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	213	210	216
11	Interest	Rs./lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	274	233	249
12	Cash Profit/loss	Rs./lakhs	***	***	***	(***)
	Trend	Index	100	170	8	-59
13	Profit/loss before interest & tax	Rs./lakhs	***	***	(***)	(***)
	Trend	Index	100	173	-22	-104
14	Return on Capital Employed	%	***	***	(***)	(**)
	Trend	Index	100	168	-23	-100

The Authority notes from the above Table that there is improvement in the production and sales of the domestic industry in POI as compared to the base year. However, the capacity utilisation of the domestic industry remained stable during the injury period. The Authority also notes that while both cost of sales as well as selling price increased over the injury period, the increase in selling price was not commensurate with the increase in the cost of sales. This has resulted in the domestic industry incurring huge losses from 2011-12 and the POI. Similarly, the return on capital after increasing from 100 basis points in 2009-10 to 168 in 2010-11, has declined to -23 points in 2011-12 and -100 points in the POI. The Authority also notes that one of the domestic producers constituting domestic industry could not cover its entire variable cost during POI due to dumped imports from the subject countries. The Authority, therefore, holds that the contention of some of the interested parties that the injury to the domestic industry is mainly on account of technical problems faced by one of the producers in its new plant is not correct.

#### **Examination of comments made by the Domestic Industry**

- i. As regards the argument of the domestic industry that even if volume of imports from China in the POI is considered as de-minimis, the Authority should rely upon the potential volume of imports (which is more than 3%) and therefore not terminate the investigation, the Authority reiterates that the provisions laid down under Rule 14 of the Anti-dumping Rules amply clarify that when either the actual imports

or the potential imports account for less than 3% of total imports, the investigation should be terminated.

- ii. With regard to the domestic industry's request to consider the lowest price as per DGCIS import data for the purpose of determining dumping margin and injury margin for the non-cooperative exporters, the Authority notes that the DGCIS import data does not give separately the details of imports of PTA made from co-operative exporters and other exporters. Therefore, the Authority does not consider the request of the domestic industry in this regard. The Authority further notes that the dumping margin and injury margin for the non-cooperative exporters have been determined on facts available basis, in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules and established practice in the DGAD, which includes the data of co-operative exporters, including month-wise data.
- iii. With regard to the request of domestic industry to include the interest bearing credit availed by M/s. MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. for purchase of imported paraxylene, the Authority notes that this Company has been importing Paraxylene on credit from foreign suppliers and the cost of raw materials include the cost of credit also. M/s MCC PTA India Corp. Pvt. Ltd. has considered the entire cost including the cost of credit and the impact of foreign exchange variation as part of material cost. Further, it has exhibited in its audited accounts the amount of credit availed from the foreign supplier as current liabilities. Since the Authority has considered the cost of PX as claimed by the Company (including credit cost and exchange rate variation), for determination of NIP, it has not agreed to the request of the domestic industry to exclude the interest bearing credit availed from raw materials suppliers from the current liabilities. Further, the Authority has determined the net working capital as the difference between the current assets and current liabilities as exhibited in the audited annual accounts of the Company in terms of Annexure III to the AD Rules. The Authority, therefore, holds that the submission of the domestic industry in this regard is not acceptable.
- iv. With regard to the submission of the domestic industry to determine injury margin by taking into account the interest cost on account of difference in the credit period allowed by the domestic industry and the exporter, the Authority notes that the injury margin has been determined as the difference between the landed value and the non-injurious price. While the landed value has been arrived at by considering the assessable value and the applicable customs duty and cess thereon as per Authority's established practice, the non-injurious price at ex-factory level has been determined in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-dumping Rules. This comparison does not capture the effect of the difference in the credit periods allowed by the domestic industry and the exporters.
- v. With regard to the comment of the domestic industry about how the Authority has satisfied about the correctness of data provided by the exporters, the Authority notes that the data on cost of production (raw materials, utilities, overheads, etc), selling & general administration expenses, financial and other expenses/income submitted by the exporters have been verified to the extent considered relevant from their audited accounts and the computerised accounting system.
- vi. With regard to the submission of the domestic industry either to include the freight incurred by the domestic industry in transporting the product to the customers factory/warehouse from the non-injurious price or to deduct from the landed value of the imported subject goods, the Authority notes that the 'Landed value' has been determined at the port level and the NIP have been determined at the ex-factory level as per the established practice and the Annexure III to the AD Rules respectively. Therefore, the freight charges incurred by the domestic industry in respect of transportation of subject goods from their factories to the customer's premises have not been considered.

vii. As regards the contention of the domestic industry that Authority must add excise duty, sales tax, discounts, commissions etc to the domestic industry's non injurious price and countervailing duty on the imports for determining injury margin, the Authority notes that these issues are similar to the issues pending before the Honourable Delhi High Court. The Authority further notes that it has, initiated action for considering the issues raised by a section of the domestic producers before the Honourable Delhi High Court very recently by inviting comments of all the stake holders. The Authority, therefore, holds that until final decision is taken in this regard, the Authority has to adhere to the principles outlined in the existing Annexure III. The Authority further notes that the NIP determined by the Authority in the instant case is as per the principles outlined in the present Annexure III to the Anti-dumping Rules.

#### **O. CONCLUSIONS:**

94. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- a. The product under consideration has been exported to India from subject countries below its associated normal value, thus resulting in dumping.
- b. The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
- c. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

#### **P. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

95. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

96. The concern expressed by the user sector that imposition of anti-dumping duty on the imports of PTA would adversely affect production of downstream industries is farfetched and not supported by verifiable evidence. The imposition of anti-dumping duty ranging from 2% to 11% might have a minimal cost push effect of about 2 – 3% on the cost of production of the downstream products like PFY and PSF. However, imposition of anti-dumping duties would create a level playing field for the domestic industry vis-à-vis unfair trade practices of dumping and the end users of PTA, who have been benefitting out of such unfair trade practices, would now have to pay for the raw materials at undumped/fair prices.

97. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti- dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

### **Q. RECOMMENDATIONS**

98. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal links in terms of the provisions laid down under the Anti-dumping Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries (Korea RP and Thailand) in the form and manner described hereunder from the date of issue of the notification of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No.36/2014-Customs (ADD) dated 25th July, 2014.

99. The Authority notes that Indorama Petrochem Ltd, Thailand and TPT Petrochemicals Public Limited, Thailand are related companies operating in Thailand and exported the subject goods to their own related party in India i.e. M/s Indo Rama Synthetics (I) Ltd. In view of their relationship, the Authority has recommended antidumping duty on weighted average basis for both the related exporters so as to avoid circumvention of antidumping duty.

100. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Col 8 of the table below is recommended to be imposed from the date of imposition of provisional duties, on all imports of subject goods originating in or exported from subject countries.

### **DUTY TABLE**

S. No.	Heading/Subheading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit MT	Currency US\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29173600	Purified Terephthalic Acid'	Korea RP	Korea RP	Samsung General Chemical Co. Ltd.	Samsung C&T	27.32	MT	US\$
2	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Taekwang Industrial Co. Ltd.	Taekwang Industrial Co. Ltd.,	23.61	MT	US\$
3	-do-	-do-	Korea RP	Korea RP	Any combination other than mentioned in S. No. 1 to 2 above		78.28	MT	US\$
4	-do-	-do-	Korea RP	Any country other than those countries subject to Anti-dumping duty	Any	Any	78.28	MT	US\$
5	-do-	-do-	Any country other than those subject to Anti-dumping duty	Korea RP	Any	Any	78.28	MT	US\$
6	-do-	-do-	Thailand	Thailand	Indorama Petrochem Ltd	Indorama Petrochem Ltd.	45.43	MT	US\$
7	-do-	-do-	Thailand	Thailand	TPT Petrochemicals Public Limited	TPT Petrochemicals Public Limited	45.43	MT	US\$
8	-do-	-do-	Thailand	Thailand	Any combination other than mentioned in S. No. 6 to 7 above		62.55	MT	US\$
9	-do-	-do-	Thailand	Any country other than those subject to Anti-dumping duty	Any	Any	62.55	MT	US\$
10	-do-	-do-	Any country other than those subject to Anti-dumping duty	Thailand	Any	Any	62.55	MT	US\$

101. Subject to the above, the Preliminary Finding notified vide notification of even No. dated 19<sup>th</sup> June, 2014 in respect of Korea RP and Thailand is hereby confirmed.

**R. FURTHER PROCEDURE**

102. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

**J.K. DADOO**, Designated Authority